राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का चौबीसवां दिवस [संख्या : 13

शुक्रवार,

20 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार। (व्यवधान) विशेष तौर से। नमस्कार।

डा. राजकुमार शर्मा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

नवलगढ़ शहर की सीवरेज परियोजना हेतु पुन: निविदा आमंत्रित करने की कार्य योजना

284. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ़ शहर की सीवरेज योजना स्टेट लेवल सेन्सनिंग कमेटी (एस.एल.एस.सी.) की बारहवीं बैठक में यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अन्तर्गत स्वीकृत की जाकर वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्यांश की सहमति लेकर भारत सरकार की सहमति हेतु भेजी गई थी और भारत सरकार द्वारा नवलगढ़ शहर की प्रथम चरण सीवरेज योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हां, तो कब? स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा नवलगढ़ सीवरेज योजना हेतु दिनांक 4 मार्च, 2014 को निविदा आमंत्रित की गयी थी? यदि हां, तो निविदा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त निविदा 5 अगस्त, 2014 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की

(डा. राजकुमार शर्मा)

अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निरस्त कर सीवरेज के कार्यों हेतु आर.यू.आई.डी.पी. को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है? यदि हां, तो निविदा किस आधार पर व क्यों निरस्त की गयी और निरस्त करने के बाद आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा क्या अग्रिम कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि नवलगढ़ शहर की सीवरेज परियोजना हेतु पुन: निविदाएं आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा आमंत्रित करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 7269 दिनांक 14 अगस्त, 2014 द्वारा आर.यू.आई.डी.पी. को निर्देशित किया जा चुका है? यदि हां, तो आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा अब तक नवलगढ़ शहर की सीवरेज परियोजना की निविदा पुन: आमंत्रित नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं और अब कब तक इस परियोजना की निविदा आमंत्रित कर ली जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): (1) जी हां। स्वीकृति आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। निविदा की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। नवलगढ़ शहर में सीवरेज हेतु स्वीकृत परियोजना की निविदाएं प्रशासनिक कारणों से निरस्त की जाकर विभागीय पत्र दिनांक 14.8.2014 के द्वारा सीवरेज के कार्यों हेतु अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा उक्त निर्देशों की पालना में 12 छोटे शहरों के स्थान पर 6 बड़े शहरों में प्राप्त की गयी सहायता को उपयोग में लाने, कार्य सम्पादित करने की स्वीकृति आदि बिन्दुओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु पत्रावली प्रेषित की गई लेकिन इसी दौरान विभागीय आदेश दिनांक 9.12.2014 द्वारा उक्त सीवरेज परियोजना की क्रियान्विति हेतु निविदाएं विभागीय स्तर पर आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) विभागीय आदेश दिनांक 9.12.2014 द्वारा उक्त सीवरेज परियोजना की क्रियान्विति आर.यू.आई.डी.पी. के स्थान पर एक प्रोजैक्ट सैल का गठन किया गया तथा उक्त परियोजनाओं की निविदाएं विभागीय स्तर पर आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभाग द्वारा उक्त परियोजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि के अतिरिक्त आवश्यक राशि (राज्यांश, निकाय का अंश, 10 वर्ष के संचालन एवं रख-रखाव की राशि, निविदा में प्राप्त

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

'जी' तालिका से अधिक प्रीमियम राशि) की व्यवस्था, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की गयी है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त उक्त परियोजनाओं की निविदाएं शीघ्र आमंत्रित की जाएंगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, सभी तकनीकी परीक्षण एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि के दृष्टिकोण से पर्याप्त परीक्षण करने के बाद राजस्थान सरकार और वित्त विभाग ने मैचिंग शेयर की सहमति लेकर नवलगढ़ सहित आठ शहरों को सीवरेज से जोड़ने के आदेश जारी किये थे जिसमें चिड़ावा, लक्ष्मणगढ़, सूरतगढ़, निम्बाहेड़ा, जैतारण, भादरा, छोटी सादड़ी, कपासन और नवलगढ़ शामिल हैं।

भारत सरकार ने योजना को स्वीकृत कर दिया, 4 मार्च, 2014 को निविदा भी आमंत्रित कर ली गयी। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण रहे कि निविदा आमंत्रित करने के बाद आपने सीवरेज की निविदा को निरस्त कर दिया?

आपने अपने उत्तर के भाग तीन में लिखा है कि प्रशासनिक कारणों से निविदा निरस्त की गयी, ऐसे क्या प्रशासनिक कारण थे कि भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत से अधिक अंशदान करने के बाद भी नवलगढ़ सहित 9 शहरों की आठ लाख जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया?

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही इन्टेलीजेंट हैं, क्योंकि हम एक ही जमात से आये हैं इसलिए जब इनको यू.डी.एच. मिला तब हमें उम्मीद बंध गयी थी कि हमारे नवलगढ़ के लिए पहली किश्त 32 करोड़ रुपये जब केन्द्र सरकार ने जारी कर दी, इन्होंने कहा कि हमने प्रशासनिक कारणों से निविदा निरस्त की है, तो सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसे क्या प्रशासनिक कारण थे कि जब केन्द्र सरकार ने 80 प्रतिशत अंशदान देने का आदेश जारी कर दिया, 32 करोड़ रुपये पहली किश्त में जारी कर दिये और शेष राशि जब भी राज्य सरकार मांगेगी, केन्द्र सरकार देगी। 10 प्रतिशत ही राज्य सरकार को देना था और 10 प्रतिशत हमने नगर पालिका की जो सहभागिता थी, अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका तो माइनस में है, 15 करोड़ रुपये हमने भामाशाह कमल मोरारकाजी से हाथ जोड़ कर नवलगढ़ के लिए सरकार में जमा कराये थे।

(डा. राजकुमार शर्मा)

आज पूरा नवलगढ़ शहर सड़ रहा है, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस प्रोजैक्ट को कृपा कर के करें, क्योंकि 9 शहर में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक हैं। यह सुन्दर काका आज आये या नहीं आये, चिड़ावा बैठे हैं, चिड़ावा के प्रधान भी इनके बैठे हैं। सुन्दर काका, आप भी बोलो। आप हमारे सीनियर, वरिष्ठ सदस्य हो, हमारे गार्जियन हो ...

श्री अध्यक्ष: आप मंत्रीजी से सवाल पूछिये। सवाल पूछिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कह रहा हूं चिड़ावा भी शामिल है और निम्बाहेड़ा भी शामिल है। श्रीचन्द कृपलानीजी, आप भी बोलिये। कम से कम, मंत्री महोदय ...

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, आप नवलगढ़ शहर तक सीमित रहिये, आप दूसरों से मत कहिये, यह नवलगढ़ शहर का ही जवाब आयेगा। पूछिये आप।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं समर्थन जुटा रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय पर दबाव डालने के लिए।

श्री अध्यक्ष: नहीं वो समर्थन, वो नहीं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): हालांकि यह बड़े भाई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि नवलगढ़ की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनका अहित नहीं होने देंगे।

वो 32 करोड़ रुपये की लास्ट तारीख अभी 31 मार्च है, 31 मार्च को वो पैसा निविदाएं शामिल कर के अगर जारी नहीं किया गया तो क्या वो लैप्स हो जायेगा? और वो लैप्स हो जायेगा उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? कृपया मंत्री महोदय यह बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राजस्थान के जिन 27 स्थानों की चर्चा की गयी है उन 27 स्थानों की डी.पी.आर. अगस्त 2013 में बनी। बनने के साथ में अप्रेजल किया लेकिन यह डी.पी.आर. सारी की सारी जल्दबाजी में बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका अप्रेजल भी जल्दबाजी में किया गया

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

और जिस प्रकार का प्रापर अप्रेजल होना चाहिए उस प्रकार का प्रापर अप्रेजल इन सीवरेज योजनाओं का नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सीवरेज की योजना एक हाइली टैक्निकल प्रोजैक्ट है और कैपिटल इंटेंसिव प्रोजैक्ट है। इसमें भारी मात्रा में पैसा लगता है। चाहे वो दिल्ली से पैसा आये, चाहे वो यू.एल.बी. से पैसा आये और चाहे राजस्थान की सरकार दे, यह सारा का सारा पैसा कहीं से भी आये जनता का पैसा है और बड़ी मात्रा में जनता का पैसा सीवरेज के नालों पर लगता है।

इस परियोजना की टैक्निकलिटी को, इस परियोजना के बेसिक रिक्वायरमेंट का पूरा एग्जामिनेशन किये बिना अगर कोई डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट जल्दबाजी में तैयार की जाती है तो उसके आधार पर काम करने का मतलब पूरे के पूरे पैसे को कुएं में डालना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके आधार के ऊपर पहली बार इसमें दो निविदाएं हुईं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि निविदाएं केवल एक बार कैंसिल नहीं हुईं। इस पूरे मामले में दो बार निविदाएं हुईं। पहली बार निविदा हुई 14.8.2013 को जिसको 14.12.2013 को कैंसिल कर दिया गया और 18.12.2013 को कैंसिल करने का आदेश जारी कर दिया। उसका कारण यह था कि लोगों ने शिकायतें कीं और कहा कि राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट है उसकी पालना नहीं हुई। जब उसको एग्जामिन किया गया तो मालूम पड़ा, यह बात सही है। इसके आधार पर इन निविदाओं को निरस्त कर दिया गया। दूसरी बार निविदाएं की गयीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये की गयीं 4.3.2014 को। और पहले जो निविदा निरस्त की गयी थी वो 27 के 27 स्थानों के लिए की गयी थी और चूंकि 27 स्थानों के लिए पैसा नहीं आया, 27 स्थानों में से दिल्ली की सरकार ने यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. प्रोजैक्ट के तहत केवल 12 स्थानों के लिए पैसा आया। केवल 12 स्थानों के लिए पैसा आया, उसमें नवलगढ़ शामिल है।

इसलिए पहला टैण्डर जो 27 के 27 जगह के लिए कर दिया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी वित्तीय व्यवस्था नहीं हो पायी क्योंकि दिल्ली की सरकार ने यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. प्रोजैक्ट के तहत, जिनके प्रोजैक्ट के अन्दर यह सीवरेज की योजनाएं बनायी गयी थीं, उनका फाइनेन्शल सैंक्शन नहीं किया इसलिए वो निविदा निरस्त की गयी। जिस ट्रांसपेरेंसी एक्ट की मैंने

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

चर्चा की उसकी पालना नहीं की इसलिए वो निविदाएं निरस्त की गयीं। दूसरी बार हमने निविदाएं इन्वाइट कीं 4.3.2014 को और 14.8.2014 को इन निविदाओं को निरस्त किया।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि ऐसे कौन से प्रशासनिक कारण थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया यह 27 की 27 परियोजनाएं हैं, जो डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनायी गयी, वो आपाधापी में बनायी गयी। आपाधापी में डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाने के अन्दर इस बात को भूल गये, इसमें नवलगढ़ शामिल नहीं है। यह भूल गये कि सीवरेज परियोजना को चलाने के लिए, सीवरेज परियोजना को फंक्शनल बनाने के लिए 135 एल.पी.सी.डी. पानी की जरूरत होती है। जब तक 135 एल.पी.सी.डी. पानी की व्यवस्था नहीं हो शहर के अन्दर, तब तक सीवरेज का प्रोजैक्ट फंक्शनल नहीं हो सकता, वो कमीशन नहीं हो सकता। यह 27 प्रोजैक्ट तो वैसे और जिन 12 प्रोजैक्ट्स की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिनके यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत पैसा आ चुका था, जिसमें नवलगढ़ शामिल है। नवलगढ़ के अन्दर और डोटासराजी जहां से आते हैं, केवल दो स्थान ऐसे थे जहां पर पानी के पी.एच.ई.डी. के द्वारा प्रोजैक्ट चलाये जाने की बात थी। बाकी सारे प्रोजैक्ट्स के अन्दर पानी की व्यवस्था नहीं थी इसलिए यह तय किया गया कि एक तो डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट के अन्दर इम्प्रूवाइजेशन किया जाए। नम्बर दो, यह देखा गया कि यह सारे के सारे प्रोजैक्ट जो यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत थे वो डी.एल.बी. के थ्रू कराने की बात थी, वेरियस एजेंसीज के थ्रू कराने की बात थी। उन्होंने कहा, भाई, आर.यू.आई.डी.पी. सबसे एक्सपर्ट है राजस्थान में, ऐसा माना गया, और यह सारे के सारे काम आर.यू.आई.डी.पी. से कराये जाने चाहिए इसलिए इन निविदाओं को इन दो कारणों से दूसरी बार निरस्त किया।

तीसरी बार, हमने फिर उसके बाद देखा कि यह निविदाएं निरस्त करने के बाद उसको जब री-एग्जामिन किया, डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट को रिव्यू किया। डिटेल प्रोजैक्ट को रिव्यू करने के बाद हमने देखा कि जो डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनायी गयी थी वो एस.ओ.आर. 11 पर बनायी गयी थी।

इस बीच कीमतें बढ़ गईं। साथ में 10 साल की मेंटिनेंस, हम देख रहे हैं कि जहां-जहां भी सीवरेज लाइनें डालते हैं वहां-वहां पर सीवरेज लाइनों की क्वालिटी क्या है, कोई देखने वाला ही नहीं है। बनाने वाला ठेकेदार दूसरा है,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

देखने वाला दूसरा। उसके बाद यूएलबी को आप दे जाते हो। यूएलबी में रोज परेशानी होती है। यूएलबी के पास पैसा नहीं होता है। 10 साल तक उसकी आपरेशनल मेंटिनेंस जो आरयूआईडीपी कई प्रोजैक्टों में कर रही है। फेज 3 में हम कर रहे हैं जो फेज 2 में हम नहीं कर पाये। 10 साल का आपरेशनल मेंटिनेंस, अब जब निविदाओं में शामिल करेंगे तो एसओआर 2011 की बजाय एसओआर 2013 में, डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट जब हमने इनकी बनाई तो डिटेल प्रोजैक्ट बनाने पर पैसा बढ़ा। वायबिलिटी गैप आ गया। एक कारण तो यह था कि एसओआर बढ़ गई, एसओआर 2013 हो गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण था कि पानी की कई जगह व्यवस्था करने की बात कर रहे थे, उस कारण से पैसा बढ़ गया। तीसरा 10 साल का आपरेशनल मेंटिनेंस की बात हमने उसमें जोड़ दी। इसलिए यह जो वायबिलिटी गैप आया, इस वायबिलिटी गैप के फंड को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार को, एफडी को भेजा है। मैं पूरी बात कर लूं। साथ में हमने इसके लिए यह भी देखा कि इन सब चीजों में कमियां हो रही हैं। डीपीआर बनानी पड़ रही हैं। फिर डीपीआर बदलनी पड़ रही हैं। पानी की व्यवस्था के बिना सीवरेज की योजनाएं बनाई जा रही हैं। यह स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए हमने एक सेल का निर्माण किया। इसी काम को वह सेल करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने फाइनेन्स डिपार्टमेंट को भेजा है कि यह जो वायबिलिटी गैप है, इस गैप को पूरा करने के लिए, क्योंकि नवलगढ़ में भी 10 साल के लिए ओएंडएम की व्यवस्था हम करना चाहते हैं। न केवल हम नवलगढ़ में सीवरेज लाना चाहते हैं बल्कि सीवरेज के साथ-साथ अगले 10 साल तक उसके आपरेशनल एवं मेंटिनेंस की व्यवस्था भी करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट जो रिवाइज्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट है, जो आगमेंटेड है, उस प्रोजैक्ट रिपोर्ट के अन्दर जो संसाधनों की कमी आई है, आपने कहा कि यह पैसा आ रहा है हमारा, 80 परसेंट पैसा दिल्ली से आ रहा है और 10 परसेंट यूएलबी दे रही है, 10 परसेंट ही केवल स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। नहीं, लेकिन उन्होंने कई चीजों में बेरियर लगा रखा है। वह ओएंडएम के लिए पैसा नहीं देते हैं। उन्होंने ओएंडएम के लिए पैसा सैंक्शन नहीं किया है। लेकिन हमारा यह मानना है कि जो आरयूआईडीपी फेज 1 और आरयूआईडीपी फेज 2, इन 2 परियोजनाओं में जितने में भी सीवरेज का

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

काम किया है, उसके आधार पर हमारा यह एग्जामिनेशन है कि जब तक ओएंडएम की व्यवस्था ढंग से नहीं होगी, तब तक सीवरेज को ढंग से फंक्शनल हम नहीं कर सकते हैं। पूरी बात सुनें, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट को रिवाइज कर दिया गया है। उसमें जो वायबिलिटी गैप आया है, उस गैप के फंड की पूर्ति के लिए एफडी को लिख दिया गया है। एफडी ने उसमें कुछ क्वैरीज लगाई हैं। उन क्वैरीज की पूर्ति हमने कर दी है। अब क्वैरीज की पूर्ति करने के बाद, मैं समझता हूं कि जब एफडी के अन्दर इस बात की सैंक्शन हो जाएगी, उसके साथ ही नवलगढ़ के अन्दर हम काम शुरू कर देंगे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अर्थशास्त्री हैं, पूरा जवाब दे सकते हैं। आपने स्वीकार कर लिया है कि नवलगढ़ के अन्दर टैक्निकल समस्या नहीं है। आपने खुद ने स्वीकार किया है कि नवलगढ़ उन शहरों से बिलकुल अलग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि सिर्फ नवलगढ़ की बात करो। जब मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया तो नवलगढ़ की निविदाएं आप कब जारी करोगे? कब सीवरेज का काम शुरू करवा दोगे? आप तो सिर्फ इतना-सा बता दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, मेरे पास में भारत सरकार की यूआईडीएसएमटी के फिगर हैं, यह जो एप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी लिस्ट है। इनके साथ मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर की भी 15-15 शहरों की परियोजनाएं स्वीकृत हुई थीं। वह काम अभी पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी आज आपको गुमराह कर रहे हैं मंत्री महोदय कि इसमें तकनीकी परीक्षण नहीं किया गया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह तकमीना बनाने वाले, तकनीकी परीक्षण करने वाले यही अधिकारी पिछली सरकार के थे। आज वही अधिकारी कह रहे हैं कि तकनीकी परीक्षण नहीं किया गया।

आप जैसे बुद्धिमान मंत्रीजी से हम तो यह उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस सदन के माध्यम से मेरी नवलगढ़ की जनता को यह तोहफा दे दीजिए और जो हमने 15 करोड़ रुपये सेठों से जमा कराए हैं और 32 करोड़

(डा. राजकुमार शर्मा)

रुपए केन्द्र सरकार ने दिए हैं, राज्य सरकार मात्र 10 प्रतिशत राशि दे रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों का संरक्षण करें।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): नवलगढ़ शहर सड़ रहा है। पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। हर चीज जब हमारे नवलगढ़ में सम्मिलित है तो हमें क्यों वंचित किया जा रहा है? सरकार तो आती-जाती रहती है। कभी इनकी और कभी हमारी। लेकिन जो योजनाएं जनहित की हैं, उनको यह लागू रखेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है मंत्री महोदय से।

श्री अध्यक्ष: आपके लिए प्रशंसात्मक शब्द प्रयोग किये हैं उनका भी ध्यान रखते हुए जवाब दे दीजिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कई डिग्रियां दीं। अर्थशास्त्री भी कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कारखाना एक ही है।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें, कृपया शांत रहें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने यह स्वीकार कर लिया है कि डीपीआर में कमियां नहीं थीं। मैंने पहले भी कहा कि डीपीआर में कमियां दो कारणों से थीं, कई स्थानों पर डीपीआर बना दी गई सीवरेज के लिए, लेकिन पानी के लिए 135 एमएलटीडी की व्यवस्था नहीं की। कई जगह सीवरेज की योजना बना दी, परियोजना बना दी, लेकिन उसके आपरेशनल मेंटिनेंस की कोई व्यवस्था नहीं थी। नवलगढ़ में पानी का तो पीएचईडी का एक प्रोजैक्ट है। लेकिन 10 साल का आपरेशनल एंड मेंटिनेंस का उसमें शामिल नहीं था। इसलिए हमने जो डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट दुबारा बनाई। उसको रिवाइज किया, तो नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि जो इनिशियल प्रोजैक्ट बना था नवलगढ़ के लिए तो वह था 82 करोड़ रुपए का और हमने जब 10 साल की ओएंडएम को शामिल किया कि हम नवलगढ़ की जनता को न केवल सीवरेज देना चाहते हैं बल्कि फंक्शनल और लोंग लास्टिंग सीवरेज देना चाहते हैं। हम वोटों के लिए सीवरेज नहीं देना चाहते हैं। जनता की सेवा के लिए सीवरेज देना चाहते हैं। इसलिए

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

10 साल की ओएंडएम मेंटिनेंस को शामिल करने के बाद अब जो प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनी है एसओआर 12 में, वह बनी है 105 करोड़ की। यह जो गैप है उस गैप को कौन देगा? यह यूआईडी एसएसएमटी नहीं देगी। यह डीएलबी भी नहीं देगी। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि डीएलबी के पास पैसा नहीं था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को और मुरारका फाउंडेशन को भी, कि उन्होंने उस पुराने प्रोजैक्ट के अन्दर 10 परसेंट पैसे के गैप की व्यवस्था की। जब हमने मांग करके गैप की व्यवस्था की है तो यह बढ़ा हुआ पैसा जो है उसमें 10 परसेंट पैसा देना भी मुश्किल हो जाएगा। यह बढ़ा हुआ पैसा जब तक राजस्थान की सरकार नहीं दे तब तक नवलगढ़ के अन्दर यह काम नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: आप कोशिश कीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसलिए जो रिवाइज्ड डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट पेश की है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सरकार की आप बात कर रहे हैं, सरकार तो आप खुद हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप विराजें। हां, सरकार है, इसलिए कह रहा हूं कि हमने हमारी सरकार के फाइनेंन्स डिपार्टमेंट को इन सारी चीजों से अवगत कराते हुए, इन तथ्यों से अवगत कराते हुए लिखा है। उन्होंने कुछ क्वैरीज की हैं कि यूआईडी एसएसएमटी पैसा तो देती है। लेकिन पैसा देने के साथ कुछ शर्तें लगाती है। रिफार्म्स की शर्तें। अगर वह रिफार्म्स आपने नहीं किए तो यूआईडी एसएसएमटी दूसरी किस्त नहीं देने वाली है। 40 परसेंट की पहली किश्त देकर के अगर उसने हाथ खींच लिए तो क्या होगा? इसलिए यूआईडी एसएसएमटी की जो रिफार्म्स की जरूरत है, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जिन रिफार्म्स की जरूरत के बारे में यूआईडी एसएसएमटी ने कही है, वह जरूरत कांग्रेस के राज में पूरी नहीं हुई। लेकिन हमारे राज में हम उन रिफार्म्स को पूरा करके यूआईडी एसएसएमटी की दूसरी किस्त की भी व्यवस्था करेंगे। यह मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आज ही जो क्वैरीज की हैं फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने इस मामले में, उन सारी क्वैरीज का काम्प्रिहेंसिव जवाब देते हुए, इस पूरे मामले को एफडी को दुबारा भेज दूंगा और उसके आधार पर मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि जितनी भी जल्दी हो पाएगी, हम नवलगढ़ की जो हमारी जनता है, उसके लिए सीवरेज की व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आपका प्रश्न नवलगढ़ शहर से है?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): इसी से है।

श्री अध्यक्ष: इससे सम्बन्धित नहीं है? नवलगढ़ शहर से सम्बन्धित है?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स एंड डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक आरयूआईएफडीओ 2013-14 लैटर क्रमांक 6137-45 इसी से सम्बन्धित माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया, उसी से सम्बन्धित है, उसके अन्दर ब्यावर के अन्दर भी योजना स्वीकृत हुई थी।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, मैं अलाउ नहीं करूंगा। ब्यावर का अलाउ नहीं करूंगा। नवलगढ़ शहर के बारे में पूछना है तो ठीक, नहीं तो विराज जाइए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी लैटर से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। लैटर तो है, हां, हां विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आपसे मेरी प्रार्थना है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। रिलेवेंट नहीं है ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आप आदेश दे दोगे तो माननीय मंत्री महोदय बहुत ही विद्वान हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: संदर्भ नहीं है, आप विराजें, आप विराजें। आप मिल लेना। मंत्रीजी से मिल लेना। आप पूरक प्रश्न करेंगे? आपका करेंगे आप तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय राजकुमारजी का और राजपालजी का जो संवाद हुआ है।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसमें इतना-सा फर्क है-उधर तो जल्दी-जल्दी है और इधर आहिस्ता-आहिस्ता।

श्री अध्यक्ष: नन्दकिशोरजी, पूरक प्रश्न करेंगे क्या? नवलगढ़ शहर के बारे में?

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): नवलगढ़ में यह डिमांड कर रहे हैं, हमारे यहां फतेहपुर में सीवरेज ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, अगला सवाल। अगला सवाल।

श्री जोगाराम पटेल।

जयनारायण विश्वविद्यालय द्वारा प्री टीचर्स एजुकेशन टैस्ट के आयोजन से प्राप्त आय

285. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयनारायण विश्वविद्यालय द्वारा गत 7-8 वर्षो से प्री टीचर्स एजुकेशन टैस्ट (पी.टी.ई.टी.) आयोजित करवाया जा रहा है? यदि हां, तो पी.टी.ई.टी. के आयोजन से विश्वविद्यालय को कितनी आय हुई और विश्वविद्यालय द्वारा किस-किस मद पर कितना-कितना व्यय किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विश्वविद्यालय द्वारा पी.टी.ई.टी. परीक्षा के आयोजन से होने वाली आय में से आधी राशि सरकार को देय है? यदि हां, तो उक्त से जो आमदनी हुई, उसका विधिवत आडिट करवाकर आय की राशि में से आधी राशि सरकार को सुपुर्द कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में नियमों की पालना नहीं करने के कारण विश्वविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) जी हां। प्री टीचर्स एजुकेशन टैस्ट (पी.टी.ई.टी.) वर्ष 2008 से 2014 तक जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के द्वारा आयोजित करवाया गया है। पी.टी.ई.टी. के आयोजन से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को वर्ष 2008 से 2014 तक हुई आय एवं व्यय का मदवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(श्री कालीचरण सराफ)

(2) जी हां। पी.टी.ई.टी. के आयोजन से होने वाली शुद्ध आय की आधी राशि राज्य सरकार को देय है।

उक्त विश्वविद्यालय को पी.टी.ई.टी. से हुई आमदनी, उसका विधिवत आडिट, आय की कुल राशि तथा राजकोष में जमा करवाई गई राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

उक्त विश्वविद्यालय के द्वारा पी.टी.ई.टी. दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने के कारण राज्य सरकार के द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई है:-

1. नियमानुसार राशि राज्य सरकार को जमा नहीं कराने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने एवं सभी वर्षों की बकाया राशि तत्काल जमा करवाने हेतु समन्वयक, पी.टी.ई.टी. को विभाग के पत्र दिनांक 13.3.2015 के द्वारा निर्देशित किया गया है।
2. आगामी पी.टी.ई.टी. के आयोजन का कार्य जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से हटाकर महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को दे दिया गया है।
3. वर्ष 2008 से 2014 तक की राशि की देयता के बारे में विशेष आडिट करवाने हेतु वित्त (अंकेक्षण) विभाग को लिखा जाना प्रस्तावित है।
4. विश्वविद्यालय के द्वारा देय राशि जमा न कराने की स्थिति में सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय को देय अनुदान में से बकाया राशि का समायोजन किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि यह जो प्रश्न लगा है, यह मरु प्रदेश, मारवाड़ के उस विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है जो ख्याति प्राप्त था। इस विश्वविद्यालय की विश्वविख्यात ख्याति थी। लेकिन विगत 5-6 वर्षों में उस विश्वविद्यालय की हालत यह हो गई है कि धीरे-धीरे वहां विद्यार्थियों का एडमिशन भी दिनों-दिन घटता जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले यह जोधपुर विश्वविद्यालय था। कालांतर में उस शख़्सियत के नाम से रखा गया जो स्वतंत्रता सेनानी थे और मारवाड़ की एक बहुत बड़ी शख़्सियत रही हैं श्री जयनारायणजी व्यास। लेकिन

(श्री जोगाराम पटेल)

उनके नाम से जिस विश्वविद्यालय की साख पर बट्टा लगाया गया, वह आप देखें। यह पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2008 से 2014 तक इस विश्वविद्यालय ने आयोजित की। लेकिन इस विश्वविद्यालय ने जो परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2 के रूप में अपनी आमदनी और खर्चे को दर्शाया है, अगर उसका थोड़ी देर के लिए आप भी अगर अवलोकन करें तो शायद आपने अपने इतने राजनीतिक जीवन में, 81-82 साल की उम्र में ऐसे खर्चे नहीं देखे होंगे, जैसे खर्चे इन्होंने इसमें दर्शाये हैं।

श्री अध्यक्ष: मेरी उम्र आप बार-बार क्यों बोलते हैं?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सर, आपको याद दिला रहे हैं। वह हमारा जो कल रखा था माननीय तिवाड़ी साहब ने, वह सहस्र दृष्टि, कौनसी दृष्टि थी सहस्र दृष्टि? इसलिए, मेरा पहला प्रश्न यह है कि जो शिड्यूल 2 दिया है, परिशिष्ट-2 दिया है, माननीय मंत्री महोदय, इसमें पद 1 में कुल आमदनी बताई है और पद 2 में कुल खर्चे बताए हैं। पद 3 में कुल बचत बताई है और पद 4 में शुद्ध 50 प्रतिशत आमदनी बताई है और इसमें राजकोष में 3 करोड़ रुपये जमा कराने बताए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टोटल जो आमदनी हुई है, इन वर्षों में इस विश्वविद्यालय को 96 करोड़, 52 लाख, 9 हजार, 526 की आमदनी हुई है। इस आमदनी में यह जो 2013-14 की जो आमदनी हुई है उसको जान-बूझकर के छिपाया गया है।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक सैकिण्ड, सवाल पूछ रहा हूं। इसमें 2013-14 की आमदनी को छिपाया गया है। अगर इस आमदनी को सम्मिलित किया जाए तो शायद यह डेढ़ या 2 अरब के आस-पास है। लेकिन मेरा जो पहला प्रश्न है, माननीय मंत्रीजी, क्या यह सही है कि आपके जवाब में बताए गए हिसाब के अनुसार वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक जयनारायण विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पी.टी.ई.टी. परीक्षा के आयोजन से कुल 96 करोड़, 52 लाख, 9 हजार, 526 रुपयों की आमदनी हुई है व सभी तरह के खर्चे जोड़ने पर कुल 41 करोड़, 24 लाख, 77 हजार, 111 रुपए का खर्चा हुआ। इस तरह 55 करोड़, 27 लाख, 32 हजार, 415 की शुद्ध बचत हुई। तो फिर आपने अपने

(श्री जोगाराम पटेल)

जवाब में सरकार को देय कुल बचत की 50 प्रतिशत राशि 25 करोड़, 70 लाख, 15 हजार, 403 ही कैसे बता दी?

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013-14 में प्रवेश आवेदन पत्र शुल्क के अलावा करोड़ों की आमदनी हुई, उसको आय के मद में क्यों नहीं दर्शाया गया? वर्ष 2013-14 के हिसाब को 3 साल व्यतीत होने के उपरांत ही टेंटेटिव हिसाब क्यों बता दिया गया? पहला प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पर हमारे जो पूर्व मुख्य मंत्री थे, उनकी बड़ी विशेष कृपा थी। श्री नाथजी देने वाले और श्री नाथजी ही पाने वाले। यानि, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब यह मुझे जानकारी मिली कि 2008 से अभी तक जो 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का बनता है, वह उन्होंने जमा नहीं करवाया। यह निश्चित रूप से बहुत ही गम्भीर बात है। इसलिए हमने यह कहा है, कल मैंने सब अधिकारियों को बुलाया था और वी.सी. साहब को भी बुलाया था। मैंने कहा कि 3 महीने में यदि आपने यह 50 परसेंट राशि वापस जमा नहीं कराई तो हम जो आपको अनुदान देते हैं 80 करोड़ रुपये का, उसमें से हम इस राशि को काट लेंगे। उन्होंने यह विश्वास दिलाया है कि 3 महीने के अन्दर-अन्दर हम इस राशि को जमा करवा देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी इन्होंने गड़बड़ियां की हैं, आपको ध्यान होगा कि पिछले विधान सभा सत्र में जब गहलोत साहब मुख्य मंत्री थे तो वहां भर्ती के मामले में जिस प्रकार की गड़बड़ियां हुई थीं, उसके बारे में सदन में बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ था। विपक्ष में होने के नाते हम लोगों ने उसकी जांच की मांग भी की थी। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि उन पर विशेष कृपा थी ...(व्यवधान) विराजो, विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपने उनसे मांग की। आप अब सरकार के अन्दर हो तो जांच कराओ इस मामले की।

श्री अध्यक्ष: बैठ जाओ, बैठ जाओ। डिस्टर्ब मत करो। बैठ जाओ।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): हमने इसी बात को ध्यान में रखकर, क्योंकि वहां गड़बड़ियां हुईं, यह तय किया है कि जितनी भी आमदनी हुई और जो खर्चा हुआ, माननीय सदस्य सही बता रहे हैं कि इसमें

(श्री कालीचरण सराफ)

हिसाब में भी गड़बड़झाला है। हम इसका दुबारा से वित्तीय अंकेक्षण करवायेंगे और जितनी राशि बनती है, वह निश्चित रूप से 3 महीने के अन्दर-अन्दर वसूल करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आ गया जवाब, पूरा आ गया।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): एक मिनट। मैं यह भी बता दूं कि अब हमने यह पी.टी.ई.टी. का जो एग्जाम है, वह उनसे ले लिया है और महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को यह काम दे दिया है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न करेंगे आप? जवाब तो पूरा ही आ गया करीब-करीब।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अभी और परतें हैं। दूसरा प्रश्न। पहले प्रश्न का तो माननीय मंत्री महोदय ने यह बता दिया कि हम वापस अंकेक्षण करायेंगे। मेरा निवेदन है कि आडिटिंग थर्ड पार्टी से करावें। इनके आडिटर से आडिटिंग नहीं करायें। इनके आडिटर से आडिटिंग नहीं होती है। थर्ड पार्टी से, निष्पक्ष पार्टी से आडिटिंग करावें। आप जो रिकवरी करें वह 55 करोड़, 27 लाख, 32 हजार, 415 की करें, न कि 25 करोड़ की। आपको आमदनी 55 करोड़ हो रही है और यह 25 करोड़ ही बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। हो गया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): प्रश्न पूछा ही नहीं। दूसरा प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: यही तो है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): देखिए, मैंने भी यह पढ़े हैं, इसमें लिखा है गोपनीय कार्य खर्च, 1 करोड़, 10 लाख, 81 हजार, 256 इसी प्रकार से आदर-सत्कार खर्च ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): प्रति वर्ष बताया है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): प्रति वर्ष का ही बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप शांत रहिए। शांत रहिए। सुनिये जवाब।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): इसी प्रकार से इन्होंने बताया है कि आदर-सत्कार खर्च 2 लाख...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 2 लाख नहीं, 28 लाख है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): 2 लाख 4 हजार 373, इसमें मुझे भी गड़बड़ लग रही है।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): गड़बड़ है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): इसलिए जो आपने कहा है थर्ड पार्टी से इसकी आडिट करायेंगे और जो भी गड़बड़ियां होंगी उसको दुरुस्त करके पूरा पैसा उनसे वसूल किया जाएगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दूसरा प्रश्न। वह पहला था।

श्री अध्यक्ष: दूसरा कर चुके हैं आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दूसरा किया ही नहीं। दूसरा प्रश्न अब पूछ रहा हूं। क्या यह सही है कि आपके जवाब में बताए गए हिसाब के अनुसार वर्ष 2008 से 2014 तक जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा पी.टी.ई.टी. परीक्षा के आयोजन में जो खर्चे बताए गए हैं, वह खर्चे देखने मात्र से ही अत्यधिक लग रहे हैं। डबल खर्चे लिखे गए हैं। अनावश्यक भी हैं। जिसमें स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। क्या मंत्रीजी इसकी आडिटिंग विशेष आडिटर से करवाने का विचार रखते हैं?

क्या विश्वविद्यालय के अधिकारी जैसे वित्तीय सलाहकार, रजिस्ट्रार, समन्वयक, पीटीईटी, को कन्वेंस अलाउंस दिया गया है, सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, गाड़ी सरकार की है फिर भी कन्वेंस अलाउंस ले रहे हैं। कन्वेंस अलाउंस, इसकी गाड़ी होते हुए भी यात्रा भत्ता, वाहन किराया देय है? क्या इसकी विस्तृत निष्पक्ष जांच करवाएंगे? एक और आखिर में, साथ ही पूछ लूं।

जयनारायण विश्वविद्यालय से पीटीईटी परीक्षा के आयोजन से जो आमदनी हुई उसमें सम्बन्धित बीएड कालेज को कोई राशि देय है, यदि देय है? यदि हां, तो ऐसी राशि सम्बन्धित कालेजों को भुगतान कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? कब तक कर दी जाएगी? घोर अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध मंत्रीजी कोई कार्यवाही करने का और जांच करवाने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? इस विश्वविद्यालय को बीएड कालेजों और सरकार को बकाया राशि पर ब्याज सहित वसूल करेंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं पहले ही कह चुका हूं कि मैंने डिटेल में देखा तो मुझे भी इन खर्चों में

(श्री कालीचरण सराफ)

गड़बड़ नजर आ रही है। इसलिए मैं निश्चित रूप से आपने सुझाव दिया, थर्ड पार्टी से इसकी आडिट करवाकर जो भी गड़बड़ होगी उसके हिसाब से सब कार्यवाही की जाएगी, नम्बर एक।

दूसरा आपने पूछा यह बीएड कालेज के मामले में, तो मैं आपको बता दूं कि 75 परसेंट राशि अब तक भुगतान कर दी गई है और जिनकी शिकायतें हैं उनकी रोकी गई है, शेष 25 परसेंट प्रैक्टिकल परीक्षा के बाद सम्बन्धित महाविद्यालय से शपथ पत्र प्राप्त कर भुगतान की जाती है। अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह। (व्यवधान) और क्या चाहिए? (व्यवधान) पूरक प्रश्न श्री बाबू सिंह। (व्यवधान) एक इधर से और एक उधर से।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा जब विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार या घोटाला चल रहा है तो प्रश्न लगने के बाद आप उनको पत्र लिख रहे हैं कि देय राशि आप जमा कराएं, उसमें अनियमितताएं हैं, यह जो शुल्क आया है, पीटीईटी का, उसके अलावा भी उन्होंने शुल्क लिया है सम्बन्धित कालेजों से लिया है। हम लोग यह चाहते हैं कि आप उच्च स्तरीय आडिट कमेटी प्रदेश की बनाकर जांच कराएं वास्तव में बहुत बड़ा घोटाला आपके सामने आएगा। आप उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर, आडिट इसकी कराकर इस घोटाले को उजागर करना चाहते हैं? गड़बड़ है पर कम से कम आप गड़बड़ मत होना। आप गडबड़ नहीं होना इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। यह बताएं आप।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जब यह प्रश्न लगाया तब यह सारी गड़बड़ियों की जानकारी हमको मिली और हाथों-हाथ हमने यह कह दिया कि इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी और यह पीटीईटी का जो टैस्ट करते हैं उनसे लेकर हमने अजमेर विश्वविद्यालय को दे दिया, अब एक उच्च स्तरीय जो मैंने

(श्री कालीचरण सराफ)

कहा थर्ड पार्टी से हम इसका अंकेक्षण करवाकर जो भी गड़बडि़यां होंगी जो भी घोटाला होगा, किसी भी दोषी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा।

श्री अध्यक्ष: चलो। दूसरा पूरक प्रश्न श्री कैलाश भंसाली, जोधपुर से सम्बन्धित है। (व्यवधान) नहीं, विराजिए आप।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मैं इस विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट का मैम्बर होने के नाते यह प्रश्न वहां आया। हमने वाउचर्स देखे, सारे फर्जी वाउचर्स, डबल वाउचर्स और अनाप-शनाप, अनियमितताओं के साथ में खर्चा किया गया और इसका जो बंटवारा होना था उसका भुगतान नहीं किया गया। यह इतनी शर्मनाक बात है और सारे अखबारों में बड़ी हैड लाइंस में छपा है कि जोधपुर विश्वविद्यालय में बीएड परीक्षा के साथ ...(व्यवधान) आप सुनिए। जो भर्ती हुई थी उसमें भी अनियमितता हुई है, मेरा निवेदन है कि हमने कमेटी बनाई है जिससे कहा गया है कि इसका स्पेशल आडिट करवाया जाए, पिछले तीन वर्षों से आडिट नहीं हुआ है और बार-बार कहने के बावजूद भी आडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है इसलिए मैं यहां से निवेदन करूंगा माननीय मंत्रीजी से कि जल्दी से जल्दी तीनों सालों का आडिट करवाएं और आडिट के साथ में इसकी जांच करावें।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। यह जोधपुर से सम्बन्धित है। अब पूरक प्रश्न नहीं होगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो बात ही कहूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहती हूं कि आडिट की जहां तक बात आई है, माननीय मंत्रीजी यह बताएं कि आडिट कितने दिन में करवा देंगे, आज इसका फैसला करें, पन्द्रह दिन में, महीने में, बीस दिन में, कब करवा देंगे, इसका निर्णय आज करें। दूसरा जो अनियमियतताएं हुई हैं और जो भर्तियां हुई हैं गलत उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? ऐसा नहीं हो कि उनको स्थायी कर दिया जाए, उनके बारे में माननीय मंत्रीजी यह बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। दोनों का जवाब दे दो, कैलाश भंसाली का भी और इनका भी।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय अनियमितताएं जो हुई हैं उसके लिए तो मैंने कह ही दिया कि थर्ड

(श्री कालीचरण सराफ)

पार्टी से इसकी आडिट करवाकर जो भी गड़बड़ियां होंगी उनके बारे में कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) और जो बाकी घोटाले हुए हैं भर्ती में, और में, तो मैं यह घोषणा करता हूं कि हमारे जो कमिश्नर हैं कालेज एजुकेशन के, उनकी अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर मैं उनको निर्देशित कर रहा हूं कि एक महीने के अन्दर-अन्दर वह जांच रिपोर्ट, जांच करके रिपोर्ट दे दें जिससे हम कार्यवाही कर सकें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। अमृत लाल। (व्यवधान) नो, नो, तीन प्रश्न हो गए। श्री अमृत लाल। (व्यवधान) नो, तीन प्रश्न हो गए, मैं अलाउ नहीं कर सकता। श्री अमृत लाल।

जयसमन्द झील में जाखम बांध व अनास से पानी लाने की योजना

286. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार एशिया की विश्व प्रसिद्ध मीठे पानी की जयसमन्द झील को पानी से हमेशा भरी रखने के लिए जाखम बांध या अनास के व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को डायवर्ट कर जयसमन्द झील को भरने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या झील भरने की महत्ती योजना का प्रारूप तैयार करवाया गया है? यदि हां, तो इसके मूर्त रूप लेने में कितना समय लगने की सम्भावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना हेतु राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): (1) जी नहीं। जयसमन्द झील को पानी से हमेशा भरी रखने हेतु जाखम बांध से कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। अनास के व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को डायवर्ट कर जयसमन्द झील में डालने हेतु बजट घोषणा वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत की गई थी। इस कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी परन्तु अपरिहार्य कारणों से इसे प्राप्त नहीं किया गया।

अनास नदी का पानी जयसमन्द में अपवर्तित करने के कार्य हेतु संसाधन उपलब्धतानुसार वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(2) जी नहीं। जाखम बांध या अनास नदी के पानी को जयसमन्द में अपवर्तित करने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने से इस कार्य हेतु बजट आबंटन प्रस्तावित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पहला।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार पेयजल की समस्या के निदान और जल संसाधन में वृद्धि हेतु नदियों को जोड़ने और अन्य बड़ी योजनाओं पर विचार कर रही है, बजट आबंटन कर रही है तो छोटी योजना पर आबंटन में क्या परेशानी है? इससे मेवाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा लाभांवित होगा। मावली, वल्लभनगर, लसाड़िया, धरियावाद, सलूम्बर, उदयपुर, सराड़ा, इससे पेयजल आपूर्ति होगी और साथ ही साथ सराड़ा और सलूम्बर में लगभग एक लाख बीघा के क्षेत्र में किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे साफ दिखाई देता है कि बहुत बड़ी राशि निवेश कर पेयजल और सिंचाई हेतु सर्वे करवाकर इस माही का पानी जयसमन्द में डाला जाए, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयसमन्द को देखा जाए तो इसकी कैपेसिटी 14 हजार एमसीएफटी की है लेकिन इसका 50 परसेंट यानी हर दो साल में जब देखते हैं जो भराव हो रहा है वह वन थर्ड ही हो पाता है। साढ़े तीन से चार हजार एमसीएफटी तक ही वह भर पाता है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह वास्तव में उचित है कि हमने जयसमन्द को भरा तो आने वाले समय में लोग ड्रिंकिंग वाटर, बहुत सारी स्कीम्स को और सिंचित क्षेत्र भी हम बढ़ा सकते हैं लेकिन फिलहाल इसके अन्दर जो प्रायोरटाइज किया है, राज्य सरकार ने ऐसी चार योजनाएं, जैसा कल सिंचाई मंत्रीजी ने अपनी डिमाण्ड के भाषण में भी कहा था, ब्राह्मणी नदी को बनास नदी से जोड़ने की जो योजना है इसके अलावा हमारी पारबती, काली सिन्ध नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है, तीसरी हमारी साबरमती नदी का पानी जवाई बांध में लाने की जो योजना है वह, ...

श्री अध्यक्ष: आप जयसमन्द के बारे में जवाब दीजिए, इसका स्कोप मत बढ़ाइए। जयसमन्द के बारे में ही बात कीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं इसीलिए कह रही हूं कि जयसमन्द का जो है, फिलहाल ये चार योजनाएं सरकार ने ली हैं, इसके अलावा जयसमन्द जो है वह अभी फिलहाल विचाराधीन नहीं है लेकिन आने वाले समय में इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे? श्री फूलसिंह मीणा। जयसमन्द से सम्बन्धित ही पूछना।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): बिलकुल। उसी से सम्बन्धित पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप उसके पेटे में आते हैं इसलिए आपको अलाउ किया है।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एशिया प्रसिद्ध झील जयसमन्द उदयपुर का नाम एशिया में है, यह एक मीठे पानी की झील है और यह भरी रहने से हमारा उदयपुर को कहीं पानी नहीं मिल रहा था, हफ्ते में एक दफे पानी मिलता था, जयसमन्द झील एकमात्र स्रोत था। उससे उदयपुर को वर्षों से पानी मिल रहा है। यह अगर भरी रहती है, जो गुजरात में वेस्ट पानी जा रहा है उसको अगर राजस्थान में उदयपुर को स्वर्णिम अवसर मिलेगा। इसमें खेती को ही नहीं हमारी आम जनता को पीने का मीठा पानी मिलेगा। पर्यटक दृष्टि से यहां पर आम जनता को व्यवसाय मिलेगा। साथ में सलूम्बर, उदयपुर ग्रामीण ही नहीं पूरा सराड़ा, सलूम्बर के आम किसानों को तीनों फसल करने का मौका मिलेगा। यह झील हमारे लिए वरदान साबित होगी। गुजरात में जो व्यर्थ पानी जा रहा है उस पानी के लिए एक ऐसी योजना बनाकर तुरन्त प्रभाव से पानी लाने की योजना हो, प्रायोरिटी पर लेकर इस झील को भरी रखें तो हमारा एशिया के अन्दर पहले ही नाम है। उदयपुर में मीठा पानी मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): इसके लिए मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रायोरिटी पर लेकर इसके लिए कोई योजना बनाएं और इस मीठे पानी की झील को भरी रखें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सुझाव है उनका।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहती हूं कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए जयसमन्द झील में जो आरक्षित पानी है वह 700 एमसीएफटी है। उसमें से 600 एमसीएफटी उदयपुर को अभी भी पीने के लिए पानी दिया जा रहा है। इसके अलावा जहां तक कमाण्ड एरिया का सवाल है एक लाख बीघा अभी सिंचित किया जा रहा है और 16 हजार हैक्टेयर कमाण्ड एरिया में जयसमन्द से हो रहा है। यह योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना को आने वाले समय में देखा जाएगा, हमारे वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ही इसके ऊपर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: गौतम भाई मीणा, आप भी पेटे में हो, आप करो सवाल।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयसमन्द झील में मेरी लसाड़िया क्षेत्र की सभी पंचायतों का पानी जाता है जिसमें 3-4 नदी-नालों का पानी जाता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है, पोंड, लसाड़िया, बलिसा, कालीमेद पंचायतों में पानी की आप क्या व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, यह उससे सम्बन्धित है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): पीने के पानी को लेकर माननीय सदस्य ने आपके माध्यम से जो बात पूछी है, मैं यह बताना चाहूंगी कि सलूम्बर के 72 गांव, कुरावड़ और लसाड़िया के 21 गांव, ये सारे जयसमन्द झील की योजना से विचाराधीन हैं। उसके बारे में पानी की अवेलेबिलिटी, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो जयसमन्द झील का रिजर्वेशन है वह लिमिटेड है। मैंने कहा, 700 एमसीएफटी पानी लिमिटेड है। उसमें से 600 एमसीएफटी आलरेडी उदयपुर को जा रहा है, 100 एमसीएफटी आसपास के गांवों को जा रहा है। इसका रिजर्वेशन ड्रिंकिंग वाटर के लिए बढ़ाने के बाद फिर ये सारी योजनाएं हम क्रियान्वित कर पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री रणधीर सिंह भीण्डर। (व्यवधान) बस, तीसरा सवाल हो गया। अगली बार लेंगे आपका।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, जयसमन्द स्कीम से मेरे विधान सभा क्षेत्र के जगत और दांतीसर गांव जुड रहे हैं। उसमें 4-5 गांव उसके आसपास के रह गये हैं वे भी उसमें जोड़ने का आप आदेश करावें।

दूसरा, जयसमन्द का पानी अगर उदयपुर जा ही रहा है तो आरएसएमएम का पानी जो उदयपुर जा रहा है उसको जगत, कुरावड़ एरिया में डाइवर्ट कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष: सुझाव है। अगला सवाल। श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): मेरे जाखम से जुडा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: तीन सवाल हो गये। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, वल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है निश्चित रूप से वल्लभनगर क्षेत्र, कुरावड़, सारी पंचायत हैं, आरएसएमएम का पानी है उसके बारे में हम लोग विचार कर सकते हैं अगर वह पानी डाइवर्जन मिलकर उपलब्ध कराया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: देवेन्द्र कटारा।

अनुसूचित जाति/जनजाति के नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों की बकाया छात्रवृत्ति

287. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2011-12 से सरकारी व निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों के कितने-कितने आवेदन छात्रवृत्ति हेतु 31 जनवरी, 2015 तक प्राप्त हुए तथा कितने आवेदकों को छात्रवृत्ति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिले में स्थित जवाहर लाल नेहरू नर्सिंग प्रशिक्षण कालेज भांकरोटा में कितने एस.सी. तथा एस.टी. के प्रशिक्षणार्थियों ने वर्ष 2012-13 में प्रशिक्षण लिया? क्या उक्त सभी प्रशिक्षणार्थियों से वर्ष 2012-13 में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आनलाइन मांगे गये थे? क्या उक्त सभी प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति दे दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक छात्रवृत्ति दे दी जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरूण चतुर्वेदी): (1) राजस्थान में सरकारी व निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं को विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 से 2014-15 (फरवरी, 2015 तक) में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं स्वीकृत आवेदन पत्रों का वर्षवार, वर्गवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जयपुर जिले में स्थित जवाहर लाल नेहरू नर्सिंग प्रशिक्षण कालेज, भांकरोटा जयपुर से विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति के 17 एवं अनुसूचित जनजाति के 18 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उक्त सभी आवेदन पत्र स्वीकृत कर दिये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, जवाहरलाल नेहरू नर्सिंग प्रशिक्षण कालेज, भांकरोटा वर्तमान में भांकरोटा में है ही नहीं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के 10 स्टूडेंट उसमें अध्ययनरत हैं। आज सुबह 10 बजे तक न तो उनको छात्रवृत्ति मिली है, न किसी प्रकार के चैक मिले हैं। जिस प्रकार से परिशिष्ट 'अ' में 16 नम्बर पर जयपुर जिले का वर्ष 2012-13 में 1337 आवेदन प्राप्त हुए थे और 1227 का भुगतान बताया है। मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में जो सूचना आयी है, एक तो कालेज भी वहां वर्तमान में नहीं होना तथा इन विद्यार्थियों को आज तक छात्रवृत्ति नहीं मिलना, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आप इस बारे में यदि भुगतान किया गया तो इन छात्रों की सूची और कौनसी तारीख को किया गया है, यह अवगत कराएं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो स्पेसिफिक प्रश्न किया है, 2012-13 में सही है कि जयपुर में 1337 एप्लीकेशन प्राप्त हुई थीं और 1227 का हमने निष्पादन किया, उनको स्वीकृत किया। कई कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से आक्षेप लगते हैं जिन कारणों से उन एप्लीकेशंस को डिस्बर्स नहीं कर पाते, स्वीकृत नहीं करते। फार्म में कोई कमी रह गई हो। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 2.5 लाख रुपये तक की आय सीमा है। उससे अधिक होगा तो उसको भी नहीं मिलेगी। हमने इसको 2012-13 से आनलाइन कर दिया था। लाकिंग

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

सिस्टम है, उस लाकिंग डेट तक अगर कोई एप्लाई नहीं करता और बाद में आता है तो वह भी आक्षेप में माना जाता है। साथ ही उस संस्था के द्वारा भी कई सूचनाएं हैं, उस बच्चे के पास कब पहुंचा, क्या हुआ, इन सबके बारे में हमें फारवर्ड करना पड़ता है। अगर उनके द्वारा फारवर्ड नहीं हुआ तो आक्षेप में रहेगा।

दूसरी बात उन्होंने कहा है कि कालेज यहां नहीं चलता। यह बात सही है कि कालेज 2011-12 के बाद शिफ्ट होकर चाकसू में चला गया। पहले भांकरोटा में था, इस कारण 2011-12 की जो इनकी एप्लीकेशंस थीं वे इसी कारण रुकीं, जिनको बाद में अलाउ करके उनको सारा डिस्बर्स भी कर दिया है। बाद में चाकसू गया, इसकी रिपोर्ट भी आ गयी, हमने अपडेट कर लिया। जिन विद्यार्थियों को कालेज शिफ्ट होने के कारण से स्कालरशिप नहीं मिली उन सबको देने का चल रहा है। आपने स्पेसिफिक बात कही है कि किन-किन विद्यार्थियों को दीं और कब-कब गयीं, वह अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा एक-एक विद्यार्थी की और किन-किन तारीखों पर दी गयी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। ठीक है। शुभकरण चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, मैं तो मात्र इतना मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब कालेज शिफ्ट होने से बच्चों की स्कालरशिप रुक सकती है तो ऐसे कौन से नियम बने कि कालेज वालों को आपने कोई दण्ड नहीं दिया और बच्चों की आपने स्कालरशिप रोक दी, बात एक।

दूसरी बात यह है कि जब स्कालरशिप सरकार को देनी है तो एक निजी शिक्षण संस्थान को ऐसा अधिकार क्यों दे दिया गया कि वह भी कुछ आक्षेप उसमें लगा दे, बच्चों का भविष्य खराब कर दे और उन गरीब बच्चों को, एससी, एसटी के लोगों को पैसा न मिले।

तीसरी बात आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या इनके कोई मापदण्ड हैं? मैं पूरे राजस्थान में ऐसी सैकड़ों इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट आपको दे सकता हूं जो दो-दो, तीन-तीन, चार-चार कमरों में चल रही हैं, मापदण्ड के अनुसार उनके भवन नहीं हैं, क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं,

(श्री शुभकरण चौधरी)

उसके बाद भी वे चल रही हैं और बच्चों को स्कालरशिप नहीं दी इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। इस सवाल से सम्बन्धित हो तो जवाब दे दीजिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि कोई कालेज कहां थी और उसके बाद शिफ्ट हो गयी, हमारे जिस आफिस में, मान लीजिए जयपुर शहर की है तो जयपुर आफिस डील करेगा, देहात में है तो देहात करेगा। शिफ्ट होने के कारण से वैरिफिकेशन की दिक्कत आती है और वैरिफिकेशन के बाद ही हम इसको करते हैं। 2012-13 से आनलाइन किया, आनलाइन सिस्टम के आधार पर इन सब कमियों को दूर किया है। फिर भी जहां-जहां शिफ्टिंग की बात आती है, शिफ्टिंग की सूचना आने के बाद पंचायत और नगरपालिका से रिपोर्ट लेते हैं, वैरिफाई करने के बाद सबकी स्कालरशिप स्टूडेंट्स की हम डिस्बर्स कर रहे हैं।

दूसरी बात आपने कही कि कहीं अलग-अलग छोटे-छोटे भवनों में चल रहे हैं। जिन-जिन इंस्टीट्यूशंस को एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा रिकाग्नाइज किया हुआ है उनको हम अपने यहां देते हैं, स्कालरशिप देने का करते हैं। वैरिफिकेशन हमारा आफिस भी करता हैं। कई कमियां ऐसी रहती हैं जब तक वे दूर नहीं होंगी तब तक उनको स्कालरशिप नहीं देते। अलग-अलग कारणों से कमियां हैं, वे पूरी होने के बाद ही हम करते हैं। आने वाले टाइम में हम एक सिस्टम कर रहे हैं। जो वैरिफिकेशन में विलम्ब होता है इसके कारण से बच्चों को स्कालरशिप में काफी डिले होती है। हमने आनलाइन किया, सिस्टम में लाक इन का एक टाइम डाला है कि 31 तारीख तक हमारे पास एप्लीकेशंस आ जानी चाहिए। पिछले सालों में स्थिति यह थी 2009 से 2013 तक 5 लाख से ऊपर तक की पैडेंसी थी। अब इसका कोई जवाब नहीं कि 2009 में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया।

हम 2013-14 तक भी उसको स्कालरशिप नहीं दे रहे हैं इसके कारण से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी होगी। जिस परिवार के पास पैसा नहीं था, 2009 से 2013 तक उसने उस बच्चे को पढ़ाया तो किस हार्डशिप में पढ़ाया होगा। हम जब सरकार में आये और आने के बाद जब यह विषय

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

ध्यान में आया तो एक अभियान चलाया और इनकी जो छोटी-छोटी चीजें और कमियां थीं, उनको दूर किया। आज लगभग 8-9 परसेंट के आस-पास पैंडेंसी बची हैं और सबको हमने दूर किया है। आने वाले समय में इस सिस्टम को और ठीक किया जाए इसलिए वैरिफिकेशन का जो क्लाज होता था उसमें इंस्टीट्यूशन करता था बच्चे से और हमारे विभाग के द्वारा। इसके लिए हम एक सैल्फ वैरिफिकेशन का क्लाज डाल रहे हैं कि बच्चे की तरफ से जो सूचना दी जाएगी उसी सूचना को मानते हुए स्कालरशिप की समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो, इस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से दो सवाल पूछना चाहती हूं। क्या यह सही है कि हायर एजुकेशन के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिल पा रही? इसका कारण बताने की कृपा करें। क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा 141 करोड़ की राशि को रोक लिया गया है जिसके कारण 1 लाख 32 हजार छात्र-छात्राएं इस छात्रवृत्ति से वंचित रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजो-विराजो। यह जनरल सवाल अलग है। आप विराजो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): इसके लिए हमारे क्या प्रयास रहेंगे? मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं। एक प्रश्न, जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, जो अपनी मनमर्जी से छात्र-छात्राओं के....

श्री अध्यक्ष: अब निवेदन कुछ नहीं। यह सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, आप विराजिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): जो छात्रवृत्ति के फार्म हैं उनको रिजैक्ट कर देती हैं, हम ऐसी संस्थाओं के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का मानस रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आपकी बात का जवाब होगा नहीं क्योंकि यह बहुत जनरल पूछ लिया।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): एक प्रश्न जो आपने किया उसका मैं जवाब दे चुका कि कालेजेज में छात्रवृत्ति नहीं देने की जबरदस्त शिकायतें थीं। हम जब सरकार में आये, मैं मंत्री बना तो लगभग

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

हर दिन काफी बड़ी संख्या में स्टूडेण्ट्स आते थे कि स्कालरशिप दिला दो। अपने यहां के सदन के भी बहुत सारे सदस्यों से सदन में बार-बार यह विषय आता था कि स्कालरशिप नहीं मिल रही है। मैंने बताया कि उसमें कमियां रहती थीं तो उस सिस्टम को ठीक करके लगातार हमारे विभाग के नीचे तक के अधिकारियों ने इसका फालो-अप किया और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर जो पैंडेंसी थी उसको दूर किया है। आने वाले समय में इसमें जो कमियां हैं उनको भी हम दूर कर रहे हैं और समय पर स्कालरशिप मिले उसका प्रयास कर रहे हैं। एक बात और माननीय सदस्य ने कही है कि केन्द्र सरकार के द्वारा एस.सी. की स्कालरशिप का पैसा दिया जाता है उसमें से कुछ पैसा अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। उसके लिए विभाग प्रयास कर रहा है, वहां के विभाग के द्वारा भी फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा गया है, प्रयास है कि जल्दी मिल जाएगा और इसके कारण से किसी विद्यार्थी को विलम्ब नहीं हो, इसका प्रयास हम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुशील कटारा। तीसरा प्रश्न है यह।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आपने पैंडेंसी के बारे में नर्सिंग प्रशिक्षण जो प्राप्त कर रहे थे उनका परिशिष्ट 'अ' में वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक का बताया है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि परिशिष्ट-'अ' अगर आप देखें तो वर्ष 2011-12 में जहां अजमेर जिले में 187 आवेदन प्राप्त हुए और मात्र 70 छात्रों को स्कालरशिप स्वीकृत की गई। उसी तरह से अलवर में 2012-13 में 222 आवेदन प्राप्त हुए और 210 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इसी तरह जयपुर का देखा जाए तो 2011-12 में 593 आवेदन प्राप्त हुए और 541 छात्रों को ही छात्रवृत्ति दी गई। 2012-13 में 1337 आवेदन प्राप्त हुए और 1227 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इसी तरह कई जिलों में अभी तक छात्रों को स्कालरशिप नहीं मिली है तो आपकी पैंडेंसी कब तक खत्म होगी? जहां एक अजमेर जिले का उदाहरण देखें तो 187 आवेदन प्राप्त हुए 2011-12 में और मात्र 70 छात्रों को, मतलब आधे से भी कम, 150 छात्रों ने पढ़ना छोड़ नहीं दिया होगा? कहां पर यह गड़बड़ी हुई है? ये आंकड़े आपने ही 2011-12 से 2014-15 तक के बताये हैं तो इनमें लगभग 1000-1500 छात्र-छात्राएं ऐसे होंगे जिनको अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): इसलिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे कौन-कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिनके माध्यम से समाज कल्याण विभाग को गये होंगे और उनको अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में पहले ही इस बात को बताया है कि लगातार पैंडेंसी थी और उनमें आक्षेप भी बहुत थे। 2012-13 से विभाग के द्वारा आनलाइन स्कालरशिप का सिस्टम किया। 2011-12 तक यह हार्ड-कापी के माध्यम से हाथ से भरे हुए आते थे और कई आक्षेप उनमें थे। आक्षेपों के अलग-अलग कारण हैं, 8-9 कारण हैं जिनके कारण से आक्षेप रहते थे और उनमें कुछ विद्यार्थियों के द्वारा होते थे और कुछ इंस्टीट्यूशन के द्वारा होते थे। अभी तक एस.सी. की स्कालरशिप कैरी-फारवर्ड होती है। यह जो मैं पैंडेसी कह रहा हूं कि 5 लाख से अधिक थी उसमें 2011-12 से लेकर आज तक के भी और 2009 से अब तक के भी केसेज हैं जो पैण्डेंसी में हैं। ये 5 लाख से ऊपर थे जो अब लगभग 7-8 परसेंट रह गये हैं और उनको हम दूर कर रहे हैं।

दूसरी बात, यह जो पैण्डेंसी का विषय है इसमें आक्षेप को दूर करने के भी हम लगातार कई अवसर दे चुके हैं, स्टूडेंट्स को भी दिये हैं और इंस्टीट्यूशंस को भी दिये हैं। आगे हमारा यह विचार है कि लगातार कई अवसर देने के बाद भी जिन विद्यार्थियों ने अपनी कमियों को दूर नहीं किया, विभाग इस पर विचार कर रहा है कि एक बार अंतिम अवसर देकर उन सारे फार्म्स को हम समाप्त करें। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिनके पार्ट पर कोई कमियां थीं और उन्होंने उनको दूर नहीं किया है तो उनको भी हम एक या दो अवसर देने का विचार कर रहे हैं। एक या दो अवसर देने के बाद भी अगर वो आक्षेप दूर नहीं होते तो जहां इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कार्यवाही करने की बात होगी तो वो करेंगे या विद्यार्थी की कमी है तो उसको अवसर देने के बाद भी बार-बार अगर कमी दूर नहीं हो रही है तो विभाग उनको समाप्त करके खत्म करेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री ललित कुमार।

उचित मूल्य की दुकानों पर सामग्री वितरण की व्यवस्था

288. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम व चीनी मिलों से खाद्य सामग्री का उठाव कर उचित मूल्य की दुकान को आपूर्ति करने का नीतिगत निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो जनवरी, 2015 तक कितनी सामग्री उचित मूल्य की दुकानों को आपूर्ति की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों से खाद्य वितरण का कार्य प्रत्येक माह सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में किये जाने का तय किया है? यदि हां, तो पूर्ववर्ती व्यवस्था व वर्तमान व्यवस्था में राशन डीलर्स के विरुद्ध शिकायतों में कितनी बढ़ोतरी या कमी हुई? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) जी हां। भारत सरकार द्वारा आबंटित खाद्यान्न (गेहूं) की मात्रा का उठाव भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित गोदामों से कर डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा पात्र लाभार्थियों को वितरित किया जाता है। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 दिनांक 2.10.2013 से प्रभावी है। उक्त योजनान्तर्गत माह अक्टूबर, 2013 से जनवरी, 2015 तक उचित मूल्य दुकानों को आपूर्ति की गई खाद्यान्न (गेहूं) की मात्रा का माहवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

दिनांक 1.6.2013 से केन्द्र सरकार द्वारा चीनी को लेवी से नियंत्रण मुक्त करने व सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु चीनी की खरीद खुले बाजार से कर आपूर्ति करने के निर्देशों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. द्वारा निविदा के माध्यम से चीनी मिलों से चीनी की खरीद कर प्रदेश के चीनी थोक विक्रेताओं को आपूर्ति की गई। चीनी का माहवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों से खाद्य वितरण का कार्य सरकारी कर्मचारी की मौजूदगी में किये जाने की व्यवस्था लागू नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो परिशिष्ट-1 पर जानकारी दी गई वो माहवार है जबकि मेरा प्रश्न है कि कितनी सामग्री उचित मूल्य दुकानदारों को आपूर्ति की गई। यह सदन की मेज पर रखें। दूसरा, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि 2010 में मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना के अन्तर्गत यह घोषणा की गई थी कि सरकारी कर्मचारी के सामने उचित मूल्य दुकान से सात दिन खाद्य सामग्री का वितरण होगा जबकि आपके विभाग द्वारा यह व्यवस्था लागू नहीं की गई है, यह बताया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को किस आधार पर बन्द किया गया तथा क्यों बन्द किया गया? साथ ही मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि 7 जुलाई, 2014 को माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार एक उच्च सचिव स्तर की कमेटी बनाई गई थी उसमें यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जो वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि तथा नियंत्रण और भविष्य में कीमतों में वृद्धि नियंत्रण के लिए एक कंटिंजेंसी प्लान तैयार करने के लिए कहा गया था...

श्री अध्यक्ष: विराजिये। जवाब आने दीजिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): इसे कब तक लागू किया जाएगा? इस कमेटी की क्या रिपोर्ट आई? यह मैं पूछना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज से आने वाले माननीय सदस्य ने जानकारी चाही तो मैंने अक्टूबर, 2013 से लेकर जनवरी, 2015 तक पूरे स्टेट में आबंटन की मात्रा को दर्शाया है। साथ ही इनके बारां जिले में सहरिया परिवारों को 22373 गेहूं जो 35 किलो प्रति परिवार नि:शुल्क जनजाति विकास विभाग द्वारा, दाल 2 रुपये प्रति किलो नि:शुल्क, तेल 2 किलो नि:शुल्क, सरस घी एक किलो नि:शुल्क, हम यहां से आबंटन प्रत्येक जिला रसद अधिकारी को करते हैं और जिला रसद अधिकारी वहां अपना उप आबंटन पी.डी.एस. के जरिये करता है। प्रत्येक पी.डी.एस. की दुकान में यदि कोई सामग्री नहीं पहुंची और इसकी माननीय सदस्य जानकारी चाहें तो मुझे बता दें, मैं उसकी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

दूसरा, इन्होंने सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में कहा है। 11.3.2010 में उचित मूल्य की दुकानों द्वारा राजकीय कर्मचारी की उपस्थिति

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

में खाद्यान्न सामग्री का वितरण पूर्ववर्ती सरकार द्वारा करने के आदेश किये गये थे लेकिन साथ ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 10.7.2012 को यह समाप्त कर दिया गया।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

अनुपस्थिति अनुमति

प्रताप सिंह, श्री, सदस्य, को दिनांक 16.3.2015 से सत्रांत तक

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 16 मार्च, 2015 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से जिला दौसा के थाना रामगढ़ पचवारा में रात्रि को घर के बाहर सोते समय श्री बीरबल, अध्यापक की बदमाशान द्वारा गला रेत कर हत्या कर देने की घटना के सम्बन्ध में।

(2) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से अभी हाल ही में जिला टीबी अस्पताल, नागौर में हुई सीधी भर्ती में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से शिक्षा विभाग में समान प्रकृति और परिस्थिति के, समायोजन से वंचित रहे, अनुदानित शिक्षण कर्मचारियों को समायोजित करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नरेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से बैंकों द्वारा किसानों को देय किसान क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल होने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(3) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से सीमावर्ती जिला बाड़मेर में अकाल एवं सूखे की स्थिति को देखते हुए पशु शिविर खोलने के सम्बन्ध में।

(4) श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, सदस्य की ओर से किसानों की भूमि का तकासमा (भूमि बंटवारा) एवं आम रास्ते खोलने सम्बन्धी कार्य नहीं होने से किसानों में व्याप्त भारी रोष के सम्बन्ध में।

(5) श्री चन्द्रभान सिंह ''आक्या'', सदस्य की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ के वर्षा एवं ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती शिमला बावरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में आगजनी की घटनाओं में प्रभावी कार्यवाही हेतु अग्निशमन कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(7) श्री भीमा भाई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में माही कैनाल का सर्वे करवाकर नोन-कमांड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(8) डा. राजकुमार शर्मा, सदस्य की ओर से झुंझुनूं जिले में सैनिक स्कूल खोलने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(9) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के कनेराघाटा क्षेत्र के ग्राम पीपलखेड़ी के रेण का नाका लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणी के जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती अलका सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के आभानेरी एवं झांझीरामपुरा पुरामहत्व के स्थानों का विकास करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से बीकानेर के स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा देने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

<u>पर्ची</u>

आज दिनांक 20 मार्च, 2015 को शून्यकाल में बोलने हेतु 40 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्री संजीव कुमार, भादरा नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज निर्माण कार्य में विलम्ब एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री छोटू सिंह, जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र व अन्य विभागों में बने गोदामों व कालोनियों का सही उपयोग नहीं होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री सुखराम विश्नोई, जालौर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गर्मियों में बाजरे का बीज जबरन खरीदने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हमीर सिंह भायल, सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

श्री धीरज गुर्जर। (अनुपस्थित) श्री नरेन्द्र कुमार।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मैंने उनका नाम पुकारा है। आप बैठिये। नहीं सुनूंगा। आप बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपके नागौर का कुछ नहीं है। आप बैठिये। नहीं, अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, अंकित नहीं हो। नो, नो, नो। आप बैठिये। बिना अनुमति के नहीं बोल सकते। आप बिना अनुमति के नहीं बोल सकते। बैठिये। आप बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: यह आपकी हमेशा की आदत पड़ गई है। नहीं। नो, नो, नो, नो, नो, नो। आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। मैं कोई जानकारी देना चाहती हूं। मुझे दो मिनट का समय चाहिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। आप भी बैठिये। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। आप बैठिये। मैंने आपके प्रस्ताव को सरकार से जानकारी करने के लिए भेज दिया है। इसके बाद आपको बोलने की इजाजत नहीं। नो। आप बैठिये। सरकार को भेज दिया है मैंने जानकारी के लिए। कोई इजाजत नहीं मिलेगी। (व्यवधान) इधर से कोई जवाब नहीं देगा। नहीं देगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, कोई गम्भीर नहीं है। सरकार को भेज दिया है। नो। अंकित नहीं हो। यह आदत में है इस आदमी की। हमेशा अवज्ञा करता है। निर्दलीय है। निर्दलीय की अपनी हैसियत के हिसाब से आप बोलिये। 10 मिनट से ज्यादा नहीं। नहीं, बैठिये आप। आप बैठिये। मैंने कहा है, आप बैठिये। आप बैठिये, अन्यथा मुझे नाम लेकर पुकारना पड़ेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: सरकार से जानकारी के लिए भेज दिया। उसके बाद अदावत से डिस्टर्ब कर रहे हो। मैंने सरकार से जानकारी के लिए भेजा है। आप बैठ जाइये। (व्यवधान) नहीं, कोई नहीं बतायेगा। इधर से किसी का जवाब नहीं आयेगा। बैठिये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: यह बात यह हुई। दबाने का सवाल नहीं है, व्यवस्था का सवाल है। व्यवस्था का सवाल है और मैंने व्यवस्था दी है कि आपका प्रस्ताव भेज दिया है। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप निर्दलीय सदस्य आते हैं। आप बैठिये। (व्यवधान) डिमांड पर आप निर्दलीय को 10 मिनट मिलते हैं। सात निर्दलीय है। अलग-अलग सबको ही करना पड़ता है। इधर 160 हैं, इधर 40 हैं। बैठिये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, कोई बदला नहीं है। बैठिये आप। आप बैठिये। अंकित नहीं हो। बैठिये, बैठिये। कोई मंत्रीजी जवाब नहीं देंगे। नो। कोई मंत्री का जवाब नहीं। नो नो। आप बैठिये। हाउस मैं चला रहा हूं, आप नहीं चला रहे हैं। (व्यवधान) इस सदन में मैं व्यवस्था स्थापित करूंगा और अव्यवस्थित रूप से, अदावत स्वरूप से जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं उनके साथ किसी भी स्तर पर जाकर सख्ती भी करूंगा। आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: निकाल देते हैं, वह भी आया हो तो। बैठ जाइये। देखिये आप। (व्यवधान) व्यवहार देखिये। इसका व्यवहार देखिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरा व्यवहार बहुत साफ है। बहुत सही है। (व्यवधान) नो, नो, नो। (व्यवधान) नहीं, आप बैठिये। बैठिये। आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो। नहीं अंकित होगा। जो आसन चाहेगा, वही होगा।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र कुमार। इनका एक शब्द भी अंकित नहीं होना चाहिये।

व्यवस्था का प्रश्न

आसन के पैरों पर होते हुए भी अधिकारी दीर्घा से व्यक्तियों के जाने की अनवरत प्रवृत्ति को रोकने हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, इस सवाल पर नहीं, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, आसन जब व्यवस्था दे रहा था। कई बार, बार-बार, आफिसर्स दीर्घा को यह कहने के पश्चात् आसन पैरों पर हो, वह खड़े होकर नहीं जायें। आज भी 12.05 बजे कुछ माननीय अधिकारी यहां से उठकर गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, उनके नाम का पता करके, उन्हें काशन दें, उन्हें चेतावनी दें। यह आसन के सम्मान के प्रति उनकी लापरवाही है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने सचिवालय को यह कहें कि जो-जो अधिकारी यहां विराजे थे और ठीक 12.05 बजे जब आसन पैरों पर था, तब कुछ अधिकारी गये और अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार नहीं, मैं कई दिनों से देख रहा हूं, इसलिए इनको आप अपने चैम्बर में बुलाकर, जो अधिकारी आज गये हैं, उनको आप अपने चैम्बर में बुलायें और उनको बाहर खड़ा रखें एक-एक घंटा और उसके बाद एक-एक व्यक्ति को बुलाकर आप लताड़ें ताकि आइन्दा भविष्य में ये नहीं करें।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि जहां तक व्यवस्था का सवाल है हम सारे इस इंस्टीट्यूशंस को चला रहे हैं। मैं आपसे भी एक निवेदन करता हूं कि आपके जो अधिकारी यहां आते हैं उनको आप यह इंस्ट्रेक्शन क्यों नहीं दे सकते? मैं तो करुंगा ही, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि व्यवस्था में आप भी सहयोग कीजिए और जितने भी अफसर यहां आते हैं उनको लिखकर भेजा जाए कि वो आसन का भी आदर रखें और व्यवस्था में कभी डिस्टर्ब नहीं करें, यह मेरा आपसे भी निवेदन है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आसन के निर्देशों के बावजूद क्या सरकार का दायित्व नहीं है यह? जैसा आपने कहा, आपने उचित कहा, अध्यक्ष महोदय, सरकार का दायित्व है, ये चीफ सेक्रेटरी को लिखें।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री महोदय, आपकी जिम्मेदारी है कि सदन के अन्दर आप उनको निर्देशित करें और चीफ सेक्रेटरी को लिखें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, आपने मेरा समर्थन किया, आप वरिष्ठ विधायक हैं, आपको धन्यवाद। श्री नरेन्द्र कुमार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, परिपत्र पहले जारी कर चुके हैं हम और दुबारा परिपत्र जारी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: और कीजिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): परन्तु अध्यक्ष महोदय, यह आसन सर्वोपरि है जब तक आप थोड़ी सख्ती नहीं दिखाएंगे, आप कई बार सख्त हो जाते हो और कई बार, अध्यक्ष महोदय, आप नरम हो जाते हो। अध्यक्ष महोदय, मेरी मान्यता है कि इस सख्त चेहरे के पीछे नरम दिल भी है। इसलिए उस नरम दिल के रूप में आप कई बार नरम हो जाते हो।

श्री अध्यक्ष: विराजें। हां, माननीय घनश्यामजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी का परिपत्र यदि अधिकारीगण नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की है, हमारी नहीं है और आसन की भी नहीं है। आसन से न तो प्रश्न पूछा जा सकता है, न आसन को सलाह दी जा सकती है कि आसन यह कार्यवाही करे। इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि आसन की मर्यादाओं का पालन करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आसन से आग्रह किया जा सकता है, माननीय सदस्य, आसन से प्रार्थना की जा सकती है, आसन से विनम्र निवेदन किया जा सकता है। मैंने निवेदन किया है, मैंने आग्रह किया है, मैंने प्रार्थना की है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अध्यक्ष महोदय, हम आसन का सहयोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं स्वागत कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, बीच में प्रीविलेज क्या अध्यक्ष महोदय अपनी तरफ से लाएंगे क्या? यह तो आपको लाना पड़ेगा। आप क्यों नहीं लाते हैं यह? सवाल यह है कि ये अपने दायित्व से भाग रहे हैं। इनकी जो अक्षमता है अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, ये अक्षम साबित हो रहे हैं। इनके आदेशों की पालना नहीं हो रही है, आपका सहयोग चाहते हैं। क्या डिसीप्लीनरी एक्शन अध्यक्ष महोदय उनके खिलाफ ले सकते हैं? सरकार को लेना पड़ेगा, आप इसके लिए कार्यवाही कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं परिपत्र 10.2.2015 का ताजा पढ़कर के सुना देता हूं आपको। यह मैं मानता हूं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ...(व्यवधान) आपकी कोई मानता ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आज अध्यक्ष महोदय, मुझे और शक्ति प्रदान की है प्रतिपक्ष ने, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और सबसे ज्यादा आपने। मैं इसका सख्ती से पालना कराऊंगा और अध्यक्ष महोदय, आप बुलायें या नहीं बुलायें, जो अधिकारी 12 बजकर 5 मिनट पर यहां से उठकर गए। उनका नाम चिन्हित करके और मैं आपके चैम्बर में आकर के निवेदन करुंगा कि ये अधिकारी गए हैं और भविष्य में ऐसा नहीं हो, उसकी सख्ती से पालना के लिए मैं चीफ सेक्रेटरी को आज फिर लिखूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांति, शांति। अब चलने दीजिए, श्री नरेन्द्र कुमार।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): इसको पढ़कर के सुनाओ, मंत्रीजी, रिकार्ड पर भी आएगा। इस परिपत्र को पढ़कर के सुनाओ माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप। श्री नरेन्द्र कुमार।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं...

श्री अध्यक्ष: क्या निवेदन करना चाहती हो?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी बात है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, एक मिनट नहीं, बहुत जरूरी है तो आप मिल लीजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं सूचना देना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, सूचना नहीं, आप उनसे मिल लीजिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आप सब जगह उठ जाएं। नहीं, आप बैठ जाइए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं तो एक सूचना देना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, सूचना आप दे दीजिए व्यक्तिगत। वही सूचना हो जाएगी उनको। श्री नरेन्द्र कुमार।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्ड की जटिल प्रक्रिया के चलते किसानों को कारित परेशानी

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बैंकों द्वारा किसानों को देय किसान क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है। किसान से अत्यधिक काग़ज़ात जमाबंदी, गिरदावरी, नक्शा, खातेदारी प्रमाण पत्र आदि मांगे जाते हैं, जबकि इन्टरनेट का जमाना है। हर खातेदार की खातेदारी इन्टरनेट पर उपलब्ध होती है। इसके बावजूद इन काग़ज़ात के लिए किसान तहसील व पटवारियों के चक्कर काटता रहता है। यही नहीं, किसान कार्डधारक किसानों की जमीन बैंक के रहन होने के बावजूद ऋण सीमा (लिमिट) बढ़ाते वक्त भी बैंक प्रबंधकों द्वारा उपरोक्त समस्त कागजात (जमाबंदी, गिरदावरी, नक्शा खातेदारी) मांगे जाने से किसान आहत होते हैं। इस बारे में किसी भी कागजात की दुबारा आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। किसानों को तहसील, पटवारियों व बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, इसके लिए सरकार को इन्टरनेट की सुविधा देने के प्रयास सहित बैंकों को पाबंद किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मेवाराम जैन।

बाड़मेर में अकाल एवं सूखे के दृष्टिगत पशु शिविर खोले जाना

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अत्यन्त ही जनहित के मुद्दे पर आकृष्ट कर रहा हूं कि सीमावर्ती एवं पिछड़े ज़िले बाड़मेर में पिछले दो वर्षों से लगातार अकाल एवं सूखे की स्थिति के चलते पशुधन की बहुत दयनीय स्थिति है।

महोदय, बाड़मेर ज़िले की अधिकांश तहसीलें अकालग्रस्त हैं। अकाल की वजह से चारे की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है जिसके कारण विशेषकर गौ-वंश मर रहा है। आये दिन ज़िले में चारे की वजह से हो रही पशुधन की मौतों से आम जन उद्वेलित हैं। विभिन्न समाचार माध्यमों से आये दिन ज़िले में चारे एवं पानी की किल्लत से पशुधन की मौतों की ख़बरें छपती रहती हैं। बाड़मेर जिला प्रदेश में पशुधन के हिसाब से समृद्ध है। ज़िले के आम गरीब की आजीविका पशुओं पर निर्भर है लेकिन वर्तमान स्थिति में पशुधन पर आये चारे, पानी के संकट के कारण आम लोग गहरी दुविधा में हैं।

महोदय, ज़िले में आज 3 महीने पहले जिला प्रशासन ने ज़िले की दो तहसीलें रामसर एवं गडरारोड़ में पशु शिविर स्वीकृत किए थे। जिसको 90 दिन पूरे होने के बाद प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए बंद कर दिया जिसके कारण स्थिति और बिगड़ गई है। इन क्षेत्रों में आज यह स्थिति हो गई है कि हज़ारों की संख्या में पशुधन जहां पूर्व में पशु शिविर लगे हुए थे, वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं और वहां पर चारे एवं पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण पशु वहीं मर रहा है। जिले में अकालग्रस्त तहसीलों में पशु शिविर खोलने को लेकर आज से कुछ दिन पूर्व जिला प्रशासन से ग्रामीण क्षेत्रों के सरपंच सहित अन्य जन प्रतिनिधि मिले। लेकिन आज तक जिले में एक भी पशु शिविर स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

महोदय, सत्ता में बैठे हुए लोग अपने आपको गौ-माता का हितैषी कहते हैं और आज सीमावर्ती क्षेत्रों में गायें मर रही हैं। लेकिन सरकार खामोश है और केवल नियमों का हवाला दे रही है। पूर्व में वर्ष 2001-02 में अकाल के समय पूरे एक वर्ष पशु शिविर चले थे जिसके कारण जिले में हज़ारों पशुओं को अकाल में मौत से बचाया था।

अत: सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिला बाड़मेर में गौ-वंश मर रहा है, पेयजल की भयंकर स्थिति है, गर्मियां तो अभी आना बाकी है और इससे पहले ही हालात विकट हो गए हैं। सरकार से

(श्री मेवाराम जैन)

अतिशीघ्र जिले में पशु शिविर खोलने के आदेश जारी करावें ताकि आम किसान का, आम गरीब का पशुधन बचाया जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

किसानों की भूमि के तकासमे (भूमि बंटवारा) एवं आम रास्ते खोलने सम्बन्धी कार्यों के अभाव में व्याप्त रोष

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत राजस्थान के किसानों की भूमि बंटवारे (तकासमे) जिसमें आम रास्ता खोलने के साथ ही किसान पीढ़ियों से जमीन पर ही अपना मकान बनाकर, बाउण्ड्रीवाल बनाकर, कृषि कनेक्शन लेकर ट्यूबवैल खुदवाकर वहां पर फलों के वृक्ष एवं अन्य प्रकार के वृक्ष लगाकर अपना जीवनयापन कर रहा है। सरकार द्वारा हर वर्ष लाखों रुपये खर्च करके समय-समय पर तकासमे के शिविर लगाए जाते रहे हैं। परन्तु इन शिविरों में किसानों को किसी तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाइयों में आपसी झगड़े एवं मनमुटाव पैदा हो रहे हैं, किसान अपनी जमीन पर पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं परन्तु उसे अपने हिस्से में बंटवारा नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण राज्य में हज़ारों किसानों के बंटवारे एवं तकासमे के मामले एसडीएम, एसीएम एवं अन्य कोर्ट में कई वर्षों से विचाराधीन चल रहे हैं। जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाती है परन्तु इनके पक्ष में फ़ैसले नहीं हो रहे हैं। किसानों को परेशानी एवं मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है, इसमें किसानों को आर्थिक एवं सामाजिक परेशानियां भी हो रही हैं। जिसके कारण किसान मायूस एवं अपने आपको ठगा-सा महसूस कर रहा है।

राज्य में इन किसानों के हित में 15-20 वर्षों से कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेशों की पालना नहीं करने के कारण इन किसानों की भूमि का तकासमा (भूमि बंटवारा), आम रास्ते खोलना जैसे कार्य नहीं होने के कारण राज्य के किसानों में भारी रोष व्याप्त हो रहा है। इस बाबत मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा जिसकी मुझे सदन में चर्चा की अनुमति प्रदान की जावे। यही राज्य के किसानों के हित में होगा, साथ ही किसानों की उपरोक्त समस्या का तत्काल समाधान कर किसानों को राहत प्रदान की जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या। (अनुपस्थित)।

श्रीमती शिमला बावरी।

अनूपगढ़ में अग्निशमन कार्यालय

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अग्निशमन कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनूपगढ़, घड़साना, रावला 635 हैड, रामसिंहपुर कृषि मंडियां हैं जिससे किसान अपनी फसलें नरमा, कपास व अन्य फसलें बेचने के लिए लाते हैं। आगजनी की घटना होने पर आग बुझाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आग बुझाने के लिए टैंकरों से पानी की व्यवस्था की जाती है और समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण अपार जन-धन की हानि उठानी पड़ती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़, घड़साना, रावला में कपास व तेल की कई मिलें व अन्य कारखाने भी हैं जिनमें कई बार आग लग चुकी है और व्यापारियों को नुकसान उठाना पडा है। व्यापार मण्डलों द्वारा भी इस समस्या के समाधान की मांग की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आगजनी की घटना को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कृषि की दृष्टि से श्रीगंगानगर जिला अग्रणी है। पूर्व में भी अनेक आगजनी की घटनाएं घट चुकी हैं और जन-धन की हानि उठानी पड़ी है। क्योंकि अग्निशमन विभाग रायसिंहनगर में है जो कि घड़साना रावला से 100 किलोमीटर दूरी पर है, वहां से आने में लगभग तीन घंटे का समय लगता है, जब तक पूरा नष्ट हो जाता है। श्रीमानजी, इस सम्बन्ध में पूर्व में भी अवगत करवा चुकी हूं। अगर अनूपगढ़, घड़साना, रावला में अग्निशमन की व्यवस्था हो जाती है तो सभी वर्गों को लाभ मिलेगा।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि किसानों, व्यापारियों व आमजन के हितों को देखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र में अग्निशमन कार्यालय खोला जाए, ताकि सभी वर्गों को लाभ मिले। सधन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमा भाई। (अनुपस्थित)।

डा. राजकुमार शर्मा।

झुंझुनूं जिले में सैनिक स्कूल

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत झुंझुनूं जिले में सैनिक स्कूल खोलने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत है। भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा सैनिक झुंझुनूं जिले से आते हैं और देश में सीमा पर सबसे ज्यादा शहीद सैनिक भी इसी जिले के हैं लेकिन यहां सैनिक स्कूल न होने का मलाल स्थानीय निवासियों को रहता है। वर्ष 2013 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में झुन्झुनूं में सैनिक स्कूल खोले जाने का मामला आगे नहीं बढ़ पाया है।

उक्त सैनिक स्कूल के लिए अभी तक जमीन का आबंटन नहीं किया गया है जिसके कारण सैनिक स्कूल खोलने के मामले में विलम्ब होता जा रहा है। अत: मेरा सैनिक कल्याण मंत्रीजी से निवेदन है कि वे राज्य सरकार से भूमि का आबंटन कराकर केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर यथाशीघ्र झुंझुनूं में सैनिक स्कूल प्रारम्भ कराने की कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचंद कृपलानी। (अनुपस्थित)।

श्री जोगाराम पटेल।

लूणी में जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अधूरे पड़े विकास कार्य

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 295 के तहत विशेष उल्लेख के विषय का प्रस्ताव। मान्यवरजी, निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र लूणी, जिला जोधपुर, जोधपुर नगर क्षेत्र के करीब-करीब चारों तरफ आया हुआ है और शहर से लगता ज्यादातर भाग शहरी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में करीब 4-5 विश्वविद्यालय, महाविद्यालय व अन्य बड़े-बड़े सरकारी विभागों के आफिस भी आये हुए हैं। विकसित हो रही समस्त कालोनियां इसी क्षेत्र में आई हुई हैं। पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने इस क्षेत्र में अन्य विकास कार्यो के साथ विभिन्न प्रकार की सड़कें बनाने का कार्य भी हाथ में लिया था, हालांकि बिना वित्तीय प्रबंधन के ही इस क्षेत्र में रोड्स बनाने का कार्य स्वीकार कर प्रारम्भ कर दिए परन्तु उन्हें अधूरा ही छोड़ दिया। जेडीए द्वारा मुख्यत: ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान, झंवर, लोरड़ी, देजगरा, डोली, रोहिचा कलां, धवा, लूणावास खारा, इन्द्रोका, बैरू, केरू, रोहिला कलां, सालोडी, चौखा, रोहिला

(श्री जोगाराम पटेल)

कल्ला, नारवा, नान्दड़ी, नान्दड़ा कलां, गुड़ा विश्नोइया, खेजड़ली, मोगड़ा कलां, संरेचा, सुभदण्ड, नन्दवान इत्यादि ग्राम पंचायतों में रोड्स बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया था और करीब 70 से 80 प्रतिशत तक रोड्स बना दी गई थीं यानी डब्ल्यूबीएम का कार्य पूर्ण कर दिया था। मात्र डामर बिछाने का कार्य बाकी था और किन्हीं-किन्हीं रोड्स पर तो एक लेयर भी डामर की बिछा दी गई थी, परन्तु शेष कार्य पूर्ण नहीं किये गये जिससे पूर्व में किये गये कार्य भी व्यर्थ में जा रहे हैं और डब्ल्यूबीएम पर डामर बिछाने का कार्य नहीं होने से पत्थर निकल रहे हैं, जिससे आम जनता का उस रास्ते पर चलना ही मुश्किल हो गया है। पिछले करीब दो वर्षों से यह कार्य रुके हुए हैं। आवागमन भी रुका हुआ है जिससे जनता में भारी आक्रोश है। इन परिस्थितियों में इन अधूरे कार्यों को न केवल पूरा कराया जाना आवश्यक है बल्कि जो रोड्स गारंटी पीरियड में हैं वे भी पूर्ण रूप से टूट गई हैं, उन्हें भी तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाया जाना आवश्यक है। लम्बे समय से जेडीए द्वारा विकास के नाम पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है, न कोई विकास के कार्य स्वीकृत किये गये हैं और न ही कोई योजना बनाई गई है जिससे जेडीए के औचित्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। जिस भावना से जेडीए का गठन किया गया था उसके विपरीत जनता में भावना पैदा हो रही है इन परिस्थितियों में जेडीए की आर्थिक स्थिति ठीक कर अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करवाना व विधान सभा क्षेत्र लूणी में नये विकास कार्य स्वीकृत कर पूर्ण करवाना आवश्यक है क्योंकि जेडीए ने मेरे विधान सभा क्षेत्र की पूरी की पूरी गैर मुमकिन/सरकारी भूमि अपने नाम करवा दी है, जबकि उसके बदले लूणी की जनता को कुछ भी नहीं दिया गया है। पूरा का पूरा विधान सभा क्षेत्र लूणी जेडीए की परिधि में आ गया है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत कोई विकास के कार्य करने में सक्षम ही नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष: आपसी बातचीत नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ऐसी स्थिति में इस गम्भीर व अति आवश्यकता के विषय को आपके मार्फत सदन में रखने की अनुमति प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी था।

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप एब्सेंट थे। मैं रिपीट करूंगा तब बोलें।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी था।

श्री अध्यक्ष: आप भी एब्सेंट थे अब रिपीट करूंगा तब बोलें।

बांदीकुई के आभानेरी एवं झांझीरामपुरा पुरामहत्व के स्थानों का विकास

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख द्वारा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में दो पुरा महत्व के स्मारक हैं। पहला आभानेरी पंचायत में 11वीं सदी की पुरा महत्व की बावड़ियां हैं जो कि यूनेस्को की साइट पर भी है। यह भारत की डीपेस्ट व लार्जेस्ट बावड़ियां हैं। ये 13 मंजिल गहरी हैं। यहां रोजाना 200 से 300 विदेशी पर्यटक आते हैं लेकिन राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा केवल आभानेरी उत्सव मना कर इतिश्री कर ली जाती है। यदि इस स्थल पर पर्यटकों के लिए शैड, होटल बनाया जावे तो राजस्व की प्राप्ति के साथ-साथ पर्यटकों को भी काफी सुविधा प्राप्त होगी। इसलिए इस क्षेत्र का विकास किया जाना अति आवश्यक है।

दूसरा झांझीरामपुरा स्थान है। इस स्थान पर प्राचीन शिव मंदिर है, जहां पहाड़ों से प्राकृतिक जल आता है व गौमुख से 24 घंटे 12 महीने पानी आता रहता है। यहां पर भी देशी-विदेशी पर्यटक साल भर आते हैं लेकिन यहां पर्यटकों के नाम कोई सुविधा नहीं है।

उक्त दोनों स्थानों को विकसित किया जावे तो राज्य को राजस्व की प्राप्ति होगी व पर्यटकों को सुविधा भी मिलेगी व पुरा महत्व के स्थान संरक्षित होंगे।

अत: माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त स्थानों का सर्वे करवाकर इन स्थानों को विकसित किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी के नियमों के नियम 295 के तहत स्वामी केशवानन्द

(श्री मानिक चन्द सुराना)

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्व विद्यालय का दर्जा देने हेतु विशेष उल्लेख।

अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत बीकानेर में संचालित स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में इस सदन के समक्ष तथ्यात्मक निवेदन करता हूं। देश के थार मरुस्थल का 62 प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान प्रदेश में है जिसका महत्वपूर्ण केन्द्र बीकानेर सम्भाग है। स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, बीकानेर शहर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर श्रीगंगानगर रोड पर स्थित है। जिसके पास बीकानेर मुख्यालय पर लगभग 600 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है। जिसमें से लगभग 20 प्रतिशत भूमि पर विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन, कृषि अनुसंधान, स्नातकोत्तर शिक्षा, गृह विज्ञान महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय के साथ-साथ केन्द्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय बीज परियोजना, कृषि विज्ञान केन्द्र इत्यादि भवनों का निर्माण उपलब्ध है।

यह विश्वविद्यालय केन्द्रीय कृषि विश्व विद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के सभी मापदण्ड एवं अर्हताएं जैसे आवश्यक कृषि भूमि, सुदृढ़ आधारभूत संरचनाएं, सिंचाई जल की पर्याप्तता, वैज्ञानिक व मानव संसाधन, आदि पूरी करता है जो प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध नहीं है। यहां की विषम भौगोलिक परिस्थिति देश में अनूठी है जहां पर कृषि अनुसंधान एवं विस्तार की प्रबल सम्भावना है।

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही। इस विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रीय समन्वयक समिति की अनुशंसा के आधार पर 11 फरवरी, 2013 को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को ही केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव को राज्य सरकार ने अपने पत्रांक प.1(11)कृषि-3/2011 दिनांक 28.3.2013 के द्वारा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने का राज्य सरकार द्वारा सैद्धांतिक निर्णय की सहमति के साथ प्रेषित किया गया।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आम बजट में मिले राजस्थान को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा 7 अगस्त, 2014 को स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से डीपीआर चाही गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा चाही गई डीपीआर विश्वविद्यालय द्वारा 26 अगस्त, 2014 को उप महानिदेशक (शिक्षा), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को भिजवा दी गई।

अत: उक्त तथ्यों के आधार पर मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को राजस्थान में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की महती कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अनुपस्थित रहे सदस्यों में श्री धीरज कुमार। (अनुपस्थित)।

श्री श्रीचंद कृपलानी।

निम्बाहेड़ा की रेण का नाका लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थन विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कनेराघाटा क्षेत्र के किसानों एवं ग्रामवासियों के आग्रह पर ग्राम पीलखेड़ी के स्थानीय नाले पर रेण का नाका लघु सिंचाई परियोजना की वर्ष, 2008 में जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृति जारी की गई थी। इस परियोजना के निर्माण हेतु पीलखेड़ी, लुणखंदा एवं कनेरा आदि गांवों के किसान लम्बे अर्से से मांग करते आ रहे हैं।

जल संसाधन विभाग की विभागीय जानकारी के अनुसार स्थानीय नाले का पानी प्रस्तावित बांध स्थल के नीचे की ओर 30 किलोमीटर दूरी पर बहने वाली गुंजाली नदी में प्रवाहित होकर राणाप्रताप बांध में जाता है। वर्ष 1967 से 1998 तक के तहसील निम्बाहेड़ा के रेन फाल डाटा के अनुसार निम्बाहेड़ा के औसत वर्षा 838.20 मिलीमीटर से लगभग 77.19 मिलीयन घन फीट पानी की आवक आंकी गई है। जिसमें से 70 मिलीयन घनफीट पानी को रोककर एक बांध बनाया जाकर पीलखेड़ी, लुणखदा, भूवानियाखेड़ी तथा कनेरा गांव के लगभग 1850 परिवार लाभान्वित होंगे। जिसमें से 580 अनुसूचित

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

जाति, 310 जनजाति तथा 960 अन्य जातियों की 439.70 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

इस परियोजना के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-3(1)कृषि-1/एमसी/08/पार्ट/दिनांक 23.8.2008 द्वारा राशि रुपये 952.53 लाख की प्राप्त हुई थी। इस परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीआई) के तहत कराया जाना प्रस्तावित था। परियोजना के पूर्ण होने पर सम्बन्धित गांवों की 439.70 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान था तथा यह योजना 2011-12 तक पूर्ण होनी थी। जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व की विभागीय टिप्पणी अनुसार पूर्व में उक्त परियोजना पर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी। वास्तविक स्थिति यह है कि कनेरा घाटा क्षेत्र चम्बल एवं बनास बेसिन की रीज पर होने से वर्षा का अधिकांश पानी बहकर जिले से बाहर चला जाता है एवं यह एरिया रीज पर होने के कारण कुओं का जलस्तर काफी नीचे रहता है। जिससे कुओं में भी पानी की गहराई एवं कम मात्रा में उपलब्ध होने से काफी कम क्षेत्र में ही सिंचाई सम्भव हो पाती है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में पेयजल की भी काफी विकट समस्या रहती है।

यह क्षेत्र पानी की कमी के कारण डार्क जोन घोषित है। कनेरा घाटा क्षेत्र तीन ओर से मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा होने के कारण यहां किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई नहीं जा सकती है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर कनेरा घाटा क्षेत्र की इस परियोजना का निर्माण किया जाना उचित रहेगा।

यह कि वर्ष 2009 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक द्वेषतावश परियोजना के टैंडर लगने व शिलान्यास हो जाने के बावजूद भी इस कार्य को रोक दिया।

मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह है कि किसानों एवं ग्रामवासियों के हित में स्वीकृत योजना को पुन: स्वीकृति प्रदान करावें जिससे कि कमाण्ड क्षेत्र के काश्तकारों के जीवन में खुशहाली आ सके तथा हरित क्रांति से किसानों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमा भाई।

कुशलगढ़ में माही कैनाल के सर्वे पश्चात् नान-कमांड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं कुशलगढ विधान सभा क्षेत्र में माही की कैनाल की सर्वे करवाकर नोन कमांड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान दक्षिणी क्षेत्र में स्थित कुशलगढ़ विधान सभा में रहने वाली जनता पिछले लम्बे अर्से से यह मांग कर रही है कि पास में बने माही डैम का पानी कुशलगढ़ तक पहुंचाया जाये। लेकिन आज तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। पिछले समय में हमारी सरकार थी उस समय 140 किलोमीटर तक का सर्वे कराया गया था। तत्पश्चात चुनाव हुए और कांग्रेस की सरकार बनी तब से यह सर्वे अपने कागजों में ही रह गया।

पिछले विधान सभा चुनावों में हमारी सदन की नेता तथा माननीय मुख्य मंत्री महोदया चुनाव के दौरान कुशलगढ़ विधान सभा में पधारी थीं। उस समय लगभग 50 हजार की जनता में आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माही का सर्वे करवाकर कुशलगढ़ की सूखी धरती को माही का पानी पहुंचाने की प्राथमिकता दी जायेगी। कुशलगढ़ की जनता को पूरा भरोसा है। हमारी नेता तथा मुख्य मंत्री महोदया से पूरी आशा है कि माही कैनाल का सर्वे करवाकर कुशलगढ़ की सूखी धरती पर पानी पहुंचाने का काम होगा तथा आदरणीय माननीय गृह मंत्री महोदय जब चुनाव के दौरान पधारे थे तब उन्होंने भी विश्वास दिलाया था कि हर हालत में माही का सर्वे करवाकर कुशलगढ़ तक माही का पानी पहुंचाया जावेगा।

अत: मेरी प्रार्थना है कि इसी सत्र में कैनाल सर्वे की घोषणा की जावे और पड़ौस में बने माही डैम का पानी उपलब्ध कराने का कष्ट करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह, 'आक्या'।

चित्तौड़गढ़ के वर्षा एवं ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत जिला चित्तौड़गढ़ में गत दो सप्ताह से लगातार हो रही बारिश एवं ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मार्च माह के प्रारम्भ से ही गत 15 दिनों से जिला चित्तौड़गढ़ एवं अन्य क्षेत्र में बेमौसम बरसात के चलते प्रमुख नकदी फसल कही जाने वाली अफीम सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तेज हवा से फसलें आड़ी पड़ गई हैं। ऐसे में किसानों के सपने तार-तार हो रहे हैं। जिन किसानों ने डोडों के चीरे नहीं लगाये हैं उन्होंने हंकाई के आवेदन कर दिये हैं। जो किसान डोडों के चीरे लगा चुके हैं उन्हें लाइसेंस कटने का डर सता रहा है। क्षेत्र में किसानों द्वारा दीपावली के पश्चात बुवाई कर दी थी। बुवाई के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिसमें बरसात नहीं हुई हो। फसल में फूल से डोडा बनने और चीरा लगने तक की अवधि में हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।

इस माह के प्रारम्भ में हुई बारिश के पानी ने डोडों का दूध धो डाला। शुक्रवार और शनिवार को हुई बारिश ने एक बार फिर डोडों का दूध बहा दिया। साथ ही ओलावृष्टि के कारण हालात यह है कि अफीम के डोडे या तो फूट कर गिर गए हैं या काले पड़ने लग गए हैं और अब उनमें चीरे लगाने की जगह भी नहीं बची है। चित्तौड़गढ़ जिला अफीम अधिकारी कार्यालय के अन्तर्गत संचालित दो खण्डों में हंकाई के लिए करीब एक हजार से ज्यादा आवेदन अभी तक पहुंच चुके हैं और किसानों का तांता लगा हुआ है। कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने गत वर्ष फरवरी में हुई ओलावृष्टि के कारण फसल हंकाई करा दी थी। इस वर्ष भी नुकसान होने पर आवेदन किए हैं लेकिन अफीम नीति के अनुसार किसान लगातार दो बार अफीम की हंकाई नहीं करवा सकता। ऐसे में दूसरे साल भी आवेदन कर चुके किसानों का संकट बढ़ गया है। कुछ किसानों ने आधी एवं कुछ ने पूरी फसल हंकाई के आवेदन किए हैं। साथ ही नारकोटिक्स विभाग की टीमें हंकाई के कार्य में जुट गई हैं। विगत चार दिनों से बारिश का दौर जारी रहने एवं ओलावृष्टि से अफीम के अलावा गेहूं की कटी हुई फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। इसी प्रकार धनिया, मेथी, जीरा, आदि फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों में ऐसी स्थिति को लेकर भय व्याप्त है कि क्या सरकार उन्हें मौसम की इस मार का पूरा नुकसान भरपाई कर मुआवजा देगी भी या नहीं?

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध है कि जल्द से जल्द प्रदेश एवं चित्तौड़गढ़ जिले के सभी प्रभावित क्षेत्रों की गिरदावरी

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

करवाकर किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा दिलवाकर राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पर्चियों के माध्यम से, श्री संजीव कुमार।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

भादरा नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज निर्माण कार्य में विलम्ब एवं अनियमितताएं

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा में एक कस्बा, नगरपालिका क्षेत्र भादरा आता है। भादरा कस्बे के लिए सीवरेज निर्माण की मांग क्षेत्र के लोग काफी समय से कर रहे थे। सीवरेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा भादरा में आईएचएसबीपी योजना के अन्तर्गत दिनांक 4.1.2011 को सीवरेज निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। सीवरेज निर्माण की स्वीकृति प्रदान होने के बाद कस्बे के नागरिकों को बहुत खुशी हुई कि बहुत जल्दी भादरा कस्बे में सीवरेज का निर्माण होगा। सीवरेज निर्माण के कार्य के लिए आईएचएसबीपी योजना के अन्तर्गत 24.2.2012 को इस कार्य का कार्यादेश भी सरकार द्वारा जारी कर दिया गया लेकिन जब सीवरेज निर्माण का काम शुरू किया गया तो शहर के अन्दर जगह-जगह से सड़कों को तोड़ दिया गया, उखाड़ दिया गया। बीच-बीच में जो चैम्बर बनाए गए, भी सड़कों से काफी ऊंचे बनाए गए। उसके अन्दर पाइप लाइन डालकर वह चैम्बर काफी ऊंचे बनाए गए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्य के अन्दर बहुत ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। कार्य पूर्ण होने से पहले ही पाइप जगह-जगह से टूट गई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई हैं। चैम्बर निर्माण कार्य में भी इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ कि वह कार्य भी जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो चुका है। चैम्बर काफी ऊंचे बने उसकी वजह से लोगों को सड़क पर आवागमन में बड़ी भारी बाधा उत्पन्न हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कार्य पूर्ण नहीं होने की वजह से पूरा कार्य अधरझूल में पड़ा है। जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज पूरा भादरा शहर एक तरीके से गंदगी व कचरे का ढेर बन चुका है। आज भी सीवरेज निर्माण का कार्य अधरझूल में है।

(श्री संजीव कुमार)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विशेष तौर से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्य के अन्दर भारी अनियमितता हुई है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कार्य में विलम्ब हो रहा है और कार्य अधरझूल में है, इस काम को बहुत जल्दी करवाया जाए। इस कार्य में जो अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ इसकी आप उच्च स्तरीय जांच करवाएं। उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी लोगों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ आप इसमें कार्यवाही करने की कृपा करें, ताकि भादरा कस्बे के नागरिकों को इससे राहत मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री महोदय यहां विराजमान है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करवाएं। जांच होने के बाद नये सिरे से इस निर्माण कार्य को करवाया जाए ताकि कस्बे के, क्षेत्र के नागरिकों को राहत मिल सके। आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंह। आप रेस्पोंड कर रहे हैं क्या? छोटू सिंहजी, जरा स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भादरा शहर के अन्दर सीवरेज लाइन डालने के लिए, पूरे भादरा शहर की जो योजना बनी, वह तो उन 27 योजनाओं में शामिल है जिनकी चर्चा मैंने प्रश्नकाल के दरमियान की थी। लेकिन इंटीग्रेट हाउसिंग एवं श्रम डवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत भादरा के कुछ इलाके के अन्दर सीवरेज डालने की योजना, जैसा कि माननीय भादरा से आने वाले सदस्य फरमा रहे थे, वह चल रही है। 39.67 किलोमीटर का सीवर बिछाने का 5 करोड़ 90 लाख रुपये का काम है। इसमें 39.67 किलोमीटर सीवरेज लाइन डलेगी। बायोडाइजेस्टर लगेगा और इसके साथ ही सड़क का निर्माण होगा जो सीवरेज के कारण खुद जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 18.3 किलोमीटर का सड़क का निर्माण भी इसमें शामिल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 39.67 किलोमीटर में से अभी तक 28.62 किलोमीटर की सीवर लाइन डालने का काम हो चुका है। 18 किलोमीटर की जो सड़क बननी थी, उसमें से 8.2 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। पहले यह बिटुमिन की सड़क बननी थी, बाद में यह तय किया गया कि यह सड़क बिटुमिन की नहीं बने, इंटरलाकिंग टाइल्स

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

की बने। इंटरलाकिंग टाइल्स की कास्ट ज्यादा आ रही थी इसलिए 18.3 किलोमीटर की सड़क बननी थी 316 लाख रुपये से, उसमें केवल 13 किलोमीटर की सड़क ही बन पाई। 5 किलोमीटर की सड़क नगरपालिका बनाने के लिए तैयार है, उन्होंने कुछ इलाकें में सड़क बनाई है और कुछ इलाके में बनाएंगे। साथ ही हमने दो जलाशय की टंकी बनाई है।

माननीय भादरा से आने वाले सदस्य ने कहा है इस काम के अन्दर क्वालिटी चैक ध्यान में नहीं रखा गया, मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक तो जल्दी से जल्दी इस काम को हम पूरा करेंगे, साथ ही जिस प्रकार की चिंता आपने क्वालिटी चैक के बारे में की है मैं निश्चित रूप से इसकी क्वालिटी चेक कराने के लिए थर्ड पार्टी इन्स्पैक्शन कराऊंगा और इस काम को जल्दी से जल्दी, आने वाले तीन-चार महीने में पूरा कर देंगे।

बाकी, भादरा शहर की सीवरेज योजना के बारे में बात है वह तो 27 प्रोग्राम, जिनकी चर्चा मैंने आज दिन में की थी, उन्हीं में वह शामिल है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटूसिंह।

जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र व अन्य विभागों में बने गोदामों व कालोनियों के सही उपयोग का अभाव

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस विभाग की ओर ला रहा हूं जिसकी सम्पत्ति, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे गोदाम हो, चाहे गैस्ट हाउस हो, लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं, अरबों रुपये की सम्पत्ति जिला जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के अन्दर निर्मित है, वह विभाग है आईजीएनपी। जिसके कई सैकड़ों गोदाम बने हुए हैं और सीमेंट के लिए बनाए गए थे, आज हालात यह हैं कि उनका कोई मालिक नहीं है। अधर में पड़े हैं, आधे-आधे टूटे हुए हैं। कई बार ऐसी विपत्ति आई कि इन गोदामों को, जैसे बिफोर लास्ट ईयर जब सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंगफली को लिया जा रहा था, तब रखने को जगह नहीं थी लेकिन रिकार्ड के अन्दर यह था कि ऐसे सैकड़ों गोदाम क्षेत्र के अन्दर बने हुए हैं आईजीएनपी क्षेत्र के अन्दर जिससे वहां यह अपना अनाज स्टोरेज रख सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उस अनाज को जैसलमेर से जोधपुर लाया गया लेकिन उन गोदामों की हालत ऐसी थी कि उसमें वह रख नहीं सकते थे।

(श्री छोटू सिंह)

ठीक इसी प्रकार से कई कालोनियां बनी हुई हैं, जिनकी हालत आज यह है आई.जी.एन.पी. के अन्दर कि उनमें रहने वाला भी कोई नहीं है। वे सूनी पड़ी हैं। किसी के दरवाजे नहीं हैं, किसी की खिड़कियां नहीं हैं। किसी की खिड़कियां और दरवाजे चोर कर ले गये हैं। उसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मोहनगढ़ कस्बे के रैस्ट हाउस के बारे में भी आपसे आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि रैस्ट हाउस बना, कई साल हो गये और अधर में पड़ा है। आज उसका कोई मालिक नहीं है। न दरवाजा है, न पूरा बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह अरबों रुपये की सम्पत्ति, यह दुनिया भर की कालोनियां, चाहे रामगढ़ हो, चाहे आसूतार हो, चाहे मोहनगढ़ हो, चाहे आपके दूसरा नाथना कस्बा हो, इन कालोनियों का कोई मालिक नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि या तो इन कालोनियों को किसी प्रकार से नीलाम कराकर आम जनता की भलाई के लिये दिया जाए, या फिर उन कालोनियों को हाउसिंग बोर्ड को देकर नये सिरे से इन कालोनियों का वापस विस्तार किया जाए और रहवास बनवाया जाए। आज नहर क्षेत्र के अन्दर हजारों अस्थाई ऐसे स्टोर भी पड़े हैं, ऐसे चौकीदार क्वार्टर भी पड़े हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अरबों रुपये की सम्पत्ति का आखिर क्या यूटिलाइजेशन लिया जाएगा। कई साल बीत गये, बीतते-बीतते, खुद ये मकान की जगह खण्डहर बनते जा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय भी विराजे हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्पत्ति को जो बड़े कस्बों में पड़ी है, आखिर में इसका किस प्रकार से यूज होगा, किस प्रकार से काम लिया जाएगा? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस हिसाब से सम्पत्ति है, एक मकान ही नहीं, पूरा क्षेत्र भी घेरा हुआ है। उसका गांव में किसी प्रकार का कोई यूज नहीं हो रहा है। आबादी को और डिस्टर्ब कर रहा है। आने-जाने के रास्ते भी नहीं हैं। खण्डहर भी इस प्रकार हो गये, कोई पत्थर ले जा रहा है, कोई पट्टी ले जा रहा है, कोई दरवाजा ले जा रहा है। आई.जी.एन.पी. के अन्दर आज स्टाफ की भी बहुत कमी है। जैसे-जैसे नहर बनती गयी और कर्मचारी की जैसे-जैसे अपनी नौकरी की अवस्था पूरी होती गई, रिटायरमेंट होने के बाद न तो कोई नया लगाया, न कोई इंजीनियर्स आदि आये। हम यह चाहते हैं कि इस सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से सरकार अपने कब्जे में लेकर उन गांववासियों

(श्री छोटू सिंह)

को या तो नीलाम किया जाए, या हाउसिंग बोर्ड के अन्दर मकान बनाकर, या मकान के हिसाब से इसको आमजन के उपयोग के अन्दर लिया जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मंत्रीजी भी विराजे हैं, आखिर इन सम्पत्तियों का क्या यूज लिया जाएगा, जवाब पूछना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: रेस्पांड कर रही हैं आप?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से जो सरकार का ध्यान आकर्षित किया, माननीय अध्यक्षजी, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का 1983-84 में कार्य शुरू हुआ था। उस समय जैसलमेर, मोहनगढ़, रामगढ़ और आसूतार, यहां पर कुछ कालोनियां जरूर बनी थीं। क्योंकि उनके अधिकारियों को रहने के लिये, कर्मचारियों के रहने के लिये ये पूरी कालोनियां बनाई गई थीं। लेकिन अब यह कार्य पूरा कम्पलीट हो चुका है और कम्पलीट होने की वजह से अधिकारियों की अब वहां ज्यादा पोस्टिंग है नहीं। इसलिये वे जो बात कह रहे हैं, यह ठीक है, अब यह सब खाली पड़े हैं, टूट-फूट भी हो रही है। विभाग के द्वारा इन सबको रिपेयर करवाकर और अन्य जो सरकारी विभाग हैं, उनको किराये पर दिये जा सकते हैं। उसके बारे में सरकार विचार रखती है। आने वाले समय में इसकी पूरी योजना बनाकर, कैसे हम इनका उपयोग ले सकते हैं, उसके बारे में निश्चित रूप से विचार करती है और रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

जालौर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गर्मियों में विशेष मार्के का बीज क्रय कराया जाना

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत पर्ची के जरिये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आ रही है, आवाज आ रही है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जी.एस.एस.एस., जो गांवों में ग्राम सेवा सहकारी समिति बनी हुई है। उन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को एक मैसर्स रूरल एण्ड फार्मर डवलपमेंट को-आपरेटिव लिमिटेड, मल्टी स्टेट, इसका पता है, एस.बी.बी.जे. के सामने, विद्याधर नगर, जयपुर। यह जो एक कम्पनी है, माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यह

(श्री सुखराम विश्नोई)

जो बाजरे की थैली है, यह बाजरे की थैली महज सौ रुपये की है और उसके ऊपर हाथों से लिखा है 430 रुपये। जो बिल काटकर इस कम्पनी ने सोसाइटी को दिया है, वह दिया है 410 का, आगे बेचने का 430 में, है यह सौ रुपये की। माननीय अध्यक्षजी, मेरा आपसे निवेदन है कि यह गर्मियों में बोने के लिये बाजरी है। पश्चिमी राजस्थान के अन्दर गर्मी ज्यादा पड़ती है और वहां जो गर्मियों में बाजरी पैदा होती है, वह या तो पायोनियर, या प्रो-एग्रो, या नन्दी, या धानिया, यह जो चार किस्में हैं, इन चार किस्मों की बाजरी विशेष रूप से किसान लोग गर्मियों में बोते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है यह जो कम्पनी है, इन कम्पनियों में जो बाजरा, बाजार में जो उपलब्ध मिलता है, उस बाजरे को, उसके ऊपर जो मार्क लगी हुई है, रेट लगी हुई है, वह प्रो-एग्रो पर 430 है और किसान को देते हैं, वह 330 में व्यापारी बेचते हैं। पायोनियर को, 415 वाली को साढ़े तीन सौ में बेचते हैं। नन्दी के ऊपर लिखा हुआ है 425, वह 325 में बेचते हैं। धनिया जो 420 है, उसको 325 में बेचते हैं। सौ रुपये का मार्जिन ले करके किसान को बेचते हैं। खुद व्यापारी कमाता है। खुद किसान जो 15-20 साल से पायोनियर, प्रो-एग्रो, धनिया और नन्दी की खेती कर रहे हैं, यह ग्राम सेवा सहकारी समिति के हमारे वहां जालौर के जो अधिकारी हैं, एम.डी. हैं को-आपरेटिव बैंक के, प्रशासक कलक्टर हैं, एक आहौर क्षेत्र में जो हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, आहौर में इसलिये नहीं दी गई, वहां की ज्यादातर जो जी.एस.एस. सोसाइटियां हैं, एक मजबूत कम्युनिटी के लोगों के हाथों में हैं, इसलिये वहां नहीं दी गयीं। भीनमाल, जसवंतपुरा, सांचौर, चीतलवाना, सभी जगह एक-एक लाख थैलियां बांटी गयीं। बांटने के बाद में उन्होंने कहा गया कि आप जल्दी ड्राफ्ट करके भेजो। जब मैंने इस बात का पता लगाया, कलक्टर से बात की, एम.डी. से भी बात की, उन्होंने हाथ खड़े कर दिये, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऊपर से, जो कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्रीजी ने टेलीफोन किया है, तब जा करके यह सोसाइटियों में वितरित की गयी हैं। माननीय अध्यक्षजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसान पहले ही इस रबी की फसल में बर्बाद हो चुके हैं और पुन: गर्मी में चारा पैदा करने के लिये, इस तरह की जो फर्जी कम्पनियां बना करके, फर्जी जो बाजरा बेच रहे हैं, माननीय कृषि मंत्रीजी आज सदन में नहीं हैं, परन्तु मेरा आपसे निवेदन है कि कृषि मंत्रीजी से जवाब दिलाया जाए। यह जो सोसाइटियों को, यह तो जालौर जिले का मामला

(श्री सुखराम विश्नोई)

है, जब जालौर में इस तरह की बाजरी बांटी गयी है, एक मंत्री के इशारे पर, तो पूरे प्रदेश में जरूर यह जो मैक्सहाट बाजरा है, इस मैक्सहाट बाजरे को करोड़ों की तादाद में बांटा गया है। मैंने अभी इस आंकड़े का जोड़ लगाया, यह सौ रुपये की थैली है और 430 में बेचेंगे, 330 रुपये एक बैग पर अगर वो कमाएगा, 99 लाख रुपये, माननीय अध्यक्षजी, एक मेरे जालौर जिले में ये लूट करके ले जाएंगे तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति बनेगी।

माननीय अध्यक्षजी, आप जालौर से एम.पी. रहे हुए हैं और जालौर आपका देखा हुआ है। शिक्षा में हम पिछड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इसब की, जीरे की खेती होती है, बरसात हो गई, वह कामर्शियल क्रोप पूरी चौपट हो गई है। फिर सरकार के मंत्री लोग दबाव डाल करके इस मैक्सहाट बाजरे को जबरन बेचना चाहते हैं। कलक्टर को आदेशित किया जाए, इस पूरे को सीज किया जाए और जिस कम्पनी ने इसको बेचा है, उसके खिलाफ मुकदमा किया जाए। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पांड करेंगे?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से यह विषय उठाया है कि जालौर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गर्मी में बाजरे का बीज जो कि एक प्राइवेट कम्पनी है, मैक्सहाट से जबरन वितरित करवाया जा रहा है। मैं इसके लिये, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि न तो सहकारी विभाग के द्वारा और न ही एम.डी., सी.सी.बी. जालौर के द्वारा इस तरह के कोई दिशा-निर्देश किसी को जारी किये गये हैं कि फलां कम्पनी से यह लिया जाए। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो सहकारी समितियां हैं, वे पूरी तरह से, एक तरह से स्वायत्त संस्थाएं हैं। लेकिन हमारे जो बीज का कार्य होता है, सहकारी समितियों में जो होता है, सहकारी विभाग में, वह राजफैड के द्वारा होता है और राजफैड, जो यह राजस्थान राज्य बीज निगम से लेता है। कुछ समितियों को इफ्को और कृभको भी डाइरेक्ट सप्लाई करते हैं।

(13.00 बजे)

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यद्यपि, वह स्वायत्त है लेकिन फिर भी विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी किसान को उक्त

(श्री अजय सिंह)

मैक्स-हाट कम्पनी का बीज है वह जबरन नहीं दिया जाए और मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि इसके बारे में जांच करवाकर उचित निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीरसिंह भायल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप विराजिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सांचौर वाले विधायक साहब जो कह रहे हैं, यह वास्तव में सही है। जालौर जिले में यह मैक्स-हाट कम्पनी का बीज सोसाइटीज के माध्यम से और जो माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि एम.डी. साहब के माध्यम से कुछ भी नहीं हुआ। यह वास्तव में सही है कि एम.डी. साहब के माध्यम से पूरे जालौर जिले में यह बीज, 100 रुपये की चीज है, 470 रुपये में बेची है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी और सदन से यह मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच की जाए।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने आश्वासन दे दिया।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यह सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.डी. खुद साथ में जी.एस.एस.एस. में गया है। वहां का कर्मचारी गया है जाकर, मैनेजर की बेचारे की क्या हैसियत है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया है कि पूरे मामले की जांच करवायी जाएगी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जांच का, यह कह रहे हैं कि एम.डी. ने नहीं बांटी है तो उनकी काल डिटेल निकलवायी जाए और उनकी जो गाड़ी लेकर गये, उसकी लाग-बुक मंगवाई जाए, बाकायदा वे साथ में गए और साथ में ले जाकर दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक मंत्री के खिलाफ आरोप लग रहा है कि मंत्रीजी की शह पर बांटी जा रही है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना उप खण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपकी मेहरबानी से, राजस्थान के पश्चिमी छोर में बाड़मेर, बाड़मेर में विधान सभा क्षेत्र सिवाना में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत निवेदन और प्रार्थना मेरी रहेगी कि वर्ष 2013 में पूर्व सरकार द्वारा महाविद्यालय खोल दिया गया। प्रिंसिपल भी आ गया। एडमिशन नहीं करके, फिर समीक्षा में लेकर इसको बंद कर दिया गया। पूरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय, तीन तहसील हैं, तीन पंचायत समिति हैं, दो उप खण्ड कार्यालय हैं। चार लाख की जनसंख्या है। 69 पंचायतें हैं। क्षेत्र में 40 सीनियर विद्यालय हैं। छात्र-छात्राएं संख्या 900 से 1100 तक अधिकतर रहती है। इनमें से, माननीय अध्यक्ष महोदय, 400 से 500 एस.सी., एस.टी. के छात्र-छात्राएं हैं। नजदीक कोई भी कालेज नहीं है। सिवाना से जलौर 60 किलोमीटर है। बाड़मेर 165 किलोमीटर है। जोधपुर 120 किलोमीटर है तो स्थिति यह होती है कि 12वीं के बाद में बालिका को पढ़ाई के लिए अपन बढ़ावा दे रहे हैं, उनको स्कूल छोड़नी ही पड़ती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के समय में विद्या के बिना या छात्राएं नहीं पढ़ी हुई हों या बालिकाएं नहीं पढ़ती हैं तो उनके सम्बन्ध भी बड़े मुश्किल से होते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन पंचायत समिति में न तो प्राइवेट कोई कालेज है और न कोई राजकीय महाविद्यालय है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्य मंत्री साहिबा से और माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कि मेरे क्षेत्र में महती आवश्यकता को देखते हुए, भू-भाग और सारी स्थिति को देखते हुए यहां पर कालेज खोलने की कृपा करें, यही महत्वपूर्ण निवेदन रहेगा मेरा।

शिक्षा के क्षेत्र में, जब तक बालिकाएं नहीं पढ़ेंगी और भवन के लिए भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि आई.टी.आई. का बहुत बड़ा भवन वहां पर बना हुआ है। अभी दो कमरे ही इस कोर्स में काम में लिए जा रहे हैं। 24 में से केवल 2, 22 कमरे काम में नहीं आ रहे हैं और पूरा भवन बना हुआ है। भवन के लिए भी अभी आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरा निवेदन रहेगा कि यह कालेज सिवाना में इसी सत्र में, कालेज खोलने के लिए मेरा निवेदन और प्रार्थना रहेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आप कुछ रेस्पांड करेंगे?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सिवाना उप खण्ड में न तो निजी महाविद्यालय है और न ही गवर्नमेंट के कालेजेज हैं पर यह सब कुछ डिपेंड करता है वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर। सरकार की मंशा है कि सभी उप खण्ड मुख्यालयों पर ... (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): खोला तो उसको बंद क्यों किया?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): बैठो भाई, बैठो। सभी उप खण्ड मुख्यालयों पर सरकारी कालेज हों और इसके लिए हमने दो केटेगरी बनायी हैं। 44 उप खण्ड तो ऐसे हैं कि जहां पर न तो सरकारी कालेज हैं और न निजी कालेज हैं और बाकी 178 उप खण्ड ऐसे हैं जहां पर सरकारी कालेज नहीं है। तो प्राथमिकता के आधार पर जहां पर सरकारी भी नहीं है और निजी भी नहीं है, ऐसे उप खण्डों पर सरकार की यह मंशा है कि वहां पर सरकारी कालेज खोला जाए परन्तु यह सब निर्भर करता है वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर। आप सारे नॉर्म्स पूरे करते हो तो मुख्य मंत्रीजी से बात करके जल्दी से जल्दी आपके यहां महाविद्यालय खोला जाए, इसका मैं प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आ गया आश्वासन।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री सुरेन्द्र गोयल। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्वयं आसन पैरों पर था तब घूम रहे हैं तो दूसरों को कैसे कहेंगे?

श्री अध्यक्ष: बैठ गए आपके भय से।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2013-14

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3) (एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-14

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-14 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री जोगाराम पटेल।

याचिका

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

कल्प वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण हेतु काश्तकारों को अनुदान

(1) कल्प वृक्ष खेजड़ी को संरक्षण देने एवं इसकी रक्षा हेतु काश्तकारों को अनुदान देने बाबत।

जोधपुर शहर में क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलकर नई पाइप लाइनें बिछाना

(2) जोधपुर शहर में लम्बे समय से दूषित पेयजल की सप्लाई होने से फैल रही बीमारियों को रोकने हेतु पुरानी जर्जर पाइप लाइनों को बदलकर नई पाइप लाइनें बिछाने के लिये वित्तीय स्वीकृति तुरन्त जारी करने बाबत्।

लूणी में पेयजल योजनाओं की स्वीकृति

(3) विधान सभा क्षेत्र लूणी में पेयजल समस्या के समाधान हेतु विचाराधीन पेयजल योजनाओं को स्वीकृत करने बाबत्।

श्री अध्यक्ष: श्री सुशील कटारा।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

चिखली में 132 के.वी.जी.एस.एस. की स्थापना

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी के उपखण्ड चिखली में 132 के.वी.जी.एस.एस. की स्थापना करने बाबत्।

(श्री सुशील कटारा)

सीमलवाड़ा में राजकीय महाविद्यालय की मांग

(2) विधान सभा क्षेत्र चौरासी के सीमलवाड़ा में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत्।

श्री अध्यक्ष: श्री मानवेन्द्र सिंह। श्री मानवेन्द्र सिंह। (अनुपस्थित) श्री मदन राठौड़।

जाड़न ग्राम (पाली) में अण्डर ब्रिज का निर्माण

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पाली जिले के ग्राम जाड़न में नवनिर्मित फोरलेन के बीच अण्डर ब्रिज का निर्माण करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री मोहन लाल गुप्ता।

समिति प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति (क्रम संख्या-16 से 25)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति 2014-15 के निम्नांकित दस प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण व जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण कम्पनियां (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) (संख्या-4) वर्ष 2009-2010 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का सोलहवां प्रतिवेदन;
2. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण व जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण कम्पनियां (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) (संख्या-4) वर्ष 2010-2011 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का सत्रहवां प्रतिवेदन;
3. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं जयपुर, जोधपुर व अजमेर विद्युत वितरण निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (संख्या-2) वर्ष

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

2011-2012 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का अठारहवां प्रतिवेदन;

4. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वा) वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 48, 49 एवं 50वे प्रतिवेदन में समाविष्ठ सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का उन्नीसवां प्रतिवेदन;

5. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन/प्रसारण/वितरण कम्पनियां (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वा) वर्ष 2001-02 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 53वें प्रतिवेदन में समाविष्ठ सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का बीसवां प्रतिवेदन;

6. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वा) वर्ष 1995-96 एवं 1999-2000 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2012-13 के क्रमश: 93वें एवं 95वें प्रतिवेदन में समाविष्ठ सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का इक्कीसवां प्रतिवेदन;

7. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन/प्रसारण/वितरण कम्पनियां (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वा) वर्ष 2003-04 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2012-13 के 97वें प्रतिवेदन में समाविष्ठ सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का बाइसवां प्रतिवेदन;

8. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वा) वर्ष 2006-07 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2012-13 के 99वें प्रतिवेदन में समाविष्ठ सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का तेइसवां प्रतिवेदन;

9. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन/प्रसारण/वितरण कम्पनियां (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वा) वर्ष 2006-07 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2012-13 के 101वें प्रतिवेदन में समाविष्ठ सिफारिशों

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का चौबीसवां प्रतिवेदन; एवं

10. राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वा) वर्ष 2007-08 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2014-15 के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ठ सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का पच्चीसवां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: मैं क्षमा चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक रह गया, साहब।

श्री अध्यक्ष: हां, वह इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूं। श्री ललित कुमार भी याचिका का उपस्थापन करेंगे। मेरे से चूक गया इधर-उधर लेने में।

याचिका

केलवाड़ा राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याता एवं फर्नीचर की व्यवस्था

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से केलवाड़ा राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याता एवं फर्नीचर की व्यवस्था करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-16, द्वितीय अवस्था। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान,

श्री वासुदेव देवनानी, शिक्षा मंत्री।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 197,96,33,11,000/- (रुपये एक सौ सतानवे अरब छियानवे करोड़ तैंतीस लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 24 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

मांग संख्या 47-पर्यटन की प्रस्तुति

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,05,67,61,000/- (रुपये एक अरब पांच करोड़ सडसठ लाख इकसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 47 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: आज की बहस का प्रारम्भ डा. जसवन्त यादव करेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्षजी, मांग संख्या-24 और मांग संख्या-47 पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह हायर एजुकेशन की अलग से डिमांड नहीं आई, इसी में है क्या?

श्री अध्यक्ष: जो है, वह यह है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): शिक्षा में सब आ गया न।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा में सब आ गया। इसी में है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): शिक्षा में सब आ गया।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): शिक्षा में आप भी आ गये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): शिक्षा में हमारे मंत्रीजी नहीं आये न।

(13:11 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

मांग संख्या 24 व 47 पर विचार

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 24 और 47 पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह का शिक्षा बजट दिया है और जो सोच रखी है, इसमें सरकार और मुख्य मंत्रीजी की जितनी तारीफ कर सकते हैं, उतना कम है। पहला साहसिक कदम है कि मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को भी स्वीकार किया कि प्रदेश में 3 लाख 34 हजार शिक्षक होते हुए भी शिक्षा का स्तर वह नहीं है, जो सरकार चाहती है। और यहां तक स्वीकार किया कि पांचवीं क्लास के जो बच्चे हैं, इतने शिक्षक होने के बाद भी उनका यह स्टैण्डर्ड है कि वह दूसरी क्लास

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

लायक भी नहीं है। इतनी बड़ी बात, कोई भी मुख्य मंत्री खुद की सरकार होते हुए इतना बड़ा साहसिक कदम नहीं उठा सकते। इतना स्वीकार नहीं कर सकते कि आज शिक्षा का यह हाल है। इसी स्तर को उठाने के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया शिक्षा के लिये, इस बार 21,788 करोड़ 97 लाख रुपये यानि 2014-15 का जो संशोधित है, जो 16 परसेंट अधिक किया है। यह एक सराहनीय कदम है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, सरकार ने जो घोषणा की है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के ऊपर एक सीनियर माध्यमिक विद्यालय होगा और यहां तक भी सम्मिलित कर लिया कि जो नई पंचायतें गठित हो रही हैं, करीबन 647 हैं, उनको भी इसमें शामिल किया है यानि 5,647 के लगभग जो सीनियर माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की है, यह भी अपने आपमें एक तारीफ के काबिल है। यह एक वेदना भी है, गम्भीरता भी है और सरकार द्वारा यह सोच भी है कि जब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा, तब तक राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, जिससे आदमी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, वह प्रदेश आगे बढ़ सकता है, वह समाज आगे बढ़ सकता है। इसी तरह प्रत्येक एक पंचायत के अन्दर माडल स्कूल बनाने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, सरकार ने घोषणा की है, यह भी अपने आपमें एक ऐतिहासिक कदम है। इसमें भी मुख्य मंत्रीजी को जितना धन्यवाद दे सकते हैं, उतना कम है।

इसी तरह जो पिछली सरकार ने माडल स्कूल बनाने के लिये पैसे उसके अन्दर नहीं मिलाने से जो वंचित रह गये, उस दुर्दशा को भी सुधारने के लिये इस बार अपना बजट रखा है। लगभग हर क्षेत्र के अन्दर चाहे वह शारदा छात्रावासों को ले लो, वहां के खाने की व्यवस्था को ले लो, हरेक में बजट के अन्दर बढ़ोतरी की है, तो यही सरकार की गम्भीरता है और यही राजस्थान के विकास और बहबूदी का सवाल है कि जब शिक्षा बढ़ेगी तो ही सब कुछ बढ़ेगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, जो साइकिल देने की योजना बीच में ठप हो गयी थी, उसको दुबारा चालू किया। यह भी अपने आपमें एक ऐतिहासिक कदम है। और सबसे बड़ा कदम कि जब छात्रा को प्रोत्साहित किया जाएगा तभी वह आगे बढ़ सकते हैं कि नवीं से बारहवीं तक, जो 75 परसेंट से ऊपर नम्बर लेंगे उनको स्कूटी दी जाएगी। तो यह भी मुख्य मंत्रीजी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। साइंस सब्जैक्ट से स्कूल खोल देना, यह भी बड़ा

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

कदम है। जितनी तारीफ कर सकते हैं, हर क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट रखा है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा शिक्षा का, जिसके अन्दर बजट में बढ़ोतरी नहीं की है या ध्यान नहीं दिया हो।

अब मैं कुछ मेरी तरफ से माननीय शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मुख्य मंत्रीजी ने तो भरपूर रूप से स्वीकारा भी कि शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है। हर क्षेत्र के अन्दर बजट में भी बढ़ोतरी की है। हर क्षेत्र में गम्भीरता भी दिखाई है और माडल स्कूल, सीनियर माध्यमिक विद्यालय, छात्रावास, प्रोत्साहन राशि, स्कूटी, साइकिल, यह सब देने के पीछे एक ही मकसद है कि शिक्षा का स्तर बढ़े, बच्चों का शिक्षा की तरफ रूझान बढ़े। अब माननीय शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी, मुख्य मंत्रीजी ने बजट दे दिया, मुख्य मंत्रीजी ने अपना विजन दर्शा दिया। अब इसको एग्जिक्यूट करने का काम माननीय शिक्षा मंत्रीजी का है। शिक्षा मंत्रीजी कितनी मेहनत करते हैं, किस दृष्टिकोण से लेते हैं कि पिछली बार भी घोषणाएं हुई थीं पर मुझे पता नहीं शिक्षा मंत्रीजी ने इस ओर ध्यान दिया कि नहीं दिया कि उसमें हमारी क्या प्रोग्रेस है? क्या उसके अन्दर प्रोग्रेस हुई? कभी फिजिकल वैरीफिकेशन भी किया कि नहीं किया है। क्या हमारे बच्चों का स्टैण्डर्ड है? क्या हमारे बच्चे चाहते हैं?

इसी तरह हायर एजूकेशन में हमारे कालीचरणजी सराफ पता नहीं किधर निकल गये।

एक माननीय सदस्य: यही बैठे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जब आप स्कूलों के अन्दर साइंस सब्जैक्ट कर रहे हैं, सीनियर माध्यमिक विद्यालय है और अभी मुझे पिछले पांच साल हो गये, मेरे यहां गवर्नमेंट कालेज है। मैं उस स्थान से आता हूं, उस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जिसमें ऐसा कोई आई.ए.एस. का बैच नहीं, जिसमें मेरे क्षेत्र के बच्चे सलैक्ट नहीं होते हों। आई.पी.एस. के अन्दर सलैक्ट होते हैं, आर.ए.एस. में सलैक्ट होते हैं, अलाइड में सलैक्ट होते हैं, आर.पी.एस. में सलैक्ट होते हैं, आई.आई.टी. में होते हैं, मेडिकल में होते हैं, एन.डी.ए. के अन्दर होते हैं। सबसे ज्यादा डिफेंस में भी हैं। मतलब एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जिसके अन्दर टैलेन्टेड बच्चे रहते हैं और वह देश के लिये, अपने क्षेत्र के लिये, राजस्थान के लिये कुछ करना चाहते हैं।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

मुझे पिछले पांच साल भी हो गये कहते-कहते, मेरे यहां गवर्नमेंट कालेज है, गवर्नमेंट कालेज के अन्दर, स्कूलों के अन्दर साइंस सब्जैक्ट है, बायोलोजी सब्जैक्ट है, ज्योग्राफी सब्जैक्ट है, पर कालेज के अन्दर, गवर्नमेंट कालेज है, जिसके अन्दर ना तो साइंस सब्जैक्ट है, न बायोलोजी सब्जैक्ट है, न ज्योग्राफी सब्जैक्ट है। अब, सभापति महोदय, सरकार इधर ध्यान दे। एक रटा-रटाया आंसर दे देना, जो अभी उच्च शिक्षा मंत्रीजी दे भी रहे थे कि वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है। यह वित्तीय संसाधन जब नया कालेज खोल सकते हो आप, और जो कालेज चल रहे हैं, जिनके अन्दर आवश्यकता है साइंस सब्जैक्ट की, बायोलोजी सब्जैक्ट की, ज्योग्राफी सब्जैक्ट की, आप कालेज खोलने की बजाय अपने आपमें जहां कालेज हैं, उनको पूर्ण कालेज बनाओ, उनके स्तर को सुधारो। एक तरफ दुनिया भर की घोषणाएं हो रही हैं और एक छोटे-से मेरे यहां कालेज के अन्दर लैबोरेट्री बनी हुई है, स्व-पोषित चल रहा है। उसमें कुछ नहीं करना है सरकार को। वहां भवन है, सब कुछ है। केवल उसको सरकारी दर्जा देना, और वह भी हम इसलिये मांग कर रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, वह अपना पैसा भरकर पढ़ाई नहीं कर सकते।

उनमें टैलेंट है, वो देश के बहुत बड़े नागरिक बन सकते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं, बहुत बड़े डाक्टर बन सकते हैं, बहुत बड़े इन्जीनियर बन सकते हैं पर सरकार ने, वो ही पांच साल कांग्रेस सरकार में जवाब आता था, मैंने पिछले बजट में लगाया, अब भी मैंने क्वेश्चन लगाया क्वेश्चन लगा भी, जवाब एक ही आता है, तो अब पिछली सरकार में और इस सरकार के अन्दर सोच में परिवर्तन करना चाहिए। जितने कालेज हैं, आप आगे घोषणाएं मत करो, आप वाहवाही लूटने की कोशिश मत करो, आप केवल इतना-सा कर दो कि जो कालेज हैं, जहां जरूरत है, जहां स्व-पोषित साइंस की, बायोलोजी की क्लासेज चल रही हैं उनके अन्दर आप गवर्नमेंट की तरफ से स्वीकार कर दो जिससे बच्चों का स्तर बढ़ जाए, बच्चों को उससे सुविधा मिल जाए।

अब माननीय शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं और मांग भी इसी पर है, जब आप शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, इस शिक्षा के अन्दर राजस्थान को आगे ले जाना चाहते हैं तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो आपकी आंखों से दूर थोड़ी है, उनको चैक करने के अधिकार आपके पास हैं। वो दुकानें बनी हुई हैं, घर बैठे डिग्रियां बांट रही हैं। बच्चे जाते नहीं हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है पर कभी किसी ने, आज तक किसी शिक्षा मंत्री ने, शिक्षा विभाग के किसी

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

अधिकारी ने या सरकार ने उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को पकड़ने की कोशिश नहीं की। उसका ताजा प्रमाण यह है कि प्राइवेट कालेजों ने, अभी पंचायती राज के चुनाव हुए, शायद इससे बड़ा तो प्रमाण मिल भी नहीं सकता, और किस तरह का प्रमाण चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्रीजी ने जो साहसिक कदम उठाया है कि दसवीं पास पंचायत समिति का चुनाव लड़ेगा, जिला परिषद का लड़ेगा, जिला प्रमुख बनेगा, प्रधान बनेगा और दुनिया भर की, मेरे यहां अलवर में ही एक-एक प्राइवेट स्कूल ने 50-50 डिग्रियां बांट दीं। अब उनके केस तो दर्ज हो गये पर उनके खिलाफ शिक्षा विभाग ने क्या एक्शन लिया? क्या उनको बंद करने की कोशिश की या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? वो अभी तक कुछ नहीं हुआ।

शिक्षा मंत्रीजी, हमारे शिक्षा मंत्रीजी देवनानीजी मेहनती आदमी हैं, जब यह शिक्षा मंत्री नहीं थे इनको सब कुछ याद था और शिक्षा मंत्री बनने के बाद तो ऐसा लगा कि इन्हें अब कुछ पता ही नहीं है। शिक्षा के ऊपर इतना चिल्लाते थे, इतना चिल्लाते थे, अब बोलती क्यों बंद हो गयी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बोलते थे, चिल्लाते नहीं थे।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अच्छा बोलते रहे, सारी।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): बोलता था और आज उत्तर दूंगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बोलते थे, यों कहते थे कि, साहब, फलां स्कूल के अन्दर टायलेट नहीं है, फलां में चपरासी नहीं है, फलां में प्रिंसिपल नहीं है, आज तो बहुत स्कूल खाली पड़े हैं। आपने घोषणा की आप भर्ती करेंगे, पर हम अलग हट कर कुछ करेंगे तो ही जनता हमको स्वीकार करेगी। क्योंकि जनता ने कांग्रेस को इतना बड़ा मेन्डेट नहीं दिया था जो आपको 163 दिया है और इस उम्मीद के साथ दिया है कि आप जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे, जनता को कुछ अलग कर के दिखायेंगे। अब एक साल में हम परिवर्तन नहीं कर पाये तो क्या जनता की सोच कुछ नहीं बदली होगी? हमें इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इतनी घोषणाएं कर रही हैं, उसको एग्जीक्यूट तो शिक्षा मंत्री ही करेगा, अधिकारी ही करेंगे। अधिकारी की मेहनत, शिक्षा मंत्री की मेहनत ही करेगी।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

अब आप ताज्जुब करोगे, मैंने पत्र लिखा। मेरे यहां ऐसे-ऐसे प्राइवेट कालेज चल रहे हैं जो एक बिल्डिंग में तीन कालेज हैं, डिग्री कालेज भी उसी बिल्डिंग में, बी.एड. कालेज भी उसी बिल्डिंग में, एस.टी.सी. कालेज भी उसी बिल्डिंग में। अधिकारी चैक करने के लिए जाते हैं तो वहां उनकी खूब खातिर तवज्जोह होती है और अपने उन्हीं बिल्डिंग में तीनों को पास कर आते हैं। क्या यह ध्यान देने योग्य बात नहीं है? क्या हमें इधर ध्यान नहीं देना चाहिए?

अब विद्यार्थी मित्रों की बात है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, सबसे ज्यादा उनकी वेदना आप उठाते थे। माफ करना यह बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, पर जो 163 सीट आयी हैं इसके अन्दर जो 25 हजार विद्यार्थी मित्र थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, माननीय वसुन्धराजी को मुख्य मंत्री बनाने के लिए रात-दिन एक किया था क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार से निराश हो गये थे, उनका भविष्य अन्धकार में नजर आता था। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वसुन्धराजी की सरकार में एक उम्मीद थी कि अगर लोगों को समझाकर किसी तरह से यह सरकार आये, तो वो 25 हजार लोग एक वर्कर की तरह लगे थे। आज दूसरा बजट आ गया है, उनके बारे में अभी हम कहते ही कहते हैं, केवल जब चाहे जो बयान ही दे देते हैं, पर यथार्थ रूप में उनके प्रति अभी तक कुछ नहीं किया है और वो ही विद्यार्थी मित्रों ने अब उलटा प्रचार शुरू कर दिया है इसलिए सरकारी चाहे जो स्टेटमेंट देते रहो, पर वास्तविकता में उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो हमको इसका बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दो। कोई भी रास्ता निकालो, किसी तरह से भी उनको दो। उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, आधों की उम्र पार हो चुकी है। उनका समायोजन करो क्योंकि उनको उम्मीद बहुत ज्यादा थी और इस उम्मीद के साथ उन्होंने आपका बहुत बड़ा सहयोग किया था।

अब प्रतिबंधित जिले हैं उसमें सबसे ज्यादा मेरे क्षेत्र के ही टीचर हैं। ऐसा तो राजस्थान का कोई विधान सभा क्षेत्र नहीं होगा जहां मेरे यहां के अध्यापक नहीं होंगे। जो प्रतिबंधित जिले हैं उनमें एक-एक अध्यापक को 15-15 साल, 20-20 साल हो गये, जो सरकार आती है वो एक ही रटा-रटाया जवाब देती है कि प्रतिबंधित जिले हैं। यह कोई अलग दुनिया के हैं? उन्होंने मेहनत

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

की, या तो उसी टाइम आप इश्तिहार में लिखते कि बाड़मेर, जैसलमेर या इधर की साइड में जो अध्यापक नियुक्ति पायेगा उसको जब तक उसकी सर्विस है तब तक इन्हीं जिलों में रहना पड़ेगा। ऐसी घोषणा हुई नहीं, कोई बाण्ड आपने भरवाया नहीं, केवल उनके साथ छलावा हुआ। वे तो इस उम्मीद से कि हम पढ़े-लिखे लोग हैं, राजस्थान के दूरदराज के क्षेत्रों में जाकर भी सेवा दे सकते हैं, शिक्षा का स्तर ऊंचा कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह रटा-रटाया जवाब बंद करो, आप एक क्राइटेरिया बना दो, पांच साल का बना दो, दस साल का बना दो।

आप धन्यवाद के पात्र हो, अभी आपने जो शिक्षकों की भर्ती शुरू की है, जो बहुत लम्बे समय से लम्बित थी। सरकार की जितनी तारीफ करो उतना कम है, पर इसमें आप लेते कि हर जिले से, जो वहां 10-10 साल से पड़े हुए हैं उनको इधर लाते, इधर की सीटें भर जाती उधर ज्यादा खाली हो जाती, नये लड़कों को 5-10 साल नौकरी करने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसको व्यावहारिक रूप से लेना चाहिए। एक वर्ड रट लिया कि प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित है तो खोलेगा कौन? भगवान आकर खोलेगा क्या? यही कांग्रेस शासन में वो कहते थे और यही आप कह रहे हो, फिर आपमें और उनमें फर्क क्या हुआ? संवेदना होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। ऐसी-ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर में दूसरा कोई नहीं है और वो आज इतनी दूर सात-सात सौ किलोमीटर, आठ-आठ सौ किलोमीटर पड़ी हैं, उनके स्थान पर आप नौकरी दे सकते हो क्योंकि जब इधर वेकेंसी भर जायेगी तो उधर तो वेकेंट ज्यादा हो जायेगी। आप पहले ही डिक्लेयर कर दो कि जो इन क्षेत्रों में टीचर लगेगा उनको इतने साल अपनी सेवा देनी पड़ेगी। कोई लिमिट तो होती है पर यहां तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई सोचना ही नहीं है, पता नहीं। शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, मुख्य मंत्रीजी से बात करें कि, मुख्य मंत्रीजी, यह समस्या है। यह मानवीय समस्या है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मुख्य मंत्रीजी सुनती ही नहीं हैं ... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मुख्य मंत्रीजी खूब सुनती हैं, सुनाने वाला चाहिए। मुख्य मंत्रीजी इतनी सेंसेटिव हैं, इतना ज्यादा अच्छा बजट कोई दे नहीं सकता था।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, यह बड़े दुःखी हैं।

श्री सभापति: आप बैठें। श्रवणजी, कृपया आप बैठें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): श्रवणजी, मेरे ख्याल से आपने शिक्षा का बजट पढ़ा ही नहीं।

श्री सभापति: आप बोलें। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अगर मुख्य मंत्री की संवेदना नहीं होती, मुख्य मंत्री के विचार अच्छे नहीं होते, मुख्य मंत्री सुनती नहीं तो शायद राजस्थान को इस तरह का शिक्षा बजट किसी ने दिया है? आपके मुख्य मंत्री ने नहीं दिया जो आठवीं पास के दिलवा दिये थे, याद है राजीव गांधी पाठशालाएं जिनके अन्दर कोई भविष्य नहीं था। राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं जो ग्वाले लगा दिये थे पढ़ाने के लिए और ग्वाले ही बनाने के लिए तैयार किया था।

श्री सभापति: कृपया आपस में बात न करें, डाक्टर साहब, आप मुझे सम्बोधित करें। कृपया आपस में बात न करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, हमारे जिले की ही मैं तो ज्यादा जानता हूं, 50 परसेंट ऐसे स्कूल हैं जिनमें पीने का पानी नहीं है। इसलिए माननीय मंत्रीजी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। टायलेट नहीं हैं, टायलेट हैं तो ऐसे टायलेट हैं कि उनमें अगर कोई चला जाए तो बेहोश होकर वहीं गिर जाए। (व्यवधान) मेरे यहां भी हैं इस तरह के। कनेक्शन नहीं है बिजली नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं सकते और स्टाफ पूरा है नहीं, माननीय मंत्रीजी, आपने पिछली बार घोषणा की थी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक बार अपनी अन्तर आत्मा से सोचो कि आपने घोषणा की थी हम पिछले नवम्बर में सारा स्टाफ पूरा कर देंगे। कौनसे नवम्बर का इन्तजार करेंगे अब? (व्यवधान) यह अपनी घोषणा थी और लोग हमसे पूछते हैं कि आप तो नवम्बर तक सारा स्टाफ पूरा करने वाले थे और अब भी कहीं प्रिंसीपल नहीं, स्टाफ नहीं, आप कर रहे हैं उसके लिए आपकी तारीफ भी कर रहे हैं कि कोशिश की है लेकिन हमसे ज्यादा उम्मीद है, सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद है इसलिए हमको इसमें जल्दी कार्यवाही करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जो माडल स्कूल बनाने की आप बात कह रहे हैं उसमें आप एक क्राइटेरिया तय कर लीजिए कि एक पंचायत में आपने

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

घोषणा कर रखी है पर जब करना है तो कम से कम एक-एक विधान सभा क्षेत्र में चार-चार, पांच-पांच माडल स्कूल बना दें तो भी हम लोगों को संतुष्ट कर दें कि देखिए, हमारी मुख्य मंत्रीजी और हमारे शिक्षा मंत्रीजी इस तरह के माडल स्कूल बना रहे हैं, इसके अन्दर टाइम लगेगा, पर मेरे ख्याल से अपन ने एक भी परफैक्ट स्कूल नहीं बनाया है तो इसके अन्दर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तारीफ हमसे जो चाहे करवा लो मुख्य मंत्रीजी का विजन अच्छा, मुख्य मंत्रीजी की सोच अच्छी, मुख्य मंत्रीजी ने बजट अच्छा दिया, लेकिन धरातल पर जो हमारी हालत आज डेढ़ साल में है उसको ठीक करने की जरूरत है। (व्यवधान) उनकी तो क्या बात करें? सारा ही बंटाधार कर दिया था। मतलब जिस आदमी ने पूरे राजस्थान को चौपट कर दिया हो, जिस सरकार ने, उस सरकार का विधायक बोल रहा है? मेरी भी तो हिम्मत देखो, मैं अपने ही माननीय मंत्रीजी से, अपनी ही सरकार से गुहार लगा रहा हूं। (व्यवधान) आप भी तो आदत से लाचार हो। वह कुछ सुनेंगे तो कुछ करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपसे मेरा आग्रह है कि चाहे वह विद्यार्थी मित्रों की बात हो, आप कोई भी रास्ता निकालिए, अब सिर से पानी ऊपर जा रहा है। अब वही लोग हमारे खिलाफ बोलने लग गए हैं, 25 हजार की संख्या कोई कम नहीं होती है। हमने उनको सपने दिखाए थे, उनके सपनों को हमें साकार करना पड़ेगा, कालेजों में हमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, साइन्स सब्जैक्ट देना पड़ेगा। अगर वित्तीय संसाधन की बात हो तो मत खोलिए अभी स्कूल, बाद में खोल लेना लेकिन जो भी है उनको तो ठीक कर लो, उनको तो परफैक्ट स्कूल बना लो। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि एक स्कूल का नाम बता दो और आप मुझसे इनाम पा लो कि यह हमारा स्कूल सौ परसेंट परफैक्ट है। मेरे जिले में तो एक भी स्कूल परफैक्ट नहीं है जिसमें प्रिंसीपल हो, या हैड मास्टर हो, चपरासी हो, पूरा स्टाफ हो, बिजली का कनेक्शन हो, टायलेट हो और पीने का पानी हो। (व्यवधान) आपसे निवेदन है कि इधर ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, आप जो कर रहे हो खूब कर रहे हो, सरकार करने का प्रयास कर रही है, पर आपको और आपके कर्मचारी, अधिकारियों को और मेहनत करने की जरूरत है जिससे कि और शिक्षा का

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

स्तर ऊंचा हो और जो फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं, स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटीज, इन पर चैक लगाओ, यह राजस्थान का बंटाधार कर रहे हैं। जिस तरह कल हमने टीवी में देखा कि बिहार के अन्दर जो हालात चल रहे थे ऊपर से नीचे तक नकल कराने के इसी तरह से हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का हाल है तो वह भी हमारे ही बच्चों का भविष्य है, उसको आपको सुधारने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, अब माननीय पर्यटन मंत्रीजी यहां बैठी हैं, भरतपुर की रहने वाली हैं।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करेंगे माननीय सदस्य?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरे पर्यटन की बात तो कह दूं जरा सी, ज्यादा नहीं कहूंगा।

पर्यटन के मामले में माननीय पर्यटन मंत्रीजी पड़ौस के जिले की हों, अलवर जिला एनसीआर में आता है। राजस्थान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे सकता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा ट्यूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। केवल राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है तो आपसे निवेदन है कि आप पड़ौस की पर्यटन मंत्री बनी हो जिस दिन आपको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पर्यटन मंत्री बनाया उस दिन अलवर में भी मिठाइयां बंटी थी कि अब शायद हमारे भी दिन सुधरेंगे। आज वर्ल्ड मैप पर अजबगढ़, भानगढ़ जो हमारे माननीय हेमसिंहजी भड़ाना का विधान सभा क्षेत्र आता है, सबसे ज्यादा डरावना अगर कोई किला है, जगह है, भूत बंगला है तो पूरे वर्ल्ड में नम्बर वन पर अजबगढ़, भानगढ़ है उसका हम फायदा उठा सकते हैं अगर पर्यटन मंत्रीजी ध्यान दें तो। वहां न कोई आने का साधन हैं, न जाने का साधन ...(व्यवधान) न वहां कोई रेस्टोरेंट है, न कोई वहां वाश रूम, न वहां कोई सड़कें, तो उधर आप ध्यान दो। अलवर, दिल्ली के नजदीक है उसका फायदा उठा सकते हैं। सब जगह के पैसे मंजूर है, हमारे भर्तृहरिजी जो दुनिया में मशहूर हैं, बहुत बड़ी सुन्दर जगह है, सरिस्का, पाण्डुपोल अपने आपमें ऐतिहासिक जगह है, वहां के लिए कोई बजट नहीं आया है इसलिए आप स्वीकृत कराओ माननीय मुख्य मंत्रीजी से, आज अपने उसमें घोषणा कीजिए। सीलीसेढ़ अपने आपमें बहुत बड़ी जगह है, आप उदयपुर की झील का जिक्र करते हैं कभी एक बार अलवर की सीलीसेढ़ झील की तरफ भी ध्यान देकर देखिए, इतने ट्यूरिस्ट

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

आएंगे, इतना रेवेन्यू आएगा, इतना लोगों को काम मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। केवल थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, अलवर को एक उपेक्षित स्थान बना रखा है, आपसे उम्मीद है कि चाहे आप मुख्य मंत्री से लड़े, भिड़ें चाहे कुछ भी करें पर निश्चित रूप से आपके पर्यटन मंत्री बनने से जो अलवर के लोगों को खुशी हुई थी उस खुशी को खुशी में ही शामिल कीजिए, उसको गम में मत बदलने की कोशिश करना, यह मेरा आग्रह है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री प्रहलाद गुंजल। कृपया समय का ध्यान रखें गुंजल साहब। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या-24 शिक्षा कला और संस्कृति पर चर्चा हो रही है। मैं आभारी हूं आपने समय दिया और समय सीमा में भी बांध दिया। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मांग है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस व्यवस्था में हम लोग बैठे हैं, मैंने पहले भी सदन में बात कही थी, सारे संसार में यह प्रचलित बात है कि जहां-जहां भी लोकतंत्र है, शिक्षा उसका मूल मंत्र है और शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों की ताकत, संस्कृति का संरक्षण और संस्कृति का संक्रमण, अगर हम किसी माध्यम से कर सकते हैं तो केवल मात्र शिक्षा उसका आधार है। माननीय सभापति महोदय, जब शिक्षा पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं बहुत लम्बे चौड़े सन्दर्भों में नहीं जाना चाहता, शिक्षा के क्षेत्र में देश और प्रदेश ने बहुत ज्यादा तरक्की की है लेकिन आज किन शब्दों में राज्य की मुख्य मंत्री का आभार व्यक्त करूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में शिक्षा पर पैरा नम्बर 96 से 111 तक राजस्थान में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन और जो आवश्यक सुधारवादी कदम उठाए जाने चाहिए, इसकी व्यापक चर्चा की है और बहुत खुले मन से इस बात को स्वीकार किया है माननीय सभापति महोदय, एनुअल स्टेटस आफ एजूकेशन रिपोर्ट 2014 के आधार पर राजकीय विद्यालयों की पांचवी कक्षा में अध्ययनरत आधे से अधिक विद्यार्थियों को दूसरी कक्षा के स्तर का ज्ञान नहीं होना पाया गया। माननीय सभापति महोदय, जब ईमानदारी से हम चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा के केन्द्र में अगर यह बात नहीं रही...

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हमारी सरकारी शिक्षा की दुर्गति कितनी हो गई। कितने खुले मन से मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकार किया और न जाने कितनी बार ऐसे सर्वेक्षण बार-बार सामने आये सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला आठवीं का बच्चा जिसको पहाड़ों का ज्ञान नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकार किया पांचवीं का बच्चा दूसरी क्लास के स्तर तक का ज्ञान नहीं रखता। यह चिन्ता और चिन्तन दोनों का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको 30-32 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। आबादी दुगनी हो गई, संसाधन बढ़े हैं, अध्यापक बढ़े हैं, विद्यार्थी बढ़े हैं, लेकिन शिक्षा के स्तर में कितनी गिरावट आयी होगी। मैंने पिछली बार जब रामगंजमण्डी से निर्वाचित होकर आया था तब यह बात सदन में कहने का प्रयास किया था। मैं 1984-85 में हायर सैकण्डरी में गुमानपुरा स्कूल का विद्यार्थी हुआ करता था। शहर की आबादी आधी थी। आज जब मैं 2013-14 में कोटा उत्तर से विधायक बनकर उस विद्यालय में जाता हूं, आबादी दुगनी। मैं जब पढ़ता था तब विद्यार्थियों की संख्या 4500 थी और आज जाकर मैं पूछता हूं, टीचर बढ़े हैं, संसाधन बढ़े हैं, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या 350, यह बहुत बड़ा चिन्ता का विषय है। बहुत ईमानदारी के साथ हमने इस पर आत्म-चिन्तन नहीं किया तो सारे प्रयासों के बाद जो सरकारी शिक्षा पर से लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है, एक दिन हम सारे लोग इस गुनाह के लिए जिम्मेदार होंगे। आज आम तौर पर गांवों में यह धारणा बन गयी कि सरकारी स्कूल में केवल वह बच्चा पढ़ने जाता है जिसके अभिभावक का प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं। मन में तकलीफ तब होती है जब गांवों में यह चर्चा होती है कि किसी अभिभावक के एक बेटा और एक बेटी है, आर्थिक स्थिति का संतुलन ठीक नहीं है। गुंजाइश है तो बेटे को किसी प्राइवेट स्कूल में भेजता है और बेटी को सरकारी स्कूल में भेजता है। गुंजाइश नहीं है तो केवल बेटे को भेजता है, बेटी को घर पर छोड़ देता है। आजादी के 67 साल बाद प्रतिस्पर्धा वैश्विक स्तर की हो गयी, दुनिया एक राष्ट्र की शक्ल में आ गयी। हम समाज के उस गरीब तबके को, बराबर की आबादी के तबके को शिक्षा के साथ जोड़ नहीं पा रहे। इन विसंगतियों पर हमें बहुत ईमानदारी से विचार करना पड़ेगा। अगर हमने इस पर विचार नहीं किया, इसके कारणों में जाने की नहीं सोची, इसके सबसे बड़े कारण हम लगातार शिक्षा पर प्रयोग करते चले गये। हमने एजूकेशन को प्रयोग का इश्यू बना दिया। मैं इसको

(श्री प्रहलाद गुंजल)

राजनीति से जोड़कर नहीं कहना चाहता। मैं कोटा उत्तर से आता हूं, हिन्दुस्तान के कोने-कोने में सीनियर सैकण्डरी के स्कूल हैं। सब जगह अपनी एजूकेशन की व्यवस्था है, लेकिन आज आठवीं पास करने के बाद कोटा में पढ़ने और कोचिंग लेने के लिए हिन्दुस्तान का 2 लाख विद्यार्थी कोटा में आता है। आखिर क्यों? मैंने पिछले सदन में कहा था जब राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी ने कहा था कि हम विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात के आधार पर विषय अध्यापक लगाएंगे। मैंने कहा था माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, यह अन्याय है। एक तरफ तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो शिक्षा में कायम हो गयी, उस समय पढ़ने वाले विद्यार्थी के मन में एक्सपर्टीज से पढ़ने की जबर्दस्त लालसा पैदा हो गयी और जो कोटा में आईआईटीस कोचिंग चला रहे हैं, पूरे देश का विद्यार्थी खिंचकर 16-16 घण्टे पढ़ने के लिए वहां आ रहा है। हम आजादी के 67 साल बाद विषय अध्यापक हटाने की बात कर रहे हैं, यह प्रयोग शिक्षा में किसी भी सूरत पर नहीं किया जाना चाहिए। एक सबसे बड़ा गंदा प्रयोग, आज मुख्य मंत्रीजी ने चिन्ता की कि पांचवीं का बच्चा दूसरी के स्तर पर नहीं पहुंचा।

माननीय सभापति महोदय, 1998 से 2003 के बीच जो शासन व्यवस्था थी, शिक्षा का सत्यानाश कर दिया। राजीव गांधी पाठशालाओं के नाम पर शिक्षा का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। खूब वाहवाही लेते, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन शिक्षा के स्तर को गुणात्मक सुधार लाने के बजाय जो बच्चा स्वयं दसवीं पास नहीं कर पाया, बारहवीं पास नहीं कर पाया, जो स्वयं अपने आपमें शैक्षणिक दृष्टि से निपुणता हासिल नहीं कर पाया, आपने स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में दसवीं, बारहवीं पास बच्चों को, राजस्थान के बच्चों को पढ़ाने के लिए हजारों की तादाद में लगा दिया, उन्होंने राजस्थान की शिक्षा के गुणात्मक स्तर को इतना गिरा दिया और बाद में जाकर आपको उनको मजबूरी में एसटीसी करने की छूट देनी पड़ी। आपको बीएड करने की छूट देनी पड़ी। यह जो प्रयोग एजूकेशन में लगातार पिछले 67 साल से चले आ रहे हैं इसने सरकारी शिक्षा का बंटाधार करके रख दिया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हम सरकारी शिक्षा की चिन्ता करना चाहते हैं तो फिर आज हमको एक स्वर में यह कहना पड़ेगा कि इस राजस्थान में कोई निजी क्षेत्र का विद्यालय चल रहा हो, चाहे राजस्थान में सरकारी क्षेत्र का विद्यालय चल रहा हो पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक जब तक समान पाठ्यक्रम निजी और सरकारी विद्यालयों में नहीं होगा तब तक शिक्षा में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

गुणात्मक सुधार होने की सम्भावना नहीं है। देर-सवेर हमको अगर इस राजस्थान के एक-एक व्यक्ति को शिक्षा का लाभ देना है, इस राजस्थान के एक-एक बच्चे को हम उसके अन्दर छिपी हुई प्रतिभा को विकसित करके उसके सामने संसाधनों की उपलब्धता तय करके इस मुकाम पर लाने का दायित्व अगर निभाना चाहते हैं, अपनी क्षमता के आधार पर स्वयं ही नहीं राष्ट्र और समाज के निर्माण के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति बनकर, दायित्ववान बनकर आगे बढ़ें तो फिर हमें इस दिशा में चिन्तन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आज आईआईटी जो दुनिया का सबसे बैस्ट कम्पीटेटिव एग्जाम है। आज सेंट सोफिया, सेंट पाल, सेंट जैवियर से आने वाला अलग पैटर्न का विद्यार्थी और सरकारी स्कूल, गुमानपुरा व महात्मा गांधी में पढ़ने वाला बच्चा, दोनों के एजूकेशन के पैटर्न अलग-अलग हैं, शिक्षा की भाषाएं अलग-अलग हैं, तौर-तरीके अलग-अलग हैं। उस विश्वस्तरीय कम्पीटिशन में वह बैठेगा तो निश्चित रूप से दोनों के स्तर में एक बड़ा भारी अन्तर आएगा। जब तक हम इस अन्तर को समाप्त नहीं करेंगे हम शिक्षा के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं आज अखबारों में समाचार छपा है। महात्मा गांधीजी ने कहा था शिक्षा वही जो बच्चे के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में सर्वोत्तम निखार ला सके। उच्च शिक्षा प्राप्त हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से जाना जाय। ऐसी अवधारणा हमारे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में कहां निहित है और अगर है, तो सारे कुलपति, प्रधानाध्यापक और नीति निर्धारक इसे उजागर क्यों नहीं करते? उससे आगे कहा उचित वातावरण, मार्ग निर्देशन और प्रोत्साहन व्यक्ति के अन्दर निहित खजाने के दरवाजे खोल सकता है, व्यक्ति को अपनी अपार क्षमताओं पर विश्वास जाग्रत हो सकता है और देश के ज्ञान कौशल सम्पदा में बढ़ोतरी हो सकती है। गंगा की तरह प्रवाह बह सकता है ज्ञान-कौशल के अन्दर। माननीय सभापति महोदय, हम क्या उचित वातावरण दे रहे हैं? हम क्या मार्ग निर्देशन और प्रोत्साहन दे रहे हैं? आज अख़बार में छप रहा है धूप में बैठकर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दीं? आजादी के 67 साल बाद हम यह वातावरण दे रहे हैं? यह मार्गदर्शन, यह प्रोत्साहन, हम उसको इस रूप में तैयार कर रहे हैं। एक तरफ हम शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात करते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कहा कि हमने राज्य के स्कूलों और महाविद्यालयों

(श्री प्रहलाद गुंजल)

को सूचना एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए ई-लर्निंग, ई-टीचिंग, ई-ट्रेनिंग, वीडियो कांफ्रेंसिंग और डिजिटल पुस्तकालय आदि संसाधनों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ाने के लिए बजट दिया है, मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। लेकिन इस पक्ष को कौन देखेगा? चार दिन पहले समाचारों में छपा है। आज भी राजस्थान के 51,933 विद्यालयों में बिजली नहीं है। यह राजस्थान के हालात हैं। गुजरात की स्थिति देखें। केवल मात्र 97 विद्यालय, जिनमें गुजरात में बिजली नहीं है, अगर हम प्रतिस्पर्धा में अपने आपको खड़ा करना चाहते हैं तो हमको एक-एक विद्यालय में संसाधन उपलब्ध कराना पड़ेगा। संसाधन, उचित निर्देशन, उचित मार्गदर्शन, उचित प्रोत्साहन इस राजस्थान के एक-एक गरीब व्यक्ति के सामने हमको उपलब्ध कराना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, अभी चार दिन पहले अखबारों में छपा 32 से 40 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों के बच्चे कम्पीटेटिव एग्जाम्स में पास हो रहे हैं, आईआईटी, सीपीएमटी, एआईईईई में, मैं कहना चाहता हूं आज राजस्थान दो तबकों में बंट गया। एक सरकारी कर्मचारी और समर्थ तबका। एक वह तबका जो गरीब तबका है। समर्थ और सरकारी कर्मचारी के सामने अपने जीवन के बाकी एजेण्डे के साथ अपने बच्चों को बैस्ट क्वालिफिकेशन दिलाना एक बहुत बड़ा जीवन का एजेण्डा है और उसके निमित्त वे सारे संसाधन जो कुछ भी जुटाने हों, जुटाता है।

लेकिन एक वह तबका जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जिसके पास न संसाधन हैं, न मार्ग निर्देशन है, न प्रोत्साहन है। आज आपसे कहना चाहता हूं कि उस बच्चे को कौन वातावरण देगा? अगर हमने उस बच्चे को वातावरण नहीं दिया तो आज भी उस बच्चे की संख्या समृद्ध और प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चों से चार गुना ज्यादा है, उसको पढ़ी-लिखी जमात कराकर, ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में देकर केवल बाहर निकालने का काम कर रहे हैं तो देर-सवेर वो अपने आपको बड़ी चुनौतियों और बड़ी प्रतिस्पर्धा से बाहर अगर व्यवस्था की कमी को कारण मानेगा तो निश्चित रूप से उसके मन में व्यवस्था के प्रति जो विद्रोह पैदा होगा, जब आत्मचिंतन होगा उस समय हम सब लोग एक गुनाहगार की श्रेणी में शामिल होंगे माननीय सभापति महोदय। इसीलिए आज हमको वो सरकारी स्कूल में जो गरीब का बच्चा पढ़ने आ रहा है, वह देख रहा है कि अंग्रेजी स्कूल में जाने वाले के अभिभावक अंगुली पकड़कर टाई लगाकर कोट-पैंट या टी-शर्ट नेकर पहने हुए बच्चा स्कूल के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

टैम्पो का इन्तजार कर रहा है, टैम्पो आ रहा है, पर सभापति महोदय, उसके अभिभावक के पास समय नहीं है, सुबह उठने के बाद उसे चौराहे पर जाना होता है इस इन्तजार में कि कोई ठेकेदार आएगा, कोई पूंजीपति आएगा, दिनभर की बेलदारी मिलेगी तो शाम को चूल्हा जलेगा। सरकार को आज निश्चित रूप से उस गरीब के बच्चे के प्रोत्साहन के लिए काम करना चाहिए, उसके निर्देशन के लिए काम करना चाहिए, उसके लिए संसाधन जुटाने के लिए काम करना चाहिए। सरकार ही, उसके अभिभावक का दायित्व भी जब तक नहीं निभायेंगे तब तक हम समाज के एक बहुत बड़े तबके को कुछ नहीं दे पायेंगे। सभापति महोदय, मैं कोटा से आता हूं, मेरे मन में पीड़ा है। माननीय सभापति महोदय, आज एक गांव का गरीब व्यक्ति 10 हजार रुपये में परिवार चलाता है जबकि मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई माननीय विधायक अपने बच्चे को कोटा में केवल कोचिंग के लिए भेज दे और 10 हजार रुपये महीने किराये से कम किराये पर कमरा लेकर बता दे। माननीय सभापति महोदय, मैं आज सदन में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज एजूकेशन जब इतनी महंगी हो गई हो, 10 हजार रुपये तो किराये के कमरे के लिए चाहिए, और संसाधन चाहिए, कोचिंग के लाखों रुपये चाहिए, उस प्रतिस्पर्धा में, वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा में समाज के उस गरीब तबके को जो 10 हजार में परिवार चला रहा है, कौन उसको संवारेगा? कौन उसको सजायेगा? सभापति महोदय, वह इतनी बड़ी तादाद है जिसकी अनदेखी नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र का अवमूल्यन हो जाएगा इतने बड़े तबके की अनदेखी करना।

माननीय सभापति महोदय, मुझे याद है कि आपने सीमित शब्दों में मुझे बांध दिया, मेरे मन में बहुत पीड़ा है, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं और आज सरकारी स्कूलों की दुर्गति देखता हूं, मेरे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हम सब भी उस गंदी मानसिकता से दूषित हो गये हैं। सरकारी शिक्षा के लिए कभी हम कहते थे कि भारत विश्व गुरु होता था, नालन्दा, तक्षशिला और विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, कहां गये वो? जिनमें दुनिया के 10-10 हजार विद्यार्थी विदेशों से पढ़ने के लिए आते थे। आज दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों की अगर सूची बनती है और उसकी मानीटरिंग होती है शर्म आ जाती है कि राजस्थान का एक भी विश्वविद्यालय दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में शुमार नहीं हो पाता माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: समय का ध्यान रखें माननीय सदस्य। दो मिनट आराम से लीजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): दो मिनट में कन्क्लूड करूंगा। माननीय सभापति महोदय, हम 200 में शुमार नहीं हैं। आज मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंचायत स्तर पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल कर रहे हैं। लेकिन हमको यह नहीं करना कि पिछली सरकार ने स्कूल कालेज कर दिए, एक प्रिंसिपल दे दिया पर लैक्चरर्स नहीं, भवन नहीं हैं। यह कैसी व्यवस्था है? शिक्षा का कैसा मजाक है यह? हम जाते-जाते शिक्षा का राजनीतिक लाभ लेंगे। अगली सरकार आएगी, भवनों और स्टाफ के अभाव में कुछ कालेज बन्द करेगी और हमें यह कहने का अवसर मिलेगा कि निश्चित रूप से हमने तो कालेज खोल दिए थे लेकिन आने वाली सरकार ने बन्द कर दिया, यह तमाशा शिक्षा के नाम पर नहीं होना चाहिए। यह राजनीति का खेल इस सदन को और इस सरकार को कम से कम शिक्षा को नहीं बनने देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां मौजूद नहीं हैं, शिक्षा मंत्रीजी बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर हम लोग ग्रामीण शिक्षा के साथ, सरकारी शिक्षा के साथ न्याय करना चाहते हैं तो सरकार तय करे। सभापति महोदय, अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपकी उपस्थिति में कहा था कि संसदीय कार्य मंत्रीजी, अगर आपको टेक्नीकल एजूकेशन, ई-एजूकेशन का, ई-लर्निंग का ज्ञान नहीं है और अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो फिर आप भी अनपढ़ हैं। जब यह स्टैण्डर्ड बन गया, एक तरफ तो मैकाले की शिक्षा पद्धति का...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण डिमाण्ड हो रही है और न तो शिक्षा मंत्री हैं और न पर्यटन मंत्री हैं, कोई नहीं हैं यहां पर।

श्री सभापति: शिक्षा मंत्रीजी बैठे हुए हैं। आर्डर प्लीज।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बड़े वाले।

श्री सभापति: आप बैठिये। शिक्षा मंत्रीजी हैं, खाद्य मंत्रीजी हैं, जनजाति मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि आज की एजूकेशन के वैश्विक सन्दर्भों की अगर जानकारी नहीं है तो डिग्री लेकर भी आप अनपढ़ हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी। यह सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था। जब हम

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सदन में इस प्रकार की बात करते हैं, चर्चा करते हैं तो फिर हमको यह विचार करने की जरूरत है। एक तरफ हमने मैकाले की शिक्षा पद्धति कहकर विरोध किया, जिसने कहा था कि अरब की शिक्षा और हिन्दुस्तान की सांस्कृतिक शिक्षा यूरोपीय देशों की एक अलमारी के खजाने के जरा से कोने के बराबर है। मैं दो मिनट में कन्क्लूड करूंगा माननीय सभापति महोदय, मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए। उन्होंने जो आधार दिया कि दुनिया का वैश्विक स्तर पर जो उत्थान है वो अंग्रेजी के माध्यम से हो सकता है। बहुत देर तक कई देशों ने स्वीकार नहीं किया और अब जाकर धीरे-धीरे सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने संसदीय कार्य मंत्री को कोट करके भी स्वीकार किया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि राजस्थान की शिक्षा के साथ न्याय करना चाहते हैं तो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का पहली से लेकर आठवीं तक का पाठ्यक्रम समान होना चाहिए, समान शैक्षणिक भाषा होनी चाहिए और एक स्तर के टीचर पढ़ाने के लिए लगाये जाने चाहिए तथा हर विद्यालय में विद्यार्थी के च्वाइस के अनुसार पाठ्यक्रम और सब्जैक्ट उपलब्ध होने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय हायर एजूकेशन मिनिस्टर आ गये हैं, मैं अंतिम बात कहूंगा। अभी कालेजों का विघटन किया है जहां 5 हजार से ज्यादा विद्यार्थी हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि केवल विघटन से काम नहीं चलेगा। कोटा बहुत बड़ा क्षेत्र है और अभी भी कोटा के साथ कितना अन्याय हो रहा है माननीय सभापति महोदय, यह मैं बताना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की औसत 43559 जनसंख्या पर एक कालेज है और कोटा सम्भाग में 85067 के औसत पर एक कालेज है। अन्य दूसरी जगह बीकानेर में 32 हजार पर, अजमेर में 59 हजार पर, जयपुर में 24 हजार पर, भरतपुर सम्भाग में 46800 पर, उदयपुर सम्भाग में 65 हजार पर कालेज है और आज भी कोटा के साथ हायर एजूकेशन में इतनी बड़ी अनदेखी हो रही है। उन्हें केवल कालेजों के विघटन करके एक नये कालेज का सपना दिखाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें आबादी के हिसाब से जितने मौजूदा कालेज हैं उनके बराबर दुगने कालेज खोलने की आवश्यकता है। ट्रिपल आई टी जो कोटा को मिली है, उस ट्रिपल आई टी की आज तक हमने तो शक्ल ही नहीं देखी है। जयपुर में क्लासें चल रही हैं और अभी तक तो उसकी जमीन का निर्धारण करने में ही समय लग रहा है। माननीय सभापति महोदय, जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं पर आपने समय सीमा में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बांध दिया है। इतनी इम्पोर्टेंट मांग है, अन्तरआत्मा की आवाज के एक-एक शब्द जब तक लोगों के नहीं सुनेंगे और उन पर आत्मचिन्तन करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक शिक्षा के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बहुत लम्बी लिस्ट है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि कोटा के साथ न्याय करें, ट्रिपल आई टी को व्यवस्थित करें, कालेज खोलें और शिक्षा के पाठ्यक्रमों को ठीक करें। आपने समय दिया, बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: दिया कुमारीजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मेरा एक पाइंट आफ इन्फार्मेशन का मामला है। एक मिनट, बहुत महत्वपूर्ण है साहब।

श्री सभापति: प्लीज, देखिये माननीय, आप इसमें बाधा उत्पन्न नहीं करें माननीय सदस्य। आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बोलने दो साहब, बहुत महत्वपूर्ण है।

सूचना

नागौर कलैक्ट्रेट का दलित समाज द्वारा घेराव

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नागौर के कलैक्ट्रेट पर 3-4 हजार दलित समाज के लोगों ने कलैक्ट्रेट को घेर रखा है। मेरे वहां नागौर सदर थाना में 38/15 एफ.आई.आर. हुई थी उसमें एक औरत की डैथ हो गई जड़ाव की और दो बाबू और हरेन्द्र बुरी तरह झुलस गये। एस.पी. वहां जांच कर रहा था पर राजनीतिक दबाव से फाइल आई.जी. के यहां दे दी, एक महीना हो गया पर सरकार दलितों के मामले में कितनी गम्भीर है इसलिए सभापति महोदय, सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजिये। अब आप राजनीति नहीं करें। आपने सूचना दे दी, कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। (व्यवधान) प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सदन चल रहा है और ऐसे मामले में सरकार इस तरह की संवेदनशीलता दिखा रही है सभापति महोदय। आज बहुत बड़ा दलित समाज जिन्होंने चुनाव के समय...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, बहरोड़ में वकीलों को बुरी तरह से पीटा गया है। एस.पी. ने खुद ने पीटा है। दलित का मामला भी है और वकीलों को भी अलवर जिले के बहरोड़ में बुरी तरह से पीटा गया है। (व्यवधान) 15 दिन से वकील हड़ताल कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठें माननीय श्रवण कुमारजी। माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पोपा बाई का राज है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। माननीय बेनीवालजी, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बैठें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप सुनिश्चित कीजिये कि वहां दलितों के साथ न्याय हो, सरकार जल्दी से जल्दी उच्च स्तरीय जांच कराकर इस मामले का जल्दी से जल्दी खुलासा करे। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज सिट-डाउन। दियाकुमारीजी, आरम्भ करें आप।

मांग संख्या 24 व 47 पर विचार

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 47 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदया का आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने इस बजट में पर्यटन विभाग को 67 प्रतिशत ज्यादा बजट दिया।

(14. 00 बजे)

यह पहली बार हुआ है और इसके लिए मैं हमारी मुख्य मंत्री साहिबा को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। ट्यूरिज्म सैक्टर की री-पोजिशनिंग, ओवर-आल प्लानिंग और डवलपमेंट के लिए भी वह बहुत गम्भीर हैं, उसके लिए भी उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी। महोदय, किसी भी स्थान पर पर्यटक क्यों आता है। पर्यटक किसी स्थान की विशेषता, हैरिटेज और रीक्रिएशनल एक्टीविटीज का आनन्द लेने के लिए आता है। नेचुरल डाइवर्सिटी के हिसाब से हमारा राज्य पूरे देश के बराबर डाइवर्सिटी रखता है। हमारे यहां पहाड़ हैं,

(राजकुमारी दियाकुमारी)

नदियां हैं, झीलें हैं, जंगल हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, फोर्टस हैं। क्या नहीं हैं हमारे राज्य में। सब कुछ हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान भी हमारे यहां है। इसलिए हमारा पर्यटन का स्लोगन भी ''पधारो म्हारे देस'' है क्योंकि हम एक देश के बराबर की विविधताएं पर्यटकों को दे सकते हैं। इतनी विविधताएं और जितना कुछ यहां मिल सकता है राजस्थान में, मुझे लगता है, और स्टेट के पास इतना सब कुछ नहीं है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हमारा राज्य भारत में पांचवें पायदान पर है। आज केरल, गुजरात जैसे छोटे राज्य भी हमसे नेचुरल असैट्स कम रखते हैं, इसके बावजूद भी वहां अधिक पर्यटक आते हैं। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया से कहना चाहूंगी कि कहीं न कहीं, कोई न कोई कमी तो है। कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो दूसरे राज्य कर रहे हैं और हम लोग उसको हमारे राज्य में नहीं अपना रहे हैं। यह मैं जरूर मानती हूं कि हमारी मुख्य मंत्री साहिबा पूरी तरह से इसमें ध्यान दे रही हैं और बहुत कुछ अब वह करना भी चाहती हैं। इस बजट में भी उन्होंने लिया है। लेकिन फिर भी कई ऐसी चीजें हैं जो ग्राउण्ड पर एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा आय का जरिया ही है जिस पर हमारे प्रदेश की बहुत सारी जनता आर्थिक रूप से निर्भर है। पर्यटन की दृष्टि से गोल्डन ट्राइएंगल का एक हिस्सा जयपुर भी हमारे प्रदेश में है और हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है।

हमारा हैरिटेज और कल्चर विश्व प्रसिद्ध है। देश की सबसे पहली प्लान्ड सिटी भी जयपुर ही है और वह भी राजस्थान में ही है। हमारे यहां रेल कनेक्टिविटी, रोड्स, एयर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हैं। दूसरे राज्यों के हिसाब से हमारे यहां यह सब कुछ हैं। इन सबके बावजूद भी हमारे यहां ट्यूरिस्ट इतने नहीं आये और रिपीट ट्यूरिस्ट तो मुझे लगता है, बहुत ही कम आ रहे हैं...

(14.03 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं यह कहना चाहूंगी कि इस विषय में हमको बहुत-बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और इस बात से यह स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं हमारे द्वारा उनको दी गई सुविधाओं में कमियां हैं और उसके लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा।

(राजकुमारी दियाकुमारी)

महोदय, थाईलैण्ड ट्यूरिज्म सैक्टर में हमारे से बहुत आगे है। 2013-14 में वहां ट्यूरिज्म में 6.66 प्रतिशत का ग्रोथ हुआ है, मलेशिया में 6.6 प्रतिशत, श्रीलंका में 19.8 प्रतिशत और भारत में 4.5 प्रतिशत हुआ है तो मैं तो यह सोचती हूं, जिस देश में इतना कुछ देने के लिए है पूरे विश्व को, वहां ऐसा क्यों है? इसमें ध्यान देने की बहुत-बहुत आवश्यकता है और कुछ नया करने की आवश्यकता है।

एक चीज और है। हम यदि हमारे प्रदेश की बात करें तो गोवा, केरल, गुजरात, एमपी जैसे राज्यों में ट्यूरिस्ट फुट-फाल बढ़ रहा है लेकिन राजस्थान में उनके कम्पेरिजन में उलटा फुट-फाल कम हो रहा है। अगर आप पिछले कुछ सालों के रिपोर्ट देखें, स्टेटिस्टिक्स देखें तो राजस्थान में वैसे इस साल तो थोड़ा बहुत बढ़ावा हुआ है नई सरकार के आने के बाद, लेकिन इससे पहले कुछ पांच-छह साल बहुत ही कम ट्यूरिस्ट आये थे। एक तो बाहर मैं सोचती हूं, जो नेगेटिव प्रचार होता है, उसके बारे में भी हमें भी कुछ पोजिटिव प्रचार करना चाहिये।

जैसा कि मैं सोचती हूं, महिलाओं की सुरक्षा पर भी अगर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे और जितने भी ये ट्यूरिस्ट स्पाट्स हैं, वहां पर महिलाओं के लिए कोई हैल्प डेस्क हो या इस तरह की कोई सुविधा हो, हैल्पलाइन नम्बर हो, जहां कोई भी ट्यूरिस्ट महिला जाकर इमिजियेटली कांटेक्ट कर सके और उसे इमिजियेटली रीएक्शन हो, उसका कुछ कर सकें। क्योंकि यह बहुत गलत नेगेटिव प्रचार बाहर हुआ है, बाहर के देशों में हो रहा है कि इण्डिया और राजस्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित डेस्टिनेशन नहीं है। इसके लिए भी अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ करे और इस तरह के हैल्प डेस्क, हैल्पलाइन नम्बर्स हों जो महिलाएं इमिजियेटली फोन कर सकें, ट्यूरिस्ट महिलाएं फोन कर सकें और उस पर इमिजियेटली कार्रवाई भी होनी चाहिये।

दूसरा, हमारी जो फैसेलिटीज हैं, जितने भी हमारे ट्यूरिस्ट डेस्टिनेशन्स हैं, वहां पर फैसेलिटी भी मैं सोचती हूं, वर्ल्ड क्लास नहीं हैं। बहुत कम टायलेट्स हैं और जैसे कि कोई अगर बैठकर रिफ्रेशमेंट भी लेना चाहें तो उसकी भी कोई सुविधा नहीं हैं। जैसे हमारे आरटीडीसी के जो होटल्स हैं, वहां पर भी जो सुविधाएं ट्यूरिस्ट को मिलती हैं, वह भी अप टू द मार्क नहीं हैं। बहुत कुछ हम लोग और कर सकते हैं। और देशों की जो गवर्नमेंट रन होटल्स

(राजकुमारी दियाकुमारी)

हैं, अगर आप उनसे हमारे गवर्नमेंट रन होटल्स को कम्पेयर करें तो हम लोग कहीं स्टैण्ड नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अब आवश्यक है कि हम पारम्परिक, मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल ट्यूरिज्म के अलावा हम ऐसे भी कोई मैथड्स देख सकते हैं थोड़ा आउट आफ द बाक्स, थोड़ा इनोवेटिव टैक्नीक टू इम्प्रूव ट्यूरिज्म की ओर भी हम लोग अगर देखें या उस पर ध्यान दें तो बहुत कुछ हो सकता है।

नये ट्यूरिस्ट हब्स को राजस्थान में डवलप किया जा सकता है। एक तो जैसे ट्यूरिस्ट जयपुर आता है तो वह एक या दो रात ही रुकता है। और भी कई डेस्टिनेशन्स में जाता है तो एक या दो रात ही रुकता है तो उसका स्टे बढ़ाया जाये। वह स्टे क्यों करेगा ज्यादा? वह इसलिए करेगा अगर आप उसको ज्यादा रिक्रिएशन के लिए या ट्यूरिस्ट अट्रैक्शन्स बढ़ायेंगे या वहां पर ऐसी कोई नई चीजें करेंगे तो वह जरूर एक दिन और रुकेगा। उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा।

उसके अलावा मैं हमारी मुख्य मंत्री साहिबा को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के पास टाइगर सफारी की स्थापना की घोषणा इस बार की है। चूरू में नेचर पार्क, जयपुर और जोधपुर में एक-एक बायोलोजिकल पार्क, बीकानेर में बीछवाल बायोलोजिकल पार्क, अजमेर में हैरिटेज वाक-वे, आमेर फोर्ट में नाइट म्यूजियम, झालावाड़ का सौन्दर्यीकरण व झालरापाटन में चन्द्रावतीजी की बावड़ी का जीर्णोद्धार तथा अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, जोधपुर, पाली, बीकानेर, सीकर एवं जैसलमेर के राजकीय संग्रहालयों के विकास कार्य। ये सब ट्यूरिज्म के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी लेकिन इन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन भी अगर जल्दी हो जाये तो वह भी बहुत-बहुत आवश्यक है। क्योंकि घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही नहीं होनी चाहिये, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तर्ज पर होना चाहिये, वैसे ही होना चाहिये, जितनी जल्दी घोषणाएं होती हैं, उतनी जल्दी उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस भी जल्दी से जल्दी शुरु हो जाना चाहिये।

एक और ट्यूरिज्म की बात, क्योंकि मैं ट्यूरिज्म से जुड़ी हुई हूं तो जो ट्यूरिस्ट राजस्थान में आता है, वह क्या चाहता है? वह यह चाहता है कि जब कोई भी ट्यूरिस्ट स्पाट पर जाता है, कोई मोन्यूमेंट देखने जाता है तो

(राजकुमारी दियाकुमारी)

वह यह चाहता है कि जो वहां पर गाइड्स हैं वे एक तो उसे परेशान नहीं करे, वह प्रोपर गाइड्स हों, वह ट्रेंड गाइड हों और वह लीगल गाइड हो। इल्लीगल गाइड और इस तरह के लपके बहुत हैं। उन पर भी कार्यवाई होनी चाहिए।

फिर हमारी कोई फिक्स प्राइसेस नहीं है। गाइड उनको दुकानों पर ले जाता है, शो-रूम पर ले जाता है। वहां उसकी कमाई ज्यादा कराता है। वहां उसे कमीशन मिलता है। इन सब चीजों पर भी कुछ न कुछ रोक आनी चाहिये।

उसके अलावा फैसेलिटीज के बारे में जैसे मैंने पहले बताया, टायलेट्स नहीं हैं। कहीं वह बैठकर कुछ चाय-काफी नहीं पी सकता। ऐसी फैसेलिटीज भी मुझे लगता है, बढ़ानी चाहिये।

दूसरा, ऐसे भी और कई चीजें हैं। सिक्योरिटी के बारे में जैसा मैंने बताया, महिलाएं और बेसिक ट्यूरिस्ट कोई भी अगर आता है वह अपने आपको सुरक्षित नहीं महसूस करता हमारे देश में। वह यह सोचता है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। कोई मुझे बेवकूफ तो नहीं बना देगा। कोई मुझे लूट तो नहीं लेगा। कोई मुझसे रेप तो नहीं कर लेगा। यह सब चीजें थोड़ा बहुत उसके मन में है। मैं यह नहीं समझती हूं कि यह सही चीजें हैं। ऐसा कुछ यहां नहीं हो रहा है। और ऐसा कुछ यहां नहीं हो रहा है जो दूसरे देशों में नहीं होता। बस यह है कि उसके लिए हमें कुछ सख्त ऐसे लाज बनाने होंगे, ऐसी कार्रवाई करनी होगी जिससे कि ऐसा करने पर मतलब ट्यूरिस्ट को भी लगे कि नहीं, मैं यहां सुरक्षित हूं और मेरा यहां ध्यान रखा जायेगा और इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन है, सेफ डेस्टिनेशन है। मैं, हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी ने स्वच्छ भारत केम्पेन की जैसी शुरूआत की और जिस तरह से यह चल रहा है उसके लिए उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि यह बहुत आवश्यक था। हमारे देश की जनता में अब सिविक सेंस की भावना जाग्रत हुई है। वह बहुत बड़ी चीज है जो पहले नहीं थी, वह अब हो गई है और उससे भी काफी कुछ ट्यूरिस्ट प्लेसेज में भी सफाई वगैरह आजकल अच्छी चल रही है। टूरिज्म यहां बढ़े, मतलब सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वह आये ट्यूरिस्ट और जो मोन्यूमेंट स्पाट्स को देखकर के चला जाए। दूसरे तरीके का भी टूरिज्म डवलप किया जा सकता है जैसे ईको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, स्प्रिचुअल टूरिज्म, वैलनेस टूरिज्म और नए कल्चरल हब्स भी

(राजकुमारी दियाकुमारी)

विकसित किए जाने चाहिए। मैं सोचती हूं कि एक टूरिस्ट कई बार हमारे जो वर्ल्ड सिटीज हैं जैसे जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर और भी जगहों पर हैं तो टूरिस्ट यह चाहता है कि मैं सिटी में घूम सकूं, फिर सकूं। इसलिए हमारे वाक वेज जो हैं वह भी अच्छी तरह से बिलकुल क्लियर होने चाहिए ताकि वह पूरे शहर में भी घूम सके, यह व्यवस्था भी अच्छी करानी बहुत आवश्यक है। वह कहीं चल ही नहीं सकता, क्योंकि चलने की कोई जगह ही नहीं है। जहां पर भी देखो लोगों ने पार्किंग कर रखी हैं तो वह वाक वेज भी अच्छी तरह से एस्टेब्लिश होने चाहिए ताकि टूरिस्ट आराम से पुराने शहर में घूम सके और आनन्द ले सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए भी एक दो बातें कहना चाहूंगी। मैं सोचती हूं हमारे लिए गर्व की बात है कि रणथम्भौर किला जो यूनेस्को वर्ल्ड हैरिटेज साइट है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में है और हमारा गणेश जी का मंदिर भी वहां पर है। उसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगी कि वहां की व्यवस्था भी थोड़ी इम्प्रूव करें। न तो वहां कोई टायलेट्स हैं, न वहां पानी पीने की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है, मतलब अभी तक वहां शुरूआत नहीं हुई है। वर्ल्ड हैरिटेज साइट तो दो साल पहले घोषित हो गया। परन्तु उसके बाद वहां की फैसेलिटीज में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं आया। इसके लिए भी मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि एक रोप-वे है जो हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग है। उससे टूरिस्ट भी आराम से किले तक पहुंच सकेंगे, उनको चलना नहीं पड़ेगा। कई ऐसे हैंडिकेप्ड टूरिस्ट होते हैं, कई ऐसे ऐजेड टूरिस्ट होते हैं जो फोर्ट के ऊपर तक जा नहीं सकते। उनके लिए भी और हमारे जितने भी पिलग्रिम्स आते हैं जो दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए भी अगर यह फैसेलिटी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे आस पास में भी बहुत मंदिर हैं, खण्डार में भी बहुत सारे मंदिर हैं उन पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, उनको कुछ बजट अलोकेट किया जाए, उनको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए ताकि टूरिस्ट को और भी कुछ करने को मिले क्योंकि हमारे वहां जब टूरिस्ट आता है सुबह सैंक्चुअरी जाता है, शाम को सैंक्चुअरी जाता है। दिन के समय में वह पूरी तरह से फ्री रहता है तो उस समय उसका यूटिलाइज किया जाए। उसको इन सब जगहों पर ले जाया जाए। मेरे सवाई माधोपुर क्षेत्र में भी कई ऐसे मंदिर हैं, कई और भी पर्यटक स्थल हैं जिनको अगर विकसित किया

(राजकुमारी दियाकुमारी)

जाए तो ये टूरिस्ट वहां तक दिन के समय जा सकते हैं और इससे लोकल्स को भी बहुत फायदा होगा।

एक हमारे वहां शिल्पग्राम भी है, पिछली गवर्नमेंट ने शिल्पग्राम तो वहां घोषित कर दिया लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं किया गया। मैं सोचती हूं कि वह एक उजाड़ जगह की तरह है। उदयपुर में जैसे शिल्प ग्राम है, उस तर्ज पर अगर यह शिल्प ग्राम डवलप किया जाए तो इससे भी बहुत फायदा होगा। वहां के लोकल जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं, हैण्डीक्राफ्ट्स हैं उनको भी बहुत इससे फायदा मिलेगा। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि हमारी जो एयर कनेक्टिविटी है वह बहुत बड़ी समस्या है। जयपुर, जोधपुर के बीच, जयपुर उदयपुर के बीच, बीकानेर में तो है ही नहीं और जैसलमेर में भी नहीं है तो एयर कनेक्टिविटी भी अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट को कहा जाए कि वो यहां एयर कनेक्टिविटी इम्प्रूव करे। क्योंकि बहुत सारा टूरिस्ट जयपुर तक तो आ जाता है उसके बाद वे सीधे कहीं ओर चले जाते हैं। और कहीं पर भी राजस्थान में वो जाना नहीं चाहते, क्योंकि रोड हमारे ठीक ठाक है, लेकिन कौन पांच छह घंटे वेस्ट करना चाहेगा। रोड्स पर भी जैसे अगर आप जयपुर से उदयपुर जाएं या जयपुर से जोधपुर जाएं तो मिड-वेज भी हमारे यहां ज्यादा नहीं है। मिड-वेज भी तो होने चाहिए। अब वह टूरिस्ट पांच या छह घंटे ट्रेवल करेगा गाड़ी में तो वह कहीं रूकेगा भी तो सही। उसे भी तो चाय पानी पीना है, रैस्ट करना है। ऐसी भी हमारे यहां फैसेलिटिज बहुत कम है। यहां से जब मैं सवाई माधोपुर जाती हूं तो हमारे यहां से वहां तक भी तीन घंटे का रास्ता है, बीच में फैसेलिटीज बहुत कम है। इन सब चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए तो मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी रहूंगी।

दूसरा, जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसको मैं सोचती हूं कि थोड़ा सा मार्केटिंग पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे जैसे कि बहुत सारे टूरिस्ट फेज होते हैं पूरे विश्व भर में और दिल्ली, मुम्बई और शहरों में वहां पर जो राजस्थान का पैवेलियन है। उस पर भी थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग करना बहुत आवश्यक है। थोड़ा और अट्रैक्टिव बनायें, उसे और ज्यादा प्रमोट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग राजस्थान आयें। क्योंकि बहुत सारे लोग अब केरल जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं लेकिन राजस्थान में आने में लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं हैं। इसके बारे में हमें ध्यान भी देना होगा और ऐसे कुछ स्टेप्स भी उठाने होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग राजस्थान आएं। सिर्फ एक

(राजकुमारी दियाकुमारी)

बार नहीं, रिपिटेडली आयें, बार-बार आयें, उसके लिए नई-नई चीजें उन्हें देनी बहुत जरूरी हैं। वो ही पुरानी चीजें कौन कितनी बार करेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगी और हमारी विजनरी, डायनामिक एण्ड एक्शन-आरिएन्टेड माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में यह उम्मीद करती हूं कि राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में एक नए व उभरे हुए राजस्थान की ओर प्रगति करेगा। हमारी मंत्री महोदय भी इस आल राउण्ड डवलपमेंट में अपनी भागीदारी निभाएंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा के माननीय विधायक श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी का एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले अखबारों के माध्यम से यह जानकारी मिली कि सरकार का हरदेव यूनिवर्सिटी आफ जर्नलिज्म को बंद करने का इरादा है। अखबारों में भी इसके बारे में लेख लिखे गए, कहा गया कि यह बहुत ही प्रतिगामी कदम होगा सरकार का अगर इस विश्वविद्यालय को बंद करती है तो। देश के अन्दर जर्नलिज्म का राजस्थान में तीसरा विश्वविद्यालय खुला है। एक भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, दूसरा रायपुर, छत्तीसगढ़ में केशुभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय और तीसरा हरदेव जोशी का नाम देकर यहां पर खोला गया है। एक सब कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष हमारे गृह मंत्री माननीय कटारियाजी थे, राजेन्द्र राठौड़जी उसके मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री उस कमेटी में थे। हमारे समाज कल्याण मंत्री माननीय चतुर्वेदीजी भी उस कमेटी के अन्दर थे जिनको यह दायित्व सौंपा गया कि पिछली कांग्रेस सरकार के छह महीने के कार्यकाल के निर्णयों की समीक्षा की जाएगी। निर्णय था, उस समीक्षा के आधार के ऊपर हालांकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 में इस विधान सभा में कानून पारित करके ही की गई थी। उस समय की जो प्रोसिडिंग्स हैं दिखाई कुछ लोगों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने जो विपक्ष में थे इसका पुरजोर शब्दों में यहां समर्थन किया था। क्योंकि अच्छी चीज है, अच्छी चीज का पार्टी लाइन से हटकर सभी लोग समर्थन करते हैं। किया यहां पर, स्थापना हुई और हर संस्था को एस्टेब्लिश करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उस संस्था को ऊपर आने में भी समय लगता है, टीथिंग प्राब्लम्स होती हैं संसाधन उपलब्ध कराये सरकार। यूनिवर्सिटी चालू हुई। एक जमीन का आबंटन उनको जगतपुरा में

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

किया गया हालांकि जो मेंडेट था इस सब कमेटी को वो इस बात के लिए था, 6 महीने में, जमीन के चक्कर में इस यूनिवर्सिटी के ऊपर गाज गिरने जा रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण राजस्थान के लिए कलंक की बात होगी अगर इस यूनिवर्सिटी को बंद किया जाता है तो। शुरू के अन्दर छात्रों की संख्या कम होती है किसी भी संस्था के अन्दर। यहां भी कम है और हर संस्था को नफे-नुकसान की दृष्टि से सरकार को देखना नहीं चाहिए। आज सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, कोई भी सरकार हो अरबों रुपये खर्च कर रही है। अगर उसके रिटर्न की बात करें तो रिटर्न तो उसमें से कुछ आता नहीं है तो मुनाफे के आधार पर शिक्षण संस्थाओं को बंद नहीं किया जा सकता है, यह मेरा आपसे अनुरोध है। वैसे भी सरकारी संस्था है यह। आपको सपोर्ट करना चाहिए उसको। आज इसका महत्व इसी बात से दर्शाता है कि इसमें रोजगार की विपुल सम्भावनाएं हैं। जिस प्रकार से टीवी चैनल्स का, रेडियो का, मास कम्युनिकेशन का, डेली न्यूज पेपर्स का, पीरियोडिकल्स का, वीकलीज का, मंथलीज का सर्कूलेशन बढ़ रहा है, दूरदराज गांवों में भी आज अख़बार पहुंच गये हैं, रेडियो, टेलीविजन पहुंच गया है और सैंकड़ों चैनल हो गये हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और लोगों तक मनोरंजन का साधन हुआ है, न्यूज का साधन हुआ है तो इसके साथ-साथ माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप भी इस कमेटी के मैम्बर थे। उच्च शिक्षा मंत्रीजी भी यहां हैं। देश के प्रधानमंत्री स्वयं, मैं आपको बताऊं अरुण जेटलीजी की अध्यक्षता में है। देश के अन्दर कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। उन्होंने खुद कहा है, अरुण जेटली साहब जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और उन्होंने अख़बार वाले और टीवी चैनल्स वालों को आमंत्रित किया है, निमंत्रण पत्र भी उनको भेज दिये गये हैं। ये अख़बार की खबर के आधार पर मैं यहां आपको बता रहा हूं और इस डिपार्टमेंट के एडिशनल सैकेट्री का इंटरव्यू पढ़कर बता रहा हूं। अभी राजेन्द्र राठौड़जी फौरन किताब दिखा देंगे कि आप यहां पर पढ़ नहीं सकते, तो बोल तो सकता हूं। बिना पढ़े बोल तो सकता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अगर आपकी अनुमति हो तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि मंत्रिमंडलीय उप समिति माननीय मुख्य मंत्रीजी गठित करते हैं और मंत्रिमंडलीय उप समिति में कई मामले विचारार्थ आते हैं, पर मंत्रिमंडलीय उप समिति को निर्णय करने का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अंतिम अधिकार थोड़े ही है। अंतिम निर्णय तो काबिना के अन्दर मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर होना है इसलिए आप जो शंकाओं के आधार पर बात कर रहे हैं, अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, विचारार्थ तो और भी बहुत से मामले हैं, ये भी विचारार्थ मामला है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मुझे बहुत खुशी है आप यहां सदन में खड़े होकर कह दें कि समिति का निर्णय होने के उपरांत केबिनेट सब कमेटी का मतलब है कि अंतिम फैसला तो मंत्रिमंडल में जाएगा लेकिन एक उप समिति की अहमियत जहां इतने वरिष्ठ मंत्री हों, मंत्रिमंडल से कम नहीं होती है। अहमियत वर्ड यूज कर रहा हूं। ईश्वर की कृपा से मेरा सौभाग्य रहा है, मैं भी मंत्रिमंडल में रहा हूं और कई मंत्रिमंडलीय समितियों का चैयरमेन भी रहा हूं। तो आम तौर से मेरे अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी काबिना में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्य, ऐसा है इस पर अभी कोई विचार...

श्री अध्यक्ष: देखिये डिस्टर्ब मत कीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की मीटिंग में यह मामला आया था। इस पर विचार हुआ है लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ है अभी तक। आप शंकाओं के आधार पर...

श्री अध्यक्ष: विराजिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने जो कुछ कहा है वह सब कुछ मैं वापस लेने के लिए तैयार हूं, आप खड़े होकर यहां घोषणा कर दीजिये कि ये यूनिवर्सिटी यहां बंद नहीं होगी। हम चाहते हैं, उन लड़कों के भविष्य का क्या होगा? बड़े-बड़े इसमें पत्रकार, जो लोग दूसरी जगह से नौकरी छोड़-छोड़ कर यहां पर आकर लग गये उनके भविष्य का क्या होगा और राजस्थान में इसकी विपुल सम्भावनाएं हैं। एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की। कुछ मंत्रियों ने अखबारों में चुनाव का फायदा उठाने के लिए कह दिया कि हम सरकारी नौकरियां देंगे। अब गले की फांस बन गई वो सरकारी नौकरियां। रोजगार की बात कर रहे हो तो रैस्पेक्टिव रोजगार है ये। आप कौशल विकास की बात कर रहे हो आप अप्रेन्टिस ट्रेनिंग

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

दिलाओगे, आप मिस्त्री पैदा करोगे लेकिन जो इस जर्नलिज्म के जरिये, टीवी के जरिये, रेडियो के जरिये, मास कम्युनिकेशन के जरिये एक बहुत बड़ी रैस्पेक्टिबल नौकरी लड़कों की बनेगी और आप देखते जाइये आप इसको सपोर्ट कीजिये। हजारों विद्यार्थी इसमें दाखिला लेंगे, मैं आपसे कह सकता हूं। यहां पर मैं कोट नहीं करना चाहता हूं, आपके यहां मीटिंग हुई थी मैं उसको भी नहीं कहना चाहता हूं। हर चीज को नफा-नुकसान, मुनाफे के हिसाब से नहीं देखेंगे आप। कुल डेढ़ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसको और सपोर्ट कीजिये। ये बहुत बड़ा जरिया होगा नौकरी का छात्रों के लिए जो इसके अन्दर जाएंगे और बढिया जर्नलिस्ट, जो आब्जैक्टिव रिपोर्टिंग करेंगे ऐसे जर्नलिस्ट पैदा होंगे। आब्जैक्टिव टीवी चैनल्स के एंकर्स पैदा होंगे, यह मेरा आपसे कहने का मतलब है। कृपया इसको बंद न करने का आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। दो वरिष्ठ मंत्री उस कमेटी के यहां बैठे हुए हैं, मैं आपसे अपील करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि आपकी मंत्रिमंडलीय उप समिति का जो निर्णय, अंतिम निर्णय जैसा राठौड़ साहब ने कहा कि मंत्रिमंडल लेगा तो मेरा आपसे निवेदन है। आप यहां मुझे इजाजत तो देंगे नहीं, ये अख़बार में है। जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, समय खराब नहीं करना चाहता हूं। प्रधानमंत्रीजी खुद चाहते हैं कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी हो तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखें। आपके दो बीजेपी के राज्यों में जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी चल रही है। आप राजस्थान में बीजेपी के राज में बंद करके क्यों कलंक का टीका लगवा रहे हो। उच्च शिक्षा मंत्रीजी, इसका आप ध्यान रखना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने का मूल मकसद आज सिर्फ यही था लेकिन हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी के ऊपर तो कोई असर होता नहीं है। पिछले साल मैंने कहा तो लिख दिया कि संसाधन उपलब्ध होंगे तब राजाखेड़ा में कालेज खोला जाएगा।

श्री अध्यक्ष: मित्रता निभा रहे हैं आपसे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ये मित्रता तो साहब आपकी बी ए सी में निभाते हैं। उसके बाद ये निभाते नहीं हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत पुरानी मांग हैं आप खोल भी रहे हैं। ऐसा व्यवहार मत करिये और ऐसा भेदभाव भी मत करिये कि मैं कांग्रेस पार्टी से

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आता हूं और खुशकिस्मत हूं वहां की जनता का इतना स्नेह अपार प्रेम मिला कि आठवीं बार जिता दिया उन्होंने मुझको। एक कालेज की आपसे मांग है। आप खोल दीजिये क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगता हुआ राजाखेड़ा आखिरी कस्बा है, वहां एसडीएम का आफिस है, तहसीलदार है, बीडीओ सब कुछ है लेकिन वहां के आगे उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है पांच किलोमीटर के ऊपर और मध्य प्रदेश लगा है पांच किलोमीटर के ऊपर, सैंडविच हो रहे हैं। लड़कों को बहुत कष्ट है, आप कर सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

तीसरी बात मैं एक कहना चाहता हूं डा. जसवन्त सिंह यादव ने यहां पर विद्यार्थी मित्रों का मुद्दा उठाया था, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार से चाहूंगा कि इसको मानवीय आधार पर आप देखें। ठीक है रोजगार किसी को बुरा लगता नहीं है। उन्होंने राजनीति जोड़ी कि हमारी पार्टी के लिए प्रचार किया। अब उनको हकीकत समझ में आ गई, उस प्रचार का क्या नतीजा निकला ढाक के तीन पात। कुछ हुआ तो नहीं। तो मेरा आपसे अनुरोध यह है माननीय मंत्री महोदय, कि इनके बारे में क्या कानूनी दिक्कत है, क्या कानूनी परेशानी है, इस समस्या का हल निकालें। कुछ लोगों को मैं जानता हूं इसी पर उनका परिवार निर्भर था, वो स्वयं निर्भर थे। यहां किसी के बारे में नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं। भूखो मरने की नौबत आ रही है वैरी पैथेटिक कंडीशन माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे मानवीय आधार पर और मैं जानता हूं कि पूरे सदन के सदस्य पार्टी सीमाओं में बंधे रहने के कारण कुछ कह पाये या नहीं कह पाये, यह बात दूसरी है लेकिन पूरे सदन के सदस्य मन ही मन इस बात को चाहते हैं। अगर आप फ्री कर दें कि बुरा नहीं मानेंगे, कहें, डा. जसवन्त सिंह यादव ने तो कह दिया यहां पर। मैं वहां आसन पर था तब वे कह रहे थे। मैं उनकी राय से बिलकुल सहमत हूं कि आप इसके ऊपर कुछ न कुछ उपाय निकालिये, कानूनी विशेषज्ञों से आप बात करिये। कानून के जरिये क्या रास्ता निकाल सकते हैं। जैसे हमने पैराटीचर्स को रेगुलराइज किया था ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है। वो भी रेगुलराइज हुए थे पैराटीचर्स। अगर आप ऐसा कोई रास्ता निकाल सकते हैं, इनमें कुछ तो बहुत हाइली क्वालिफाइड हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, टीचर बनने की सारी क्वालिफिकेशन उनमें मौजूद है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इस तरफ भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इस समस्या का निदान करें और कृपया करके, मैं आपसे हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करता हूं कि इस हरिदेव जोशी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यूनिवर्सिटी को बंद ना कीजिए अन्यथा यह राजस्थान के माथे पर कलंक होगा और इसके जिम्मेदार उच्च शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में ऐसा हुआ और उच्च शिक्षा मंत्री कौन थे, श्री कालीचरण सराफ थे, इससे आप बचने की चेष्टा कीजिए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 24 और 47 पर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। विराटनगर ...

सूचना

अलवर में वकीलों पर लाठीचार्ज

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्रावधान तो है नहीं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अलवर में वकीलों के द्वारा पुलिस के खिलाफ, एक सूचना देनी है मात्र। पुलिस के खिलाफ कोई प्रदर्शन किया जा रहा था वहां पुलिस और वकीलों में जबरदस्त झड़प हुई है। इसको एक बार...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्षजी, गम्भीर मामला है, बैठे हुए वकीलों पर लाठीचार्ज कराया है। निहत्थे वकीलों को पिटवाया है, अलवर में बड़ा माहौल खराब हुआ पड़ा है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): वहां वातावरण खराब हो रहा है, थोड़ा दिखवाने के आदेश आप जारी करा दें।

श्री अध्यक्ष: बस, बस, बात सरकार के संज्ञान में आ गई, विराजिए।

मांग संख्या 24 व 47 पर विचार

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं पर्यटन पर निवेदन करना चाहता हूं। मैं जहां से विधायक हूं वह एक पौराणिक स्थान है। जो मत्स्य जनपथ था, महत्वपूर्ण जनपथ था, उसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर एक ऐसा स्थान है जहां चार धर्मों के पवित्र स्थल हैं। राजस्थान में एक मात्र बौद्ध स्तूप वहां है। बिजक की डूंगरी है, अशोक का

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

शिलालेख है और एक शिलालेख वहां से कलकत्ता म्यूजियम में भी रखा हुआ है। जैन नसियां है, जैन समाज श्वेताम्बर और दिगम्बर, दोनों के पौराणिक मंदिर हैं। गणेशगिरी और हनुमान मंदिर है। इतना ही नहीं, वहां पर जो भारत में 52 शक्तिपीठ है अखण्ड भारत में, इस भारत में नहीं, इस भारत में तो 45 ही हैं, कुछ बाहर हैं, उनमें से 41वे नम्बर का जो शक्ति केन्द्र है अम्बिका माता का वह विराटनगर में है। इसी वर्ष 2014 में एक स्थल और जुड गया जिसको नोबल प्राइज मिला है, उसका जो प्रयोग केन्द्र है बालाश्रम, वह भी विराटनगर में है। इस कारण से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसको धार्मिक और पौराणिक पर्यटन स्थल बनाया जाये। पौराणिक पेनोरमा और बौद्धिक कालिक पेनोरमा बनाया जाये। दिल्ली जयपुर हाई-वे के बीच में वह आता है। 248 नम्बर का नया हाई-वे भी बन गया है जो विराटनगर होकर गुडगांव तक जायेगा, इस कारण से परिवहन सुविधाओं के लिये भी महत्वपूर्ण हो गया है। पास में अलवर फैक्ट्री मौजूद है। इस कारण मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आज की जो मांगें पारित हों उसमें विराटनगर को विशेष महत्व देकर घोषित किया जाये जिससे विराटनगर एक महत्वपूर्ण स्थल बन जाये। अकबर की टकसाल भी वहीं है, उसका मुगल गेट भी वहीं है। चार स्थल कहीं भी नहीं है। औद्योगिक कोरिडोर के रूप में जापान के लोग जब नीमराना में, अगर बौद्ध स्तूप को बढ़ावा मिलेगा तो जापान के पर्यटक अपार संख्या में आयेंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। सरकार इसमें पहल करे और बड़ी मात्रा में सुविधाएं जुटाने की कोशिश करे।

अब मैं मांग संख्या 24 पर आता हूं। इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अबकी बार जैंडर बजट शीर्षक के नाम से उन्होंने अलग बजट दिया है। पिछली सरकार के समय बालिकाओं का नामांकन 40 परसेंट को पार कर गया, वर्तमान माननीय मुख्य मंत्री 34 परसेंट जैंडर बजट में व्यवस्था कर के गईं थीं उसको वापस 30 परसेंट पर ले आये और नामांकन 40 परसेंट से भी आगे निकल गया। मैं इसी पर बोलना चाहता हूं कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये, बढ़ावा इसलिए भी जरूरी है कि राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री महिला हैं और राजस्थान का महिला शिक्षा में पूरे भारत में 35वां स्थान है। इसके लिये जिन्होंने 53 साल तक शासन किया वह जिम्मेदार हैं। क्योंकि उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। पिछले 5 वर्ष

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

में उन्होंने साढ़े पांच हजार संस्थाएं खोलीं, लेकिन महिलाओं के नाम पर एक भी स्कूल नहीं खोला, एक भी कालेज नहीं खोला। इतना ही नहीं, जब 1998 से 2003 तक थे तब मैं आपको एक बेशर्मी की स्थिति बताता हूं कि 11 कालेज ऐसे हैं जो स्व-वित्त पोषित हैं और दोनों पार्टियों द्वारा बार-बार घोषणा की जा रही है कि उच्च शिक्षा में बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी। मैं आपके माध्यम से वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में चार स्व-वित्त पोषित महिला कालेज हैं जिनमें लड़कियां फीस देती हैं फिर पढ़ती है। सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी जमीन है लेकिन फीस लड़कियों से लेकर अध्यापकों को दिया जाता है। उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हैं, उनके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं आज के बजट में घोषणा करें कि यह जो चारों महिला कालेज हैं, जिसमें बांदीकुई का बहुत बड़ा कालेज है, साढ़े सात सौ लड़किया पढ़ती हैं, उनको सरकारी कालेज घोषित किया जाये। कुछ नहीं करना, बच्चों से जो फीस लेते हैं उसको माफ करना है और पेमेंट आपको करना है, बाकी कालेज आपका है, बिल्डिंग आपकी है।

इसी प्रकार से राजस्थान में महिला शिक्षण संस्थाओं को लेकर अन बैलेंस भी हो गया है। राजस्थान में उच्च माध्यमिक शिक्षा में केवल 7.35 परसेंट संस्थाएं टोटल हैं उनमें 7 परसेंट ही संस्थाएं महिलाओं और बालिकाओं की हैं। जबकि माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति में 17 परसेंट महिला संस्थाएं हैं और कालेजों में भी साढ़े 11 परसेंट कालेज हैं। 40 के लगभग तो सरकारी कालेज हैं और 411 के लगभग प्राइवेट कालेज हैं जो केवल महिलाओं के लिये हैं। यह जो अनबैलेंस हुआ है इस कारण से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो पांच हजार स्कूलें खोली गई हैं उनके साथ-साथ जेंडर बजट में भी 5 परसेंट, 10 परसेंट इस अनबैलेंस को ठीक करना, क्योंकि यह राजस्थान पर एक कलंक है कि दूसरी बार महिला मुख्य मंत्री बन गईं फिर भी महिला शिक्षा में 35वां स्थान है। केन्द्र शासित प्रदेशों के बाद हमारा 35वां स्थान है, यह भी ठीक होगा और असंतुलन भी ठीक होगा।

मैं वर्तमान मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगा। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं उन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं, माध्यमिक शिक्षा को ठीक करने के लिये उन्होंने जिला शिक्षा बोर्ड सलाहकार की स्थापना करने की घोषणा की, मैं यह अच्छा प्रयास मानता हूं। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य गुंजल साहब ने बार-बार कहा कि पांचवी के बालक को दूसरी की किताब पढ़ना नहीं आता।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

यह तभी सुधरेगी जब कोई मानीटरिंग सिस्टम होगा। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने भी सदन में प्रश्न के उत्तर में आश्वस्त किया था कि प्राइवेट सैक्टर को कंट्रोल करने के लिये नियामक आयोग बनायेंगे, मैं यह उनके लिये अच्छी शुरुआत मानता हूं, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में उच्च शिक्षा में बहुत बड़ा असंतुलन है, 10 गुणा असंतुलन है। झुंझुनूं में 16848 की जनसंख्या पर एक कालेज है। पूरे भारत का औसत है 47 हजार लेकिन झुंझुनूं का औसत है 16848, जैसलमेर का है 1 लाख 68 हजार, बाड़मेर में 1 लाख 44 हजार पर एक कालेज है, जालौर में 1 लाख 14 हजार पर एक कालेज है भीलवाड़ा में जहां के मुख्य मंत्री भी रहे हैं, झालावाड़ की जहां की वर्तमान मुख्य मंत्रीजी हैं उनकी भी यही स्थिति है 1 लाख 8 हजार पर एक कालेज है झालावाड़ में। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि इस अनबैलेंस का औसत है राजस्थान का 43 हजार पर एक कालेज का, लेकिन 22 जिले ऐसे हैं जो औसत से ऊपर हैं, 11 जिले ही औसत से नीचे है। इसमें भी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, हम सामाजिक सरोकार नहीं रखते, सामाजिक संस्थाओं का उपयोग नहीं करते। मैं एक आश्चर्य की बात बताऊंगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर में औसत के बराबर है, बांसवाड़ा औसत पर आ गया, 43 हजार पर एक कालेज है। उसका कारण सरकार नहीं है, प्राइवेट सैक्टर भी नहीं है, वहां एक सामाजिक संस्था है भारतमाता मंदिर के नाम से उनका केन्द्र है, उन्होंने वहां शिक्षा का जागरण किया। एकल शिक्षक विद्यालय खोले, प्राइवेट स्कूलें जो वह चलाते हैं, एक तरीके से जिसको विश्व हिन्दू परिषद चलाती है। लगभग 800 संस्थाएं हैं। वनवासी कल्याण आश्रम चलाता है इस कारण से शिक्षा का जागरण हुआ और औसत पर बांसवाड़ा है, लेकिन 22 जिले नहीं है। डूंगरपुर भी औसत के नजदीक आ गया, इस कारण से जो अनबैलेंस हैं मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से कहूंगा, आप यह कालेज की बार-बार कह रहे हैं कि पहले उन उपखण्डों में खोलेंगे, मैं तो कह रहा हूं पहले उन उपखण्डों में खोलो जो औसत से ऊपर हैं। पहले उन पर खोलो जहां एक लाख पर भी एक कालेज नहीं है। सबसे पहले जैसलमेर में एक कालेज की नहीं दो कालेज की घोषणा करो। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा 1 लाख 68 पर एक कालेज है, हम शिक्षा को जब बैलेंस करना चाहते हैं। इसी प्रकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

कि 60 हमारे सम्भाग केन्द्र हैं, सम्भाग केन्द्र पर डीसी भी बैठता है, कलेक्टर्स बैठते हैं, सारे कार्यालय वहां हैं फिर शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? आप स्थिति देखिये, बीकानेर नीचे है, अजमेर नीचे है, जोधपुर नीचे है, पाली नीचे है, उदयपुर नीचे है, कोटा नीचे है, यह सब औसत से नीचे हैं। केवल जयपुर और जयपुर की भी स्थिति देखिये कि जयपुर का पूरे सम्भाग का औसत है उससे जयपुर स्वयं नीचे है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: 11 मिनट हो गए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अभी मैं बोल रहा हूं। मैं महिला शिक्षा के बारे में कह रहा हूं। महिला शिक्षा पर रिपोर्ट छपी है आय-व्ययक 2015-16, उसके 19 पेज पर पहला वाक्य है सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय, महाविद्यालय की अध्ययनरत छात्राएं शिक्षण शुल्क से मुक्त हैं, इस गलती को तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी ठीक करें। आपने यह पन्ना हम सबको दे दिया। यह पब्लिक डाकूमेंट है कि शिक्षा से मुक्त है और 11 कालेजों में बच्चों से फीस ली जा रही है, लड़कों से भी ली जा रही है, लड़कियों से भी ली जा रही है, इसको करैक्ट करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। राजस्थान में अच्छी बातें भी हुई हैं। राजस्थान में सामान्य वर्ग की लड़कियां हैं वह उच्च शिक्षा में लड़कों से ज्यादा पढ़ रही हैं। 74 हजार लड़के जहां पढ़ रहे हैं वहां 88 हजार लड़कियां पढ़ रही है। इतना ही नहीं, एक और सुखद उदाहरण है कि 6 जिले ऐसे हैं जहां अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियां लड़कों से ज्यादा पढ़ रही हैं।

मैं अब संस्कृत शिक्षा पर आता हूं। 20 साल से प्राचार्य, प्रधानाचार्य के प्रमोशन के नियम नहीं है। पिछली बार भी मैंने इस विषय को खूब उठाया था। नियम बन रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि नियम नहीं है। इस कारण से संस्कृत शिक्षा की दुर्गति हो रही है। मैं यह भी चाहूंगा, मेरे विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में तीन उपाध्याय स्कूल हैं लेकिन एक भी कालेज नहीं है, बच्चे 12वीं करने के बाद में भटकते रहते हैं इसलिए एक संस्कृत का कालेज मुझे भी। इतना ही नहीं कोटकासिम और तिजारा में संस्कृत के कालेज हैं और दोनों स्ववित्त पोषित हैं। संस्कृति से जुड़ा हुआ संस्कृत विषय है उसमें भी

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

बच्चे पैसे देकर पढ़ेंगे तो कैसे होगा? यह भी कालेज वाला विषय है, उच्च शिक्षा का विषय है कि फीस देकर बच्चे पढ़ रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं।

विद्यार्थी मित्रों की बात आई थी। मैं भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वस्त किया था लेकिन विलम्ब होने से उनको आशंका होती है, पांच लोग अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। उनमें से अधिकांश, 80 परसेंट लोग बीए, बीएड हैं। उस जिले के विज्ञापन या स्कूल के विज्ञापन से लगे हैं, केवल कोर्ट ने एक असंवैधानिक शब्द काम में ले लिया इस कारण से अडचन आ रही है लेकिन बहुत पद हैं, इस कारण से एडजस्ट किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से विश्वविद्यालय की स्वायत्ता की बात आती है। मैं दो ही मिनट बोलूंगा। स्वायत्ता का अर्थ होता है उनको खर्च करने का अधिकार, लेकिन खर्च करने का अधिकार नहीं, उनको तो चाहिए नियुक्ति का अधिकार। तीन विश्वविद्यालयों के पलीता लगाकर चले गए। इंडिया में 5 नम्बर पर राजस्थान यूनिवर्सिटी थी लेकिन ऐसे-ऐसे वाइस चांसलर ने आकर विश्वविद्यालयों को बिगाड़ दिया और ऐसी नियुक्तियां कर गए जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते, अयोग्य लोगों को लगा गए। अभी का उदाहरण है, आज भी मैंने माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया था, आपके माध्यम से ध्यानाकर्षण भी लगाया। गवर्नमेंट कालेज चिमनपुरा वहां 850 बच्चे फर्स्ट ईयर के, उनको सीकर जिले में प्राइवेट स्कूल में केन्द्र दे दिया। कल उन बच्चों ने जाम लगाया। उन बच्चों की स्थिति यह है कि उनसे कहते हैं 1500 रुपये दो। कालेज में उन्होंने प्रेक्टिकल सीखा उसके बाद कहते हैं 1500 रुपये दो तब आपको परीक्षा में बैठने देंगे, ऐसी अव्यवस्था कर रहे हैं, यह स्वायत्ता का अर्थ नहीं है। स्वायत्ता का अर्थ है कमाकर खर्च करो, उससे आर्थिक स्वायत्ता भी होती है। एडमिशन की स्वायत्ता ही नहीं होती, नियुक्ति की स्वायत्ता नहीं होती, नियुक्तियों में तो फिर भी स्वायत्ता नहीं मिल सकती, योग्यता होती है यूजीसी की। वहां यूजीसी के नियमों को ताक में रखकर जोधपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय और जयपुर विश्वविद्यालय ने सारी गड़बड़ियां की हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। इस प्रकार की जो प्रवृतियां हैं उसका एक ही समाधान है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो उतने ही स्थाई वाईस चांसलर लगाए जाएं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक-दो मिनट और लूंगा मैं।

श्री अध्यक्ष: बहुत ले लिया आपने।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, अच्छा एक मिनट।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): जयपुर, कोटपूतली और अलवर इनके बीच में एक भी सरकारी पालिटैक्निक नहीं है। मैं आपके माध्यम से तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जमीन देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास जमीनें हैं, मेरे पास 14 हजार बीघा जमीन सरकारी है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मेरा यह सौभाग्य है। एक भी नहीं है, लेकिन इण्डस्ट्रियल एरिया कितने हैं, नीमराना, शाहजहांपुर है, खुशकेड़ा है, भिवाड़ी है और अलवर है, और इधर कालेज ही नहीं है। जब हम 15 लाख विद्यार्थियों की बात करते हैं तो भारत सरकार ने जयपुर जिले को एक पालिटैक्निक कालेज दिया एक साल पहले, उसको मेरे क्षेत्र में खोला जाए, ऐसा निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, हो गया आपका। श्री जगदीश नारायणजी।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक और।

श्री अध्यक्ष: एक आ गई आपकी, एक-एक करके तो बहुत आ जाएगी।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक और।

श्री अध्यक्ष: आप लिखकर दे दो मुझे, मैं पास....

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): चलो, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: जगदीश नारायणजी।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 और 47 पर बोलने की अनुमति प्रदान की इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा हमारा वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा ही हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। सही मायने में अगर देखा जाए तो गांवों का विकास शिक्षा के ऊपर टिका हुआ है। शिक्षा की महत्ता को देखते हुए हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अब की

(श्री जगदीश नारायण)

बार जो निर्णय लिया और पंचायती राज चुनावों में शिक्षा की अनिवार्यता लागू की, 8वीं और 10वीं क्लास करके, इसके लिए मैं पूरे ग्रामीण क्षेत्र की ओर से माननीय मुख्य मंत्री महोदया का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जब पढ़े-लिखे लोग पंचायत राज संस्थाओं में आएंगे तो वह योजनाओं को समझेंगे, काम को समझेंगे, उनमें काम करने की ललक होगी, मैं समझता हूं कि सही मायने में गांव का विकास कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरों में तो फिर भी चल सकता है क्योंकि शहरों में पूरी व्यवस्था है, पर गांवों में अभी तक शिक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई है। गांवों में लोग अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। गांवों में जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं उन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अगर हम आज देखें तो देखकर रोना आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन आपके माध्यम से चल रहा है, सदन चले तो सदन में आपका होना बहुत जरूरी है, आपकी अनुपस्थिति में सदन नहीं चल सकता। ठीक उसी प्रकार से मेरी मान्यता, मेरा सोच है कि अगर एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल का प्रिंसिपल नहीं हो तो वह सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं चल सकता। एक सैकण्डरी में एक हैडमास्टर नहीं हो तो वह सैकण्डरी स्कूल भी हैडमास्टर के बिना नहीं चल सकता। आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा, हमारे दोनों शिक्षा मंत्री महोदय विराजमान हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रिंसिपल की जहां-जहां भी खाली जगह है, मेहरबानी करके आप उन सब स्कूलों में प्रिंसिपल लगाने की कोशिश करें। जमवारामगढ़ में मेंगी, टोडामीणा, जमवारामगढ़, नायला, नीमला, रायसर, धोला और साइवाड़, 8 सीनियर सैकण्डरी वह स्कूल हैं जिनमें प्रिंसिपल नहीं है। इसके अलावा 15 सैकण्डरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें अभी तक प्रधानाध्यापक नहीं हैं। बिना हैडमास्टर के वह स्कूल चल रहे हैं। फर्स्ट, सैकण्ड, थर्ड ग्रेड की मैं बात करूं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अभी तक अध्यापकों की बहुत कमी है। लगभग 213 पद अभी भी खाली चल रहे हैं जिसमें 125 पद फर्स्ट, सैकण्ड, थर्ड ग्रेड के और 88 पद प्रारम्भिक शिक्षा के हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे गुजारिश करूं कि 213 पद अगर एक विधान सभा क्षेत्र में कम हों तो वहां की शिक्षण संस्थाओं का क्या हाल होगा। वे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिये आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जमवारामगढ़ क्षेत्र में जो 213 पद आज की तारीख में खाली पड़े हैं, मैंने लेटेस्ट सूचना निकलवाई है, उन पदों को अविलम्ब

(श्री जगदीश नारायण)

भर करके उस क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें, उस क्षेत्र की जनता को अनुग्रहीत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सरकारी स्कूलों से लोगों का विश्वास उठ गया। आज कमजोर से कमजोर व्यक्ति, एक मजदूर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है। यह भी पता है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की, शिक्षकों की कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, ज्यादा वे योग्य भी नहीं हैं, बनिस्पत सरकारी स्कूलों के। लेकिन लोगों में एक सोच पैदा हो गया और उस सोच के पीछे मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं कोई कमियां हैं, कहीं न कहीं कोई लापरवाही बरती गई है। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से भी निवेदन करुंगा कि सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण की व्यवस्था लागू करें। सरकारी स्कूलों के रिजल्ट पर आप ध्यान दें और जहां सरकारी स्कूलों का कम रिजल्ट आता है उन स्कूलों के अध्यापकों की जिम्मेदारी तय करें और इसमें अगर आप कदम उठाएंगे तो मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में इस व्यवस्था में सुधार होगा, स्कूलों की दशा सुधरेगी और वापस जनता का इन स्कूलों में एक विश्वास पैदा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बेमौसम बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, किसानों की फसल तबाह हो गई। खेती से जुड़ा हुआ जितना दलित या मजदूर वर्ग था, वह भी हाथ में हाथ लेकर बैठ गया। सरकारी स्कूलों में अगर संसाधन सही नहीं होंगे, सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं होंगे तो ऐसे गरीब तबके के लोग अपने बच्चों को कैसे शिक्षित कर पाएंगे? इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर सरकार को गम्भीरता से पूरा ध्यान देना चाहिए और व्यवस्था को सुधारने का काम करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आज भी घर से बच्चे जब निकलते हैं स्कूल के लिये तो हाथों में बोतल लेकर निकलते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य है प्रदेश का कि हमारी शिक्षण संस्थाओं में पानी की व्यवस्था नहीं हो, हमारे बच्चों को पानी के लिये दूरदराज भागना पड़े या बोतल साथ में लेकर जाना पड़े। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पेयजल के बारे में गम्भीरतापूर्वक निर्णय ले करके कम से कम हमारे सरकारी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था जरूर करवाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मिड-डे-मील खाना बच्चों को खिलाया जाता है। यह भी आपको पता है कि मिड-डे-मील के अन्तर्गत जो खाना बच्चों को

(श्री जगदीश नारायण)

खिलाया जाता है, वह मात्र सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिल रहा है। प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को तो खाना नहीं मिलता। आज लोगों का सोच बन गया है प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजने के लिये। ऐसा भी कहीं नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में जाने वाले बच्चे कहीं कोई संसाधनों से सम्पन्न हों या अच्छे अमीर वर्ग के हों। सब गरीब वर्ग के बच्चे उन स्कूलों में भी जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक इन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जब तक सरकारी स्कूलों में ग्रामीण जनता का विश्वास नहीं बनेगा, तब तक आपकी जो महत्वपूर्ण योजना चल रही है, मिड-डे-मील, इससे भी हमारे प्रदेश के बच्चे वंचित रहेंगे। उन बच्चों को यह भी पोषाहार नहीं मिल पाएगा। इसलिये इस ओर भी सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रत्येक स्कूल के पास में खेल-कूद करने के लिये खेल मैदान है। लेकिन स्थिति यह है कि बहुत सारे खेल मैदानों पर आज लोगों का अतिक्रमण चल रहा है या खेल मैदान है तो वह स्कूलों से दूर हट करके है, उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिये मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि उन खेल मैदानों पर चल रहे अतिक्रमण को दूर करवाएं और जहां स्कूलों में खेल मैदान की व्यवस्था नहीं हो, वहां खेल मैदान की व्यवस्था पर ध्यान दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जमवारामगढ़ एस.टी./एस.सी. बाहुल्य क्षेत्र है और जयपुर के नजदीक क्षेत्र है। लेकिन वहां सरकारी कालेज नहीं है। सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी करने के बाद उस क्षेत्र के बच्चे और बच्चियां, क्योंकि गरीब तबके के लोग हैं, वे जयपुर तक नहीं पहुंच पाते। जब वे जयपुर तक नहीं पहुंच पाते तो वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इसमें तो कोताही नहीं बरतें। शिक्षा का मामला है और शिक्षा ही एक उत्तम विकास है। सरकारी कालेज वहां खोला जाना चाहिए ताकि गरीब तबके के लोगों को एक पढ़ने का माध्यम मिले, एक व्यवस्था मिले। इसके साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा और माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी का भी आभार प्रकट करूंगा कि पिछले कार्यकाल में हमारे जमवारामगढ़, मूंडला गांव में भीमराव अम्बेडकर विद्यापीठ की स्थापना की थी और स्थापना करने के बाद में लगभग 7 करोड़ की राशि से एक भव्य भवन भी बनवाया था। भवन बनाने के बाद में आज पांच, सात, दस दिनों से मैं लगातार सुन रहा हूं,

(श्री जगदीश नारायण)

अखबारबाजी भी हुई है। हमारे अम्बेडकर मंच के भाई भी मेरे से मिले हैं। उन्होंने भी मुझे आग्रह किया है, बताया है कि अभी मंत्रिमण्डलीय उप समिति की जो बैठक हुई उस बैठक में भीमराव अम्बेडकर विद्यापीठ में जो विधि विश्वविद्यालय चलाने की मान्यता मिली थी, उसको बंद करने का एक प्रस्ताव लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही नहीं की जाए। उस विधि विश्वविद्यालय को यथा सम्भव चालू रखा जाए। मैं तो चाहता हूं, उसमें और व्यवस्था में सुधार किया जाए। अगर उसको बंद कर दिया गया तो हमारे क्षेत्र की जनता के साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं समझता हूं कि भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में भी एक गिरावट के रूप में लोग इसको देखेंगे।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन के आदेश की मैं अवहेलना नहीं करता, पर एक मांग बच गयी थी, थोड़ी सी, अगर एक मिनट मुझे दे दें तो मैं निवेदन कर दूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां। वह मांग रख दीजिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के साथ पर्यटन क्षेत्र में मैं बात करूं तो पर्यटन क्षेत्र की दृष्टि से जमवारामगढ़ एक रमणीय स्थान है। वहां अरावली श्रृंखलाएं हैं और सुप्रसिद्ध झील, जमवारामगढ़ झील, 1982 में जहां एशियाड के अन्तर्गत नौकायन प्रतियोगिता हुई है, पूरे एशिया में उसका नाम है। वह झील जो वर्षों से जयपुर शहर को पानी पिलाती आ रही है, आज वह झील खुद अपने आपमें प्यासी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि यथासम्भव जल्दी से जल्दी पानी ला करके उस झील को भरा जाए। उस झील को वापस उस स्थिति में लाया जाए ताकि झील के माध्यम से जयपुर शहर को भी पानी मिले और उस झील के माध्यम से ठेठ जमवारामगढ़ से ले करके भरतपुर तक के इतने बड़े भू-भाग का वाटर-लेवल भी रिचार्ज हो। पानी का स्तर भी ऊपर आये और कृषकों को भी एक बहुत बड़ा फायदा हो सके। इसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जमवारामगढ़ में झील के अलावा एक सुप्रसिद्ध जमवाय माता का दार्शनिक स्थल है, पुराना मन्दिर है और उस मन्दिर में कई बार महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी दर्शन करने के

(श्री जगदीश नारायण)

लिये आये हैं। प्रदेश से नहीं, अपितु पूरे देश के कोने-कोने से लोग आते हैं। ऐसा एक दार्शनिक स्थल होते हुए वहां वीर राव मेधाजी का एक भव्य पुराना स्मारक है और दुर्ग होते हुए, वह एक रमणीय स्थान है। उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पर्यटन मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि उस क्षेत्र में भी काम करें और जमवारामगढ़ का पर्यटन दृष्टि से विकास करें। आपने टाइम दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मास्टर श्री मामनसिंह यादव।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, एक राइट टू इंफार्मेशन है।

श्री अध्यक्ष: राइट टू इंफार्मेशन की व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान) नहीं, नहीं, एक मिनट नहीं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, आज पर्यटक-डे है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, आप बैठिये। अंकित नहीं हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: यह नई बात हो गई है। जब जो चाहे, अंकित नहीं हो। यह एक आदत सी पड़ गई है। आप बैठिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: बस, ठीक है।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा पर निवेदन करना चाहूंगा। आपने मुझे इजाजत दी, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। चर्चा से पहले, माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय कालेज शिक्षा मंत्रीजी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि सन् 1952 से अब तक एक ऐतिहासिक घोषणा की, पांच हजार सीनियर सैकण्डरी स्कूल, यह राजस्थान में ही नहीं, मेरे ख्याल में हिन्दुस्तान में पहला इतना बड़ा कदम है। पांच हजार प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं, मिडिल स्कूल खोले जा सकते हैं। कोई और छोटा काम किया जा सकता है। पांच हजार सीनियर सैकण्डरी स्कूल एकमुश्त, एक ही कलम से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खोले, इनके लिये बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(मास्टर मामन सिंह यादव)

(15.00 बजे)

मेरे तिजारा विधान सभा क्षेत्र में, हमारी चर्चा का विषय था कि दो, तीन, चार अधिकतम पांच या केवल एक-दो ही खुलते थे सीनियर सैकण्डरी, 17 स्कूल तिजारा विधान सभा क्षेत्र को मिले। मेरी ओर से और हमारी तिजारा की जनता की तरफ से माननीया मुख्य मंत्रीजी को, माननीय शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

उसके साथ-साथ और भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे यहां तिजारा में कला महाविद्यालय कांग्रेस सरकार ने आनन-फानन में खोल दिया। ठीक चुनाव के एक-डेढ़ महीने पहले, दो महीने पहले। न तो वहां पर प्रिंसिपल और न बजट और न कहीं पर बिल्डिंग, कुछ भी नहीं, केवल वोट बटोरने के लिए। जनता समझती थी कि यह छलावा है। उसके बाद जैसे ही कालेज खुला, माननीया मुख्य मंत्रीजी की सरकार आयी और हमने माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन किया कि वहां पर बच्चे मैदान में बैठे हैं, बालक-बालिकाएं तो बजट में 3 करोड़ 80 लाख रुपये बिल्डिंग निर्माण के लिए पहले ही दिये जा चुके हैं, हमारे खाते में जा चुके हैं, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

पदोन्नति का काम किया पहली बार। कई सालों से शिक्षकों की पदोन्नति बंद पड़ी थी। उसके कारण द्वितीय श्रेणी के अध्यापक लगाये गये जो कि काफी हद तक पूर्ति होती जा रही है। प्रिंसिपल का, अब पांच हजार प्रिंसिपल की पदोन्नति होगी तो इन विद्यालयों में पूर्ति होगी। जैसा कि अभी कई माननीय सदस्य प्रिंसिपल्स की कमी बता रहे थे तो सभी जगह पर कमियां हैं क्योंकि एक साथ इतनी स्कूल खोलने में यह व्यवस्था होगी और कांग्रेस सरकार ने जो पिछले सत्र में खोले, उनमें प्रिंसिपल, हैड-मास्टर, अध्यापक कोई नहीं। मिडिल स्कूल के, पी.एस., बजट के पुराने दो या तीन, ऐसे-ऐसे स्कूल्स हैं तिजारा में जहां पर दो-दो, तीन-तीन पर भी स्कूल, सैकण्डरी स्कूल चल रहे हैं, उनकी पूर्ति में भी समय लगता है।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी बहुत संवेदनशील हैं इस मामले में। अभी पिछले ही शनिवार को हमारे अलवर का दौरा भी किया था इन्होंने। बड़ी जागरुकता और संवेदनशीलता से काम किया। शिक्षा अधिकारियों को, पूरे जिले भर के, उनकी मीटिंग ली, हम जन-प्रतिनिधि भी मौजूद थे और उनको आगाह किया, उन सबसे कहा कि मानीटरिंग, निरीक्षण होना चाहिए, स्कूलों का। जब

(मास्टर मामन सिंह यादव)

तक निरीक्षण नहीं होगा तब तक सही व्यवस्था नहीं चलेगी। सबको निर्देशित करके आए हैं और नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया है। जो भी स्कूलों की, हमारे जिले की जो समस्याएं थीं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी उनको लेकर आए हैं, इसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। इस तरह से दौरा करके, जिले के अन्दर ही जाकर, जिले की समस्याओं को नोट करके लाकर और उनको क्रियान्वित करने का काम करेंगे, माननीय शिक्षा मंत्रीजी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

पिछले सत्र में हमारे तिजारा विधान सभा क्षेत्र में एक आई.टी.आई. का बड़ा हब, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार की तरफ से खोला गया था साढ़े सात सौ करोड़ का, जिसका काम चल रहा है। उसके अन्दर केवल अल्पसंख्यकों को शिक्षा का कांग्रेस सरकार ने तय किया था, जो कि गलत था। धर्म के नाम पर कोई शिक्षा में आरक्षण नहीं हो सकता। माननीया मुख्य मंत्रीजी और माननीय शिक्षा मंत्रीजी से हमने निवेदन किया इसी हाउस में, माननीय मंत्रीजी ने घोषणा की कि यह सबके लिए होगा और वह सबके लिए चल रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि शिक्षा में कोई धर्म, जाति का आरक्षण नहीं होना चाहिए। सबके लिए, सबके बच्चे होते हैं।

मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगें भी मंत्री महोदय रखना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, तिजारा विधान सभा क्षेत्र, जिसमें भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र आता है, राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र और एन.सी.आर. में आता है। दिल्ली के बिलकुल निकट है। दो लाख के करीब वहां की आबादी हो चुकी है। एनरोल भी है और कुछ काफी बिना एनरोल भी वहां पर बसे हुए हैं। कितने ही वहां पर उद्योग हैं। सोसाइटीज सैक्टर बने हुए हैं। उनके अन्दर इतनी ज्यादा आबादी है लेकिन आज तक वहां पर कोई महाविद्यालय नहीं है। पिछले बजट सत्र में भी शिक्षा की डिमांड पर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था। अब पुन: विशेष आग्रह करते हुए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर अभी वार्षिक उत्सव था। माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री हेमसिंह भड़ानाजी विराजमान हैं, इनको मुख्य अतिथि के रूप में भी वहां पर बुलाया गया था। हमारे भिवाड़ी में बाबा मोहनराम के नाम से एक संस्थागत स्कूल चल रहा है जो पूरे क्षेत्र के वासी चंदा इकट्ठा करके चलाते हैं। पूरी चारदीवारी और बिल्डिंग भी बना रखी है और संचालन भी हो रहा है केवल आपको स्वीकृति देनी है उसके अन्दर और स्टाफ के लिए वेतन। 40 बीघा, 38 बीघा में

(मास्टर मामन सिंह यादव)

चारदीवारी, जमीन, पूरी बिल्डिंग और यह बना रखी है। महाविद्यालय कई सालों से चालू है, माननीय मंत्री महोदय भी उसको देखकर आए थे और उनकी मांग थी कि पूरा मैनेजमैंट, कोई व्यक्तिगत नहीं है वह, पूरे क्षेत्र के समाज का, लोगों का, उसमें सैनिकों की भागीदारी है और सैनिकों ने जितना ऐसा सराहनीय काम कर रखा है वहां पर शिक्षा का, तो उसको सरकारी स्कूल बनाया जाए, यह मेरा मंत्रीजी से विशेष आग्रह है।

इसी तरह का स्व-वित्त पोषित संस्कृत कालेज कोटकासिम में भी है सबसे पुराना जिले में कालेज है। उसको भी सरकारी बनाने की कृपा करें। एक ऐसा ही सीनियर सैकण्डरी स्कूल है वहां पर, तो इस तरह से आपसे विनम्र निवेदन है।

सैनिकों के सम्मान के लिए, सैनिकों ने भिवाड़ी में जो कालेज चला रखा है, वह बहुत सराहनीय कदम है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, मंत्रीजी से भी और आप सभी माननीय सदस्यों को एक प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि इसमें न तो कोई बजट लगेगा और न ही पैसे लगेंगे। माननीय मंत्री महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी से विचार-विमर्श करके यह केवल एक आदेश प्रसारित करना है, निर्देश देना है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी को जिस गांव में और जिस वार्ड में, कस्बों में वार्ड और शहर में वार्ड होते हैं तो उनके अन्दर जो-जो भी शहीदों की विधवाएं हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो देश की सेवा करके आये हैं उनको सम्मानित कर दिया जाए, फूल-माला डाल दी जाएं तो उनका सम्मान होगा और वहां के बालक-बालिकाओं में भी देश भक्ति की भावना को बढ़ावा मिलेगा, यह मेरा प्रस्ताव है, निवेदन है। इससे हम सबकी सोच बदलेगी और हमारा समर्पण होगा उन सैनिकों के लिए। हमारी सोच, सरकार की सोच और सभी की इसमें, न कोई दलगत बात है, यह सभी के लिए सम्मान क्योंकि सैनिक सबका होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब-जब भी देश पर कोई आपत्ति आयी है, पूरा हर दल, हर इंसान, बच्चा-बच्चा, हर जाति, धर्म सब एक हुए हैं तो यह मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, विशेष रूप से ध्यान देकर गौर करें और सैनिकों के सम्मान में, सैनिकों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए समर्पित भाव रखते हुए इस प्रस्ताव को पास करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): एक साहब, अभी थोड़ा सा है। मेरे यहां पर जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणाएं की हैं, सभी पांच हजार स्कूल और उसके अलावा कुछ शेष पंचायतें बच गयीं मेरे क्षेत्र में। किस कारण से रहीं, वह भी मैं माननीय मंत्री महोदय को नोट करवाना चाहूंगा।

सलारपुर, मंडा, मसीद, बिरामपुर, मुडाणा व रायखेड़ा, जो पंचायत मुख्यालय होते हुए भी सीनियर सैकण्डरी स्कूल से बच गयीं। मंत्री महोदय, निवेदन करना चाहूंगा इनको भी सीनियर सैकण्डरी स्कूल दें और 11 पंचायतें, जो नव-निर्मित हुई हैं, वह तो माननीय महोदय ने घोषणा कर ही दी, उनको भी बनाया जाये।

एक और ज्वलन्त समस्या है। नगर परिषद भिवाड़ी में पंचायतें सम्मिलित हो गयीं, लेकिन पंचायत मुख्यालय थे 6-7, उनको भी नहीं बनाया गया क्योंकि वह नगर परिषद में शामिल हो गयीं। जबकि मुख्यालय वह भी है। शिक्षा का अधिकार उनका भी है। उच्च माध्यमिक विद्यालय वहां भी खोला जाना चाहिये, यह मंत्रीजी से मेरा आग्रह है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये बस।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): मैं बुजुर्गवार, साडो, सेटपुर, मिनकपुर गुर्जर, आलमपुर, सांतलघट ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह नोट करा देना आप। श्री सुखराम विश्नोई। अब हो गया, आप विराज जाइये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): अभी तो साहब रह रहा है। एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: अभी विराज जाइये। आप नोट करा देना।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): एक निवेदन और है। एक निवेदन छोटा-सा है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक निवेदन आने दीजिये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): पिछली सरकार ने भर्ती की 2 हजार अध्यापकों की, वह केवल प्रतिबन्धित जिलों में ही लगाये गये। जिनकी मैरिट बहुत उच्च थी, 2 हजार में से एक भी अलवर जिले में नहीं लगाया गया,

(मास्टर मामन सिंह यादव)

जबकि अलवर जिले में 300 पद खाली थे हैडमास्टर के। अलवर ही नहीं, भरतपुर, जयपुर, सीकर, धौलपुर, करौली, झुन्झुनूं, किसी जिलों में नहीं। केवल दस प्रतिबन्धित जिलों में लगाया गया। यह उनके साथ अन्याय है। मैरिट उच्च थी। 2 हजार में से 500 तो इन जिलों में देते। 10 जिलों में 1500 देओ, उनको देना चाहिये था। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तो उनमें भी मिलना चाहिये। मेरा निवेदन है कि जब उस सरकार ने गलती की है, और वह आशाएं करे बैठे थे हैड मास्टर कि सरकार बदलेगी, तो हमारे साथ न्याय होगा, जो उच्च मैरिट वाले थे। तो कम से कम 500 मैरिट तक उनको वापस उनके गृह जिलों में लगाये जाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: आपका पाइंट आ गया।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): कोर्ट ने भी, उच्च न्यायालय ने भी सरकार के लिये लिखा है कि इसमें पुनर्विचार करके फैसला दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये-विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। श्री सुखराम विश्नोई।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): एक मिनट साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब हो गया। नहीं, अब हो गया। पाइंट आ गया आपका।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): शौचालय, जो विद्यालयों में हैं, उनके अन्दर पानी की व्यवस्था नहीं है। ताला लग रहा है। गंदगी हो रही है, तो उनमें पानी की व्यवस्था चाहे एम एल ए हैड से हो, चाहे एम पी हैड से हो, हर विद्यालय में सब-मर्सिबल मोटर लगकर पानी होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण कीजिये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): शिक्षा हो गयी। अब स्थानान्तरण नीति...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब विराजिये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): फसल खराबा पर मुझे मौका नहीं मिला। वह दो मिनट दे दो, मेरी बची हुई है। आपने सबको टाइम दिया था।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): एक और रह गया साहब। प्रतिबन्धित जिलों में, जिस तरह से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने डाक्टरों के लिये, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जो नौकरी करते हैं, उनको 25 हजार रुपये विशेष भत्ता दिया जा रहा है, तो अगर उनमें रखना ही है तो उनको कुछ भत्ता दिया जाए विशेष रूप से और एक समय सीमा तय की जाए पांच साल, सात साल, उसके बाद उनको गृह जिला दिया जाए। महिलाओं के लिये विशेष छूट दी जाये।

श्री अध्यक्ष: यह सब पाइंट्स आ गये आपके। सब पाइंट्स आ गये, अब विराजिये। श्री सुखरामजी विश्नोई। (व्यवधान) नहीं, अब विराजिये। अब फिर नोट नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूं। नहीं, अब बैठ जाइये। आप कृपा करके स्थान ग्रहण कीजिये। कृपा करके।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): पर्यटन पर एक बात तो कह दूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब नहीं।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): तिजारा में एक बहुत ही ऐतिहासिक किला है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब आप बैठिये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): और भर्तृहरिजी का है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बस आ गया न आपका। (व्यवधान)

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय मुख्य मंत्रीजी भी उसमें दो बार जा चुकी हैं। उसका भी जीर्णोद्धार करके विकास किया जाये।

श्री अध्यक्ष: आप नोट करा दीजिये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम जी विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, शिक्षा, कला, संस्कृति और पर्यटन के विषय पर मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा में गुणवत्ता लायेंगे, शिक्षा में सुधार करेंगे, परन्तु सुधार के नाम पर 17 हजार स्कूलें बंद कर दी गयीं और कई स्कूलें एक ही छत के नीचे, पड़ौस में प्राइमरी स्कूल चल रही थी, पास में सैकण्डरी स्कूल चल रही थी उसमें मर्ज कर दिया गया। सैकण्डरी में कमरे पर्याप्त नहीं थे, प्राइमरी के

(श्री सुखराम विश्नोई)

लड़के बाहर पढ़ रहे हैं और जो प्राइमरी के कमरे हैं, फालतू पड़े हैं। इसके साथ ही यह सिस्टम जो लागू किया गया, जैसे ही जिस गांव में आठवीं से दसवीं बना दी गयी, स्कूल क्रमोन्नत कर दी गयी। क्रमोन्नत होने के बाद में जो पांचवीं तक के छात्र-छात्राएं थीं, उनकी अलग से स्कूल खोलने की व्यवस्था आज दिन तक चली आ रही है। वह व्यवस्था बड़ी सोच-समझकर रखी गयी थी कि पहली से पांचवीं तक के बच्चे, जिनको पहले पढ़ाना पड़ता है। मैं माननीय अध्यक्षजी, आपसे कहूं कि अगर सबसे कठिन चीज है, तो पहली से पांचवीं तक के बच्चों को पढ़ाना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस शिक्षक को, वह सब पूरी की पूरी पहली से लगाकर दसवीं तक एक छत के नीचे ला दी। मेरा तो आपके मार्फत सरकार से यह निवेदन है, आरोप भी है कि केवल यह जो योजना लागू की गयी कि एक ही छत के नीचे, गांव के बच्चों को पीछे रखने की एक साजिश है कि छोटे बच्चे हो-हल्ला करें और बड़े बच्चे नहीं पढ़ें। उस व्यवस्था को क्यों चेंज किया गया? जब बच्चे पास के स्कूल में पढ़ रहे थे, पढ़ने की पर्याप्त व्यवस्था थी।

सवा साल से जो थर्ड ग्रेड भर्ती का रिजल्ट आउट किया गया, कुछ शिक्षक लगे। परन्तु जो शिक्षक लगे माननीय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन शिक्षकों को लगाने का माननीय अध्यक्षजी, कोई मापदण्ड नहीं है। अब दो दिन हम फील्ड में थे और उन टीचर्स की पोस्टिंग हुई, जहां सत्ता पक्ष के प्रधान थे, सत्ता पक्ष के विधायक थे, केवल मात्र मनमर्जी से जिस मास्टर ने चाहा, न तो छात्र-अनुपात का ध्यान रखा गया, न मास्टरों की संख्या का ध्यान रखा। जहां जैसी सिफारिश थी, उस टीचर को वहां लगा दिया। हम रोते रहे कि एक टीचर है, अपर प्राइमरी स्कूल है वहां चार टीचर और लगाओ। मेरे चितराणा पंचायत समिति में करीब सवा सौ टीचर आये, परन्तु जहां लोगों की, गांव वालों की मांग थी, वहां टीचर नहीं लगे। कम से कम अब आप जो टीचर लगाने जा रहे हो, एक मापदण्ड होना चाहिये, एक तरीका आपके सामने होना चाहिये, ताकि उस तरीके का मापदण्ड का वह प्रधान, वह बीडीओ उसकी पालना करे तभी जाकर जो अनुपात छात्रों का-टीचर्स का दे रखा है, उस अनुपात में टीचर लगेंगे वरना कोई फार्मूला तय नहीं है, कोई मापदण्ड नहीं है। जो टीचर आपने थर्ड ग्रेड के लगाये हैं, बिल्कुल ही आधे से ज्यादा टीचर, जहां जरूरत नहीं थी, वहां लगाये गये।

(श्री सुखराम विश्नोई)

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि प्रत्येक उपखण्ड पर एक कालेज खोलने की घोषणा पिछले बजट में की गयी। मैंने पहले भी आपके मार्फत मुद्दा उठाया था, सांचौर आप पधारे हुए हैं, मेरा सबसे बैकवर्ड तहसील है, जिला भी बैकवर्ड है। आप अगर एजूकेशन का आंकड़ा देखें तो जालौर, सिरोही ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसान तो वहां के बहुत धनवान हैं। किसान तो धनवान हैं, पैदावार अच्छी करते हैं। मैं जाकर आया हूं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): पैदावार तो मेहनती है। जालौर और सिरोही, दोनों जिलों में लड़कियों का जो शिक्षा का अनुपात है, वह 38 प्रतिशत है। 50-60 प्रतिशत पुरुषों का है, 38 प्रतिशत महिलाओं का है। सबसे बैकवर्ड जिले, आप आंकड़ा उठाकर देखोगे तो दो जिले ही सिरोही और जालौर, वहां दोनों जगहों से आपने चुनाव लड़ा है, दोनों जिले ही शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से बैकवर्ड हैं, तो माननीय अध्यक्षजी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार ने कालेज खोला। प्रिंसिपल को लगा दिया वहां पर, स्टाफ लगा दिया, लड़कों को भी एडमिशन दे दिया और जैसे ही सरकार बदली तो वह मेरा कालेज बंद हो गया। माननीय अध्यक्षजी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जब इस बजट में प्रावधान दिया है कि प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर एक कालेज खोला जाएगा तो क्यों नहीं उस सांचौर के कालेज को वापस रिइन्स्टेट किया जाए ताकि बच्चे वहां का फायदा उठा सकें।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत एक और निवेदन है कि स्कूलों में जो पोषाहार का कार्यक्रम चलता है, मैं व्यक्तिगत रूप से इस पोषाहार के कार्यक्रम के खिलाफ हूं। अगर मेरी व्यक्तिगत राय जानी जाये तो गांव के बच्चों को केवल-केवल मात्र एस.सी., एस.टी. और ओबीसी के लड़के जो गांव में रहते हैं, उनको पढ़ाई से वंचित रखने के लिये, पीछे रखने के लिये एक धोखा, एक चाल है, क्योंकि दो कमरों में बच्चे पढ़ रहे हैं और सामने वह रसोई बन रही है। बच्चे जब स्कूल आते हैं और वह जो पोषाहार कार्यकर्ता है, वह सामने रोटी बनाने शुरू करती है, सब्जी बनानी शुरू करती है तो पूरे लड़कों का ध्यान उस रसोई की तरफ रहता है। कुल मिलाकर जो पढ़ाई होनी चाहिये थी, इस पोषाहार की वजह से नहीं हो रही है और इस पोषाहार में माननीय अध्यक्षजी,

(श्री सुखराम विश्नोई)

आपसे निवेदन करना चाहूंगा गेहूं तो बांटते हैं पंजाब का कंट्रोल का गेहूं वहां एक बीघे में दस कट्टा यूरिया डालते हैं और प्रत्येक तीसरे घर में पंजाब में कैंसर है। अपने जो बीकानेर का हास्पिटल है कैंसर का, एक रेलगाड़ी आती है पंजाब-हरियाणा-बीकानेर से, उस रेलगाड़ी का नाम ही कैंसर रेलगाड़ी है। वह गेहूं उन बच्चों को देते हैं। पौष्टिक आहार की बात करते हैं। पंजाब का जो यूरियायुक्त गेहूं है, उस गेहूं को खाने के लिये देते हैं।

सब्जी में आपका जो यह कार्यक्रम बना हुआ है, सोमवार को क्या देंगे, मंगलवार को क्या देंगे, बुधवार को क्या देंगे, छह दिन का जो कार्यक्रम बना हुआ है पोषाहार का, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि उस कार्यक्रम की कोई पालना नहीं करते हैं। केवल मात्र आलू टमाटर सस्ते मिलते हैं, वहां पैदावार होती है। आलू टमाटर में यूरिया डालते हैं। आज से दो साल पहले पंजाब और हमारे पड़ौस गुजरात का आलू अमेरिका गया था, पूरा का पूरा 50 परसेंट आलू में यूरिया। लेबोरेट्री जांच की, इस पौष्टिक आहार के नाम से गांव के बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर पोषाहार देना है, जैविक खेती होती है उस जैविक खेती के आधार पर जैविक गेहूं, जैविक ही चावल, जैविक बाजरा और जिस सब्जी के अन्दर यूरिया नहीं हो, जैसे आलू, टमाटर है, जिसमें यूरिया नहीं हो, जिसमें पेस्टीसाइड नहीं हो ऐसा पौष्टिक खाना बच्चों को दिया जाए तब तो गांव के बच्चे पढ़ेंगे, गांव के बच्चे सुधरेंगे। जो कैन्टीन होती है, रसोई वो रसोई नहीं होती है। कई स्कूलों में रसोई नहीं है, उन कमरों में ही बनती है। अलग कैन्टीन हो, कम से कम एक-दो बीघा दूर हो ताकि बच्चे न तो उस वातावरण में रसोई को देखें न बच्चों का ध्यान डाइवर्ट हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि खेल-कूद के मामले में आप यह आंकड़े उठा कर देख लो। समय कम है, हर आंकड़े में जो स्टेट लेवल के प्राइमरी स्कूलों के टूर्नामेंट हुए चाहे अपर प्राइमरी स्कूल के टूर्नामेंट हुए हैं, चाहे तीनों पदक जो हैं, राजस्थान का मामला है कहीं एक पदक जीता है, कहीं दो जीते हैं कहीं जीरो है। यह इसलिए जीरो है, माननीय अध्यक्षजी, जब हम पढ़ते थे, आप जब पढ़ते थे तो बाकायदा चार बजे के बाद में एक घंटे का खेल के लिए समय होता था, चाहे कबड्डी खेलो, चाहे खोखो खेलो, चाहे वालीबाल खेलो, चाहे रिंग खेलो। एक घंटे का बाकायदा कम्पलसरी कार्यक्रम होता था, मास्टर को वहां स्कूल में रहना पड़ता था और जैसे ही पढ़ाई

(श्री सुखराम विश्नोई)

पूरी हुई खेल मैदान में जाकर के बाकायदा एक घंटे बच्चों को खिलाते थे। आज की तारीख में स्कूलें खोल दीं, खेल मैदान है ही नहीं। खेल मैदान नहीं हैं और जहां खेल मैदान हैं वहां शिक्षक जैसे ही चार बजे, मोटर साइकिल चालू की और रवाना हो जाते हैं, बच्चों के खेल की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। जिस तरह से छठे वेतन आयोग में टीचर की तनख्वाह बहुत बढ़ी है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि जैसे ही छुट्टी हो एक घंटे का कार्यक्रम हो, बच्चों के खेलने के लिए मैदान होना चाहिए तभी जाकर बच्चे स्टेट और ऑउट आफ स्टेट पदक प्राप्त कर सकेंगे।

मेरे वहां एक परीक्षा केन्द्र का मामला था, माननीय शिक्षा मंत्री ने बड़ी तत्परता दिखाई और वो केन्द्र तो खोल दिया परन्तु जहां जिस जाति का बाहुल्य होता है, लोग थोड़ी-बहुत उनकी अवहेलना करते हैं। मेरे यहां जब यह परीक्षा चालू की गयी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक जाति विशेष की जहां आबादी थी उस जगह वो कैमरे लगाये गये और दूसरी जगह कैमरे लगाये नहीं। डावल गांव है, मालवाड़ा गांव है, एक जाति विशेष की आबादी ज्यादा थी, 90 परसेंट एक समाज के लड़के थे वहां कैमरे लगे, केवल केवल-मात्र सांचौर में छह जगह कैमरे लगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं कैमरे लगाये नहीं। इतना पक्षपात हो रहा है।

दूसरी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परीक्षा केन्द्र की बात करूं, परीक्षा केन्द्र मनमर्जी से ही बदले गये। एक जाति विशेष के केन्द्र कहीं चल रहे थे तो उन केन्द्रों को हटा करके एक गर्ल्स स्कूल में चेंज किया गया, कोई करने का तात्पर्य नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं मंत्रीजी से निवेदन किया कि उस केन्द्र को क्यों चेंज किया? केन्द्र चेंज करने का औचित्य क्या था? उस अधिकारी के खिलाफ कम से कम कार्यवाही तो करनी चाहिए। आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह का जो पक्षपातपूर्ण वातावरण है वो पक्षपातपूर्ण वातावरण नहीं होना चाहिए ताकि लोग पढ़ सकें।

माननीय अध्यक्षजी, मैं कट-मोशन पर पहली बार बोल रहा हूं, आप घंटी मत दबाना, मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां, एक मिनट।

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय अध्यक्षजी, मेरा आपसे निवेदन है कि मुफ्त किताबें वितरण का जो मामला है इसमें बड़ा घोटाला हो रहा है। मुफ्त किताबें, पाठ्य पुस्तकें हैं उन पाठ्य पुस्तकों का आंकड़ा उठा करके देखोगे कि इस साल किताबें कम दी गयीं परन्तु खर्चा ज्यादा आया। 2014-15 में कम दी गयीं, खर्चा ज्यादा आया है और पहले किताबें ज्यादा दीं और खर्चा कम आया। उसके बाद में नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें चाहे नौंवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं की हों, नौंवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं की 2012-13 में 17 के आसपास थी, एक करोड़ 23 हजार कुछ और यह 15, मतलब दो लाख किताबें कम बांटी गयीं। कम बांटने का क्या आधार था? कोई औचित्य नहीं है। किताबों में जो घोटाला होता है, कहां से पेपर खरीदते हैं, प्रिंट पर कितना खर्चा आता है, उस पर आंकड़ा और मूल्य लिखा हुआ नहीं होता है। लाखों, करोड़ों रुपये की किताबें छपती हैं, माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो किताबें, पाठ्य पुस्तकें नि:शुल्क बांटी जा रही हैं इन पुस्तकों के छपने में जहां खरीददारी होती है उसमें एक कमेटी बनायी जाए। सत्ता पक्ष, विपक्ष सभी जो पार्टियां हैं बाकायदा उनके विधायकों को लिया जाए और उसके बाद किताबों की खरीद की जाए वर्ना करोड़ों रुपये की, अरबों रुपये की पुस्तकें खरीदी जाती हैं और होता कुछ नहीं है। इसलिए पारदर्शिता की जो बात करते हैं, कम से कम जो नि:शुल्क पुस्तकें हैं उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए। संस्था का पैसा है, ज्यादा किताब बढ़ सके ताकि फायदा मिल सके।

सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र सरकार ने 65 परसेंट के बजट की कटौती, बंद करने का कह दिया, हम आपको जो देते हैं सर्व शिक्षा में आज के बाद कुछ नहीं देंगे तो उच्च शिक्षा के और प्राइमरी शिक्षा के दोनों मंत्री विराजमान हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सर्व शिक्षा के तहत बहुत सारे छात्रावास चल रहे हैं, मेवात में चल रहे हैं, हमारे यहां बैकवर्ड हैं, पश्चिमी राजस्थान में भी चल रहे हैं, सब जगह यह जो बालिका छात्रावास चल रहे हैं उन छात्रावासों की क्या स्थिति होगी, यह बजट में आना चाहिए था। जब भारत सरकार ने इसकी 65 परसेंट राशि बंद कर दी तो कम से कम इस बजट में यह हवाला आना चाहिए कि हम न तो उस छात्रावास को बंद करेंगे, न हम सुविधाएं कम करेंगे और जहां तक हो सकेगा उनको बनाने का प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्षजी, घंटी मत बजाना, मैं अपने आप बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट और। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): एक मिनट। मुद्दे की बात है।

एस.सी., एस.टी. के विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति बांटी गयी वह छात्रवृत्ति पहले के अनुपात में कम बांटी गयी है, कम दी गयी है। जैसे पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति है, उसकी भी संख्या कम कर दी गयी। हर क्षेत्र में छात्रवृत्ति न तो टाइम पर मिलती है और जो प्राइवेट कालेज के लोग हैं, प्राइवेट कालेज के जो प्रबंधक हैं वो टाइम पर छात्रवृत्ति नहीं देते हैं तो कम से कम इस बात पर स्पष्ट नीति तय होनी चाहिए और जब लड़का एडमीशन लेता है उसी वक्त छात्रवृत्ति उसके खाते में जानी चाहिए वरना उस छात्र का वहां के प्रबंधक मिसयूज करते हैं, कटौती करते हैं।

अध्यक्षजी, मुझे बोलने का मौका दिया, घंटी नहीं बजायी, आपको धन्यवाद है। ऐसा सहृदय आप रखो ताकि आपको भी आनन्द आये, हमें भी आनन्द आये इस उम्र में। आप 82 के हो गये और 85-86 पहुंच जायेंगे, इसके बाद में बी.जे.पी. ने बैन लगा रखी है बुड्ढों को कोई स्थान नहीं इसलिए आप अब हमारी रखो। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): दिल तो जवान है, साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली। दस मिनट का ध्यान रखें आप।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 और मांग संख्या-47 पर बोलने के लिए आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक नारा दिया है 'सशक्त भारत शिक्षित भारत', शिक्षा के लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस बार हमें बहुत अच्छा बजट दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मन से कर रहे हो?

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): बिलकुल। ऐसा है सांचौर की बात मैंने सुन ली है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जोधपुर के झालामंड एरिया में तीन लाख की पापूलेशन है, वहां कोई महाविद्यालय नहीं है, आपने नीतिगत तय किया है कि पंचायत समिति क्षेत्र में किया जाएगा तो झालामंड के एक किलोमीटर दूर पर दिगाड़ी एक पंचायत

(श्री कैलाश भंसाली)

समिति है, वहां एक महाविद्यालय खोला जाए तो उसमें झालामंड के सब लोग भी फायदा उठा सकेंगे।

दूसरी बात, सुबह जयनारायण विश्वविद्यालय के बारे में काफी चीजें आपके ध्यान में आ गयी हैं, मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि उसका स्पेशल आडिट करवाया जाए और जो अधिकारी दोषी हैं उनको दंडित किया जाए तथा जो भर्ती में घोटाला हुआ है उसमें जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आये ...

श्री अध्यक्ष: यह आप कह चुके हैं, दूसरा पाइंट कहिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मैं उसी को एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। उसको समाप्त कर रहा हूं।

उनको स्थायी नहीं किया जाए।

श्री अध्यक्ष: अच्छा।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): इसी तरह से विद्यार्थी मित्र रोज हमारे घरों के चक्कर लगाते हैं। आपने सदन में पहले आश्वासन भी दिया था कि हम सहानुभूतिपूर्वक इनका कोई समाधान करेंगे तो इस बारे में भी मैं निवेदन करता हूं।

बालिका विद्यालयों की हालत खराब है। जो टीचर्स आपने लगाये थे वह समानीकरण में बाहर चले गये हैं। ज्यादातर निजी महाविद्यालयों में टीचर्स थे। जब तक निजी शिक्षण संस्थाओं को आप कुछ अनुदान नहीं देंगे, तब तक वह अच्छे टीचर्स नहीं रख पा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आदर्श विद्यालय, माडल स्कूल के नाम से आप जो ओपन कर रहे हैं, उसमें सरदारपुरा, जोधपुर का सबसे प्राचीन एक विद्यालय है, जो सीनियर सैकण्डरी है। उसका बहुत बड़ा भवन है। उसमें बालिकाओं का महाविद्यालय प्रारम्भ किया जाए।

संस्कृत विश्वविद्यालय जोधपुर में है। परंतु जो प्राचीन संस्कृत विद्यालय, माता का थान, बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर है और उसके पास में घनश्यामजी का मंदिर है, जैसा यहां गोविन्द देव जी का मंदिर है वैसे ही घनश्यामजी का मंदिर जोधपुर में प्रसिद्ध है। उसको महाविद्यालय का दर्जा दिया जाए, यह मेरा निवेदन है।

(श्री कैलाश भंसाली)

पुरानी बात कह रहा हूं, एक विद्यालय के वार्षिकोत्सव में जनरल करिअप्पा आए थे, उन्होंने पूछा कि स्कूल के पास में खेल का मैदान कहां है। हमने कहा कि इसके पास में तो नहीं है, बस्ती में आया हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है जहां भी सरकार की जमीन पर कोई अतिक्रमण है उसको हटाकर खेल का मैदान अवश्य बनाया जाए। जोधपुर के आधे से अधिक स्कूलों में खेल मैदान नहीं है, उसकी व्यवस्था की जाए।

अल्पसंख्यक विद्यालयों को जो अनुदान दिया जाता है उसमें सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों को एक ही दर्जे में गिना जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि आपने जयपुर में, उदयपुर में आईआईएम खोल दिया है, जोधपुर इसका पूरा हकदार है। जोधपुर विश्वविद्यालय की जो एमबीए की डिग्री है, अब वह फर्जी डिग्री के अन्दर आ गई है। जोधपुर में एमबीए के लिए सरकारी तौर पर महाविद्यालय शुरू किया जाए।

श्री अध्यक्ष: पाइंट आ गए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मैं कर रहा हूं। आपने 10 मिनट कहा है, मैं 12 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, 10 मिनट ही लीजिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): अच्छा ठीक है। आपकी आज्ञा का पालन होगा।

श्री अध्यक्ष: आप तो चार्टेड अकाउंटेंट हैं, शोर्ट करना जानते हैं।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): विकलांगों को आप पारितोषिक के लिए अनुदान देते हैं। अगर वह किसी स्पोर्टस में आगे आते हैं। अनुश्री मोदी का एक उदाहरण है, जिसके 8 लाख रुपए के पारितोषिक पैडिंग पड़े हैं। मैंने पिछली सरकार से निवेदन करके 75 हजार रुपए उनको दिलवाये थे। आपसे निवेदन है कि अनुश्री मोदी का बकाया करीब 7 लाख 25 हजार रुपए हैं। वह दिलाने का कष्ट करें।

माननीय प्रारम्भिक शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि जितनी भी स्कूलें अभी आपने प्रारम्भ की हैं, उसमें सब्जैक्ट टीचर्स नहीं हैं। सब्जैक्ट टीचर्स नहीं होने से बच्चों को बहुत ही तकलीफ हो रही है। विशेषकर मैथमेटिक्स और इंग्लिश के टीचर्स नहीं हैं।

(श्री कैलाश भंसाली)

इसी तरह से हमारे यहां जो डीईओ लगे हुए हैं वह कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है कि हम जाकर के जांच कर सकें, निरीक्षण कर सकें। डीईओ की 4 पोस्ट खाली पड़ी हैं। कृपया इनको भराने का प्रयास करें।

पंचायत राज में शिक्षित महिलाओं के लिए जो प्रोत्साहन भारत में सबसे पहले दिया गया उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद।

हमारे यहां 8 स्कूलें जर्जर अवस्था में हैं। बच्चे खुले मैदान में धूप में पढ़ते हैं। रातानाड़ा एक ऐसी ही जगह है। जहां पर 1400 बच्चे पढ़ते हैं। उसमें सिर्फ 4 कक्षाएं हैं और 4 मैंने अभी एमएलए लैड से बनाई हैं। अभी वर्तमान में 8 कक्षाएं हैं। वहां पर 16 क्लासें हैं। आपसे निवेदन है कि एक ब्लाक अवश्य वहां पर बनाया जाए। जिसमें 8 कमरे हो जाएं।

कम्प्यूटर शिक्षा पर आपका जोर है लेकिन काफी स्कूलों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। उसको वापस लगाया जाए। क्योंकि इतना बिल बना दिया गया है, वह स्कूल के बजट में ही नहीं आता है। वह पेमेंट कर ही नहीं सकते।

अब मैं पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जोधपुर का रणछोड़जी का मंदिर स्टेशन के बिलकुल सामने स्थित है। वह इतनी ऊंचाई पर है कि आदमी पैदल चढ़ नहीं सकता है। एक वहां लिफ्ट लगाई जाए। वह गुजरात से आया हुआ मंदिर है। वहां भगवान कृष्ण की मूर्ति है। बहुत ही ऐतिहासिक मूर्ति है। हैरिटेज लुक है उसका। इसी तरह से घनश्यामजी का मंदिर, कुंजबिहारीजी का मंदिर यह भी बहुत ही पुराने मंदिर हैं। जर्जर हालत में हैं। घनश्याम जी का मंदिर सबसे प्रमुख मंदिर है। मैं जहां रहता था, उसके पास में ही हैं। आपने देखा हुआ है। वहां जो गया है उसकी मन्नत पूरी हुई है। आपको भी ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इसी तरह से जोधपुर के पास ओसियां में जो जैन तीर्थ और सच्चीय माता का मंदिर है वहां पर एक सरकारी स्तर पर धर्मशाला खोली जाए। उसकी बहुत आवश्यकता है। प्राइवेट धर्मशालाएं बहुत हैं लेकिन वह एक-दूसरे के हिसाब से देते हैं। दूसरे को नहीं देते हैं।

इसी तरह से नाकोड़ा तीर्थ में पानी की बहुत कम सप्लाई होती है। 3 इंच की लाइन है, इसको 4 इंच की लाइन से, सीधे पचपदरा से डायरेक्ट लाइन और दे दी जाए तो वहां अच्छा पानी मिलेगा। नहीं तो वहां के कुएं का पानी बहुत खारा है। वहां आर.ओ. लगाने के बाद भी पीने योग्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपसी बातचीत नहीं, आपसी बातचीत नहीं। सुनिये आप।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): जोधपुर में रावण की शादी हुई थी मंदोदरी से। मंडोर के इलाके में उनका विवाह हुआ था। वह बहुत ही रमणीक स्थान है। अभी भी वहां हवन की चंवरी अभी मंढी हुई है। लोग दर्शन करने जाते हैं। उसका भी विकास पर्यटन मंत्रीजी करायें। मंडोर बहुत ही सुरम्य स्थान है। उसमें अच्छा बग़ीचा और वहां जितने भी मंदिर हैं, महाराजाओं के देवल हैं, 36 करोड़ देवताओं की जो मंदिर है, उसको वापस अच्छा रंग-रोगन करायें तो अच्छा रहेगा।

जोधपुर का हैरिटेज लुक खतम होता जा रहा है। उस हैरिटेज लुक को वापस लाया जाए। हमारे माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने बहुत वायदे किए, परन्तु काम कुछ हुआ नहीं था। मेरा निवेदन है पर्यटन मंत्रीजी से कि इसमें विशेष रुचि लेकर जोधपुर के हैरिटेज की रक्षा करें। यह मारवाड़ का धन है। मारवाड़ के 9 किलों का एक सरताज है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं निवेदन के साथ आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद। अभी शिक्षा की जो स्थिति है, पूरे देश में मोदी जी ने जिस तरह से शिक्षा की बात को आगे बढ़ाया है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी बजट के द्वारा शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया है।

श्री अध्यक्ष: बोलिये आप।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): श्रवणजी को बोल लेने दो पहले।

श्री अध्यक्ष: कौन?

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): श्रवण जी बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्रवणजी आप बोल रहे हैं क्या? विराजें, विराजें। आप बोलिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): लेकिन कल-परसों में सुनने में आया कि कैबीनेट की उप समिति ने प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों को बंद करने की जो सिफारिश की है, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। जहां देश के प्रधानमंत्री शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और बजट में मुख्य मंत्री जी ने इतना बढ़ावा दिया है।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

प्रधान मंत्रीजी ने तो खास तौर से पत्रकारिता विश्वविद्यालय हर स्टेट में खोलने की बात कही है और अपने यहां भी स्किल डवलपमेंट को बहुत बढ़ावा देने की बात चल रही है। पूरे विश्व में इस समय मास कम्यूनिकेशन की सम्भावनाओं से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता। मास कम्यूनिकेशन एवं पत्रकारिता में हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो देश का तीसरा व प्रदेश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय है उसको जब पिछली सरकार ने खोला था उस समय सदन में सभी सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया था, आज उसको बन्द करने की जो बात की जा रही है, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ओर प्रधान मंत्रीजी की सोच के बिलकुल खिलाफ की सी बात दिखती है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों के वहां एडमीशन भी हुए हैं और सैकड़ों बच्चे वहां पढ़ भी रहे हैं उसको हर हाल में चालू रखा जाए जिससे हमारा स्किल डवलपमेंट और पत्रकारिता को बढ़ावा देने की, दोनों बातें पूरी होंगी। पिछले एक वर्ष में जो एडमीशन लिया है बच्चों ने और चालीस-चालीस हजार के करीब फीस लगी है उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा और आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी पत्रकारिता में कोई स्कोप नहीं मिलेगा, पढने का कोई स्थान नहीं मिलेगा इसलिए उसको निश्चित रूप से चालू रखा जाए।

इसके अलावा हमारा शेखावाटी विश्वविद्यालय है सीकर का, उस शेखावाटी विश्वविद्यालय को खुले आज करीब सात साल हो गए लेकिन हालात यह है कि अभी उसकी चारदीवारी भी पूरी नहीं बनी है, न ही वहां पर कोई कर्मचारी अधिकारी है, सिर्फ वीसी और दो-चार कर्मचारी और अधिकारी हैं। उसको कार्य क्षेत्र भी दे दिया गया है लेकिन काम के नाम पर आज भी वहां कुछ नहीं हो पा रहा है। स्थिति यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जो अभी वहां सार सम्भाल उस क्षेत्र की कर रहा है, अभी माननीय मंत्रीजी ने प्रयास किया था लेकिन मेरे फतेहपुर क्षेत्र में चालीस किलोमीटर तक 6000 छात्रों के लिए परीक्षा का केन्द्र भी नहीं मिल पाया। राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रशासन है उसकी इतनी बुरी हालत है कि माननीय मंत्रीजी के कहने के बावजूद भी वह परीक्षा केन्द्र की व्यवस्था नहीं कर सके और आज लड़कियों को, लड़कों को, सबको सुबह सात बजे परीक्षा देने लगभग तीस से चालीस किलोमीटर तक जाना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सड़कें ढंग की नहीं हैं। अभी भी

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

विश्वविद्यालय इस दिशा में कुछ करे तो बहुत सी परीक्षाएं बाकी हैं, बच्चों को बड़ा फायदा मिलेगा।

फतेहपुर क्षेत्र में लगभग 6000 छात्र-छात्राएं हैं, उनके लिए कोई सरकारी कालेज नहीं है। अभी जब मैंने पत्र लिखा तो सचिव महोदय का जवाब आया कि वहां पांच-छह सरकारी कालेज हैं। मैं मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि सरकारी कालेजें जिनकी उन्होंने लिस्ट बनाकर दी है वह दरअसल प्राइवेट कालेज हैं और आईटीआई की कालेज है या कोई एक-दो सब्जैक्ट की कालेज है। एक भी कालेज ऐसी नहीं है जहां तीनों सब्जैक्ट हों या छात्रों को सही फीस पर पढ़ाई हो सके। यह जो क्राइटेरिया बना रखा है कि जहां प्राइवेट कालेज हों वहां सरकारी कालेज खोलेंगे तो आराम से खोलेंगे और जहां कुछ भी नहीं है वहां पहले खोलें। यह सोच अपने को बदलनी पड़ेगी क्योंकि प्राइवेट दुकानें, प्राइवेट कालेज वहां खुलती हैं जहां बच्चे हों, तो जहां बच्चे हैं वहां पहले सरकारी कालेज खोलने की आवश्यकता है।

सरकारी स्कूलें अभी जो खोली हैं, बड़ी अच्छी संख्या में खोली हैं, बढ़िया खोली हैं लेकिन कई जगह गलत भी खुल गई हैं। जहां आवश्यकता नहीं थी वहां खुल गई हैं और पड़ौस के गांव में जहां बच्चे हैं, जहां आवश्यकता थी वहां नहीं खुल पाई तो उनको रिव्यू किया जाए और जन-प्रतिनिधि जो हैं उनको साथ में लेकर उनका फीड बैक लेकर जहां जरूरत है वहां खोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

स्टाफ की जो स्थिति है उसमें खूब सुधार हुआ है लेकिन आज भी कई स्कूलें ऐसी हैं जिनमें दस-दस, ग्यारह-ग्यारह साल से हैड मास्टर नहीं है, चपरासी तो कभी लगे ही नहीं, एलडीसी, यूडीसी का नामोनिशान नहीं है, खेल के मैदानों की अभी पूर्व वक्ताओं ने जो बात की वह बिलकुल ठीक है। स्कूलों का ढांचा भी सुधारने की आवश्यकता है। खेल के मैदान और अन्य सुविधाएं स्कूलों में देना बड़ा जरूरी हो गया है।

स्किल डवलपमेंट की बात चल रही है उसमें सुझाव देना चाहूंगा कि हमारी जो सरकारी स्कूलें हैं उनमें ग्रीष्मकालीन अवकाश होंगे उसमें अगर स्किल डवलपमेंट की क्लासेज लगाई जाएं तो बच्चों को बड़ा फायदा होगा। दूसरा सुझाव यह है कि जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके बच्चों के लिए अगर लाजिमी कर दिया जाए, उसमें चाहे एमएलएज को भी शामिल

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

कर दें कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें तो आधी देख-रेख अपने आप ही हो जाएगी।

कला एवं संस्कृति के बारे में मैं मेरे क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारा फतेहपुर क्षेत्र लोक कला, गींदड़, ढप, चंग, नृत्य आदि के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। लेकिन अभी सरकारी सुविधा न होने से, कोई सरकारी इन्सेन्टिव नहीं होने से शेखावाटी की लोक कला धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है। अब गिने-चुने लोग ही इन कलाओं को जानते हैं। अभी भी अपने पास मौका है, अपने पास समय है कि अगर उस कला को बढ़ावा दिया जाए तो देशी-विदेशी पर्यटकों को भी फायदा मिलेगा, अपने क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा और अपनी कला भी जिन्दा रहेगी। इनको सम्बल देने वाला होना बड़ा आवश्यक है। सरकारी स्तर पर लोक कला संस्कृति को बचाने के लिए कोई न कोई काम अपने को करना चाहिए।

अभी आर्थिक अभाव से जूझ रहे इन कलाकारों को कोई सहारा मिल जाए, आरटीडीसी या पर्यटन विभाग इनके लिए कोई कार्यक्रम जारी रखे तो निश्चित रूप से यह कला अपनी जिन्दा रह पाएगी।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी बजट में भी पर्यटन पर खूब बढ़ोतरी की गई है। हमारे शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां हैं, भित्ती चित्र हैं, जो खूबसूरती उनकी है उनको देखने खूब लोग देशी और विदेशी आते हैं। फतेहपुर, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़ की जो हमारी हवेलियां हैं, वे हवेलियां बड़ी सुन्दर हैं लेकिन वहां तक पहुंचना पर्यटक का बहुत मुश्किल है क्योंकि रास्ते बड़े ऊबड़-खाबड़ हैं, पानी भरा रहता है, कीचड़ भरा रहता है, सड़कें नहीं हैं। लाइट पानी और गाइड की व्यवस्था नहीं है। जबकि उन हवेलियों के संरक्षण की जो बात अभी चल रही है उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर, वहां पहुंच की जो बात है उसको भी ठीक किए जाने की आवश्यकता है। उसको कैसे करेंगे? पर्यटन मंत्रीजी बैठे हैं, उसके लिए कोई बढ़िया प्रोग्राम बनाया जाए जिससे वहां पर्यटक की पहुंच सुगम हो जाए। ओपन आर्ट गैलेरी के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हमारा फतेहपुर, रामगढ़, मण्डावा है, वह निश्चित रूप से देशी-विदेशी पर्यटकों को और बुलाएगा यदि उन हवेलियों तक पर्यटकों के पहुंचने की सुविधा हो जाए।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

पर्यटन को बढ़ावा देने और संस्कृति को बचाने के लिए इन हवेलियों को जो संरक्षित किया जा रहा है उसमें मालिकाना हक को लेकर बहुत सी बातें चल रही हैं और अब तक कोई दिशा-निर्देश भी स्पष्ट जारी नहीं हुए हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में लाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था की जाए।

पिछली बार जब भाजपा सरकार थी तो फतेहपुर और रामगढ़ को हैरिटेज सिटी घोषित किया था, बजट भी दिया था, एक किश्त भी दी थी लेकिन वह काम एक किश्त के बाद रुक गया। हैरिटेज सिटी घोषित होने के साथ ही उन हवेलियों का भी बचाव हो जाएगा, बजट भी लगेगा और निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र को फायदा मिलेगा। कुछ गाइड वहां अगर ट्रेंड कर दिये जाएं तो भी क्षेत्र को फायदा मिलेगा और रोजगार भी बच्चों को मुहैया होगा।

इसी तरह आरटीडीसी की जो स्थिति है, हमारे यहां आरटीडीसी का जो होटल है फतेहपुर में, उसमें सुविधाओं की काफी कमी है। आज भी अभी सुनने में आया था आते वक्त की आरटीडीसी के कर्मचारी तीन-चार महीने से सैलेरी के लिए जूझ रहे हैं और उन्होंने डाइरेक्टर के यहां प्रदर्शन भी कर रखा है तो उनकी व्यवस्था जितनी जल्दी की जाए अच्छा होगा।

पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से शेखावाटी में धार्मिक ट्यूरिज्म का बड़ा स्कोप है। शाकम्भरी, लोहार्गल, रानी सती मन्दिर, झुन्झुनूं, फतेहपुर में दो जांटी बालाजी, अमृतनाथ का आश्रम, लक्ष्मीनाथजी मन्दिर, बुधगिरी मण्डी, सालासर धाम, जीणमाता, रैवासा धाम, खाटूश्यामजी, ये सभी वर्ल्ड फेमस मन्दिर हैं तो इनमें अगर एक धार्मिक सर्किट बनाकर इसका लाभ लिया जाए तो निश्चित रूप से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा लेकिन अपने जो हालात हैं यहां बड़ा कमजोर खर्च करने वाला पर्यटक आता है क्योंकि सुविधाएं उसी हिसाब की हैं। आज जयपुर से उदयपुर के लिए फ्लाइट नहीं है, जयपुर से जोधपुर के लिए फ्लाइट नहीं है, ऐसी स्थिति में खर्चा करने वाला ट्यूरिस्ट आने में हिचकता है तो यह सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की आवश्यकता है, इससे निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 एवं 47 पर्यटन पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम तो

(श्री गोतम कुमार)

माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में बहु प्रतीक्षित महाविद्यालय की जो मांग थी उसको स्वीकृति प्रदान की और हमारे क्षेत्र में बहुत दिनों से जो कालेज की डिमाण्ड चल रही थी उसको स्वीकृत कराया है उसके लिए अपने क्षेत्र के वासियों और गरीब जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में शिक्षकों की बहुत कमी है। मैंने पिछले वर्ष इसी सत्र के दौरान एक क्वेश्चन भी लगाया था।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमारे यहां की रिक्त पदों की सूची आयी उसमें माध्यमिक शिक्षा में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जो अध्यापक हैं उनके लगभग 72 परसेंट पद खाली हैं। माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वो इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। चूंकि अभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी की पदोन्नतियां भी हो रही हैं तो उसमें हमारे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के पद 70 परसेंट खाली हैं इसलिए उनको भरवाने की कृपा करें। हमारे वहां रोज कहीं न कहीं तालाबंदी होती है, ऐसे में अगर वहां पद भर दिए जाएंगे तो आपका बहुत-बहुत आभार होगा।

हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुछ प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्कूल में, जिनकी सूची मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, अगर वो भी क्रमोन्नत हो जाएं तो आपका बड़ा आभार होगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिला भी आता है जहां लोक जुम्बिश के अन्तर्गत कुछ विद्यालय चल रहे थे। प्राथमिक विद्यालय चल रहे थे और प्राथमिक से वो उच्च प्राथमिक हो गए हैं। लोक जुम्बिश योजना बन्द हो गयी है परन्तु उनकी वित्तीय स्वीकृति अभी तक जारी नहीं हुई है जिससे जहां दो का स्टाफ था वहां पर अभी तक दो अध्यापक ही काम कर रहे हैं और तीन अध्यापक थे वहां तीन अध्यापक ही काम कर रहे हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में मैं आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ तहसील के प्राथमिक विद्यालय चौकड़ी, ढीकनिया, बिहारा, केशरपुरा, कनोरा और बावड़ी खेड़ा जो विद्यालय हैं, इनकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने

(श्री गोतम कुमार)

से यहां पर शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। यहां आठवीं का स्कूल है और एक-दो टीचर से काम चल रहा है इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि अगर इन स्कूलों की वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाएगी तो निश्चित रूप से क्षेत्र को राहत मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, रमसा योजना सरकार की चलती है, बहुत अच्छी योजना है। उसमें पिछले साल भी हमारे वहां पर कक्षा कक्षों के लिए माननीय मंत्री महोदयजी ने स्वीकृत कराये थे उसके लिए तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि अगर इस योजना में विद्यालय के कक्षा कक्षों की स्वीकृति मिले तो कोई दिक्कत नहीं है परन्तु चूंकि कक्षा कक्ष अब पर्याप्त मात्रा में हो भी चुके हैं तो अगर रमसा में बाउण्डरी वाल भी जुड़ जाए तो ठीक रहेगा। क्योंकि स्कूलें शहर और कस्बों के बीच में होती हैं और उस पर अतिक्रमी नये-नये अतिक्रमण करते हैं, अगर बाउण्डरी वाल की भी रमसा में इस साल से स्वीकृति मिल जाए तो निश्चित रूप से इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद होगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले 7-8 सालों से विद्यार्थी मित्र काम कर रहे थे, 7-8 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे थे जिनको कोर्ट के आदेश से सरकार ने हटाया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि उनको किसी तरह से समायोजित करके, भले ही विद्यालय सहायक हों, या कैसे भी हों, उनको समायोजित करके सहायता प्रदान करें। उन्होंने अपने जीवन के सात साल इसमें निकाल दिए हैं, उनका भविष्य अंधकार में है इसलिए कहीं न कहीं उनको समायोजित किया जाए। बहुत बड़ी संख्या में, 700 विद्यार्थी मित्र मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं और 700 परिवार इससे प्रभावित होंगे इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कैसे भी करके उनके भविष्य को ध्यान में रखकर उनको समायोजित करने का प्रयास करें। विद्यालय सहायक में या किसी भी तरह से करें क्योंकि वो कहीं पर भी लगने को तैयार हैं। 4 हजार रुपये में वो काम कर रहे थे और इसी पेमेंट पर वो आगे भी काम करने के लिए तैयार हैं।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हमने मानदेय पर प्रेरकों की नियुक्ति की थी जिनको हम 2 हजार रुपये देते थे। लेकिन आज महंगाई के इस दौर में 2 हजार रुपये का मानदेय

(श्री गोतम कुमार)

पर्याप्त नहीं होता है। अगर उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, क्योंकि न्यूनतम वेजेज अगर देखें, वो न्यूनतम वेजेज पर कोर्ट में गए तो आपने उनको पार्ट टाइम कर दिया है तो पार्ट टाइम नहीं करके भले ही उनसे फुल टाइम काम लें लेकिन उनका मानदेय थोड़ा बढ़ाने का कष्ट करावें।

मैं माननीय पर्यटन मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस बार पर्यटन को विशेष रूप से मुख्य मंत्री महोदयाजी ने बढ़ावा दिया है और माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने पर्यटन के लाभ को भी परिभाषित किया। इसके लिए तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक सीता माता वन्य जीव अभयारण्य भी है जिसमें 12 महीने नदियां बहती हैं, हरियाली भी बहुत सारी है। उसमें एक ऐसा जीव है उड़न गिलहरी, जो विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है। पैंथर वगैरह बहुत सारे वन्य जीव प्रचुर मात्रा में वहां पर रहते हैं। राजस्थान में इतना अच्छा जंगल कहीं नहीं है तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि एक बार वहां पधारें, उस सीता माता वन्य जीव अभयारण्य को भी रणथम्भौर और सरिस्का की भांति डवलप करने का प्रयास करें। उस क्षेत्र को वास्तव में देखेंगे तो वहां पर पर्यटक बार-बार आना पसन्द करते हैं। वहां एक मेला भी लगता है, अगले महीने वो मेला भी लगेगा और उस मेले में लाखों की तादाद में लोग आते हैं। ऐसा कोई मेला नहीं होगा जो जंगल में लगता हो और लाखों की तादाद में लोग आते हों। मध्य प्रदेश से, गुजरात से वहां पर सैलानी आते हैं और उस मेले का आनन्द लेते हैं। चूंकि प्रकृति की छाया में होता है, ऐसे गर्मी के मौसम में मई महीने में वह मेला लगता है और उसके बावजूद भी लाखों की तादाद में वहां लोग आते हैं इसलिए उसको भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा तो निश्चित रूप से राजस्थान का एक और नया पर्यटन क्षेत्र डवलप होगा।

ऐसे ही हमारे विधान सभा क्षेत्र में बड़ी सादड़ी नगरपालिका में, हमारी झाला मान की नगरी है, राजा झाला मानसिंह द्वारा एक सूर्य सागर तालाब का निर्माण कराया गया था सैकड़ों वर्ष पूर्व। रखरखाव के अभाव में वो थोड़ा-सा खण्डित हो रहा है, तो मेरा माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है कि आज ही उसके लिए कुछ न कुछ घोषणा कर दें ताकि उसकी पाल पर बने पार्क और सुन्दर-सुन्दर छतरियां जो बनी हुई हैं तो निश्चित रूप से वहां पर पर्यटन क्षेत्र भी डवलप होगा और बहुत सारे पर्यटक भी आएंगे। चूंकि आप राजघराने से हैं और आपके राजघराने की धरोहर है इसलिए इस पर ध्यान देकर इसको

(श्री गोतम कुमार)

संरक्षित करवाने का प्रयास करें। ज्यादा नहीं बोलते हुए, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शैतान सिंह। समय का ध्यान रखें।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा है, मेरा नाम पुकारा था आपने।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं शैतान सिंह का। इसके बाद आपका आएगा। एक इधर से मेवारामजी बोलेंगे तब आपका आएगा। तीन इधर से और एक इधर से।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय अध्यक्षजी, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिसका नाम लेने से पूरे भारत का सीना गर्व से फूल जाता है वह पोकरण है और पोकरण शक्ति स्थल है। मुझे सदन में पहली बार बोलने का मौका मिला है इसलिए थोड़ा समय दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इनके नाम का उच्चारण किया तब शैतान नाम जोर से बोले और सिंह थोड़ा धीरे से बोले इसलिए इसको जरा तरन्नुम में बोलें अध्यक्ष महोदय, वरना लोग अलग-अलग अंदाजा लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: सिंह शैतान। बोलिए दस मिनट पूरे हैं।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय अध्यक्षजी, पहले मैं मेरी मांग रखता हूं। मांग संख्या 24 और 47 पर बोल रहा हूं। शिक्षा के हमारे इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जो राजस्थान को सोपान दिया है, वह आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। हमारे सभी पंचायत मुख्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षा खोल दी गयी है और उसके साथ-साथ आठवीं और दसवीं सरपंच, ब्लाक मैम्बर्स और जिला परिषद सदस्यों में शिक्षा की जो अनिवार्यता की है, इससे शिक्षा में बहुत ज्यादा जागृति आयेगी।

मैं आपको छोटे-से उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि इस वर्ष हर जन-प्रतिनिधि को शौचालय के लिये एक एफेडेविट देना पड़ता था, तो मेरी एक नई पंचायत बनी है सिनावड़ा में, एस.सी. की सीट थी, अध्यक्षजी, मैं आपको निवेदन करता हूं, हकीकत बता रहा हूं कि 30 नये शौचालय इसीलिये बने कि उन तीसों को उम्मीद थी शायद मैं सरपंच बन सकता हूं। इसीलिये यह शिक्षा

(श्री शैतानसिंह)

की अनिवार्यता जरूरी की है। इसीलिये महिला शिक्षा, बालिकाएं ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगी कि 50 प्रतिशत इस राजतंत्र में, इस लोकतंत्र में, इस पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी है, तो बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं।

मेरा प्राथमिक शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि हमारा क्षेत्र, जैसे स्पेशली मेरा क्षेत्र साढ़े 300 किलोमीटर लम्बा और 75 किलोमीटर चौड़ा है। वहां जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, पूरा क्षेत्र ढाणियों में बसा हुआ है। गांवों में बहुत कम लोग रहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग ढाणियों में रहते हैं। इसलिए ढाणियों को ध्यान में रखते हुए हमारे वहां नये विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय खोले जायं। अभी इस नये बजट में ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी है। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय भी किये जायं और उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय भी किये जायं, क्योंकि वहां पढ़ने के लिए लोगों को बहुत दूर-दूर तक जाना पड़ता है, आवागमन के साधन नहीं हैं, आवागमन के बहुत कम साधन हैं। आपको भी ध्यान है, माननीय अध्यक्षजी, आपका भी हमारा एरिया देखा हुआ है, बहुत दूर-दूर तक ढाणियां हैं। इसलिए उन ढाणियों व भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष ध्यान दें।

माध्यमिक विद्यालय हर पंचायत हैडक्वार्टर पर खोलने की घोषणा की उसके साथ-साथ एक बेरियर लगाने की कोशिश की जा रही है कि 120 छात्रों पर व्याख्याता देंगे। मेरा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि हमारे उस एरिया में यदि 120 छात्र मिल जायं तो ये ढाणियां, ये आबादी, हमारे जिले से मात्र दो एमएलए आते हैं बाकी कई जिलों से आठ-आठ एमएलए आते हैं क्योंकि वहां जनसंख्या कम है। हमारा अभावग्रस्त क्षेत्र है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि लगातार दो साल से हम भयंकर अकाल में हैं, फिर भी हम किसी के सामने रोते नहीं हैं क्योंकि हम बहुत मनोबली हैं, मन में बहुत दृढ़ता रखते हैं। फिर भी सरकार यह ध्यान रखे कि ये सीमाएं हमारे क्षेत्र में लागू न की जायं, यह मेरा आपसे विशेष निवेदन रहेगा।

एक मेरा निवेदन है कि जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिलों में जो शिक्षक भर्ती की जाती है तो उन जिलों के लिए विशेष छूट प्रदान की जाय। माननीय भैरोंसिंहजी के समय इन विशेष जिलों के लिए

(श्री शैतानसिंह)

विशेष छूट दी थी। उस वजह से वहां पुराने शिक्षक स्थानीय हैं, आज वह स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारा बैकवर्ड एरिया है। वहां शिक्षा में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है वे सुविधाएं हमारे एरिया में मिल नहीं सकतीं क्योंकि लोगों का जीवन स्तर इतना ऊंचा नहीं है। वहां अकाल पर अकाल पड़ते हैं। हम सब खेती पर जीवन-यापन करने वाले हैं। पशुधन है तो वह अकाल में खतम हो जाता है। इस अकाल की भयंकर विषमता की वजह से विशेष ध्यान दिया जाय। हमारे क्षेत्र में शिक्षकों की भर्ती की जाती है उसमें छूट प्रदान की जाय, यह आपसे निवेदन है।

थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्तियां हैं ये पंचायत राज के माध्यम से न की जायं, आरपीएससी से की जानी चाहिए ताकि जो झमेला होता है वह न हो। मैं निवेदन करता हूं पूर्ववर्ती सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में, अभी सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य सुखरामजी बोल रहे थे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि हमारे पोकरण के पास में नजदीकी चार-पांच पंचायतों में जितने स्वीकृत पद हैं उससे ज्यादा स्कूलें की गयी हैं। राजनैतिक दबाव से ये नियुक्तियां हो जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये भर्तियां आरपीएससी से की जायं। भर्ती सरकार अपने स्तर से शिक्षा-विभाग ही करे ताकि नियुक्तियां सही हों।

मेरा निवेदन है कि हमारे जैसलमेर जिले में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बोर्ड के परीक्षा केन्द्र हैं, उनके लिए जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसमें कुछ शिथिलता दी जाय क्योंकि 100 पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केन्द्र है और 50 पर उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केन्द्र है, पर हमारे एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 15 से 17 किलोमीटर है जहां माध्यमिक विद्यालय है, 20-20 किलोमीटर भी दूर है। वहां इसमें शिथिलता देते हुए केन्द्र खोले जायं ताकि विद्यार्थियों को कम से कम तकलीफ हो। हम शिक्षा किसलिए देते हैं? शिक्षा इसलिए देते हैं कि उनको सुविधाएं मिलें। इन सीमाओं को हमारे जैसलमेर, बाड़मेर जिले में विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष शिथिलता प्रदान करें।

अब मेरा निवेदन कालीचरणजी सराफ से है, ये उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उस टाइम शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने मेरे वहां एससी, एसटी बस्तियों के विद्यालयों का एकीकरण किया था, मेरे निवेदन पर इन्होंने वापस उन स्कूलों को मुक्त

(श्री शैतानसिंह)

किया। मैं इनका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैंने जितना प्रतिवेदन दिया उसमें शत प्रतिशत इन्होंने सही किया। हम उस क्षेत्र से आते हैं, हमारी ढाणियां बहुत-बहुत दूर हैं, हमारे एससी, एसटी परिवार ज्यादा हैं, बहुत गरीब हैं। माननीय मंत्रीजी ने विशेष ध्यान दिया। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि उच्च शिक्षा में मेरे यहां मुख्य मंत्रीजी के आशीर्वाद से पूर्व कार्यकाल में पोकरण में कालेज खोला गया। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वसुन्धराजी ने खोला था। उसमें अभी कला विषय के 7 लैक्चरर हैं जिनमें 4 सीटें खाली हैं। इसलिए वे सीटें भरी जायं। वाणिज्य में 3 पोस्ट हैं जिनमें 2 खाली हैं। एक बाबू की पोस्ट खाली है, एक लैब असिस्टेंट की पोस्ट खाली है। नजदीक में कालेज नहीं है, जैसलमेर 110 है, जोधपुर 180 किलोमीटर है। मेरा निवेदन रहेगा कि वहां कला में तीन सैक्शन जितने स्टूडेंट प्रथम वर्ष में हैं और मात्र एक सैक्शन है। इसलिए दो सैक्शन और बढाये जायं क्योंकि मेरा क्षेत्रफल बहुत लम्बा-चौड़ा है। वहां पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बहुत परेशानी होती है। मेरा निवेदन है कि अपन उपखण्ड क्षेत्र पर कालेज खोलें तो भिनियाना भी नया उपखण्ड क्षेत्र बना है उसमें भी कालेज हो। एक बालिका कालेज के लिए मेरा विशेषकर मंत्रीजी से निवेदन रहेगा।

अब मैं आपसे विशेषकर सीमाओं को लांघकर दो शब्द यहां रखूंगा। इस आसन के पीछे बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि यह सदन जहां हम बैठे हैं यह साढ़े सात करोड़ राजस्थानियों के विश्वास का केन्द्र है। इसमें जो बात कही जाएगी वह सत्य कही जाएगी। नहीं बोलना भी पाप है और असत्य बोलना भी पाप है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि यदि मर्यादाओं का पालन अपन नहीं करेंगे तो लोगों की नजरें अपने ऊपर हैं। शास्त्र कहता है कर्मयोगी राजयोगी होते हैं। राजयोगी राजयोग में जीए तो कोई अनीति नहीं होगी, लेकिन राजभोग में जीएंगे तो वह बहुत अनर्थ होगा। मेरा निवेदन है कि इस पवित्र सदन में कम से कम असत्य नहीं बोलें, सीमाओं का सभी सदस्य ध्यान रखें। आसन और बोलने वाले के बीच में नियम और प्रक्रियाओं में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब आसन पैरों पर खड़ा होता है तो किसी भी माननीय सदस्य को खड़ा नहीं रहना चाहिए, फिर भी सब खड़े रहते हैं। जब अपन ही मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो साढ़े सात करोड़ राजस्थान की आम-अवाम क्या देखेगी, मेरा यह विशेष निवेदन है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: मानसिंह गुर्जर। 10 मिनट। इससे ज्यादा नहीं।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। इसी के साथ में आपने सीमा भी बना दी है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा, शिक्षा का जो हमारा आमूल ढांचा है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार राजस्थान के शिक्षा के बजट को सबसे अधिक पैसे देने का काम किया है, निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी और सरकार की मंशा है कि राजस्थान के उन बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले जिन सरकारी स्कूलों की दशा और स्कूलों के बारे में मान्यता बन चुकी है कि इन सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजने का मतलब है उनका जीवन खराब करना। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान भरतपुर सम्भाग में हमारे जिले में जिस प्रकार से स्कूलों को देखा और उसके बाद में शिक्षा के लिए कदम उठाये हैं वे सराहनीय हैं। जिस प्रकार से हमारे पंचायत स्तर पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल किये हैं उसके लिए भी हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। उसी के साथ-साथ मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि हमारा जो शिक्षा का कैलेण्डर है, उस शिक्षा कैलेण्डर को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीज मिलती है कि किस प्रकार से आपको प्रवेश का उत्सव मनाना है, किस प्रकार से आपको परीक्षण करना है, किस प्रकार से आपको रिपोर्ट भेजनी है, लेकिन यह सारा का सारा काम कागजों में हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए प्रैक्टिकल रूप से हमारा परीक्षण का काम जिस प्रकार से पहले हुआ करता था, आज एक अधिकारी वहां जाता है तो वह मांग करता है कि उसके स्कूल का निरीक्षण करने से पहले गाडी आ जाय। पहले जिस प्रकार से मोटरसाइकिल, बस में बैठकर निरीक्षण करने के लिए सीआई या उसका अधिकारी ईओ वगैरह जाते थे, वे आज अपेक्षा करते हैं कि वे गाड़ी में जायं, सरकारी भत्ते के साथ में जायं। मैं कहता हूं कि उसमें कहीं दोष नहीं है, वह जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से गुणवत्तायुक्त शिक्षा की सरकार की मंशा है उस मंशा पर खरा उतरने का काम करें, ऐसी आपके माध्यम से सदन की मंशा से हम विभाग को अवगत कराना चाहते हैं और यह निवेदन करना चाहते हैं कि आज जिस प्रकार से हमारी प्राथमिक शिक्षा है उस प्राथमिक शिक्षा का ढर्रा जिस प्रकार से बिगड़ा है, आम आदमी का विश्वास जिस प्रकार से प्राइवेट एजुकेशन की तरफ हुआ है। उसमें निश्चित रूप से एक चीज सामने आई है कि हमारी शिक्षा की

(श्री मान सिंह)

गुणवत्ता कमजोर हुई है चाहे वहां पर सरकारी स्कूल में खूब बड़ा फील्ड होगा, लेकिन सबसे ज्यादा गंदगी भी देखने को वहां मिलती है, सबसे ज्यादा अव्यवस्था भी देखने को वहां मिलती है। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल में चाहे उसका छोटा प्रिमाहसिस होगा, लेकिन उस प्रिमाहसिस में जिस प्रकार गुणवत्ता शिक्षा दे रहे हैं, जिस प्रकार वे रिजल्ट ओरियेंटेड शिक्षा दे रहे हैं, निश्चित रूप से हमको सोचने को मजबूर होना चाहिये कि हमारी सरकारी स्कूलों की शिक्षा को सुधारने का काम हो। निश्चित रूप से इस पर भी ध्यान देना चाहिये कि जिस प्रकार का शिक्षा का निजीकरण हो रहा है और जिससे आम आदमी, आम गरीब के पिसने का काम हो रहा है, गरीब का बेटा उस शिक्षा से वंचित हो रहा है। उसके लिए हमको ठोस कदम उठाने होंगे।

आज स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, आज जिस प्रकार से एक-एक शिक्षक 20-20 साल तक एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है तो निश्चित रूप से पारिवारिक समस्याओं से वह जूझता है और जब वह वहां रहता है तो इस प्रकार का ढर्रा हो जाता है कि उस गांव में वह छाछ पीकर, गांव वालों के साथ बैठकर ऐसा हो जाता है कि मास्टरजी के कंधे पर हाथ रखकर बच्चे बात करते हैं। उस मास्टर के हालात ये हो जाते हैं कि वह भूल जाता है कि मैं वह शिक्षक हूं जो इस पीढ़ी का निर्माण करने वाला है। इसलिए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि हमारे स्कूलों का प्रैक्टिकल रूप से शिक्षा विभाग दूर-दराज में जाकर उनका निरीक्षण करके, इस बात की वास्तविकता को जांचने का काम करें कि किन मापदण्डों के आधार पर हम शिक्षकों का, शिक्षा की नीति का, ट्रांसफर की नीति का निर्माण करें क्योंकि यह अब भी बहुत बड़ी खामी है। भीड़ लगी रहती है, सचिवालय में जिस प्रकार से घूमते रहते हैं। आधा समय तो ट्रांसफर में ही चला जाता है। इस प्रकार की नीति का अगर हम निर्माण नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इससे भी हमारी शिक्षा में, हमारे जो बालक हैं, उनके प्रभावित होने का काम होता है।

आज जिस प्रकार से हमारी कालेज शिक्षा है। हायर सैकण्डरी स्कूल के बाद में जो ग्रेजुएशन में बच्चा जाता है, थ्री ईयर डिग्री कोर्स करता है और उसके बाद में जब वह बाहर आता है तो उसको यह पता नहीं रहता कि उसे कहां जाना चाहिये। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, क्यों नहीं हम

(श्री मान सिंह)

आज राजस्थान में इस बात का प्रयोग करें कि हाई स्कूल दो प्रकार के बनायें। एक टैक्निकल हाई स्कूल होना चाहिये, एक नार्मल हाई स्कूल होना चाहिये। चाहे हम सम्भाग स्तर पर टैक्निकल हाई स्कूल खोलें लेकिन उन बच्चों को, जिस स्किल डवलपमेंट की बात आज देश में होने लगी है। माननीय प्रधान मंत्रीजी ने जिस स्किल डवलपमेंट का नारा दिया है, उस स्किल डवलपमेंट को बढ़ाने के लिए अगर हम टैक्निकल हाई स्कूल खोलने का काम करेंगे तो राजस्थान देश में एक माडल साबित होगा कि सम्भाग स्तर पर हम टैक्निकल हाई स्कूल खोलकर उन बच्चों को नई दिशा देने का काम करेंगे, जिनको न आईटीआई करने की आवश्यकता होगी, न पालीटैक्निक का डिप्लोमा करने की आवश्यकता होगी, न गरीब के बच्चे को कोटा के एलन में भर्ती लेने की आवश्यकता होगी। उसका स्किल डवलपमेंट टैक्निकल हाई स्कूल में होगा तो निश्चित रूप से वह रोजगार प्राप्त कर सकेगा और टैक्निकल स्कूल के अन्दर टैक्निकल शिक्षा ले सकेगा। नार्मल हाई स्कूल में वही बच्चा जाये, चाहे वह एडमिनिस्ट्रेशन में जाये, चाहे वह सामान्य शिक्षा में जाये, चाहे अन्य दूर-दराज में जाये, उस प्रकार का एक माडल राजस्थान में बनाने की मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि राजस्थान के सम्भाग स्तर पर इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिये।

हमारे कालेजेज के अन्दर जिस प्रकार से हमारा बच्चा जब थ्री ईयर डिग्री कोर्स करता है, कभी कोई सोचने का काम नहीं होता है कि उस बच्चे का होगा क्या। मैं कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, उन बच्चों को क्यों नहीं ट्रेनिंग दी जाती है? क्यों नहीं पंचायत समिति के नरेगा के कार्यालय में भेजा जाता? क्यों नहीं पंचायत समिति के कार्यालय में बैठाकर कार्यालय का फाइलिंग का काम सिखाया जाता? क्यों नहीं उनको एसडीओ कोर्ट और तहसील के अन्दर भेजा जाता? इस प्रकार की व्यवस्था के अन्दर हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, न उसको केवल फाइलिंग का, प्रजेन्टेशन करने का काम हो सकता है लेकिन उसके अन्दर मेहनत करने का काम होगा। उस मेहनत से बचना चाहते हैं। तहसीलदार नहीं चाहता कि मेरे दफ्तर में आकर कोई मेरे यहां इस प्रकार की अव्यवस्था करने का काम करे, उन बच्चों को सिखाने का काम होना चाहिये।

जिस प्रकार से आज गांव का आदमी जो जमीन की नाप को अंगुलियों पर बता देता है कि किस प्रकार से किस प्रकार का गठठा, जरीब

(श्री मान सिंह)

होता है, किस प्रकार से जमीन को नापा जाता है। आज पढ़ा-लिखा नौजवान इस बात को नहीं बता सकता है कि मेरी जमीन का माप कैसे होता है क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें छूट गई हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि हमारी शिक्षा नीति में और हमारे राजस्थान की शिक्षा की गुणवत्ता में जिस प्रकार की माननीया मुख्य मंत्रीजी की मंशा है, हम लोगों को उसमें ठोस कदम उठाने चाहिये। शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि आपको इस मामले में ठोस कदम उठाने होंगे।

आज जिस प्रकार की हमारे स्कूलों के अन्दर टीचर्स की कमी है, उसको भी निश्चित रूप से पूरा करने का काम होगा और विशेषकर हमारी बालिका शिक्षा का। बालिका शिक्षा गांवों में जिस प्रकार की है, जहां आवश्यकता हो, वहां उसका पूरा होने का काम होगा।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आप बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। मेरे गंगापुर सिटी विधान सभा क्षेत्र में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने 1977 में कालेज खोला। उस कालेज के अन्दर कामर्स और आर्टस दोनों विषय थे। पिछली सरकार ने जब उसको पीजी में क्रमोन्नत किया तो केवल आर्टस में किया। वहां पूरे संसाधन मौजूद हैं, पूरा स्टाफ मौजूद है। कामर्स का विषय खोल दिया जाये तो उन बच्चों को और उनके साथ-साथ में दूसरों को भी कामर्स पढ़ने का विषय मिलेगा। भूगोल का विषय खोल दिया जाये तो उन बच्चों को भूगोल का विषय पढ़ने को मिल जायेगा, उसकी फैकल्टी मिल जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में उन कालेजों में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं। गंगापुर में मेरे वजीरपुर उपखण्ड है, जो एसडीएम उपखण्ड है। जब भी सरकार की नीति हो, 46 स्थान हैं, उसमें वजीरपुर को भी शामिल किया जाये और जब भी सरकार उन 46 स्थानों पर कालेज खोले तो वहां की भी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे शारदा बालिका विद्यालय का छात्रावास है, उसकी दशा दयनीय है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने पिछली बार भी इस विषय को उठाया था। गंगापुर के अन्दर जहां शारदा बालिका विद्यालय के छात्रावास को बनाया गया है, वहां पानी भरता है। पिछली सरकार

(श्री मान सिंह)

ने ऐसी जगह पर छात्रावास बनाया, मैंने कहा कि उसकी जांच होनी चाहिये। मैं मांग करता हूं कि ऐसी जगह पर कैसे बनाया गया। उन बालिकाओं को रहने में कितनी परेशानी होती है। सामने अतिक्रमण हो रहा है। मैं विभाग से मांग करूंगा कि गंगापुर के शारदा बालिका छात्रावास की जांच हो और वहां की बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था हो। सरकार बजट दे कि वहां पर बाउण्ड्रीवाल बने अन्यथा इस प्रकार के बालिका छात्रावासों में बालिकाओं को हम छोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से समाज के लिए, हमारे लिए यह दर्द की बात है।

अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-47 रखी गई है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारा सवाई माधोपुर जिला धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रणथम्भौर हमारे यहां है, त्रिनेत्र गणेशजी का मंदिर भी है। कैलादेवी हमसे लगता हुआ है। कैलादेवी का मेला चल रहा है। राजस्थान में अगर रोडवेज को सबसे अधिक किसी एक मेले से आय होती है तो वह कैलादेवी के मेले से होती है। गंगापुर के रेलवे स्टेशन पर अलग से यदि बस स्टैण्ड बनाया जाता है, वहां के धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने की मैं सरकार से मांग करता हूं। गंगापुर में धुंधेश्वर धाम है, रणथम्भौर, चौथ का बरवाड़ा में हमारा घुश्मेश्वर महादेव और चौथमाता का मंदिर है, उनको धार्मिक कोरीडोर के रूप में डवलप करने का माननीय पर्यटन मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा। हमारे सवाई माधोपुर जिले और करौली का पूरा का पूरा बैल्ट है जो पहले एक ही जिला था, उसको आप बढ़ाने का काम करें और आज पर्यटन के क्षेत्र में विपुल सम्भावनाएं हैं, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें आपको निजीकरण करना है तो आप करिये, लेकिन इसमें कमी करने का काम मत करें मंत्री महोदय, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जिसमें हमारी पर्यटन और हमारी संस्कृति को किस प्रकार से लोग देख सकते हैं, किस प्रकार से निहार सकते हैं। यही हमारी धरोहर है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी पूंजी है, जिसको हमको बढ़ाने का काम करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अंत में एक बात और कहूंगा शिक्षा मंत्रीजी से कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायतें हैं महूकलां और श्यारोली। जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल होने से बच गई हैं। मैं आपसे पुन: अनुरोध करूंगा कि पूरे प्रदेश के हित में है। हमको यह नहीं सोचना चाहिये कि जहां पर प्राइवेट सीनियर सैकण्डरी स्कूल है, वहां नहीं खोलें क्योंकि गरीब के

(श्री मान सिंह)

बच्चे को लुटने के लिए नहीं छोड़ना चाहिये वहां पर भी सरकार को सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलकर उनको सुविधा देनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: आपने तो 11 मिनट में 22 मिनट का भाषण दे दिया। कमाल है, भई। श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 और 47 पर आज चर्चा हो रही है। शिक्षा महत्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार आरटीई के तहत एक अध्यादेश लायी कि कोई भी बच्चा या बच्ची शिक्षा से वंचित नहीं रहे। उनको एक-डेढ़ किलोमीटर दूर पैदल पढ़ने जाना नहीं पड़े। आठवीं तक बच्चे को दो-ढाई-तीन किलोमीटर से दूर पैदल जाना नहीं पड़े और सैकण्डरी वाले बच्चे को भी पांच किलोमीटर से ज्यादा दूर जाना नहीं पड़े, इसके तहत स्कूलें खोलें और बच्चों को नजदीक पढ़ने जाने के लिए अच्छी सुविधा मिले। ताज्जुब इस बात का है कि इस सरकार ने चुनाव के अन्दर तो बड़े-बड़े वादे किये थे। स्कूलों में अध्यापक नहीं, नजदीक स्कूलें नहीं, विद्यार्थी मित्र जिसके लिए तो, हमारी सरकार आते ही पक्की नौकरी आपकी हो जाएगी। हैडमास्टर हैं नहीं। दुनियाभर की बातें कीं, स्कूल में भवन नहीं, भवन दे देंगे, बच्चे बबूल के नीचे बैठे हैं। ये वादे कर कराकर के भारी बहुमत से सरकार आई। आते ही पहला काम किया 17 हजार स्कूलें बंद करने का। अब मैं, माननीय अध्यक्षजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां सब लोग ढाणियों में बैठते हैं, एक-डेढ़-दो किलोमीटर बच्चे पैदल जाकर विद्यालय में पढ़ते थे और वे स्कूलें अगर बंद होती हैं तो उनको कितनी तकलीफ होगी। अब हमारे मंत्रीजी को तो यह पता नहीं, क्योंकि यहां बैठे हैं। जो वहां ढाणियों में बैठे हैं उनको पता है कि वास्तव में हकीकत क्या है। आपने हर सीनियर सैकण्डरी करके एकल स्कूल विद्यालय एक पंचायत में खोल दी। उस पंचायत में प्राइमरी बच्चियों का स्कूल था, वह स्कूल भी आपने बंद कर दी। भवन बना हुआ था उस भवन को खाली कर दिया और एक स्कूल में जहां बिल्डिंग सुविधा नहीं है पूरी, बच्चे बाहर बैठ रहे हैं और अध्यापकों का पता नहीं, हैडमास्टर वहां है नहीं, अब वह आदर्श स्कूल कैसे बनेगी यह तो हमारे शिक्षा मंत्रीजी को पता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो अभी पुनर्गठन हुआ पंचायती राज के अन्दर, उसमें नई पंचायत समितियां बनीं। उसके अन्दर जितनी भी पंचायत

(श्री मेवाराम जैन)

समिति बनी है वहां बी.ई.ओ. कार्यालय खुले ताकि वहां मानीटरिंग की सुविधा हो सके, यह सुझाव मेरा रहेगा। थर्ड ग्रेड अध्यापक जिनकी भर्ती होनी थी और अभी आपने की है, रिजल्ट आउट भी किया है और मेरे ख्याल से हमारे यहां अभी तक वह पोस्टिंग नहीं दी। आज तक तो दी नहीं है और कल देंगे तो मुझे पता नहीं। आज तक नहीं दी है, मुझे पता है, मैंने आज सवेरे ही पता किया है। अभी माननीय सुखरामजी ने भी कहा है कि अध्यापक उस विद्यालय में लगे जहां वास्तव में आवश्यक है। दूर-दराज एरिया में तो जाते नहीं और शहर के नजदीक दस किलोमीटर पहले भी कहीं तीस बच्चे हैं, चालीस बच्चे हैं वहां चार-चार अध्यापक बैठे हैं और जहां 200 बच्चे हैं वहां एक-एक अध्यापक है। अब इस तरह से स्कूलों में जहां वास्तव में अध्यापक नहीं है वहां अध्यापक लगें तो यह भर्ती और अध्यापक लगाने का जनता को और बच्चों को फायदा होगा। जहां भवन नहीं है, प्राथमिकता के साथ भवन बनाया जाए। कई स्कूलें तो खोल दी थीं उसके लिए भवन अभी भी नहीं है, खेल का मैदान नहीं है और दो ढाई साल पहले जो थर्ड ग्रेड के अध्यापक लगे थे, वे भी चिल्ला रहे हैं कि हमें परमानेंट का परिलाभ नहीं दिया जा रहा है। जब उनका टाइम पूरा हो चुका है तो उनको भी उनका जो परिलाभ का हक है वह दिया जाना चाहिए। अब आपने टेट की परीक्षा को खतम करने की भी बात कही है, अभी आपने प्राइवेट स्कूलों की बात कही है तो आपने अभी देखा है कि शिक्षा के क्या हालात हैं? आप देखना कि थोड़े दिनों में सरपंचों के कुल कितने फर्जी डिग्रियों के मामले आएंगे, ये सारे प्राइवेट विद्यालयों से ही उन्होंने ली है। प्राइवेट शिक्षा का किस तरह से जाल फैल रहा है। अगर इसकी हकीकत में जाएं तो प्राइवेट वाले किस तरह से मैनेज करते हैं इन पर मानीटरिंग की आवश्यकता है।

अब रही प्रतिबंधित ज़िलों की बात, अभी मेरे साथी कह रहे थे हमारे इन पांच ज़िलों में पहले भी अध्यापक कम हैं। कहीं-कहीं तो सिर्फ एक-एक अध्यापक है और कहीं तो सिर्फ पहले वो विद्यार्थी मित्र लगा हुआ था आठवीं पास, वही लगा हुआ है, ऐसी भी स्कूलें हैं। अभी जो 1800 की भर्ती हुई उसमें 180 बाड़मेर जिले के हैं और 1620 वो सारे बाहर के हैं। जब प्रतिबंधित ज़िलों से इनको बाहर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा तो पूरा का पूरा जिला वापस खाली हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप वापस ट्रांसफर करना भी चाहते हो तो पहले वहां अध्यापक दें, स्कूलें भरें और

(श्री मेवाराम जैन)

फिर भेजें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। जिन स्कूलों में आवश्यकता है वह तो खाली की खाली ही रहेंगी। अब हैडमास्टर को देख लें, पूरे के पूरे खाली पड़े हैं। माडल स्कूलें कुछ पहले खोल दीं, भवन बने पर उनकी पूरी राशि नहीं है, अधूरी माडल स्कूलें पड़ी हैं और कुछ चालू की हैं तो उसमें स्टाफ नहीं है। अब हमारे बाड़मेर की बात कर लीजिए, वहां चालू तो कर दी है, वहां स्टाफ एक-एक, दो-दो लगाया है। अब माडल स्कूल तो कम से कम अच्छी हो, वहां शिक्षा अच्छी गुणवत्ता की मिले। इसके लिए तो माडल स्कूल एक नमूने के तौर पर एक पंचायत समिति पर एक-एक खोली जा रही है।

अब खेल के प्रोत्साहन की अपन बात कर रहे हैं। खेल में बच्चों को, मैं कहना चाहूंगा कि जो टूर्नामेंट की प्रतियोगिता की जा रही है। आप उनके बजट के लिए एक पैसा दे नहीं रहे, हर साल अध्यापक गांवों में चंदा करके प्रतियोगिताएं करते हैं। यह कितने दिन चलेगी? इसके लिए बजट होना चाहिए ताकि बच्चे खेलें। एक घंटे नियमित खेलने की बात करते हैं, अब टूर्नामेंट होते हैं तब बुलाते हैं, झण्डा कैसे पकड़ा जाता है यह भी उनको आता नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिस तो होती नहीं है, पी.टी.आई. है नहीं। सिखाने वाला कोई है नहीं। तो इस प्रकार के जो हालात हैं इनको ठीक करने की आवश्यकता है।

मिड-डे मील की बात भी कर रहे थे, वास्तव में उसी स्कूल के अन्दर मिड-डे मील पक रहा है, बच्चे उसकी ओर देख रहे हैं और पढ़ाई की ओर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अध्यापक ही एक है और वह उस व्यवस्था में लगा हुआ है, कौन पढ़ाये, कौन डाक पहुंचाये और फिर बच्चों को देखें तो इस पर भी ध्यान की आवश्यकता है कि इसको अपन कैसे ठीक करें।

आप स्कूलों के अन्दर देख लीजिए, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां देखें तो आधे से ज्यादा स्कूलों में पानी की व्यवस्था नहीं है। अब पानी नहीं है वहां, लाइट नहीं है और अगर टायलेट की बात करें तो टायलेट कोई बना भी दिया तो उसमें जाने के लायक ही नहीं है क्योंकि पानी नहीं है तो साफ कैसे होगा? इसलिए पानी की समुचित व्यवस्था कम से कम वहां हो, टायलेट्स और लाइट हो, अच्छी सुविधा बच्चों को मिले, यह हम सब चाहते हैं और इसमें सुधार की आवश्यकता है। आज बाड़मेर में राजकीय महाविद्यालय भवन बना हुआ है, बिल्डिंग में कालेज चल रही है। हालत ऐसी है, बिल्डिंग में जाकर जब आप देखेंगे तो इतनी जर्जर है कि कभी वहां जन हानि नहीं हो

(श्री मेवाराम जैन)

जाए। उसकी रिपेयर की आवश्यकता है, उस पर आप फण्ड दें, नहीं तो कोई ऐसा हादसा होगा कि उसके अन्दर बच्चे खतम हो सकते हैं। वह बिल्डिंग बहुत जर्जर अवस्था में है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। हमारे यहां पोलीटैक्निक कालेज है, हालत यह है कि उसमें पोस्टें तो साठ या पैंसठ हैं और लगे हुए हैं पांच। पूरा का पूरा खाली है अब आप बताइए कि कैसे शिक्षा में सुधार होगा। आई.टी.आई. कालेज हमारे यहां पर पहले अल्पसंख्यकों को राज़ी करने के लिए खोली और इन्होंने आते ही वह बंद कर दी। यह अल्पसंख्यकों को राज़ी पता नहीं कैसे कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं, अध्यक्षजी, ज्यादा समय नहीं लूंगा सिर्फ पर्यटक पर एक ही बात कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा, एक ही बात कही है आपने।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): हमारे बाड़मेर में एक प्राचीन स्थान है जूना किराडु जो बहुत ही पुराना है और उसकी कारीगरी जिस तरह से है। नेशनल हाइवे रोड पर पर्यटकों को उधर जाने नहीं दे रहे हैं अगर उसका अच्छा जीर्णोद्धार हो जाए तो वहां पर्यटकों की बहुत ही ज्यादा सम्भावना है। दूसरा, हमारे भादरेस में महात्मा ईसरदासजी का मंदिर है वहां श्रद्धालु भी खूब जाते हैं। लखावत साहब वहां आये थे और घोषणा करके आये थे कि हम ईसरदासजी का एक पेनोरमा वहां बनायेंगे ताकि पर्यटक वहां आयें। वह घोषणा अभी इस बजट में तो मैंने देखी नहीं है। इसलिए मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि वह भी अगर सम्भव हो उनकी की हुई घोषणा पूरी हो जाए तो अच्छी बात है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा को राजनीति से दूर रखें और इसमें हमें कठोर निर्णय लेने होंगे। जितनी भी पोस्टिंगें हैं राजनीति के हिसाब से नहीं करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, अच्छे संस्कार कैसे मिलें, इस हिसाब से करने पड़ेंगे तभी तो यह शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। अगर नहीं तो हमारे यहां हालत है कि एक स्कूल में दस-दस बैठे हैं...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। श्री पूरणमल सैनी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ठीक है, अध्यक्षजी। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या-24 पर मुझे बोलने के लिए अनुमति दी इसके लिए आपका आभार

(श्री पूरणमल सैनी)

व्यक्त करते हुए आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों स्कूलों के एकीकरण हेतु नियम बनाकर एकीकरण के आदेश किये गये, लेकिन उससे इस राजस्थान प्रदेश की शिक्षा स्थिति में काफी कमी आई। कमी आने का कारण अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने भी बताया कि राजस्थान प्रदेश की बसावट भौगोलिक दृष्टि से अच्छी नहीं है कहीं नाले बीच में आये हुए हैं, तो कहीं हाइवे। ओवरलोडेड वाहनों को क्रास करके छोटे-छोटे बच्चों को जाना पड़ता है तो माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा और इस राजस्थान सरकार द्वारा पिछले दिनों जो एकीकरण का नियम इस राजस्थान प्रदेश में लागू करके और काफी बड़ी संख्या में छोटी स्कूलों को मर्ज फर्माया गया वो वाकई में सरकार का सराहनीय कदम नहीं था। मैं इस बात के लिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, अगर हम नयी स्कूलें खोलने की स्थिति में नहीं हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन जो व्यवस्थाएं पूर्ववर्ती सरकार चाहे वो बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, उन सरकारों के माध्यम से स्कूली क्षेत्र में गांव-ढाणियों के लिए जो व्यवस्थाएं दी गई थीं, उनके एकीकरण के लिए जो नियम बनाये गये जैसे एक ही राजस्व ग्राम में छोटी-छोटी स्कूलों का समायोजन किया जाएगा। उन नियमों को भी बहुत-सी जगह तो ताक में रखते हुए राजस्थान में स्कूली शिक्षा में एकीकरण का काम फर्माया गया है। इस एकीकरण पर दुबारा सरकार विचार करके और वास्तव में जांच करवाकर जहां आवश्यक हो, छोटे बच्चे सुदूर क्षेत्रों में नहीं जा पाते, वहां उनको पुन: शुरू करवाने के लिए निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरा निवेदन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके साथ-साथ मैं सरकार से भी आशा और विश्वास रखता हूं कि माननीय सदस्यों के द्वारा आपको विराट हृदय और हम भी मानते हैं, आप जैसे हैं वैसे ही सरकार भी है तो जब पूर्ववर्ती सरकारों ने जैसे आज भी आप कर रहे हैं कि विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर नियुक्तियां फर्मा रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे दूसरा पशु चिकित्सा विभाग हो वैसे ही स्कूलों में भी पूर्ववर्ती सरकारों ने पैराटीचर्स के रूप में जो अध्यापक कार्यरत राजस्थान प्रदेश में थे, उनका किसी न किसी प्रकार कोई उपाय निकालकर राजस्थान की शिक्षा में समायोजन करते हुए उनका नियमितीकरण किया। आज भी बहुतों का नहीं हुआ है लेकिन एक व्यवस्था खड़ी करके और उसमें उनको डाल दिया गया तो इस विषय के लिए भी मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस

(श्री पूरणमल सैनी)

राजस्थान प्रदेश के ही वो शिक्षाकर्मी साथी लोग थे जो मतदाता चाहे किसी भी पार्टी के रहे हों, लेकिन सरकार से बहुत बड़ी आस लगाये बैठे हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप उनको अपना मानते हुए और विराट हृदय का परिचय देते हुए, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे जिन शिक्षाकर्मियों को हटाया गया उनका समायोजन करने के लिए मैं अपील करना चाहूंगा।

तीसरा विषय, माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व में भी जब मुझे मौका मिला तो मैंने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि कालेज एजुकेशन में जो नियम कालेज निदेशालय ने बनाये हुए थे उनमें काफी बदलाव इस सरकार के आने के बाद किया गया जो बिलकुल ही असहनीय उन निजी महाविद्यालयों के निदेशकों के लिए रहा और उसका प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता गया। सरकार ने नियम ये बनाये कि निजी महाविद्यालय की मान्यता प्राप्त करने के लिए पूर्व में पांच हजार वर्गमीटर जमीन की जरूरत होती थी जबकि अब उस जमीन को बढ़ा कर आठ हजार वर्गमीटर कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि महाविद्यालय की स्थापना चाहे वो निजी रहे चाहे सरकारी रहे, कहीं जंगल में नहीं होती। किसी न किसी गांव या बड़े शहर में महाविद्यालय खोले जाते हैं। 2005-06 या 2004 में जिसने अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त की और उसके पास पांच हजार वर्गमीटर जमीन थी उसको सरकार ने मान्यता दे दी थी लेकिन अब उस जमीन को बढ़ाकर आठ हजार वर्गमीटर कर देने से ये समस्या पैदा हो गई कि उस महाविद्यालय भवन के दायें-बायें, आगे-पीछे की सभी भूमियां दूसरे लोगों के द्वारा, दूसरी कम्पनीज के द्वारा, दूसरी फर्मों के द्वारा एक्वायर कर ली गई हैं और वहां दूसरे प्रकार के भवनों को निर्माण किया जा चुका है अत: ये पांच हजार वर्गमीटर से हटाकर कालेज शिक्षा निदेशालय के द्वारा बिलकुल ही गलत नियम बनाया गया है, इसको मेरे खयाल में वापस लेते हुए और राजस्थान प्रदेश में चल रहे निजी महाविद्यालयों के निदेशकों को, इससे स्थिति यह उत्पन्न हुई माननीय अध्यक्ष महोदय, कि निजी महाविद्यालयों में जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे उसके बाद इन्होंने फीस भी बढ़ाई और फीस इतनी बढ़ाई सम्बद्धता के लिए, सवा लाख, डेढ़ लाख और पौने दो लाख। जब वो निजी शिक्षण संस्थाएं इनकी भरपाई नहीं कर पाईं तो फिर इन्होंने एक नियम लगाया और एक नोटिस जारी किया उन निजी शिक्षण संस्थाओं को कि आप लोग अगर ये पैसे जमा नहीं करवा रहे हो तो

(श्री पूरणमल सैनी)

फिर आपके विद्यार्थियों को जो रैगुलर विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई कर रहे थे उनको कालेज निदेशालय ने या विश्वविद्यालय, जयपुर ने एक आदेश जारी कर कहा कि आपने फीस जमा नहीं करवाई तो आपकी संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्वयंपाठी का दर्जा दे दिया जाए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नियमों में इतनी बड़ी तब्दीली की गई उसके बाद वो फीस जमा और वो जमीन एक्वायर वो संस्थाएं नहीं कर पाईं इसके चलते ये समस्या पैदा हुई और कालेज निदेशालय ने उन निजी शिक्षण संस्थाओं को चलाने वालों को ये दंड दिया। लेकिन ये दंड धीरे-धीरे उस गरीब के घर के बेटे तक भी पहुंच गया। जैसे प्राइवेट स्कूलों में कम फीस में वहां रहते हुए वो ग्रामीण एरिया में एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अब उनके साथ इतना कुठाराघात कि पूरे वर्ष तो रहे वो नियमित विद्यार्थी के रूप में लेकिन अब उसको स्वयंपाठी के रूप में माना गया जो बहुत ही गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि जो ये अपरिहार्य नियम लागू किये गये उनको वापस लेते हुए और राजस्थान विश्वविद्यालय में स्वयंपाठी के रूप में उन निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को रैगुलर विद्यार्थी के रूप में ही परीक्षा दिलवायी जाए।

तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि पिछले दिनों....

श्री अध्यक्ष: बस तीसरा कर दो आप।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): छोटे-छोटे तो होते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: दस मिनट हो गये आपको।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): कभी तो समय दे दो, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: एक-दो मिनट और बोल लीजिये आप।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने लैक्चरर भर्ती के लिए योग्यता के जो मापदंड तय किये उनमें गुड एकेडेमिक रिकार्ड के नाम पर दसवीं, बारहवीं, स्नातक और स्नातकोत्तर में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बाद नैट और सैट को तय किया है, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायक प्रोफेसर के लिए निर्धारित योग्यता में गुड

(श्री पूरणमल सैनी)

एकेडेमिक रिकार्ड, स्नातकोत्तर में 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी नेट और सेट उत्तीर्ण योग्यता निर्धारित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आज कालेज लैक्चरर का एग्जाम देने के लिए प्रोफेसर के रूप में कोई विद्यार्थी आया उस विद्यार्थी को जब उसने दसवीं और बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की उस समय सरकार के द्वारा यह नहीं बताया हुआ था क्योंकि पहले नियम था कि स्नातकोत्तर में जब 55 प्रतिशत अंक आप प्राप्त करेंगे तो कालेज लैक्चरर के लिए योग्य होंगे। इसी बात को ध्यान रखते हुए उस विद्यार्थी के चाहे दसवीं में और कक्षा बारहवीं में अंक कितने भी प्रतिशत रहे होंगे लेकिन उसने पीएचईडी भी कर ली, नेट भी किया और सेट भी किया, एमफिल भी की उसके बाद पूर्ण रूप से वो कालेज एजुकेशन में प्रोफेसर के लिए तैयार है लेकिन सरकार ने यह नया नियम लगा करके कक्षा दस और बारह में जिन्होंने पचपन प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं वो ही विद्यार्थी प्रोफेसर के लिए योग्य माने जाएंगे। मैं आपके माध्यम से अपील और निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि आज अगर आप लोगों ने यह बात तैयार कर ली तो माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच वर्ष बाद के आने वाले छात्रों के लिए प्रोफेसर पद हेतु यह बात लागू की जानी चाहिए। जिन्होंने ये डिग्रियां प्राप्त करके अपना काफी समय, धन बर्बाद कर दिया उसकी उपयोगिता प्रापर रहे और उन गरीब लोगों की उच्च शिक्षा में प्रोफेसर के रूप में नियुक्तियां हो सकें इसके लिये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि दसवीं, बारहवीं के अंकों का जो नियम लागू किया है उसको वापस लेते हुए राजस्थान प्रदेश के प्रोफेसरों को अनुग्रहीत करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 व 47 पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्यों में कैसे आये, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर रहने वाले बालक व बालिका उसी पंचायत मुख्यालय पर पढ़ें, इसके लिये राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ और प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया। पूरे राजस्थान में इससे पांच हजार उच्च माध्यमिक विद्यालय एक ही आदेश के तहत

(श्री नारायण सिंह देवल)

क्रमोन्नत हुए। गांवों में अक्सर समस्या यह रहती थी कि हमारी बच्ची बड़ी हो गयी है पास के शहर में कैसे भेजें। इस आदेश के तहत पंचायत मुख्यालय में ही बारहवीं की स्कूल होने से जो बच्चियां ड्रापआउट होती थीं, शिक्षा से वंचित हो जाती थीं, वे अपने पंचायत मुख्यालय में ही पढ सकेंगी। जालौर जिले में देश आजाद होने के बाद आज दिन तक मात्र 89 उच्च माध्यमिक विद्यालय थे। इस आदेश के तहत हमारे जालौर जिले में 174 माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत कर दिये गये। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में हमें विरासत में अध्यापकों की भारी कमी मिली है। एकीकरण का काम हुआ और इससे अध्यापकों की जो काफी कमी थी उस समस्या का समाधान हुआ। डीपीसी हुई और अभी नयी भर्तियां भी हुईं। इससे जो एक बड़ी समस्या थी उसका काफी कुछ समाधान हुआ। जालौर जिला शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़ा जिला है। (व्यवधान)शिक्षा पर नजर डालें...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अर्जुन लाल (राज्य मंत्री, विधि): अध्यक्ष महोदय, सदन का समय माननीय मंत्री महोदय अपना वक्तव्य नहीं दें, तब तक के लिये बढाया जाये।

श्री अध्यक्ष: अनुदान मांगें, स्वीकार नहीं हो जायें तब तक...

श्री अर्जुन लाल (राज्य मंत्री, विधि): अनुदान की मांगें पारित नहीं हो जायें, तब तक समय बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: समय बढाया जाता है।

मांग संख्या 24 व 47 पर विचार

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): राजस्थान के राज्यों में शिक्षा पर अगर नजर डालें तो राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत 66.11 है। इसमें ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत 61.44 है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालौर है। जालौर की साक्षरता की दर 55.58 है और महिला साक्षरता में जालौर जिला राजस्थान के अंतिम पायदान पर है।

(श्री नारायण सिंह देवल)

मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे इस जिले पर जो साक्षरता का कलंक है, उसको मिटाने के लिये विशेष पैकेज दिया जाये। पूरे जालौर जिले में 13 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर हायर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुए। उसका कारण था कि वहां निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में मात्र दो ग्राम पंचायत हैं आजोदर और कोटड़ा, इनको भी आप क्रमोन्नत करें। जालौर जिले में जो साक्षरता की दर कम है उसके लिये नये स्कूल खोले जायें और जो पांचवी के स्कूल हैं उनको आठवीं और आठवीं के स्कूल को दसवीं में क्रमोन्नत किया जाये। शिक्षकों की भर्ती के लिये जिला कैडर स्थापित किया जाये और यह व्यवस्था की जाये कि जो शिक्षक जिस जिले में चयनित होता है उसका पूरा सेवाकाल उसी जिले में रहे। ऐसा करने से शिक्षकों के बार-बार ट्रांसफर होने की समस्या का समाधान होगा और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े जिलों में बार-बार स्थानांतरण होने से शिक्षकों की कमी उत्पन्न नहीं होगी। जालौर जिले में वर्तमान में 89 बारहवीं की स्कूल है उनमें मात्र 19 प्रधानाध्यापक हैं, 78 परसेंट पोस्ट अभी भी वैकेंट हैं। स्कूल व्याख्याता के स्वीकृत पद 577 के विरुद्ध में 119 स्कूल व्याख्याता कार्यरत हैं, शेष 80 परसेंट पोस्ट खाली हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र जसुलपुरा में पंचायत समिति मुख्यालय है और उप खण्ड अधिकारी का कार्यालय भी है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि वहां पर एक माडर्न स्कूल खोला जाये। एक मेरा सुझाव है आरटीई में पढ़ने वाले आठवीं कक्षा के किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं करने पर पुन: विचार करना चाहिये जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हो। जालौर जिले में एक अतिरिक्त नवोदय विद्यालय खोलने का भी एक प्रस्ताव लेकर यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाये। जालौर जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19.53 परसेंट है, एसटी की 9.77 परसेंट है। मेरी मांग है मेरे विधान सभा क्षेत्र में एससी व एसटी की शिक्षा का स्तर काफी कम है इसलिए छात्रावास खोले जायें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री महोदय को भी निवेदन करना चाहूंगा। जालौर जिले में भीनमाल शहर में ब्रह्मगुप्तजी का जन्म हुआ था। ब्रह्मगुप्तजी ने दो ग्रंथ लिखे थे, एक तो ब्रह्म स्पुट सिद्धांत और एक खाद्य पद्धति। वर्तमान में विद्यालयों में पढ़ायी जाने वाली जो अंक गणित है, बीज गणित है उन सिद्धांतों को भी ब्रह्मगुप्तजी ने ही बनाया था। ब्रह्मगुप्तजी

(श्री नारायण सिंह देवल)

ने पृथ्वी की परिधि का माप भी ज्ञात किया था। दशमलव के सिद्धांत को भी सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्तजी ने स्थापित किया था। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को भी सर्वप्रथम स्थापित करने वाले ब्रह्मगुप्तजी थे। हम जालौर जिले वाले अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसी विश्वविख्यात हस्ती का जन्म भीनमाल में हुआ। माननीय मुख्य मंत्रीजी की इच्छा भी है कि इन महापुरुषों के लिये स्मारक बने। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ब्रह्मगुप्त और महाकवि माघ के पेनोरमा हमारे भीनमाल में बनाये जायें।

अंतिम बात निवेदन कर रहा हूं कि हमारे जालौर जिला मुख्यालय पर वीरम देव चौहान का किला है। भीनमाल के पास जसुंधरा में सुंधामाता का मंदिर भी है जो जालौर जिले और जोधपुर सम्भाग में विश्वविख्यात है, इन दोनों को ट्यूरिज्म मैप के साथ जोड़ा जाये, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित कुमार।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24 व मांग संख्या 47 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

शिक्षा के माध्यम से आज इस सदन में चर्चा हो रही है। शिक्षा का स्तर उठाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री ने 2014-15, 2015-16 का बजट प्रस्तुत किया उसमें शिक्षा को प्रमुखता देते हुए अलग से बजट के प्रोवीजन किये। मेरा यह कहना है कि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए जो बजट दिया गया है इसकी मानिटरिंग बहुत आवश्यक है। आज हम पूरे भारतवर्ष में देखें तो राजस्थान की शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति है। आज केरल भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम माना जाता है, दूसरे नम्बर पर मिजोरम आता है। केरल की साक्षर स्थिति 91 परसेंट है। महिला शिक्षा के अन्तर्गत आज हम देखें तो राजस्थान पूरे भारतवर्ष में बहुत पिछड़ा हुआ है। इन सबका ध्यान रखते हुए हम राजस्थान की शिक्षा को बढ़ाते हुए एक अच्छे पायदान पर लें जाएं ताकि जो गरीब स्टूडेंट हैं वे आगे बढ़ सकें। आज हम शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन देने की बजाए हम क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हैं। क्वांटिटी के माध्यम से पढ़ाकर हम उनको आगे डिग्रियां दे रहे हैं। मेरा यह कहना है कि हम क्वालिटी पर भी ध्यान दें ताकि प्रतिभाएं बाहर निकलकर आएं। अत: ज्यादा इधर-उधर

(श्री ललित कुमार)

की बात न करते हुए मैं अपने विधान सभा पर आना चाहूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र सहरिया आदिवासी बहुल क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मिड-डे मील, अक्षय पात्र योजना के अन्तर्गत 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम, 150 की जगह 300 ग्राम पोषाहार स्कूलों में वितरण किया जाता है परन्तु इनमें बहुत अनियमितताएं पाई जाती हैं। पोषाहार देना अच्छा है, बच्चे उसकी वजह से पढ़ने आते हैं। मेरा कहना यह है कि अध्यापक और स्कूल का पूरा प्रशासन इसकी व्यवस्था में लगा रहता है, वे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में कई बार सस्पैंड किये जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रीट की घोषणा की थी, यह बहुत सराहनीय कदम है क्योंकि एक थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए पहले उसको बीएड का एग्जाम देना पड़ता था, साल भर की ट्रेनिंग के बाद, आरपीएससी का पंचायती राज का एग्जाम देना पड़ता था, उसके बाद उसको पोस्टिंग मिलती थी। इसी प्रकार हमारे आई ए एस, आर ए एस के प्री, मैन, इंटव्यू देकर। एजुकेशन दोनों बराबर कर दिए, जबकि वहां पर आप थर्ड ग्रेड टीचर बना रहे हैं। मेरा यह बहुत अच्छा प्रस्ताव था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो रीट किया था अब आगे जब भी एग्जाम होगा तो इसका सुधार हमें अवश्य ही दिखाई देगा।

मेरे सहरिया आदिवासी क्षेत्र में एक से पांचवीं तक पढ़ने वाले बच्चों को 150 रुपये दिये जाते हैं। चौथी के बच्चों के लिए 250, पांचवीं के लिए 350 और छठी से आठवीं तक के बच्चों को एक हजार रुपये प्रति माह दिये जाते हैं। इनमें भी अनियमितताएं होती हैं क्योंकि कई बच्चों के एडमिशन होते हैं, कई पढ़ने नहीं आते। अध्यापक और प्रशासनिक टीचर लगे हुए हैं वह इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार करते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 26 स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। 26 में से पंचायती राज के पुनर्गठन के समय 6 ग्राम पंचायतें पूरे किशनगंज और शाहबाद में बनी हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्रीजी से अनुरोध है कि इन 6 नई ग्राम पंचायतों में भी माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्कूल क्रमोन्नत करने की अनुशंसा करें।

मेरे शाहबाद क्षेत्र में एक माडल स्कूल 2012 में बना था परन्तु उसमें अभी तक टीचर्स और स्टाफ अपर्याप्त है। किशनगंज में माडल स्कूल अभी लम्बित पड़ा हुआ है, मेरा अनुरोध है कि इसकी विसंगतियों को देखते हुए

(श्री ललित कुमार)

इसको तुरन्त आगे बढ़ाने का श्रम करें। मेरे क्षेत्र में, केलवाड़ा कस्बे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2008 में कालेज खोला था, उस कालेज में फर्नीचर और लैक्चरर्स की बहुत बड़ी कमी है। पिछले दो साल से केवल एक प्रिंसिपल है और कोई पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए मेरा माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि केलवाड़ा राजकीय महाविद्यालय में फर्नीचर और व्याख्याता लगाने की घोषणा करें और व्यवस्था करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र से बारां मुख्यालय 45 किलोमीटर पड़ता है, आने-जाने में उनको बहुत परेशानी होती है। अभी वर्तमान में पेपर चल रहे हैं, मार्च का महीना है, 45 किलोमीटर बच्चों को पेपर देने जाना पड़ता है। मेरे केलवाड़ा कस्बे में 2010 में पोलीटैक्निक घोषणा करते हुए खोला गया था उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। बिल्डिंग बनी हुई है वह एक इंजीनियरिंग कालेज की तरह बहुत अच्छी और वेल डेकोरेटेड बनी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लाक वगैरह सब अच्छे बने हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बारां जिले में एक इंजीनियरिंग कालेज की घोषणा की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध है कि केलवाड़ा कस्बे के पोलीटैक्निक कालेज के इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए पोलीटैक्निक की जगह इंजीनियरिंग कालेज उसमें शिफ्ट किया जाए ताकि आदिवासी क्षेत्र में टैक्निकल एजुकेशन को आगे बढ़ावा मिल सकेगा। प्राथमिक स्कूल, आने-जाने में बच्चों को समस्या होती है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध कर चुका हूं कि एकीकरण बंद किया गया था उनको पुन: खोलने की अनुशंसा करें। प्रकाशपुरा, जगदेवपुरा, कदीली, पगारा, खिरूना, रामनगर, अखेरवम, मोदरिका यह स्कूल हैं इनको पुन: चालू करें ताकि बच्चों को आने-जाने में समस्या नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे किशनगंज और शाहबाद में तीरंदाजी के लिए एक आर्चर की भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले घोषणा की थी उसकी भी स्थापना, बच्चों को तीरंदाजी, हाकी और वालीबाल के लिए भी वहां पर उद्‍घाटन किया गया था उसके लिए वित्तीय स्वीकृति दी जाए उसको आगे बढ़ाया जा सके।

पर्यटन के क्षेत्र में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में केलवाड़ा कस्बे में सीताबाड़ी बहुत धार्मिक स्थल है, आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण सीताबाड़ी को आदिवासियों का एक तीर्थस्थल माना जाता है। पिछले कार्यकाल में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अलग से बजट देकर यहां के मंदिरों के जीर्णोद्धार के

(श्री ललित कुमार)

लिए विशेष पैकेज दिया था। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्रीजी से अनुरोध है कि इसको देखते हुए कुछ वित्तीय स्वीकृतियां दें। इसी प्रकार मेरे रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित रामगढ़ माताजी का एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें दूर-दूर से यात्री आते हैं, यहां भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र के शाहबाद की पहाड़ी पर 16वीं शताब्दी में बना बहुत बड़ा प्राचीन किला है, एडवेंचर फैस्टीवल के अन्तर्गत 2008 में यहां पर फैस्टीवल रखा गया था, उसमें उस समय के सचिव महोदय भी गए थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उन्होंने इसके कार्यक्रम को देखते हुए इसको लेने की घोषणा की थी। हमारे भंडदेवरा को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पर्यटन में लिया है उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। किशनगंज में फूलडोल उत्सव 106 वर्ष से प्रत्येक वर्ष होली के समय मनाया जाता है, इसे पर्यटन के क्षेत्र में लेने की कृपा करें।

(16.58 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

सहरिया आदिवासियों का एक नृत्य है, नृत्य के माध्यम से उनकी संस्कृति की झलक दिखाई देती है, उनकी संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देते हुए उसको भी लेने का प्रयास करें। मेरे शाहबाद क्षेत्र के ब्लाक हैं उसमें 24 छात्रावास आते हैं जिसमें से 6 सहरिया आश्रम छात्रावास हैं। एक मां शारदा विद्यालय शाहबाद आश्रम है, वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, इन 26 संचालित छात्रावासों में वार्डन्स की बहुत बड़ी समस्या है, इन छात्रावासों के मैनेजमेंट में बड़ी दिक्कत आती है। यहां समाज कल्याण मंत्रीजी भी विराजमान हैं, अत: मेरा अनुरोध है, इनमें अच्छी व्यवस्था हो सके।

मेरे शाहबाद क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी के 63 पद स्वीकृत हैं। उनमें से केवल 30 पद भरे हुए हैं, 33 खाली हैं, अत: मेरा अनुरोध है कि इन पदों को भरते हुए तत्परता से टीचर लगाए जाएं। द्वितीय श्रेणी में 458 पद हैं, उनमें से 320 भरे हुए हैं, 138 खाली हैं। इन पंचायती राज की नियुक्तियों में भी मेरे क्षेत्र में परसों नियुक्तियां दी गई हैं, उससे मेरा क्षेत्र कुछ अच्छी स्थिति में आया है ताकि मेरे आदिवासी भाइयों की शिक्षा का बहुत अच्छा स्तर बन सके।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से केवल मैं यही कहना चाहूंगा कि किशनगंज-शाहबाद, में आदिवासी भाइयों के लिये जो छात्रावास समाज कल्याण

(श्री ललित कुमार)

के, हमारे सहरिया आदिवासियों के स्कूलों के और राजकीय महाविद्यालय, जो चल रहे हैं, उनके लिये बारां जिले में एक डी.ई.ओ. की पोस्ट है अतः सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में 33 डी.ई.ओ. की पोस्टें हैं। किशनगंज-शाहबाद में आदिवासियों की शिक्षा के उत्थान के लिये और उनकी मानीटरिंग के लिये एक अलग से डी.ई.ओ. की पोस्ट स्वीकृत की जाए। यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं बहुत-बहुत आपको धन्यवाद दूंगा। आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री तरुण राय कागा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका प्रदान किया, जिसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राजस्थान की पाकिस्तान से सटी हुई अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित चौहटन विधान सभा क्षेत्र, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इस क्षेत्र से मैं आता हूं। हालांकि हम देश के सजग, बिना तनख्वाह के प्रहरी हैं लेकिन जहां तक देखा जाए तो जो कहा जाता है, कोई भी कौम, कोई भी समाज, इन्सान की तरक्की का जो पैमाना होता है, वह तालीम होती है। तालीम के नजरिये से हम बिलकुल पशमांदे हैं। जो तालीम का शो है, उसमें हम बिलकुल पिछड़े हुए हैं। हमारे कुछ माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय भी हैं जहां शिक्षकों की बहुत कमी रहती है। हालांकि हमारे वहां शिक्षा के क्षेत्र में जहां-जहां स्कूल हैं, वह बिलकुल बार्डर से सटे हुए होने की वजह से डेढ़ सौ, दो सौ, ढाई सौ किलोमीटर परिधि में, उस इलाके में उच्च शिक्षा से महरूम हो जाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में हमारी माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री ने इस बजट में इजाफा किया है, वह तारीफ ए काबिल है और हमारे राजस्थान के लिये बिलकुल अच्छा और मुस्तकबिल रोशन करने वाला है। फिर भी हमारा जो चौहटन विधान सभा क्षेत्र है, उसमें हमें एक अदद कालेज की जरूरत है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो उप खण्ड मुख्यालय, दो तहसीलें, तीन पंचायत समितियां हैं लेकिन कालेज की कमी की वजह से जो लोग तालीम में आगे बढ़ना चाहते हैं, वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। हमें दर-दर भटकना पड़ता है। मुझे ज्यादा नहीं, मैं एक ही कहूंगा हमारे कन्या महाविद्यालय चौहटन मुख्यालय पर खोला जाए तो मैं सरकार का बहुत-बहुत आभारी रहूंगा। यह मेरे लिये एक बहुत अच्छी सौगात होगी। हालांकि हमारे क्षेत्र में तीन पंचायत समितियों की

(श्री तरुण राय कागा)

वजह से, चौहटन पंचायत समिति में एक बी.ई.ओ. कार्यालय है। लेकिन अभी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जो भर्ती हो रही है, उसी में से हमारी जो दो पंचायत समितियां हैं, वहां भर्ती प्रक्रिया में एक रिक्तिता पैदा हो गई है तो हमारे पांच पोस्टें जो ए.बी.ई.ओ. की चौहटन पंचायत समिति में हैं, उनमें से एक-एक ए.बी.ई.ओ. को वहां कुछ समय के लिये डेप्यूट किया जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया का सरलीकरण हो सके, जहां-जहां आवश्यकता हो, वहां उन अध्यापकों का पद-स्थापन किया जाए। हालांकि मैं यह कहूंगा कि सरकार ने जो कदम उठाया कि आठवीं का बोर्ड किया, यह बहुत ही अच्छा किया है। इस तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, गरीब तबके में और पशमांदे इलाके में शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि शिक्षा के साथ-साथ संस्कार, हमारे शिक्षा मंत्री ने कुछ पहल भी की हैं जिससे हमारे संस्कारों का इजाफा होगा, वह भी इनके लिये तारीफ ए काबिल है।

हमारे माननीय सदस्यों ने कुछ मांगें भी उठाईं। हमारे क्षेत्र की स्थानान्तरण नीति के बारे में बातें कहीं। इस तरह से स्थानान्तरण नीति बनाई जाए, मेरा यह सुझाव है कि स्थानीय लोगों को तवज्जोह दे करके, उनको बोनस अंक दे करके, वहां के लोगों का वहां समावेशन किया जाए। हां, यह उन लोगों की पीड़ा भी है। लेकिन हमारे वहां जो अध्यापक आ करके इस तरह से स्थानान्तरण कर जाते हैं तो फिर हमारे स्कूल वैसे के वैसे खाली रह जाते हैं और तालीम का जो मयार होता है, वह बिलकुल कमजोर हो जाता है इसलिये इस विषय पर भी एक बहुत अच्छी तन्मयता से, अच्छी तरह से सोच करना हमारा फर्ज बनता है। हमारे वहां स्कूल में हमने देखा है, मैंने खुद ने जा करके देखा है। स्कूलों में कम्प्यूटर कक्ष हैं, कम्प्यूटर उपलब्ध हैं और कम्प्यूटरों के लिये बजट भी है। उनकी मरम्मत के लिये भी बजट है। बिजली का भी व्यय हो रहा है, मरम्मत का भी बिल उठा रहे हैं। लेकिन कम्प्यूटर आपरेटर की वजह से कम्प्यूटर की शिक्षा नहीं हो रही है इसलिये मेरा सुझाव है कि उस ओर भी ध्यान दिया जाए तो अच्छा होगा। हालांकि हमारे वहां जिस तरह से स्कूलों का जो एकीकरण और समानीकरण का आपने पैमाना बनाया है, वह हमारे क्षेत्र के लिये अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारा क्षेत्र छितरी हुई ढाणियों में रहता है। हमारे छोटे-छोटे, नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल अंधेरे के गर्त में जा रहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि इस नीति पर पुनर्विचार करके हमारे

(श्री तरुण राय कागा)

वहां पर जो एकीकरण है, इसकी जो मुसीबत नाजिल की गई है, इससे छुटकारा दिलाया जाए।

जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री ने जो मरु विकास बोर्ड का गठन किया है, हमारे बाड़मेर और जैसलमेर को उसकी सौगात दी है, इसमें यह विशेष प्रावधान किया जा करके उस इलाके में जिस तरह से पंचायतों के पुनर्गठन के बारे में कुछ रियायतें दी गई थीं, उन रियायतों को भी वहां लागू किया जाना बहुत ही जरुरी है। हालांकि अभी विद्यार्थी मित्रों की भी बात आई है। विद्यार्थी मित्रों की सब लोगों की मांग है, मेरे हिसाब से सदन के सारे मैम्बरान इससे इत्तफाक रखते होंगे। जिस तरह से अभी विद्यार्थी मित्र हैं, अभी जो कहा गया है, अब विद्यार्थी मित्र निकट भविष्य में हमारे विद्यार्थी दुश्मन होने जा रहे हैं। इस वजह से मैं आप सबसे, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से गुजारिश करुंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्र हमारे दुश्मन न बनाएं। हम इसी सत्ता के नशे में मदहोश हो करके सत्ता में ऐसी कोई खता नहीं करें जो यह लोग हमारा पत्ता साफ करने में लग जाएं इसलिये मैं आपसे कहूंगा कि विद्यार्थी मित्रों की ओर भी ध्यान दिया जाए क्योंकि यह हमारे समाज के अंग हैं। इन लोगों के परिवार बेघर हो रहे हैं। उन्हें रोजगार लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने इस हिसाब से मेरे माडल स्कूल की बात कही। मेरे माडल स्कूल भी एक है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब मेरे दो पंचायत समितियां बनी हैं तो माडल स्कूल का भी समावेश किया जाए।

हालांकि यहां कला, संस्कृति और पर्यटन की भी बात आई है। सभापति महोदय, आपने जो मुझे इजाजत बख्शी है वह मांग संख्या 24 और 47 पर है। मांग संख्या 47 के हिसाब से मैं निवेदन करना चाहूंगा चौहटन विधान सभा क्षेत्र में 1965 और 1971 में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी जंग हुई है उन जंगों का दंश हमारे इलाके के लोगों ने भुगता है। आप लोगों को पता होगा इसी देश में रहने वाले लोग भी यहां विस्थापन का दंश भुगत चुके हैं। वहां से जो लोग माइग्रेट होकर आए हैं, वह अपने साथ कहते हैं- नर तो हुनर नहीं तो खर का खर। तो इसलिए जो हुनर लेकर आये हैं उसमें एक शिल्प का काम है। कपड़े पर कांच और कशीदाकारी का बहुत ही बड़ा अच्छे स्तर पर काम चलता है। लकड़ी पर नक्काशी काम चलता है, उस कला को प्रोत्साहन दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए जिस तरह से

(श्री तरुण राय कागा)

शिल्पग्राम है या कोई, किसी भी तरह से व्यवस्था करायें, यह भी बहुत ही अच्छी बात है।

मैं पर्यटन के हिसाब से, इतिहास की दृष्टि से या इस नजरिए से बात करूं तो नवीं शताब्दी में हमारे क्षेत्र में जिस तरह से कहते हैं कि आवड़ माता का जो जन्म है, हमारे जो देवियां, कुल देवियां हैं, तनोट राय है, देगराय है, भादरियाजी है, तोमड़ राय है, यह देवियों का आवड़ मूल माताजी हैं, उनकी जन्म स्थली मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन के भैरूंड़ी ग्राम पंचायत के चालकना ग्राम में है। बहुत बड़ा अच्छा स्मारक और इस तरह से कहते हैं कि जिस समय महमूद गजनवी, सोमनाथजी का मंदिर तहस-नहस करके जब लौटा था... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सीमित करें। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें आप। (व्यवधान)

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): नहीं, मैं यही निवेदन करूंगा कि वहां पर हम कई महान पुरुषों के स्मारक बनाते हैं तो चालकना माता के लिए सरकार वहां जमीन भी आबंटित कर चुकी है। हमारे लखावत साहब का भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में भ्रमण हुआ था। वह बहुत ही अच्छा रमणीक स्थान है। वहां पर भी एक स्मारक बनाया जाए, मेरी यह मांग है।

चौहटन खुद में, जिस तरह से मेरा गांव है, वहां सूइयां का मेला लगता है। जिस तरह से कहते हैं कि पांच नक्षत्रों का जब मिलान होता है तो वहां पर कुदरती एक धारा निकलती है, एक चश्मा है वहां। जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। हमारे क्षेत्र के एम.एल.ए. साहिबान भी बैठे हैं उनको ध्यान है। कहते हैं कि पांडवों ने कई सालों तक तपस्या की लेकिन नक्षत्र मिलान नहीं हुआ, वह श्राप दिया था वे पांच नक्षत्र क्या हैं? पोष-मास, सोमवार, अमावस्या तिथि मूल नक्षत्र और व्यतिपात योग, यह पांच नक्षत्र होते हैं तो यह एक धारा निकलती है। वहां हमारे कपालेश्वर, बेर माता के मंदिर भी है। 'सुराज संकल्प यात्रा' के दौरान हमारी यशस्वी माननीया मुख्य मंत्रीजी वसुन्धराजी बेर माता के स्थान पर आयी थी। बड़ा ताज्युक कर प्रशंसा की थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): वहां एक तरफ बहुत बड़ा रेत का टीला, दूसरी तरफ चौहटन का बड़ा पहाड़, बीच में वह मंदिर था, उसका नजारा देखकर आप ताज्जुब करेंगे कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें। बैठें अब आप।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, वहां उस तरह से एक पर्यटन केन्द्र खोला जाए। यह हमारी बहुत बड़ी मांग है। इस तरह से मैं कहता हूं कि हम दूर से आए हैं और बड़े आपके लिए तोहफे लाये हैं। वहां के हालात आपको बता रहे हैं। देखिए, मेरे को पानी नहीं मिला कल लेकिन यह दो चीजें कालेज और पर्यटन केन्द्र की बात करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सुरेश सिंह रावत।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति एवं मांग संख्या-47- पर्यटन की मांग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, तीर्थ राज पुष्कर के अन्दर एक महाविद्यालय संचालित है। उस महाविद्यालय के अन्दर न तो भवन है, न भूमि है और माननीय सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि जब पिछली सरकार ने उसकी घोषणा की थी तो तब एक प्रिंसिपल की नियुक्ति की। उस प्रिंसिपल ने खुद की कार में बैठ कर विद्यार्थियों के फार्म भरवाए और अभी भी वह महाविद्यालय एक सरकारी स्कूल के दो कमरों में संचालित है। स्पेशली कांग्रेस सरकार ने झूठी वाहवाही लूटने के लिए...(व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): खोली तो है। (व्यवधान)

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): परम पिता ब्रह्माजी, आप अपने पाप तो सुन लो। परम पिता ब्रह्माजी, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जो सृष्टि के रचयिता हैं, आपने तो उनको भी नहीं छोड़ा और उन्हीं का अभि-श्राप है कि आप चंद सीट्स पर निपट गये। आप दिल्ली में भी निपट गये, यह परम पिता ब्रह्माजी का श्राप था। आपने उनको भी नहीं छोड़ा। आपको पता है कि तीर्थ राज पुष्कर तीर्थों का गुरु है। आपने तीर्थ राज पुष्कर को भी नहीं छोड़ा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सीधी अपनी मांग पर आएं। समय बहुत सीमित है आपका।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी मांग पर ही आ रहा हूं कि पुष्कर के अन्दर महाविद्यालय के लिए जमीन जल्दी उपलब्ध हो और वहां एक भवन बने ताकि विद्यार्थियों को सुविधा मिल सके।

साथ ही, रूपनगढ़ एक बहुत बड़ा उप खण्ड क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा भू-भाग है। वहां पर न तो कोई निजी महाविद्यालय है और न कोई सरकारी महाविद्यालय ही है तो मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मांग करता हूं कि वहां पर एक सरकारी महाविद्यालय की घोषणा करें ताकि वहां के विद्यार्थियों को लाभ मिल सके।

साथ ही, रूपनगढ़ क्षेत्र के अन्दर मार्बल के साथ ही नमक का एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। वहां पर आई.टी.आई. अगर खोल दी जाए तो वहां के विद्यार्थियों को फायदा होगा। साथ ही, मेरे पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर करकेड़ी, नरवर, बीर, ये बहुत बड़े कस्बे हैं अगर वहां पर भी आई.टी.आई. खोलेंगे तो वहां के विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धराजी को जिन्होंने पुष्कर के महाविद्यालय के लिए तीन करोड़ रुपये की घोषणा की और जल्दी ही वहां की नगरपालिका जमीन दे देगी ताकि पुष्कर के अन्दर महाविद्यालय बन जाएगा।

साथ ही, मैं जन-जन की हृदय साम्राज्ञी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धराजी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने तीर्थ राज पुष्कर के लिए बहुत सारी बहुआयामी सौगातें दीं।

माननीय सभापति महोदय, भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदीजी ने एक अभियान चलाया कि सभी स्कूल्स के अन्दर शौचालय का निर्माण हो लेकिन, आप और हम सभी जानते हैं कि स्कूल्स के अन्दर जो पुराने शौचालय बने हुए हैं उनकी रख-रखाव, यहां तक कि स्कूल्स की भी पर्याप्त मात्रा में साफ-सफाई नहीं हो पाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जल्दी ही भर्ती करके पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के सभी विद्यालयों के अन्दर नियुक्ति करें।

मेरे पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के स्कूल्स के अन्दर काफी रिक्त पद हैं तो उन रिक्त पदों को भी जल्दी ही भरने की कृपा करें एवं स्कूल्स के अन्दर मूलभूत सुविधाओं का भी काफी अभाव है, चाहे वह फर्नीचर हो, चाहे वह बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वह पानी की व्यवस्था हो। इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से जल्दी करवाएं ताकि छात्रों को फायदा मिल सके।

(श्री सुरेश सिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे गांवों की स्थिति है, वहां पर जो सरकारी भूमि है, उस पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि जहां पर सरकारी विद्यालय में खेल की भूमि नहीं है, वहां पर आप ऐसा आदेश पारित करें कि खेल के लिए भूमि आबंटित हो जाए, नहीं तो बाद में लोग अतिक्रमण कर लेंगे और खेल के लिए भूमि नहीं बचेगी।

माननीय सभापति महोदय, आज हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल्स के अन्दर चाहे दसवीं का परिणाम हो, चाहे बारहवीं का हो, निरन्तर गिर रहा है। आज स्कूल्स के अन्दर जब हम जाते हैं कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति और नामांकन के बारे में जब जानकारी लेते हैं तो कहीं पर पांच बच्चे मिलते हैं, कहीं पर दस बच्चे मिलते हैं और कहीं पर पन्द्रह बच्चे मिलते हैं। आखिर, इसकी जवाबदेही उस स्कूल के स्टाफ पर तय हो, वहां पर जो शाला का इंचार्ज है उस पर तय हो। एक ऐसी कठोर नीति बनायें कि दसवीं और बारहवीं का परिणाम अच्छा रहे, विद्यार्थी पर्याप्त मात्रा में रहें, इसके लिए शाला इंचार्ज की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारा देश सदियों से संस्कारवान रहा है लेकिन वर्तमान काल खण्ड के अन्दर हम देखते हैं तो आज के हमारे जो विद्यार्थी हैं वह अपना पथ बदल रहे हैं, इसीलिए सरकारी स्कूल्स के अन्दर समय-समय पर संस्कार शिविरों का आयोजन होना चाहिए। योग कक्षाएं लगनी चाहिए।

प्रार्थना के बाद सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम भी रखा जाना चाहिये। हमारे भारतवर्ष में महापुरुषों की कोई कमी नहीं है, और उन्हीं की दिशा पर आज हमारा देश चल रहा है, तो उनके जो अनमोल वचन हैं, उन अमृत वचनों का भी प्रसारण होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो सैकण्डरी के विद्यालय हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से मांग करता हूं कि उनको हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, अजमेर जिला राजस्थान ही नहीं, बल्कि शिक्षा की दृष्टि से पूरे भारतवर्ष में एक अपना अलग स्थान रखता है। अजमेर सम्भाग मुख्यालय को छोड़कर पूरे राजस्थान के बाकी सम्भाग मुख्यालयों पर एक से अधिक विश्वविद्यालय हैं। चाहे वह जोधपुर हो, जोधपुर के अन्दर तीन

(श्री सुरेश सिंह रावत)

विश्वविद्यालय हैं, चाहे वह उदयपुर हो, उदयपुर के अन्दर दो विश्वविद्यालय हैं, कोटा के अन्दर तीन हैं, जयपुर के अन्दर छह हैं, बीकानेर के अन्दर तीन विश्वविद्यालय हैं लेकिन अजमेर के अन्दर एक ही विश्वविद्यालय है। मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि अजमेर के अन्दर पर्यटक विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता है। तो आज ही आप किसी न किसी एक विश्वविद्यालय की घोषणा करें।

माननीय सभापति महोदय, पुष्कर की लोक संस्कृति विश्वविख्यात है। यहां का कालबेलिया नृत्य विश्व में प्रसिद्ध है। तीर्थराज पुष्कर और आस-पास के अजमेर जिले में ऐसे बहुत सारे लोक-कलाकार हैं, उनकी कला को निखारने के लिये एक कला केन्द्र की अगर पुष्कर में स्थापना हो जाये, तो कलाकारों को काफी सुविधा रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, अजमेर पर्यटन और कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अजमेर से ही थे। उन्होंने दिल्ली में रहकर पूरे भारतवर्ष पर शासन किया। अजमेर का सामरिक दृष्टि से सदियों से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और अजमेर की जो पुरातत्व धरोहर है, दुनिया के अन्दर उसका कोई द्वितीय उदाहरण नहीं है। चाहे मुगल हो, वह भी अजमेर आये थे। चाहे अंग्रेज हो, उन्होंने शुरुआत भी अजमेर से की थी। अजमेर के अन्दर प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है। साथ ही विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर है जहां लाखों की संख्या के अन्दर प्रतिवर्ष श्रद्धालु आते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अजमेर के महत्व को देखते हुए पर्यटक जिला घोषित कराने की कृपा करें। साथ ही तीर्थराज पुष्कर के आंचल के अन्दर बहुत बड़ा नाग पहाड़ का भूभाग है, उसको पर्यटक पहाड़ क्षेत्र घोषित करने की कृपा करायें। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का किला तारागढ़, जो आज बड़ी जर्जर अवस्था के अन्दर है, उसके जीर्णोद्धार के लिये अलग से फण्ड की व्यवस्था करावें। अजयपालजी की गुफा का विकास करें। खोड़ा गणेशजी का मंदिर, रूपनगढ़, करकेड़ी, सलेमाबाद, तेजाजी का धाम, सुरसरा, बाबा रामदेवजी का धाम खुंड़ियावास, जैन समाज की तीर्थस्थली नारेली, वैद्यनाथजी का मंदिर, तीर्थराज पुष्कर का समुचित विकास करके मंदिरों को आपस में जोड़कर एक

(श्री सुरेश सिंह रावत)

पर्यटक मानचित्र बनाकर विकसित करें तो निश्चित रूप से हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा और हमारे श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी।

(समय-सूचक-समाप्ति घंटी)

साथ ही पुष्कर के अन्दर रोप-वे का कार्य भी चल रहा है लेकिन समय-समय पर वह प्रशासनिक कारणों से रुक जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री साहिबा से निवेदन करता हूं कि आप तुरन्त प्रभाव से इस रोप-वे के कार्य को पूर्ण करावें। तीर्थराज पुष्कर के अन्दर लाइट एण्ड साउंड कैफेटेरिया, होर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग के विशेष प्रोग्राम बनाये जायें तथा प्रतिमाह तीर्थराज पुष्कर में डे और नाइट सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन करने से देश और विदेश के पर्यटकों में वृद्धि होगी जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और राजस्थान को रेवेन्यू मिलेगी। आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री हीरालाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): विराजेंगे नहीं। आप बता दो, हमारा नाम हैं तो बैठें नहीं तो नहीं बैठेंगे। आप बताओ। यहां कोई भाषण सुनने के लिये थोड़े ही आते हैं। हम तो खुद बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपसे ज्ञान लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा बोलने का टाइम है तो बैठेंगे, नहीं है तो आप बता दो कितने दिन तक नहीं बोलेंगे, उतने दिन नहीं आयेंगे विधान सभा के अन्दर। इस तरह हम सुनेंगे क्या इन लोगों को, यह पढ़-पढ़कर, रट-रटकर दे रहे हैं भाषण।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। आप आपके बोलने का समय निर्धारित नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): चुनाव जीतकर आये हैं। वसुन्धराजी ने हमको कोई अपाइंटमेंट नहीं किया है यहां पर। हमारा नम्बर है क्या?

श्री सभापति: आज आपके बोलने का समय निर्धारित नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कितने दिन बाद है, वह भी बता दो। हम बात कर लेंगे। आप बता दो?

श्री सभापति: श्री हीरालालजी।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सदस्य, मेरा नाम पुकार लिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट रुको आप।

श्री हीरालाल (निवाई): आप विराजें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मेरा नाम पुकार लिया। अपन नाम राशि है दोनों। हीरालाल और हनुमान।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी ने मेरे को बोलने से रोका है और सभापतिजी, जो बार-बार मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं.... (व्यवधान)....

श्री हीरालाल (निवाई): मेरे अधिकारों का हनन तो आप कर रहे हो। (व्यवधान) मेरा नाम सभापतिजी ने बोल दिया है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अगले चुनाव में अगर नहीं हराया तो मेरा नाम भी हनुमान बेनीवाल नहीं है। वापस जीतकर नहीं आ पायेंगे यह। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सदस्य, सभापतिजी ने मेरा नाम पुकार लिया।

श्री सभापति: आप बोलें ना आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

(माननीय सदस्य, श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-24-शिक्षा, कला और संस्कृति एवं मांग संख्या-47 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा के लिये जो प्रावधान किये बजट में, वह शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम पैदा करेंगे। पिछली सरकार ने शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई भर्ती नहीं, की टीचर्स की कोई भर्ती नहीं की। उससे सरकार के सामने परेशानी आयी कि स्कूल में टीचर नहीं है। यह सब पिछली सरकार की देन है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने अभी थर्ड ग्रेड से सैकण्ड ग्रेड में अध्यापकों की पदोन्नति की, उससे शिक्षा में जो कमी थी, उसमें भी

(श्री हीरालाल)

थोड़ा योगदान मिला है। स्कूल व्याख्याता, प्रिंसिपल्स और हैड मास्टरों की भी पदोन्नति होनी है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह पदोन्नतियां हों, उस विधान सभा क्षेत्र के जो अध्यापकगण, व्याख्यातागण, हैड मास्टर्स हैं, वहां जो खाली जगह है, उनको वहां लगा दें, तो टीचर्स की काफी कमी पूरी हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में अभी जैसे पांच हजार से ज्यादा हायर सैकण्डरी स्कूल पंचायत मुख्यालय पर क्रमोन्नत किये, बल्कि पांच हजार से ज्यादा हैं, क्योंकि नई पंचायतें बनी हैं, उनमें भी होना है। उसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 6 पंचायतों पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत होने से रह गयी हैं। ये हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय लुहारा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सेदरिया, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नटवाड़ा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुनारा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बिडोली, राजकीय माध्यमिक विद्यालय ढाणी जुगलपुरा,

ये छह स्कूलें रह गयी हैं। मैंने शिक्षा मंत्रीजी को भी निवेदन किया, उन्होंने बताया इस तरह की पालिसी बनी है कि जहां निजी स्कूलें संचालित हैं वहां यह स्कूलें नहीं खोली गयी हैं। यह सही है कि निजी स्कूलें संचालित हैं, उसमें एस.सी., एस.टी., माइनोरिटी, ओ.बी.सी. के बच्चे और मध्यम वर्ग के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ें, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है और निजी स्कूलों के भरोसे भी इन बच्चों को नहीं छोड़ा जा सकता।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी से या आप अपने स्तर पर ऐसा करें कि जहां सीनियर हायर सैकण्डरी पूरे राजस्थान में क्रमोन्नत होने से रह गये हैं वहां पर एक इस तरह से पालिसी तय कर के उन बच्चों को भी लाभ मिले और निजी विद्यालयों के भरोसे इन बच्चों को नहीं छोड़ा जाए चूंकि निजी विद्यालय की फीस भी ज्यादा होती है।

रहा सवाल निजी विद्यालयों का, ऐसे विद्यालय हैं, मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को भी लिखकर दिया कि जो छह स्कूलें रह गयी हैं, जहां छह निजी विद्यालय चल रहे हैं वहां जांच तो कराएं। कहीं तो ऐसे हैं कि बंद ही हो गये,

(श्री हीरालाल)

कहीं दस बच्चे हैं और सीनियर हायर सैकण्डरी सरकार ने यह तय कर दिया कि इसमें यह नहीं मिलेगा। अगर जांच करायेंगे, उनकी वास्तविक स्थिति देखेंगे तो वे स्कूलें उस स्थिति में नहीं हैं कि बच्चे वहां पढ़ सकें। तो इसके लिए जांच करायी जानी चाहिए। उन स्कूलों में लड़कों का नामांकन कम है, तो उन स्कूलों को बंद किया जाए। पूरे राजस्थान में मैं निवेदन करूंगा माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जो बच्चे वंचित हो गये, आप इस तरह की पालिसी बनायें और उन स्कूलों को क्रमोन्नत कर दें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में पिछली सरकार ने आनन फानन में एक कालेज खोल दिया। शिक्षा मंत्री कालीचरणजी सराफ साहब जो विराजमान हैं उनको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने स्टाफ लगाया और तीन करोड़ रुपया उस राजकीय महाविद्यालय को बनाने के लिए स्वीकृत किया। इसके लिए मैं माननीय वसुन्धराजी का और माननीय कालीचरणजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। (व्यवधान) यह कांग्रेस वालों ने आनन फानन में खोला था न इसलिए इन्होंने वह थोड़ा ध्यान रखा इसके लिए बहुत-बहुत बधाई।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मेरे जिले में पिछली सरकार की गलती से 50 पैराटीचर जो योग्यता रखते हैं उनको रख दिया है और माननीय पूर्व शिक्षा मंत्रीजी, कालीचरणजी सराफ साहब को मालूम है कि वह 50 पैराटीचर रह गये हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उनकी भी कोई व्यवस्था करें। हालांकि वह रह गये हैं ...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): पीछे बैठे देवनानीजी मंत्री हैं, उच्च शिक्षा का इनसे विभाग ले लिया। पीछे वाले मंत्री देवनानीजी हैं आपके।

श्री हीरालाल (निवाई): पिछली बात बतायी है मैंने। अभी तो मुझे मालूम है देवनानीजी हैं। शिक्षा मंत्रालय का पूरा प्रभार है। (व्यवधान) अब इशारा कर रहा हूं पैराटीचर के लिए। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): यह आपको भटकाना चाह रहे हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हमारे हीरालालजी अकेले ही बहुत हैं आप सबके लिए। इतने मजबूत आदमी हैं हीरालालजी।

श्री हीरालाल (निवाई): गैदरिंग नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा मुझे तो बोलने में। मुझे तो टोकेंगे जब बोलने में आनन्द आयेगा न, फिर मैं भी बताऊं इनको। कहूंगा, मैं अपनी बात बताऊंगा, इनकी बात बताऊंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माध्यमिक और सैकण्डरी के जो 50 पैराटीचर रह गये हैं, जिन लोगों ने गलती की, जिन अधिकारियों ने गलती की उनको सज़ा मिल गयी लेकिन अब इन पैराटीचर को सज़ा नहीं दें और जो नियम में हो, इनको भी वापस लिया जाना चाहिए। (व्यवधान) आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अधिकारियों को सज़ा कहां मिली, हमें सज़ा मिली, उनको दो न सज़ा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सज़ा तो उसको मिलती है जो सज़ा के काबिल है।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, उच्च शिक्षा मंत्री बोलूं जब समझना कालीचरणजी है, इसलिए आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूं बात। शिक्षा मंत्री का मतलब है देवनानीजी। पूर्व में बोला, जो उन्होंने किया उनको मैंने धन्यवाद दिया। आप बीच-बीच में बोल रहे हैं। थोड़ा ज्ञान वृद्धि करें आप।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार समानीकरण और एकीकरण हुआ उसमें वाकई में कई जगह ऐसी थीं जो जरूरी थीं, एकीकरण, समानीकरण होना था। अभी भी कुछ ऐसी स्कूलें एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटी की जहां गांवों में बस्तियां हैं, रह गयी हैं, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी देवनानीजी से निवेदन करूंगा कि कलक्टर के स्तर पर एक समीक्षा करके, इसका एग्जामिनेशन करके जो स्कूलें मापदण्ड रखती हैं और डिजर्व करती हैं उनको आप वापस वहीं रखें, वो ज्यादा बढ़िया है। कई तो ऐसी जगह हैं जैसे बीच में नाला पड़ता है और आ नहीं सकते फिर भी हो गयी क्योंकि लड़के कम थे, मेरा आपसे निवेदन है कि उन ग्रामीण एस.सी., एस.टी., माइनोरिटी, ओ.बी.सी. के बच्चों के हित को देखते हुए उन स्कूलों का पुन: विचार करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): ये देवनानीजी हैं, देवरानीजी नहीं हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): हैं?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): यह देवनानीजी हैं, आप रानी बोल रहे हो इनको।

श्री हीरालाल (निवाई): आप ही कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता। पिछली बार जब मैं एम.एल.ए. था हम साथ-साथ बैठते थे, इतना तो मुझे मालूम है। आप ही कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता। मैंनें तो देवनानीजी ही कहा और आपके हो सकता है सुनने की कमी है तो यह कोई लगाते हैं न, लगा लो कानों में। कानों-वानों में लगा लो। (व्यवधान) आपके सुनने की कमी है तो लगा लो। देवनानीजी और मैं काफी टाइम बैठे हैं, आज वह मंत्रीजी हैं और मैं तीसरी लाइन में हूं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये तो अभी भी देवरानी सुन रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको जो कुछ कहना है, आप आसन को सम्बोधित करते हुए कहो।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं आप ही को सम्बधोत कर रहा हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: तो आप बीच में क्यों उलझते हो?

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के नहीं हैं न तो आज यह मेरा ध्यान बंटा रहे हैं। कम हैं न कांग्रेस के।

श्री सभापति: अभी आपका समय पूरा हो जाएगा, आपकी मांग रह जाएगी।

श्री हीरालाल (निवाई): दस-बीस की तो परवाह ही नहीं करता मैं। आज कम हैं तो अब यह उनकी पूर्ति कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपलू में 23-24 साल पहले सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हुई थी, वहां कालेज नहीं है। पीपलू उपखण्ड काफी पिडछ़ा हुआ है। जहां उपखण्ड है, अधिकारी बैठते हैं, सी.आई. बैठते हैं, वहां तहसील कार्यालय है, पी.एच.सी. है, सी.एच.सी. है, ए.ईएन. पी.एच.डी., ए.ईएन. आर.एस.ई.बी., ए.ईएन. पी.डब्ल्यू.डी. ये सारे बैठते हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, उच्च शिक्षा मंत्रीजी से, शिक्षा मंत्री जी अब बोल रहा हूं मैं, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी सराफ साहब से निवेदन करूंगा कि पीपलू उपखण्ड जो बहुत पिछड़ा हुआ है बैकवर्ड है और आपका तो

(श्री हीरालाल)

टोंक जिले से काफी सम्पर्क रहा है, उस पीरियड में आप पधारते रहे हैं, आपने यह भी बताया कि निजी कालेज नहीं हो, पीपलू सब खाना पूर्ति, मानदण्ड पूरे कर रहा है, आप वहां इसी सत्र में कालेज खोल दें। यह मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। (व्यवधान)

हां, पंचायत समिति नहीं बनी तो आप कालेज तो खोल दें तो मेरी भी बात रह जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, निवाई की आबादी 60-70 हजार के लगभग है, वहां राजकीय कन्या महाविद्यालय नहीं है, निवाई बहुत अच्छा कस्बा है, औद्योगिक नगरी है, धार्मिक नगरी है और रक्तांचल पर्वत के नीचे बसी हुई है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि बालिकाओं के भविष्य को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में बालिकाओं को बहुत प्राथमिकता दी है, स्कूटी की यह सारी व्यवस्था की है, मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे यहां गर्ल्स कालेज की इसी सत्र में घोषणा कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री हीरालाल (निवाई): एक मिनट बोलूंगा। आप कह दो तो मैं बैठ जाऊं।

श्री सभापति: एक मिनट की अनुमति है आपको।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, यहां पर्यटन मंत्रीजी भी विराजमान हैं। मैं मेरे निवाई की ओर उनका भी ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि निवाई में रक्तांचल पर्वत है। जहां 500-1000 साल पुराना मंदिर है। जालंधर नाथजी का मंदिर है, नाथ संप्रदाय का मंदिर है। जहां जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मछेन्द्रनाथ ने तपस्या की है, बहुत पुराना मंदिर है। मेरा पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन है कि उसको पर्यटन लिस्ट में शामिल करके जीर्णोद्धार करें तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा।

मेरे यहां जोधपुरिया में देव धाम है जहां लक्खी मेला भरता है। वह सभी लोगों की आस्था का केन्द्र है। वहां लाखों लोग आते हैं। जिस तरह से लक्खी मेला डिग्गी श्री कल्याणजी का भरता है, टोंक जिले में दो ही लक्खी मेले हैं, एक मेरे क्षेत्र में देवनारायण भगवान का है जो निवाई से 20 किलोमीटर

(श्री हीरालाल)

दूर है। उस मेले को भी पर्यटन की दृष्टि से लिया जाए, यह मेरी प्रार्थना है। मंदिर के आसपास सड़कें भी हैं, पानी की व्यवस्था है, लेकिन अगर पर्यटन स्थल में उसको शामिल कर लेंगे तो उस स्थान का और विकास होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने एक मिनट का ही टाइम दिया है। आपके आदेश की पालना करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द। जय भारत। वन्दे मातरम।

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति एवं मांग संख्या 47 पर्यटन पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, कहावत है कि शिक्षा ही सभी विकास की जननी होती है। शिक्षा ही प्रदेश और देश की पहचान बनाती है। हमारा भारतवर्ष शिक्षा की दृष्टि से विश्व विख्यात रहा है और विश्व गुरु कहलाया है। लेकिन इस विश्व विख्यात देश को कांग्रेस रूपी दीमक ने सर्वनाश करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और राइट टू एजुकेशन उन्होंने लगाया। उनका सपना, उनकी सोच तो यह थी कि इस देश का कैसे सर्वनाश करें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सदस्य, दीपक था दर्शन का।

एक माननीय सदस्य: दीमक कह रहे हैं दीमक।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): दीमक बोल रहा हूं दीमक। सभापति महोदय, लेकिन हमारे देश का, हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि इधर तो राजस्थान की मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधियाजी बनीं और देश के प्रधानमंत्री श्री, कौन बने? नरेन्द्र मोदीजी बने। उन्होंने इस पर ब्रेक लगाया। मैं उनसे बुलाना चाह रहा था लेकिन आप बीच में बोल गये।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश का कुछ भाग्य तेज था, जैसे ही हमारे प्रदेश की सेंसेटिव और विजिलेंट चीफ मिनिस्टर वसुंधराजी बनीं, इन्होंने राइट टू एजूकेशन पर ब्रेक लगाया। एक वैकल्पिक आधार बनाया कि जो भी बच्चा आठवीं में अगर बोर्ड में बैठना चाहता है तो बैठ सकता है। यह एक बहुत अच्छा निर्णय है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वैकल्पिक को भी आप परिवर्तन करके उसको नैसेसरी करें क्योंकि 100 में से 70 बच्चे गांव में पढ़ते हैं। गांव में सभी सरकारी स्कूलें होती हैं। शहर में तो प्राइवेट

(श्री हरिसिंह रावत)

स्कूलों में बच्चे पढ़कर कम्पीटिशन में आ सकते हैं लेकिन गांव के बच्चों को अपने भविष्य के बारे में क्या पता कि मैं परीक्षा दूं या नहीं दूं। न तो उनको पता होता है और न ही उनके अभिभावकों को पता होता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे शिक्षा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि इस वैकल्पिक को भी कम्पलसरी, करें ताकि बच्चे बोर्ड में कम्पीटिशन में आएं और अपना भविष्य बना सकें।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की दृष्टि से मैं 2003 से 2008 की बात करना चाहूंगा। उस समय हमारी मुख्य मंत्री वसुंधराजी सिंधिया थीं, हमारे शिक्षा मंत्री कालीचरणजी सराफ थे So I have no words in my dictionary to give him thanks और साथ-साथ ही 2003-2008 में उन्होंने भीम में राजकीय महाविद्यालय खुलवाया और फिर जैसे ही हमारा राज आया तो देवगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खुलवाया। इसके लिए मैं पुन: हमारे शिक्षा मंत्री श्री सराफ साहब और चीफ मिनिस्टर महोदया को धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही निवेदन करना चाहता हूं उच्च शिक्षा मंत्रीजी को कि आपने हमारी कालेज तो खोल दी, वहां भूमि आबंटन हो चुका है। हमारी फाइल यूडीएच सैक्रेटरी के पास आई हुई है। उसकी तत्काल वहां निर्माण कराने के लिए वित्तीय स्वीकृति निकालें ताकि हमारे कालेज का भवन बन सके और बच्चों को एक सुव्यवस्थित जगह मुहैया हो सके।

मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें 30 बीघा जमीन अलाट हो रही है, उसमें भवन के साथ-साथ प्राचार्य एवं अन्य व्याख्याताओं के रेजिडेंस क्वार्टर भी साथ-साथ दे देंगे, बाउंड्री भी साथ-साथ दे देंगे तो मैं समझता हूं कि यह हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। क्योंकि वहां पर आजकल बहुत अतिक्रमण होते हैं। अगर बाउंड्री हो जाएगी तो वहां पर पेड़-पौधे भी लग सकेंगे तथा और भी व्यवस्था हो सकेगी।

इसी के अनुरूप भीम राजकीय महाविद्यालय में भी बाउंड्री की कमी है। उच्च शिक्षा मंत्रीजी आपसे निवेदन है कि वहां पर भी बाउंड्री की सैंक्शन दे दें। अगर स्टाफ क्वार्टर्स की सैंक्शन भी वहां पर दे देंगे तो वहां पढ़ाने वाले प्राचार्य और शिक्षकों को भी सुविधा हो जाएगी। इसके साथ ही वहां पर अगर जगह को आप प्लेन कर देंगे तो बच्चों के लिए खेलकूद की भी व्यवस्था हो सकेगी।

(श्री हरिसिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि देवगढ़ महाविद्यालय में प्राचार्य और एक ही व्याख्याता है। जो 5 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हुए हैं, उनको भी आने वाले सत्र तक तो कम से कम भर दें ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। उनको अच्छी शिक्षा मिल सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में बात करना चाहूंगा, हमारे शिक्षा राज्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शिक्षा को मजबूत करने के लिए सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी स्कूल पंचायत मुख्यालयों पर खोले। इसके अलावा जितनी भी प्राचार्य और व्याख्याता की पोस्टें हैं, जो सृजित पदों के हिसाब से रिक्त चल रही हैं, उनको भी आप तत्काल भरें तो बच्चों के भविष्य के लिए भी एक अच्छी पहल होगी।

इसके साथ ही सीनियर सैकण्डरी स्कूलों को आपने क्रमोन्नत कर दिया है, लेकिन वहां बच्चों के बैठने की व्यवस्था कम है इसलिए कक्षा कक्षों की भी आप साथ ही साथ घोषणा कर देंगे तो मैं समझता हूं कि यह भी बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। पेयजल और शौचालयों की व्यवस्था भी काफी स्कूलों में नहीं है। शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर भी आप गौर फरमायें। जिन स्कूलों में पानी की और शौचालयों की व्यवस्था नहीं है उसको आप तत्काल पूर्ण करें, क्योंकि इसमें बच्चियों को ज्यादा परेशानी रहती है। मैं कई जगह देखता हूं कि गांवों में बच्चियां इसीलिए स्कूल नहीं जा पाती हैं कि वहां शौचालय नहीं है। इसके लिए हमारी केन्द्र सरकार ने भी एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और अगर उसी के अनुरूप हमारी स्कूलों में व्यवस्था हो जाएगी तो यह अच्छा रहेगा।

दूसरा, मेरे जिले राजसमन्द में सैकण्ड और थर्ड ग्रेड के शिक्षकों की काफी कमी है। मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि भीम में सैकण्ड ग्रेड की 14 और थर्ड ग्रेड की 131, देवगढ़ में सैकण्ड ग्रेड 29 और थर्ड ग्रेड 162, आमेट में सैकण्ड ग्रेड 28 और थर्ड ग्रेड 160, कुम्भलगढ़ में सैकण्ड ग्रेड 41 और थर्ड ग्रेड 195 खाली हैं, रेलमगरा में सैकण्ड ग्रेड की 15, थर्ड ग्रेड 16, राजसमन्द सैकण्ड ग्रेड 26, थर्ड ग्रेड 165, खमनौर सैकण्ड ग्रेड 52, थर्ड ग्रेड 160 और टोटल इस प्रकार, 205 और 1033 पोस्टें हमारे खाली चल रही हैं इस

(श्री हरिसिंह रावत)

वक्त। शिक्षा मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल इन पोस्टों को भरने की कृपा करें ताकि हमारे बच्चों की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो सके। साथ-साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत कराने हैं, जिसमें करीबन 11 स्कूलें हैं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धोलाजी खेड़ा जो जीरण पंचायत में आता है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चिथड़ली जो स्वादड़दी में आता है, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, ताल, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालसिंह काकूड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नींझर, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, लसानी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, शक्करगढ़, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, देवगढ़, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पातनियाकी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पानड़ी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय साधुखेड़ा, ये स्कूलें मेरी देवगढ़ में हैं जिनको क्रमोन्नत करना है।

इसी प्रकार नवीन स्कूल, पालूण्डिया, स्वादड़ी, तालाका क्वाथल, माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार मेरे भीम में भी करीब 11 स्कूलों की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से राजकीय माध्यमिक विद्यालय की जरूरत है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धर्रा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हाटावाला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयनगर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हमालकी मेद, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालातीकंवार, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोदाजी गांव, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जारपा रूपारेल, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कालाखेड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पालरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नन्दावत, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिका, नन्दावत, इस प्रकार ये 11 स्कूलें मेरे क्षेत्र में खोलनी हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रावत समाज एक मार्शल कौम रही है और मेरे क्षेत्र में हमारे रावत समाज के लोग हर परिवार से एक-एक, दो-दो सेना में भर्ती हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे वहां एक सैनिक स्कूल खोलते हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य भी उज्ज्वल बनेगा और इस ओर आप विशेष गौर करें।

(श्री हरिसिंह रावत)

कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो हमारे सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से चल रही है, उसमें 6 से 14 साल की बच्चियां जो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं या उसमें वह बच्चियां पढ़ती हैं जो या तो बीपीएल परिवार की हैं या एससी एसटी परिवार से होती हैं या जिनके मां-बाप कोई भी नहीं होता है तो ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आठवीं की जगह उसको बारहवीं तक क्रमोन्नत करें तो मैं समझता हूं कि उन बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा। आज स्थिति क्या होती है माननीय सभापति महोदय, कि आठवीं के बाद वह बच्ची अपने घर चली जाती है। न उसके परिवार के सदस्य उसको पढ़ा सकता है, लिखा सकता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस आठवीं तक को अगर बारहवीं तक करें तो मैं समझता हूं कि बच्चों का भविष्य सुधरेगा और बच्चियां अपने खुद के जीविकोपार्जन का साधन ढूंढ सकती हैं। तो इनको क्रमोन्नत किया जाए।

विद्यार्थी मित्रों की मैं बात करना चाहूंगा। मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने बोला भी था, विद्यार्थी मित्रों का हमने लास्ट टाइम 2003-2008 में लिया था लेकिन अभी उनको करीब पांच-छह महीने हो गए, वह बेरोजगार हो रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यार्थी मित्रों को पुन: लिया जाए। शिक्षाकर्मी स्कूल जो हमारी सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं उसको भी क्रमोन्नत करके प्राथमिक विद्यालय में जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे स्कूलों का भविष्य भी सुधरेगा और बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा।

मेरे क्षेत्र भीम और देवगढ़ में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की भी एक महती आवश्यकता है। आज युवा पीढ़ी पढ़ाई के बाद हर व्यक्ति न शिक्षा ग्रहण कर सकता है और न पढ़-लिखकर अपना कोई रोजगार कर सकता है तो आईटीआई का सैंटर खुलेगा तो कम से कम युवा बेरोजगार प्रशिक्षण लेकर खुद अपनी नौकरी में भी सक्षम हो सकेगा या अपना खुद का रोजगार भी वह ढूंढ सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भीम और देवगढ़ में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं।

पर्यटन के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं पर्यटन की दृष्टि से भी मेवाड़ हमारा अव्वल रहा है, जिसमें सभी धर्म स्थलों पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने काफी कुछ दिया है लेकिन मेरा निवेदन है कि चार भुजा धाम, जिस ढंग से

(श्री हरिसिंह रावत)

परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ था, उस चार भुजा धाम का विकास करने की भी एक विशेष योजना बनाई जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर भी गौर फरमायें। आपको याद होना चाहिए कि महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में, माननीय सभापति महोदय, वह युद्ध अनिर्णीत युद्ध था लेकिन उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी फौज का पुन: संकलन किया और दिवेर में युद्ध लड़ा जहां महाराणा प्रताप की विजय हुई और उसी विजय स्मारक पर हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2005-2006 में साढ़े छह करोड़ रुपए लगाकर एक युद्ध स्थल और एक स्टेच्यू का निर्माण किया और उसी के जीर्णोद्धार के लिए मैं पर्यटन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर उससे सम्बन्धित कुछ जगहें बाकी रह गई हैं जैसे मनक्या वास, धमधम रोडी, गोकुलगढ़, गोर आदि वंचित रह गए हैं उनका भी वहां पर विकास किया जाए और साथ-साथ ही मेवा का मथारा, जहां महाराणा प्रताप की स्टेच्यू लगी हुई है और बैटल फील्ड तक अगर रोप वे की व्यवस्था कर दी जाए तो पर्यटकों को वहां आकर्षित करने का बहुत अच्छा जरिया होगा। वन विभाग के माध्यम से भी हमने एक पाथ वे बनाया था और उस पाथ वे पर अगर होर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग की व्यवस्था भी कर दी जाए तो पर्यटकों के वहां बहुत अच्छी आने की व्यवस्था होगी। उड़ेसर महादेव है, यह भी बहुत बड़ी नाल है और उड़ेसर वहां पर जो बैटल फील्ड बना हुआ है वहां तक एक नाल बनी हुई है अगर वहां भी 150 मीटर का बांध बना दिया जाए तो मैं समझता हूं कि पर्यटक जो भी आएंगे तो उनके लिए बोटिंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकेगी और वहां बहुत हरियाली भी हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर भी विशेष ध्यान दें और सर्वे कराएं ताकि वहां का विकास हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपने पन्ना धाय का नाम तो सुना होगा, जब चित्तौड़ का नाम आता है तो पन्ना धाय का नाम भी सबके मानस पटल पर आता है। माननीय सभापति महोदय, उस पन्ना धाय का ससुराल भी मेरे क्षेत्र में ही है जो भीम की कमेरी के नाम से प्रख्यात है और वहां पर भी आरटीडीसी के माध्यम से पांच बीघा जमीन अलाट हो गई है लेकिन वहां पर भी ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यटन की दृष्टि से भी वहां पर कोई स्टेच्यू और

(श्री हरिसिंह रावत)

कोई निर्माण कार्य करके उसको भी इतिहास के पृष्ठों में आप रखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी।

माननीय सभापति महोदय, आपको ध्यान होना चाहिए कि महाराणा कुम्भा की जन्म स्थली भी मेरे क्षेत्र मदारिया में ही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि महाराणा कुम्भा का जो महल है वह भी जीर्ण-शीर्ण हो गया है उसका भी वापस आप पुरातत्व विभाग से सर्वे करवाकर पूर्ण उद्धार करावें ताकि पर्यटन का यह भी एक बहुत बड़ा वहां साधन होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत, जय जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सलूम्बर का राजकीय महाविद्यालय 1991 में बना था, 24 वर्ष हो गए। मेरा निवेदन है कि इस जनजाति क्षेत्र में मात्र बीए तक का कालेज है, 2000 से अधिक छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं और उसको पीजी कालेज में अगर क्रमोन्नत करने का विचार रखते हैं तो मेरे क्षेत्र को काफी फायदा होगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र पूरा टीएसपी एरिया है।

(18.00 बजे)

दो उपखण्ड क्षेत्र हैं सलूम्बर और सराड़ा। तीन तहसीलों में मेरा विधान सभा क्षेत्र है और तीन उप तहसीलों में करीब 7 पुलिस थाने हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सभापतिजी, चिकित्सा मंत्रीजी ने अभी कुछ मंत्रियों को स्वाइन फ्लू थैरेपी इनहेलर यहां वितरित किये, लेकिन इतना भेदभाव रख रहे हैं कि सबको देना चाहिए। जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, मेरे खयाल से गोविन्द सिंहजी डोटासरा भी मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे कि सबको देना चाहिए। यह स्वाइन फ्लू थैरेपी इनहेलर सबको नहीं दिया। मंत्रियों में भेदभाव किया। मंत्री क्यों, यह तो सबको देना चाहिए, सारे मैम्बर्स को देना चाहिए। इसलिए माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से मांग करते हैं कि सबको यह इनहेलर दें।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, आप स्पष्टीकरण भी दें और सबको वितरित भी कराएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं तो संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आसन से बिलकुल बंधा हुआ हूं, आसन की आज्ञा की पालना करना मेरा फर्ज भी है, मेरा दायित्व भी है, मेरा धर्म भी है। आसन जो आज्ञा करेगा उसकी पालना करूंगा सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय की इच्छा पूरी कर दें आप।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र पूरा जनजातीय क्षेत्र है, टीएसपी एरिया है और उपखण्ड तहसील, 7 पुलिस थाने व 10 पुलिस चौकियां हैं। एक्सईएन लेवल के सारे अधिकारी सलूम्बर क्षेत्र में हैं, लेकिन पीजी कालेज नहीं होने की वजह से वहां के विद्यार्थी दूरदराज जाते हैं, कई तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इतने गरीब होने की वजह से उदयपुर नहीं आ सकते। वहां से डूंगरपुर, बांसवाड़ा या चित्तौड़ जाना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि इसी सत्र में सलूम्बर हाडा रानी का जो कालेज है वह स्नातकोत्तर में तब्दील किया जाय।

दूसरा सराड़ा उपखण्ड है, 4 पुलिस थाने हैं, 2 तहसीलें हैं। वहां भी अभी हाल में राजकीय महाविद्यालय खुला है। वहां भवन नहीं है, जमीन अभी आबंटित हुई है। उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि जल्दी से माननीय सैक्रेट्री साहब के पास फाइल आयी हुई है, रुपये रिलीज करके जल्दी भवन, खेल मैदान, फुटबाल मैदान, क्रिकेट, उस कालेज की संरचना के लिए आदेश करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह कई कारणों से विकसित है। भीम से आने वाले माननीय सदस्य, हमारे सीनियर विधायक कह रहे थे कि महाराणा प्रताप का प्रथम युद्ध और अंतिम युद्ध, महाराणा प्रताप की तृतीय राजधानी चावण्ड रही जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। वहीं उन्होंने हर क्षेत्र का सामना किया और अंतिम सांस भी महाराणा प्रताप ने चावण्ड भूमि में ली। उनका वहां समाधि स्थल है, स्टेच्यू भी है। मेरा पर्यटन मंत्री से निवेदन है कि आपके विभाग के आप अच्छे ज्ञाता हैं, पर्यटकों को अच्छी तरह समझती हैं। सभापति महोदय, हाडा रानी जिन्होंने अपने पति की आन-बान और शान को सही तरीके से रखने के लिए अपना सिर कटाकर थाली में रख

(श्री अमृतलाल)

दिया था वह महल सलूम्बर के मध्य स्थित है। इससे 30 किलोमीटर दूर महाराणा प्रताप की समाधि स्थल और स्मारक है। वहीं से 20 किलोमीटर दूर विश्वविख्यात मीठे पानी की जयसमन्द झील है जिसमें रूठी रानी का महल, हवामहल है। अगर रूठी रानी व हवामहल को रोप वे से जोड़ा जाता है तो पर्यटन की दृष्टि से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि मेवाड़ कई योद्धाओं और महाराजा, महारानियों से विख्यात है। हाडा रानी कहो, महाराणा प्रताप की भूमि कहो, महाराणा पुंजा की भूमि कहो, रानी पद्मिनी कहो, मीरा बाई का देश कहो, पन्नाधाय का देश कहो, यह सारा मेवाड़ क्षेत्र में ही है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि सलूम्बर के लिए जो बातें कहीं, आपने बोलने का समय दिया, विशेषकर पुन: उच्च शिक्षा मंत्रीजी से सभापति महोदय, आपके द्वारा करबद्ध निवेदन है कि मेरे यहां कालेज मात्र है जनजातीय क्षेत्र में, इसके पीछे कई कालेज, खैरवाड़ा का कालेज पीजी तक हो गयी, सागवाड़ा का कालेज हो गया, अन्य क्षेत्रों में बाद में खुले वे कालेजेज सारे पीजी हो गये, लेकिन सलूम्बर का हाड़ा रानी का कालेज बीए तक ही रहा, उसको पीजी में इसको क्रमोन्नत करें। धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, कला और संस्कृति मांग संख्या 24 और पर्यटन-47 पर आज यहां चर्चा हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज आपने मुझे बोलने का समय दिया। बिना किसी भूमिका के सीधे-सीधे कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी मैं यहां पर रखना चाहूंगी। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सीएम साहिबा ने कुछ ही नहीं बल्कि बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करके राजस्थान को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। उन सभी कामों के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात को रामगंजमण्डी से शुरू करना चाहूंगी। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं बिलकुल खनन क्षेत्र है। श्रमिक वहां पर निवास करते हैं। मैं बड़े विश्वास के साथ बोल सकती हूं कि वहां का श्रमिक न तो अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता, इतनी गरीब स्थिति में हमारा मजदूर भाई बैठा हुआ हैं, लेकिन विगत 6 वर्षों से देख रही हूं कि जो स्कूलों के हालात हैं, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

माध्यमिक हो, चाहे हमारे सीनियर सैकण्डरी स्कूल हो और चाहे महाविद्यालय हो, भले ही हमारा संस्कृत महाविद्यालय क्यों न हो, जो हालत वहां बने हुए हैं उन हालातों को देखकर लगातार हमारे छात्र-छात्राओं को वर्तमान में मेरे खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अगर हम राजकीय महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय और रामगंजमण्डी के स्कूल हैं उनके स्टाफ की पूर्ति करेंगे, वहां पर अध्यापक लगाएंगे तो मुझे लगता है कि हम वहां की जनता के साथ न्याय कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से मेरा जुड़ाव है और पूरे कोटा जिले की स्थिति का मैं आकलन करना चाहूंगी कि वर्तमान में परीक्षा के नाम पर पूरे कोटा जिले से, ग्रामीण से न जाने कितने अध्यापकों को शहर में लगाकर बिठा दिया।

यह बड़ी शर्म की बात है। मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि क्या हम नहीं चाहते कि स्कूल में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हुआ बालक है उसको भी शिक्षा मिले। टीचर्स शहर में आकर बैठ गये, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी उनकी परीक्षाएं आने वाली हैं, उनके एग्जाम चल रहे हैं। यह स्थिति वर्तमान में पूरे कोटा जिले की बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि जब मैं गांवों में जाती हूं और कभी-कभार मुझे अचानक जाने का मौका मिला तो मैंने ऐसे टीचर्स देखे हैं जो उस स्कूल से 3-3 साल से गायब हैं और वो पेमेंट उठा रहे हैं। चाहे मोडक के अध्यापक हों चाहे और किसी क्षेत्र के हों, उन लोगों ने जब जोइन किया उस समय उस स्कूल की शक्ल देखी होगी लेकिन उसके बाद उन्हें मालूम नहीं है कि स्कूल कहां हैं और वर्तमान में वो लोग कहां रह रहे हैं लेकिन फिर भी उनको पेमेंट मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे अध्यापकों के खिलाफ भी हम लोग कार्यवाही करें ताकि वहां की जनता के साथ हम न्याय कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, जो विद्यार्थी मित्र थे उन्हें वापस लेने की माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने घोषणा की, उनका नाम भी परिवर्तन किया इस बात के लिए मैं तहेदिल से और मन से धन्यवाद देती हूं। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं उन्हें विद्यार्थी मित्रों द्वारा इतनी अच्छी सेवायें दी जाती हैं और वही उन स्कूलों को सम्भालते हैं। आज हमारे स्कूलों में यह हालत है कि कोई ताला खोलने वाला नहीं है और अनेकों स्कूल हमारे वहां पर ऐसे हैं। मैं तो कहूंगी कि अगर पूरी डिटेल भी माननीय मंत्रीजी लेना चाहें तो

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मैं उनको दे सकती हूं। आप देखिये कि वरिष्ठ अध्यापक के 33 पद रिक्त हैं, 115 पोस्टें अध्यापक की रिक्त हैं तो इस प्रकार 150 पोस्टें तो यहीं पर रिक्त हैं। यह मैं एक ब्लाक का बता रही हूं, लाडपुरा को छोड़कर मात्र खैराबाद का। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक जो प्लान में हैं उनकी भी 7 पोस्टें रिक्त हैं, एस.एस.ए. में 80 पोस्टें रिक्त हैं, 45 पोस्टें पंचायती राज में रिक्त हैं। इसके अलावा टोटल में मैं आपको बताऊंगी तो पूरे पद हमारे वहां पर खाली पड़े हुए हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इनको भी भरें। मैं तो यहां तक कहूंगी कि शहरों में प्रतिनियुक्ति पर लगाते हैं लेकिन देहात में प्रतिनियुक्ति पर लगाकर अगर इन स्कूलों में हम व्यवस्था करेंगे तो मैं मानूंगी कि उन बच्चों के साथ कुछ अच्छा किया है और उनको हम शिक्षा दे पायेंगे।

अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोटा में एक छात्रावास भवन बनाने की घोषणा की उस बात के लिए धन्यवाद देती हूं। कोटा के अन्दर इतना बड़ा समुदाय रहता है और अगर ऐसा छात्रावास आप वहां पर बना रहे हो तो मुझे लगता है उन लोगों को इतना फायदा मिलेगा कि वो लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। मैं तो कहूंगी कि अगर इस छात्रावास को आप रामगंजमण्डी, खैराबाद में बनाओगे क्योंकि वहां पर मुसलिम समाज बहुत बड़ी संख्या में रहता है तो उनको और ज्यादा फायदा मिलेगा। एक बात और कहना चाहूंगी कि जो जीरो रिजल्ट देने वाले हमारे अध्यापक हैं उन्हें हम जिले से बाहर भेजें। आप देखिये कि बोराबास मेरी एक ऐसी पंचायत है जहां का जीरो रिजल्ट रहा है। शहर के नजदीक का स्कूल है, वहां पर 15-15 टीचर हैं 300 बच्चे हैं और वहां का जीरो रिजल्ट रहा है, पर उनके खिलाफ हमने कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए मैं तो कहूंगी कि उनके खिलाफ हम लोगों को कार्यवाही करनी चाहिए और थोड़ी बहुत सज़ा हमने दी तो उनको लगेगा कि हम आगे से स्कूल में टाइम से आएं, टाइम से बच्चों को पढ़ाएं, यह मेरा आपसे निवेदन है।

(18.14 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्षजी, रामगंजमण्डी कालेज में विज्ञान संकाय की बहुत आवश्यकता है। अगर यह सब्जैक्ट आप खोलेंगे तो बहुत अच्छा फायदा वहां के स्टूडेंट्स को मिलेगा।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

एक बात तकनीकी शिक्षा की भी मैं कहना चाहूंगी। तकनीकी शिक्षा में हम लोग कौशल विकास की बात कर रहे हैं। स्किल डवलपमेंट के लिए माननीय मोदीजी भी लगे हुए हैं और हमारी सी.एम. साहिबा ने भी बहुत बड़ी घोषणा की है। हम लोग अगर इस काम को करना चाहते हैं तो निश्चित है कि हमें तकनीकी शिक्षा में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करना पड़ेगा। परिवर्तन करें या नहीं, लेकिन तकनीकी शिक्षा के जितने भी कर्मचारियों, अधिकारियों के पद खाली हैं उन्हें हमें भरना पड़ेगा। मुझे पूरे कोटा जिले का मालूम है, पांचों ब्लाक में हमारी आई.टी.आई. हैं उन सब में सारे पद रिक्त हैं। चाहे हम अधिकारियों को लें, चाहे हम छोटे कर्मचारियों को लें तो सारे पद खाली हैं। फिर हम लोग स्किल डवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके बिना यह कतई सम्भव नहीं है, ये पद हमें भरने ही पड़ेंगे। दूसरी मांग मैं करना चाहूंगी....

श्री अध्यक्ष: अब शार्ट में कर लीजिये और सीधी-सीधी मांग कर लीजिये। कर लो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): सीधी-सीधी मांग कर रही हूं साहब। सैण्ट्रलाइज एडमिशन की बात है उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि काउंसलिंग के द्वारा ही हम लोग प्राइवेट सैक्टर में भी और जो हमारी सरकारी आई.टी.आई. है उसमें भी एडमिशन लेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरा निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी निजी आई.टी.आई. जितनी भी पूरे राजस्थान में हैं उनके ऊपर हमारा कोई अंकुश नहीं है। वो लोग सब-कुछ मनमर्जी से करते हैं। हमारे पास इतने केसेज आते हैं कि किसी की फीस तो ले ली पर उसे एग्जाम में नहीं बिठाया और दो-दो, तीन-तीन साल तक वो चक्कर काटता रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार का इसके ऊपर कहीं न कहीं अंकुश हो। हम लोग जो भी हमारे आई.टी.आई. के अधिकारी हैं उनसे हमेशा उनकी विजिट करवाएं तो मुझे लगता है कि यह भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरा निवेदन करना चाहूंगी कि...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। सिर्फ एक मिनट।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): शार्ट में ही करती हूं। आई.टी.आई. में दसवीं पास विद्यार्थी जाता है और उस दसवीं पास विद्यार्थी को शायद यह भी मालूम नहीं होता होगा कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। जो शायद मुझे लगता है कि इस वर्ष हुआ और जो मेरी जानकारी में है। उस

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मार्किंग की वजह से आप देखें कि सारे बच्चे फेल हो गये हैं। वो लोग जानते ही नहीं हैं कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है और हम दसवीं पास बच्चे को वहां आई.टी.आई. में भेज रहे हैं तो यह भी हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। कोटा के बच्चे मेरे पास आये थे और इतने बच्चे फेल हुए कि वो रो-रो कर परेशान थे। सरकारी आई.टी.आई. में गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं और वो कैसे पैसे का जुगाड़ करते हैं, कैसे फीस जमा कराते हैं तो यह भी हम लोगों को परिवर्तन लाने की जरूरत है। मैं दूसरी एक बात और कहना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। श्री संदीप शर्मा। नहीं, नहीं, 10 मिनट आपने ले ली है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): दो मिनट का समय पर्यटन पर दें साहब। हाड़ौती में इतनी प्रबल सम्भावनाएं हैं पर्यटन की। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप लिखकर दे दो सारी सम्भावनाएं। श्री संदीप शर्मा। समय का ध्यान रखें। फिर मंत्रियों के उत्तर आएंगे।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा के बारे में बोलना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में शिक्षा के साथ-साथ राज्य में कला एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्कूली शिक्षा के लिए 21788 करोड़ 97 लाख रुपये का प्रावधान किया जो वर्ष 2014-15 से 16 प्रतिशत अधिक है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं सीधे-सीधे कोटा में आई.आई.टी., ट्रिपल आई.टी. के विषय में बात करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे, सीधे-सीधे करो आप।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, कोटा में राज्य सरकार द्वारा चार वर्ष पूर्व आई.आई.टी. की स्थापना की घोषणा की थी लेकिन चार वर्ष हो चुके पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और कोई प्रयास नहीं हुए हैं। हमारा कोटा पूरे देश में शैक्षणिक नगरी के रूप में जाना जाता है और पूरे देश से, पूरे प्रदेश से कोटा में विद्यार्थी पढ़ने आते हैं परन्तु आई.आई.टी. का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो भी अभी तक कम्पलीट

(श्री संदीप शर्मा)

नहीं हुआ है और जहां तक मुझे जानकारी है हालांकि वहां पर बाउण्डरी वाल का काम हो चुका है और एक चौकीदार कक्ष बन चुका है। लेकिन आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी से मांग है कि वहां शीघ्र अध्ययन के लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाए और भवन निर्माण की व्यवस्था जल्दी से जल्दी ट्रिपल आई.टी. के लिए की जाए।

कोटा में तीन नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई है उसके लिए मैं आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। परन्तु इन महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भवन का निर्माण नहीं हुआ है, न ही शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुचारु रूप से हो सका है इसलिए भवन निर्माण एवं स्टाफ की नियुक्ति की जानी आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान देश के पिछड़े राज्यों में शामिल है इस कारण यहां आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार बड़ी संख्या में निवास करते हैं जो कि अपने बच्चों को उच्च तकनीकी शिक्षा दिलवाने में असमर्थ हैं। राजस्थान विधान सभा में दिनांक 22 मार्च, 2007 को तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी द्वारा बताया गया था कि राजस्थान में 4 नये अभियांत्रिकी महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में खोले जा रहे हैं उनमें से एक झालावाड़ में प्रस्तावित था।....

वर्तमान में राजस्थान में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की फीस निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के बराबर ली जाती है, जो बी.टेक में 60,000/- एवं एमबीए में लगभग 49,400/- प्रतिवर्ष है। यहां यह आवश्यक होगा कि दिनांक 25.11.2013 को हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ने कोटा के युवाओं से सीधा संवाद कर उन्हें बताया था कि राजस्थान में 10 राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय हैं, जबकि गुजरात में 19 राजकीय महाविद्यालय हैं। गुजरात में फीस मात्र 1,500/- रुपये है। राजस्थान में राज्य पोषित सीटों पर फीस बी.टेक. एवं एमबीए के लिए 30,000/- है जो कि गुजरात के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की फीस से 20 गुना अधिक है। वर्तमान में इन राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में बी.टेक. में 600 सीटें तथा एमबीए में 250 सीटें रिक्त हैं। इसके पीछे सीधा सा कारण इन महाविद्यालयों में फीस का अधिक होना है। राजस्थान में आवश्यक है कि हम भी इस फीस के ऊपर जो निर्धारित हमारे मापदण्ड हैं, उनको भी गुजरात की तर्ज पर करके अपनी फीस को कम करें।

(श्री संदीप शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद एवं जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में नहीं आता है तो यह सर्वविदित है कि यद्यपि जनसंख्या एवं भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश विश्व के कई देशों से बड़ा भी है। ये दोनों आंकड़े एक-दूसरे के विपरीत क्यों हैं? इस पर गहन चिंतन और मनन की आवश्यकता है क्योंकि यदि हम इतनी बड़ी जनसंख्या समूह और युवा साथियों के प्रदेश होने के बाद भी विकास नहीं कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता अभी भी काफी हद तक है।

माननीय प्रधान मंत्रीजी एवं माननीया मुख्य मंत्री महोदया का विजन बिलकुल क्लियर है और वे चाहते हैं कि देश में हर हाथ को काम मिले और इस क्रम में प्रदेश में कौशल दक्षता प्रशिक्षण के क्रम में काफी काम भी हुआ है। इसी कड़ी में एक बड़ी आवश्यकता प्रदेश में कौशल दक्षता प्रशिक्षण विश्वविद्यालय प्रारम्भ करने की है जिससे इस मिशन को साकार करने में मदद मिले।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि राजस्थान में जन साधारण के समग्र आर्थिक एवं बौद्धिक विकास हेतु कौशल दक्षता प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना मेरे विधान सभा क्षेत्र में की जाये। कोटा शैक्षणिक नगरी होने के कारण यहां एजुकेशन हब की स्थापना की जाये। यदि यहां पर स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है तो पूरे राज्य के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में यद्यपि अग्रणी प्रदेशों में है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा आईआईटी, एआईपीएमटी, मेडिकल एवं अन्य एन्ट्रेंस एग्जाम के विषय में भी राजस्थान ने देश भर में ख्याति प्राप्त की है। यद्यपि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान प्रदेश अच्छे कार्य कर रहा है। यहां के मंगल मिशन मंगलयान से भी राजस्थान से शिक्षा प्राप्त इंजीनियर जुड़े हैं। इससे प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में तकनीकी शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है।

प्रदेश में बढ़ते निजी एवं सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों के व्याख्याताओं का कोई औपचारिक प्रशिक्षण केन्द्र न होने के कारण तकनीकी

(श्री संदीप शर्मा)

शिक्षा के स्तर में सुधार होने की सम्भावना नगण्य है क्योंकि व्याख्याता समुचित प्रशिक्षित होगा तो ही विद्यार्थी को इंजीनियर बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास कर पायेगा। देश की सर्वोच्च तकनीकी संस्था एआईसीआईटीआई, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुसार प्रत्येक इंजीनियरिंग कालेज के व्याख्याता, सहायक आचार्य को तकनीकी एवं शैक्षणिक दक्षता के लिए प्रत्येक वर्ष एक या दो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाना आवश्यक दर्शाया गया है परन्तु राज्य के अधिकांश व्याख्याताओं द्वारा इसकी पालना की जाती है, यह किसी भी प्रकार परिलक्षित नहीं किया जाता और ना ही निजी महाविद्यालय संचालकों द्वारा कोई ध्यान दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमारे माननीय पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी के नाम पर एक स्टेट लेवल टैक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाये, जो कि पूरे राजस्थान के तकनीकी विद्यालयों के व्याख्याताओं को न सिर्फ प्रशिक्षण कार्यक्रम करायें, तथापि उनकी परफोर्मेन्स पर भी नजर रख सके ताकि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता आ सके।

अध्यक्ष महोदय, राज्य में बेरोजगारी काफी बढ़ रही है और राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम में तकनीकी शिक्षा का अभाव है। अध्यक्ष महोदय, यदि स्कूली स्तर पर विद्यार्थी को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाये तो इन्हें तकनीकी ज्ञान में दक्ष कर स्वरोजगार की योजना से जोड़ा जा सकता है जिससे बेरोजगारी पर काफी हद तक अंकुश लग पायेगा।

अध्यक्ष महोदय, राज्य में तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ छात्रों का समग्र विकास किये जाने की आवश्यकता है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में बच्चों के चारित्रिक विकास, शारीरिक विकास के लिए विशेष प्रयास किया जाना नितान्त आवश्यक है जिससे बच्चे राष्ट्र के उत्थान में अपनी महती भूमिका निभा सके।

अध्यक्ष महोदय, बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य, चारित्रिक विकास के लिए योग, प्राणायाम को पाठ्यक्रम में जोड़कर इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाये जिससे बालक-बालिकाएं प्रारम्भिक अवस्था में ही मजबूत मनोबल एवं स्वच्छ मानसिकता से परिपूर्ण होकर समाज में अपनी विशेष छाप बना सकें।

(श्री संदीप शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, सीबीएसई और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों के ज्ञान के स्तर में काफी अंतर देखने को मिलता है। सीबीएसई में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के पास अपने कुशल अंग्रेजी ज्ञान के कारण रोजगार के काफी अवसर रहते हैं जबकि सरकारी विद्यालयों के हिन्दी मीडियम में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं इसमें काफी पीछे हैं।

अध्यक्ष महोदय, संविधान ने हम सबको समानता का अधिकार दिया है। समाज के सभी वर्गों के लिए कानून व्यवस्था समान है तो शिक्षा की व्यवस्था भी समान होनी चाहिये। इसलिए आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को सीबीएसई के तुल्य किया जाये एवं एक पाठ्यक्रम वैकल्पिक चलाया जाये जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय चयन कर सके।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): बस एक मिनट साहब।

श्री अध्यक्ष: हां, एक मिनट।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में हाड़ौती सम्भाग के किसी भी राजकीय महाविद्यालय में भूगर्भ शास्त्र विषय नहीं है। इस विषय के प्रारम्भ होने से कोटा सम्भाग में छात्र हित में व्यापक रूप से रोजगार की नई सम्भावनाएं निर्मित होंगी। कोटा सम्भाग में भूगर्भ शास्त्र विषय से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे कि कोटा स्टोन उद्योग, सिलिकासैण्ड उद्योग, सीमेंट उद्योग व अन्य खनिज उद्योगों में रोजगार की अपार सम्भावना है जिसको देखते हुए छात्रों को इस विषय का ज्ञान प्रदान करवाने हेतु भूगर्भ शास्त्र विषय आरम्भ किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित कई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य विषय नहीं है। साथ ही व्याख्याताओं की भी कमी है। पूरे देश में औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है और राज्य के अग्रणी जिलों में शामिल है। इसलिए यहां राजकीय विद्यालयों में वाणिज्य और विज्ञान विषयों की नियमित व्यवस्था होनी चाहिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे। अब माननीय मंत्री महोदय अपने क्रम से, उच्च शिक्षा मंत्री श्री कालीचरण सराफ बहस का जवाब देंगे।

(माननीय सदस्यगण सर्वश्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) एवं भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) के लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखे जाने की अनुमति आसन द्वारा प्रदान की गयी)

(लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से सदन में मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्यों ने उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा के 84 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि इन तीनों विभागों के कटौती प्रस्तावों के जवाब लिखित में उनके पास तीन दिन में भिजवा दिये जायेंगे। आज की चर्चा में 24 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। माननीय सदस्यों ने कई बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने-अपने तरीके से मेरा मार्गदर्शन किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले उच्च शिक्षा में पिछले 15 महीनों में हमने क्या-क्या उल्लेखनीय कार्य किये हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। पिछले साल आठ नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई और नौ राजकीय महाविद्यालयों का पुनर्गठन कर 11 नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई। गत वर्ष 21 राजकीय महाविद्यालयों को भूमि आबंटित की गई और 31 महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु तीन करोड़ रुपये प्रति महाविद्यालय के हिसाब से...

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि...

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): एक दफा मैं बोल लूं, फिर आप पूछ लेना।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): इसमें बीवीरानी कालेज में जो भूमि आबंटन होना है, 1999 से बकाया है, वह भी है क्या? नहीं है तो उसको कब तक अलाट कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। जवाब दे देंगे। जवाब देंगे। ठीक प्रश्न कर लिया आपने।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): भवन निर्माण के लिए प्रति कालेज हमने 3 करोड़ रुपये के हिसाब से 93 करोड़ रुपये की स्वीकृति इस वर्ष जारी की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 31 दिसम्बर, 2008 से कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत व्याख्याताओं के वरिष्ठ वेतनमान और चयनित वेतनमान लम्बित थे। हमने कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत 190 व्याख्याताओं को वरिष्ठ वेतनमान और 356 व्याख्याताओं को चयनित वेतनमान का लाभ दिया है। इतना ही नहीं, हमने 30 जून, 2015 तक पात्र होने वाले सभी व्याख्याताओं से कैरियर एडवांसमेंट स्कीम हेतु प्रस्ताव आमंत्रित कर लिए हैं और इसी कैलेण्डर वर्ष में उनको उसका लाभ दे दिया जाएगा।

इसी प्रकार पिछले सालों से लम्बित प्राचार्य, उपाचार्य के पदों की डी.पी.सी. आयोजित कर पी.जी. प्राचार्य के पद पर 78, यू.जी. प्राचार्य के पद पर 161 एवं उपाचार्य के पद पर 260 यानी कुल 499 पदोन्नतियां की गई हैं। इसी प्रकार अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कार्मिकों की लम्बित डी.पी.सी. भी करवाकर 187 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है और भविष्य के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में सभी पात्र कार्मिकों को...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी पढ़कर के जवाब दे रहे हैं, पढ़कर के नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं है, पढ़कर के दे लेने दो, अपने कई विधायक पढ़ते हैं, आप भी पढ़कर के देंगे तो मैं आप पर भी एतराज नहीं करूंगा।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): रिकार्ड की बात तो पढ़कर के ही देनी पड़ेगी। आप बिना देखे बोल लेंगे क्या? जो रिकार्ड की बात है वह तो रिकार्ड से ही बोलनी पड़ेगी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इतने आंकड़े याद रखना सम्भव नहीं है, ये तो मंत्रीजी हैं जो इकट्ठे करके लाए हैं सारे।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): इस प्रकार की व्यवस्था हमने भविष्य के लिए की है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि पात्र कार्मिकों को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में डी.पी.सी. आयोजित की जाएगी और पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा, 2008 से ये सारी पदोन्नतियां लम्बित थीं, आपने पांच साल में कुछ नहीं किया, 2008 से 2013 तक आपने एक भी डी.पी.सी. आयोजित नहीं की और एक भी प्रधानाचार्य का, प्राचार्य का आपने प्रमोशन नहीं किया।

श्री रमेश (सपोटरा): तबादला उद्योग के कारण आपका प्रमोशन हो गया, प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन में चले गए।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अच्छा, वाह-वाह क्या बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, आपके कारण प्रमोशन हो गया मेरा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस वर्ष हमने 23 आश्रितों को विभिन्न संवर्गों में नियुक्तियां प्रदान की हैं। मैं बताना चाहूंगा कि तत्कालीन सरकार ने पांच गवर्नमेंट बी.एड. कालेज खोलने की घोषणा तो कर दी परन्तु उनमें अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं की। हमने प्रयास करके चिमनपुरा, कालाडेरा, नसीराबाद, भोपालगढ़ और खैरवाड़ा में गवर्नमेंट बी.एड. कालेज संचालन के लिए एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त कर ली है और जुलाई के अगले सत्र से इन पांचों बी.एड. कालेजों में छात्रों को प्रवेश देकर और अध्ययन प्रारम्भ करा दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2008 में आदरणीय वसुंधराजी जब राजस्थान की मुख्य मंत्री थीं तो हमने तीन नए विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की। अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय, भरतपुर में ब्रज विश्वविद्यालय और शेखावाटी में शेखावाटी विश्वविद्यालय परन्तु...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): शेखावाटी की तो हमने की है, बताओ तो सही मंत्रीजी, जितनी बात बताओ, उतनी तो सही बताओ।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आप विराजो तो सही, आप पूरी बात सुन ही नहीं रहे हो। आप दुर्भाग्य से उस समय मैम्बर नहीं थे, मैं जो बात बताना चाहता हूं वह सुनिए। 2008 में हमने इनकी घोषणा की, चार साल आपने इनको ठण्डे बस्ते में रखा, कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। हम उधर से मांग करते रहे परन्तु आप अनसुनी करते रहे। पर जब चुनाव का समय आया तो जाते-जाते आपने इन तीनों यूनिवर्सिटीज की घोषणा कर दी और तीनों यूनिवर्सिटी की घोषणा करके कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया। पुन: हमारी सरकार बनी, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो गलती की थी कि जो नाम हमने रखे थे जैसे मत्स्य विश्वविद्यालय का नाम हमने रखा था राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। इन तीनों के जो नाम आपने परिवर्तन कर दिए थे, हमने विधान सभा में बिल लाकर इन तीनों नामों को दुरुस्त किया नम्बर एक और दूसरा हमने इसके लिए बजटीय प्रावधान

(श्री कालीचरण सराफ)

किया। अब हमने सभी वाइस चांसलर को बुलाकर तीनों विश्वविद्यालयों के और जो-जो स्टाफ उनको चाहिए था इसकी शुरूआत करने के लिए, ऐसे पन्द्रह-पन्द्रह स्टाफ की उनको नियुक्ति दी और उनको यह बता दिया कि एक जुलाई से अगला सत्र अलवर जिले की गवर्नमेंट और प्राइवेट कालेजेज अलवर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत, भरतपुर और धौलपुर जिले की सभी कालेजेज ब्रज विश्वविद्यालय के अन्तर्गत और सीकर और झुन्झुनूं की सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट कालेजेज शेखवाटी यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत होगी। इसकी अधिसूचना हमने जारी कर दी है और एक जुलाई से ये तीनों विश्वविद्यालय प्रारम्भ हो जाएंगे और जो मैंने बताया वो महाविद्यालय इनके अन्तर्गत आ जाएंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने जो चारदीवारी का पैसा दिया था ना, वह भी अभी तक डेढ़ साल में नहीं बना पाये आप।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आपने तो एक नया पैसा ही नहीं दिया, गलत बोलते हो आप, आपको पता ही नहीं है। आपने न तो भूमि आबंटित की...(व्यवधान) आपने तो कुछ नहीं किया, आपने तो केवल घोषणा कर दी झूठी वाहवाही लेने के लिए। यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमने 17 गवर्नमेंट कालेजों के भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है इस साल, 335 नवीन पदों का सृजन किया है और 110 राजकीय महाविद्यालयों में आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हमने इस साल प्रारम्भ कर दी और अगले सत्र से जितनी भी गवर्नमेंट की कालेजेज हैं उनमें आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी।

इसी प्रकार महाविद्यालयों में पहले क्या सिस्टम था कि कोई फर्स्ट ईयर पास करता तो उसको सैकिण्ड ईयर में दुबारा एडमिशन लेना पड़ता था। सैकिण्ड ईयर कोई पास करता तो उसको थर्ड ईयर में एडमिशन लेना पड़ता था। हमने इस व्यवस्था को सरलीकृत करके पिछली साल से जो लड़का जिसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर पास आउट किया तो उसका सैकिण्ड ईयर में आटोमैटिक एडमिशन हो जाएगा और सैकिण्ड ईयर में जो बच्चा पास आउट कर लेगा उसका थर्ड ईयर आटोमेटिक एडमिशन हो जाएगा, उसको दुबारा एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से पिछली सरकार ने जाते-जाते 42 महाविद्यालय खोले जाएंगे, कोई बजटीय प्रावधान नहीं। उनके लिए टीचर्स की क्या व्यवस्था होगी, कुछ नहीं, घोषणा कर गए। हमने

(श्री कालीचरण सराफ)

उनमें बजटीय प्रावधान किया और 1 हजार 118 व्याख्याताओं के पद, जो आपने कालेजेज की तो घोषणा कर दी पर व्याख्याताओं के पदों को भरने की कोई कार्यवाही नहीं की। नोट कर लीजिए डोटासरा जी, हमने 1 हजार 118 व्याख्याताओं के रिक्त पदों के लिए आर.पी.एस.सी. को रिक्वीजिशन भेजा और मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि 12 जनवरी, 2015 को आर.पी.एस.सी. ने इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी है, 31 मार्च लास्ट डेट है और हमारा प्रयास रहेगा, मैं गारंटी तो नहीं ले सकता आर.पी.एस.सी. का मामला है, पर हमारा प्रयास रहेगा कि अगला सत्र जब चालू हो, उसके पहले-पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे आर.पी.एस.सी. से कि इन सब रिक्त पदों पर व्याख्याताओं की नियुक्ति हो जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने जो थर्ड ग्रेड की परीक्षा की थी ना, उसका रिजल्ट नहीं निकाल सके और अब निकाल रहे हो।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): हमने इसमें एक व्यवस्था और की है, आज तक व्यवस्था यह थी कि जो व्याख्याताओं के रिक्त पद भरे जाते थे उसके लिए केवल इंटरव्यू लिए जाते थे। आर.पी.एस.सी. के जो माननीय सदस्य होते थे उनकी मर्सी पर जिसको इंटरव्यू में पास करे, करे या नहीं तो, नहीं करे। हमने अब नियमों में यह परिवर्तन कर दिया कि 88 परसेंट का तो होगा रिटर्न एग्जाम और 12 परसेंट का होगा केवल इंटरव्यू। जिससे वह बच्चा जो एग्जाम देगा वो इंटेलीजेंट बच्चे ही उसमें पास हो सकें, किसी की मर्सी पर उनका अपाइंटमेंट नहीं हो।

इस बार हायर एजुकेशन में जो अधीनस्थ कर्मचारियों के पद रिक्त हैं उनके लिए भी प्रक्रिया चल रही है और जो अधीनस्थ बोर्ड बना हुआ है उसमें भी रिक्वीजिशन भरके जल्दी से जल्दी वो पद भरे जाएं इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि पूरे हिन्दुस्तान में डीफ, डंब और ब्लाइंड बच्चों के लिए कहीं पर हायर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है। मैं सेठ आनन्दी लाल पोद्दार डीफ, डंब एंड ब्लाइंड स्कूल में गया था वहां बच्चों ने मुझसे अनुरोध किया कि हमारी हायर एजुकेशन की व्यवस्था करिये तो हमने यहां जो जयपुर का गवर्नमेंट कालेज है उसमें डीफ, डंब एंड ब्लाइंड बच्चों की हायर एजुकेशन की व्यवस्था की है। फर्स्ट ईयर की उनकी पढ़ाई पूरी हो गयी है और अब सैकिण्ड ईयर में भी वो बच्चे एडमिशन ले पाएंगे और

(श्री कालीचरण सराफ)

हायर एजुकेशन में मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में राजस्थान पहला स्टेट है जहां डीफ, डंब एंड ब्लाइंड बच्चों को हम हायर एजुकेशन दे रहे हैं।

एक बात मैं और बताना चाहूंगा जो उल्लेखनीय काम हमने किया। आज तक क्या होता था कि हायर एजुकेशन में परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन होते थे। सीबीएसई के बच्चों की मार्किंग ईजी होती थी और हमारे बोर्ड आफ सैकेंडरी एजुकेशन के बच्चे उसमें पिछड़ जाते थे। 70 परसेंट सीबीएसई वाले बच्चों का एडमिशन होता था और हमारे बच्चों का एडमिशन होता था केवल 30 परसेंट। हमने कहा कि नहीं हमारे बच्चों का एडमिशन पहले होगा तो हमने इस बार परसेंटाइल सिस्टम लागू किया और परिणाम यह हुआ कि सात लाख बच्चे जो बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, अजमेर से पढ़ते थे उनके एडमिशन होते थे तीस परसेंट, उनके तो इस बार एडमिशन हुए 75 परसेंट और एक लाख विद्यार्थी जो सीबीएसई से पास होकर आते थे उनके एडमिशन पहले 70 परसेंट होते थे, उसकी जगह उनके एडमिशन केवल 25 परसेंट, तो हमारे स्टेट के बच्चे जो बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन से पास आउट करते हैं उनके लिए हमने यह सुविधा की, परसेंटाइल सिस्टम से एडमिशन किये इस बार हमने। यहां कई माननीय सदस्यों ने भी नये महाविद्यालय खोले जाने की बात की। कइयों ने कहा कि हमारे यहां सब्जैक्ट खोले जाएं। कइयों ने कहा कि यूजी कालेज है इसको पीजी किया जाए। तो जितने भी सबके जो प्रस्ताव आये हैं उन पर हम विचार कर रहे हैं और गुण-दोष के आधार पर, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर हम ये कालेज खोलेंगे पर इस बार हमने यह तय किया है...(व्यवधान) सुनिये-सुनिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): मंत्री महोदय, दौसा में आप वायदा करके आये थे सब्जैक्ट खोलने का।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): जो घोषणा की है वो पूरी की जाएगी आप चिन्ता मत करें। इस बार बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ...(व्यवधान) सुनिये। इस बार हमने, नये महाविद्यालय तो हर बार खोले जाने की घोषणा होती है पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण की कोई व्यवस्था नहीं होती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहें। मंत्रीजी का वक्तव्य आने दें।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): इस बार हमने यह निर्णय किया है कि महाविद्यालय तो दो ही खोलने की घोषणा की है पर इस बार उच्च शिक्षा में जो महाविद्यालय हैं, जो विश्वविद्यालय हैं उनका सुदृढ़ीकरण करेंगे। अभी तक तो हमने केवल क्वांटिटी पर ध्यान दिया अब इस साल हम क्वालिटी पर ध्यान देंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष चौंतीस नये राजकीय महाविद्यालयों का भवन निर्माण। नोट कर लो। धौलपुर व कोटा विधि महाविद्यालयों का भवन निर्माण, बीएड पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विधवाओं व परित्यक्ताओं के लिए छात्रवृत्ति योजना, राज्य के सभी 190 महाविद्यालयों के युवा विकास केन्द्रों के संचालन, सभी राजकीय महाविद्यालयों में ब्राड बैंड व इंटरनेट कनेक्टीविटी, मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, राज्य के 75 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज प्रारम्भ करने, राज्य के सभी सम्भागीय स्तर के राजकीय महाविद्यालयों एवं आयुक्तालय मुख्यालयों को वाई-फाई सुविधा से जोड़ने, जेडीबी गर्ल्स कालेज, कोटा, मीरा गर्ल्स कालेज, उदयपुर तथा राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में चीनी व जापानी विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, सात सम्भागों के मुख्यालयों के राजकीय महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा विषय प्रारम्भ करने हेतु राशि का प्रावधान किया गया है और इस वर्ष हमने एक बात और तय की है। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में किस प्रकार के घोटाले हुए, किस प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं हुई फर्जी डिग्री के प्रकरण हमारे सामने आये तो इस बार हमने यह तय किया है कि इस वर्ष उच्च शिक्षा के... (व्यवधान) सुनिये। निजी एवं राजकीय शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए और निरंकुश प्रवृत्ति को रोकने के लिए राज्य नियामक आयोग का गठन इसी वर्ष किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्षों में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। राज्य के पिछड़े तीन जिलों के तीन राजकीय महाविद्यालयों को प्रचलित माडल कालेज योजना के तहत माडल कालेजों में परिवर्तित करने हेतु सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 6 जिलों के 6 महाविद्यालयों को माडल कालेज में क्रमोन्नत किया जाएगा। राज्य के 165 राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा और

(श्री कालीचरण सराफ)

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च, इनोवेशन एवं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इतना टिपीकल भाषण किसने लिख कर दिया आपको?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): यह टिपीकल भाषण नहीं है यह तो मेरी ही उपज है। आप तो सुनते जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गोविन्द सिंहजी कह रहे हैं कि ऐसी भाषा हमने तो कभी पढ़ी ही नहीं। अब सीखो। अब सीखो ये भाषा।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आपके ऊपर से निकल रहा है मुझे पता है। टैक्नीकल एजुकेशन में मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा कौशल प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पिछले साल हमने अभूतपूर्व प्रगति की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रत्येक पंचायत समिति में आईटीआई खोलने के उद्देश्य से पैंतालीस पंचायत समितियों में नयी आईटीआई खोलने की घोषणा की है। इस हेतु भूमि आबंटन की कार्यवाही चल रही है एवं आगामी वर्ष में शेष रही 17 पंचायत समितियों में जहां पर राजकीय या निजी आईटीआई नहीं है वहां भी आईटीआई खोल दिये जाएंगे। इसी प्रकार...

श्री रमेश (सपोटरा): आईआईटी या आईटीआई?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आप कम पढ़े-लिखे नजर आते हैं। आईटीआई की बात हो रही है आईआईटी की बात नहीं हो रही है। मुझे पता नहीं था कि आप इतने गैर समझदार हो कि आईटीआई और आईआईटी का भी मतलब नहीं समझते हो। अब दुरुस्त कर लें मैं आईटीआई की बात कर रहा हूं, आईआईटी की नहीं कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार अगले वर्ष राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित 28 आईटीआई में प्लम्बर व्यवसाय खोला जाएगा। जिसकी रोजगार प्रदान करने के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सम्भावना है। राजसमन्द और किशनगढ़ आईटीआई में स्टोन प्रोसेसिंग का नया कोर्स खोला जाएगा। अगले वर्ष आईटीआई में छात्रों का प्रवेश आनलाइन प्रक्रिया से सम्पादित किया

(श्री कालीचरण सराफ)

जाएगा। मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि राजकीय आईटीआई में अनुदेशकों के जो 413 पद रिक्त हैं उनकी भर्ती करने की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है और अगले तीन महीने में इन पर भर्ती कर दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जो तकनीकी विश्वविद्यालय बंद किया बीकानेर में उसके बारे में भी कुछ फरमायें।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): विराजिये। अभी मैं पहले मेरा भाषण पूरा कर लूं फिर आपकी एक-एक बात का जवाब दूंगा। बैठिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में इस वर्ष हमने रिकार्ड, रिकार्ड शब्द का उपयोग कर रहा हूं, 646 आईटीआई की स्थापना निजी क्षेत्र में की है जिनमें 86.3 फीसदी की वृद्धि हुई है जो कि पिछले 67 वर्षों में खोली गई 842 निजी आईटीआई के सापेक्ष में अभूतपूर्व वृद्धि है। यानी 67 साल में राजस्थान में 842 निजी क्षेत्र में आईटीआई खोली गईं और हमने एक साल में 646 आईटीआई खोल दीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक प्राइवेट आईटीआई खोलने की रेट क्या है?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): यह मुझे लगता है कि आप अपने जो मंत्री थे उनकी बात बता रहे हो। मैं चुनौती देता हूं, सुनिए...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह तो आपकी रेटें आपके पास हैं।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): चुनौती देता हूं कि एक भी आईटीआई में कोई बंदा यह कह दे कि कोई पैसे लिये गये हों तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और नहीं तो आप इस्तीफा दे देना।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मंत्रीजी आप चिंता मत करो यह तो इन्होंने अपनी रेट बताई।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): गलत बात मत करो। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ...(व्यवधान) आईटीआई खोलने में आपका योगदान क्या रहा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): बैठो महाराज। आपकी संस्कृति का बखान मत करो, हमें सब पता है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ...(व्यवधान) मेरा निवेदन है कि जितने भी प्राइवेट या सरकारी आईटीआई आप खोल रहे हैं, अच्छी बात है लेकिन आप इनमें भौतिक सत्यापन करवा लें यह फर्जी सर्टीफिकेट से नौकरियां मिल रही हैं, लोग फर्जी नौकरी कर रहे हैं, उनको अनुभव है नहीं और समाज कल्याण के माध्यम से जो छात्रवृत्तियां मिल रही हैं वह भी फर्जी हैं। जिन-जिन जिलों में प्राइवेट आईटीआई खुली हैं उनकी जांच करवायें। (व्यवधान) सरकार में आप हो, सरकार की मंशा हो, हिम्मत हो आपकी तो उनकी जांच करवायें और यह जो दो पांच आईटीआई खोलने की बात कर रहे हो, मेरे जिले में ही सवा सौ आईटीआई होंगी फर्जी।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आपकी गलती नहीं है, आपके पांच साल का अनुभव यही बताता है कि फर्जी डिग्रियां दी जाती थीं, पर अब आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें कि पिछले एक साल से कहीं पर भी कोई भी फर्जी प्रकरण का मामला हमारे सामने नहीं आया और आपके पास यदि कोई ऐसी सूचना हो तो कृपया हमें सूचित कीजिए, हम उस पर कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) बैठो, बीच में मत बोलो। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 170 तो राजकीय और 1488 निजी आईटीआई संस्थान संचालित हो रहे हैं और इनमें विभिन्न व्यवसायों की 236234 सीट छात्रों के प्रशिक्षण, अध्ययन हेतु स्वीकृत हैं। (व्यवधान) आ गया फिर भी सुन लो। पिछले सत्र में हमने एप्रेंटिसशिप एक्ट यहां पर संशोधन के साथ स्वीकार किया था। मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी की उस पर स्वीकृति मिल गई है। यह पहला महत्वपूर्ण अधिनियम है जो 53 वर्षों में किसी राज्य में लागू हुआ है। इससे युवाओं के कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में और रोजगार के अवसरों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी और कौशल प्रशिक्षित मानव संसाधन हमें उपलब्ध हो पायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष आईटीआई जयपुर एवं सेमसंग इंडिया इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य आईटीआई शाहपुरा और टोयटा मोटर कारपोरेशन के मध्य एमओयू किया गया है तथा आईटीआई उदयपुर को माडल आईटीआई के रूप में विकसित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा आईटीईईएस सिंगापुर के साथ एमओयू किया गया है। इसी प्रकार केयर्न एजेंसी

(श्री कालीचरण सराफ)

एवं आईटीआई बालोतरा एवं आईटीआई बाड़मेर के मध्य भी एमओयू की कार्यवाही चल रही है। इन एमओयू से छात्रों को आवश्यक औजार, उपकरण, प्रशिक्षण की व्यवस्था सम्बन्धित कंपनियों द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी जिससे छात्रों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

महिला आईटीआई जयपुर में महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिये इन्क्यूबेशन केन्द्र की स्थापना की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। इनको उद्योग संचालन हेतु आवश्यक सहयोग दिया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से प्रदेश में इस वर्ष पोलीटेक्निक कालेजों में आरपीएससी के माध्यम से 240 प्रवक्ताओं को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है और विभाग की अभ्यर्थना पर प्रवक्ताओं के 343 पदों पर भर्ती हेतु आरपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार 242 अशैक्षणिक पदों पर भी नियुक्ति के लिये विभाग द्वारा अधीनस्थ आयोग को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। विभाग के ट्रिपल आई इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन सेल के माध्यम से कैम्पस इंटरव्यू के द्वारा इस वर्ष 1203 अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। आगामी वर्ष में राजकीय पोलीटेक्निक कालेज, जोधपुर में, सूर्यकान्ताजी यहां नहीं है उन्होंने मांग की थी, आगामी वर्ष में राजकीय पोलीटेक्निक कालेज जोधपुर में माइनिंग इंजीनियरिंग और बारां में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की नई शाखा खोली जायेगी। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य संदीपजी ने कहा कि टैक्निकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि एनआईटीटीटीआर, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टैक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एवं रिसर्च, चंडीगढ़...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी यह क्या चीज है?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): मैं यही बता रहा हूं कि जो टैक्निकल टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिये चंडीगढ़ में जो सेंटर है वहां के निदेशक ...(व्यवधान) बैठिए, बैठिए एक मिनट।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): चार बार टी बोला है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): बैठ जाओ, बैठ जाओ, यह आपमें ज्ञान की कमी है, इसमें मेरी गलती नहीं है। चंडीगढ़ में जो यह टैक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर है वहां के निदेशक महोदय से हमारी बात चल

(श्री कालीचरण सराफ)

रही है और उन्होंने इस बात की स्वीकृति दे दी है कि जयपुर में उसकी एक ब्रांच वह खोलेंगे जिससे हमारे टैक्निकल टीचर्स को ट्रेनिंग देने का जो सेंटर है वह जयपुर में ही उपलब्ध हो जायेगा, उनको चंडीगढ़ नहीं जाना पडेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां एसएफएस में 8 इंजीनियरिंग कालेज चल रहे हैं और तीन की घोषणा पिछली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की। इनके राज में 8 इंजीनियरिंग कालेज की यह स्थिति थी कि 8 में से केवल एक में प्रिंसिपल था, बाकी 7 के पद रिक्त पड़े थे। मैं यह बताना चाहूंगा और आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमने सभी आठों इंजीनियरिंग कालेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति पारदर्शिता के आधार पर इंटरव्यू लेकर कर दी है और जो तीन नये कालेज खोले जाने की घोषणा की थी उनके लिये धौलपुर और बारां में जमीन आबंटन की कार्यवाही चल रही है और करौली के लिये भी जमीन ढूंढी जा रही है। इन तीनों कालेज के प्रिंसिपल की नियुक्ति भी अगले तीन माह में कर दी जायेगी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अजमेर के लिये जो आपने मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत साहब को लिखा था कि यह भ्रष्ट प्रिंसिपल है और आपने ही समय बढ़ा दिया, उसको हटा दिया क्या?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आपने तो उस भ्रष्ट प्रिंसिपल को 4 इंजीनियरिंग कालेज का चार्ज दे रखा था, हमने उसको केवल एक ही कालेज में सीमित कर दिया। जांच बिठाई, एक नहीं दो जांच बिठाई पर जांच में कुछ आया नहीं, इसलिए जब तक उनका ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब जांच में कुछ नहीं आया तो उसको चार्ज शीट क्यों ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डोटासरा साहब।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): विपक्ष में क्या हमको सपना आता है, हम किसी पर आरोप लगायेंगे तो यही कहेंगे कि इसकी जांच करो। आज जैसे जोधपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती घोटाला हुआ अशोक गहलोतजी की शह पर, लोगों ने मांग की तो हमने जांच बैठा दी। अब जांच में यदि दोषी पाये गये तो कार्यवाही होगी और नहीं होगा तो नहीं होगी। नहीं होगी, आप तो भविष्य दृष्टा हो, क्योंकि आपको तो पता है कि उन्होंने क्या क्या घोटाले किये, आपके साथ मिलकर ही तो किये हैं उन्होंने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि

(श्री कालीचरण सराफ)

जितनी भी इंजीनियरिंग कालेज एसएफएस में चल रही हैं उनमें जितने भी लैक्चरर्स और नोन टीचिंग स्टाफ के पद रिक्त पड़े हैं वह भी अगले छह महीने में भर दिये जायेंगे।

संस्कृत शिक्षा के बारे में मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत में निहित ज्ञान को सर्व साधारण तक पहुंचाने के लिये संस्कृत शिक्षा विभाग निरन्तर प्रयासरत है। हमने पिछले बजट सत्र में संस्कृत शिक्षा की गुणवत्ता, विकास हेतु अनेक घोषणाएं की थीं, उनमें से प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना जुलाई मास को सम्भाषण मास के रूप में मनाना, प्रथम कक्षा से संस्कृत विषय को आरम्भ करना, शास्त्रों की रक्षा हेतु अनौपचारिक शास्त्र शिक्षण केन्द्र खोलना एवं नई भर्तियां करना मुख्य थी। मुझे यह बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है तथा इस सत्र में राजस्थान में 11 स्थानों पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी प्रकार जुलाई मास को सम्भाषण मास के रूप में मनाया गया जिसका परिणाम उत्साहजनक देखने में आया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने प्रथम कक्षा से संस्कृत प्रारम्भ करने की जो घोषणा की थी उसके अन्तर्गत पुस्तक के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हाल ही में हमने एक अनौपचारिक शास्त्र शिक्षण केन्द्र का आरम्भ कर स्वास्थ्य संरक्षण की योजना की क्रियान्विती भी आरम्भ कर दी है। इस योजना का विस्तार करते हुए हम अनौपचारिक स्वास्थ्य परिचय केन्द्र भी स्थापित करने का विचार कर रहे हैं। हमने आरपीएससी में, अभी भिण्डाजी ने यह मामला उठाया था कि नियम नहीं है संस्कृत टीचर्स के। मैं बताना चाहूंगा कि आरपीएससी ने भर्तियों हेतु अभ्यर्थना भेजी थी किन्तु नियमों के अभाव में आरपीएससी का खेप आ जाने से भर्तियां नहीं हो पाई। इस समस्या के समाधान के लिए 15 वर्षों से संस्कृत शिक्षा के नियमों की जो आवश्यकता बनी हुई थी उसको हमने पूर्ण कर लिया है और संस्कृत शिक्षा विभाग के नये नियम अपने अंतिम चरण में है, उनको शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाएगा। वर्षों से डीपीसी अटकी हुई है उसके लिए भी डीपीसी कलैण्डर तैयार किया जा रहा है, हम शीघ्र ही सभी स्तरों पर डीपीसी भी करेंगे।

आज जहां तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है वहीं अभिभावक अपने बच्चों को भारत की समृद्ध संस्कृति से भी अवगत कराना चाहते हैं। इसलिए

(श्री कालीचरण सराफ)

सांध्य संस्कृत विद्यालयों के संचालन की योजना हमने बनाई है। जिसमें विस्तृत पाठयक्रम तैयार किया जाएगा जो भारतीय संस्कृति के अमूल्य ग्रंथों को समझने की योग्यता विकसित कर सकेगा। इसमें कक्षा 3 से 10 तक के विद्यार्थी प्रतिदिन सायंकाल तीन घण्टे के लिए सांध्य विद्यालयों में भारतीय संस्कृति से परिचित हो सकेंगे।

सांध्य विद्यालयों के साथ-साथ यह भी विचार किया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्यार्थी में विस्तृत प्रतिभा का विकास करने के लिए ग्रीष्मकालीन संस्कृति वर्गों का आयोजन किया जाए। इनमें विद्यार्थियों की कमजोरी दूर करने के साथ-साथ साहित्यिक, नैतिक एवं व्यक्तित्व सम्बन्धी गुणों की अभिवृद्धि का प्रयास भी किया जाएगा।

संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत दिवस पर विद्वानों एवं उच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया जाता है व प्रोत्साहित किया जाता है। हमने युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए युवा प्रतिभा पुरस्कार की संख्या जो पहले आपके समय में एक थी वह चार कर दी। विद्वानों के सम्मान में संस्कृत साधना सम्मान की संख्या दो से बढ़ाकर तीन कर दी।

जानकारी में आया है कि संस्कृत शिक्षा से सेवानिवृत होने वाले विद्वान, शिक्षक, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक स्वेच्छा से अपना समय देकर विद्यालय अध्ययनरत छात्रों की गुणवत्ता के विकास हेतु कार्य करने के इच्छुक हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए हम विद्यालयों को शैक्षणिक दृष्टि से गोद देने के सम्बन्ध में भी विचार कर रहे हैं। हमने यह निर्णय किया है, बस हो गया अब आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, अब सुन लो। यह बोर हो रहे हैं। यह दुःखी हो रहे हैं, हमारे नहीं हो रहे, वह दुःखी हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह बोर नहीं हो रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं आपका कुछ न कुछ।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): हमने यह भी निर्णय किया है ...(व्यवधान) सुनिये, सुनिये, आपके काम की बात बता रहा हूं, सुनिये। हमने यह भी निर्णय किया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत उच्च तकनीकी और संस्कृत शिक्षा की सभी शिक्षण

(श्री कालीचरण सराफ)

संस्थाओं में प्रतिमाह एक दिवस किसी भी सार्वजनिक स्थल की, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, कहीं भी, स्वच्छता के लिए निर्धारित किया जाएगा जिससे छात्रों में सामुदायिक सेवा एवं श्रमदान की भावना विकसित हो सके। इससे आम जनता का भी स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ाव होगा। एक व्यक्ति के जीवन में जो कार्य लम्बे अर्से की शिक्षा प्राप्त करने से नहीं होता वह कभी-कभी एक प्रेरक वाक्य से भी सम्भव हो जाता है। उसका सम्पूर्ण जीवन बदल जाता है। आपको यह जानकारी देते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि हमने प्रदेश के विद्यार्थियों में चारित्रिक गुणों के विकास, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक तत्वों के उन्नयन की दृष्टि से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा के सभी भवनों में, दीवारों पर हमने प्रेरक सद्वाक्य, सूक्तियां और श्लोकों का लेखन करवाया है। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उन वाक्यों के पठन से कई व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहूंगा...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मंत्रीजी एक सैकण्ड, आपके पास कोई योजना है इनका मन बदलने की। इनकी योजना हो तो बताओ कोई। इनका मन बदल जाए ऐसी योजना हो तो बताओ।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): सुनिये, सुनिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): भवन निर्माण और भूमि आबंटन कब तक कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): मैं अभी बैठा नहीं हूं, आप सुनिये। राजाखेड़ा से आने वाले प्रद्युम्न सिंहजी ने कहा कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय बंद करने का आपने निर्णय ले लिया। पता नहीं उनको कहां से सपना आ गया। अभी हमने बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। मंत्रिमण्डलीय उप समिति है उसमें यह मामला विचारार्थ आया था। उस पर विचार किया गया, इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। अंतिम निर्णय तो मंत्रिमण्डल की मीटिंग में होगा। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि राजाखेड़ा में राजनीतिक भेदभाव के आधार पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई। मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस का राज रहता है तब तो जरूर राजनीतिक भेदभाव होता है पर हमारे राज में जब भैरोंसिंहजी राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने यह निर्णय किया था कि जहां ...(व्यवधान) आप बीच में क्यों खड़े हो जाते हो, स्प्रिंग लगी हुई है क्या, बैठ जाओ।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कालेज बंद कर दिये और खोलने की बात कर रहो हो ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): विराजो, आप विराजो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): विराजें क्या, कालेज बंद क्यों किया और भेदभाव की बात करते हो। भेदभाव आपने किया है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): विराजो, पता ही नहीं है आपको। मैं यह बताना चाहूंगा...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय मंत्री महोदय, बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय और कोलायत में सरकारी महाविद्यालय, 15 महीने हो गए मंत्रिमण्डलीय उप समिति के पास, यह निर्णय कब करेगी। पांच साल के बाद निर्णय करेंगे क्या ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): यह हमारे सम्भाग का मामला है। पूरे सम्भाग का नुकसान हुआ ...(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): पिछले बजट में आपने कहा हमने बंद नहीं किया, इस बजट में आपने ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सम्भाग में तकनीकी विश्वविद्यालय के बारे में जरूर बताएं ...(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): इस बजट में आपने कहा कि हमने बंद नहीं किया या तो आप बंद कर दीजिए...(व्यवधान) मंत्री महोदय, आप समीक्षा का नाम लेकर बीकानेर की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आपका अख़बार में नाम छप जाएगा, बैठिए आप। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अख़बार में नाम ...(व्यवधान) लोकसभा चुनावों में मंत्री महोदय बीकानेर गए, राजेन्द्रजी राठौड़ साहब बीकानेर गए, इन्होंने बीकानेर की जनता को कहा कि बीकानेर का तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में रहेगा। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आप भी मंत्री महोदय, ...(व्यवधान) आप भी उसी सम्भाग से हैं, आप भी सरकार से कहिए हमारा तकनीकी विश्वविद्यालय हमारे बीकानेर से नहीं जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अच्छा अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय पंचायत चुनावों में गए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): तो इन्होंने बीकानेर की जनता को कहा, मुख्य मंत्रीजी गए, सुराज संकल्प यात्रा में ....

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): उस समय इन्होंने कहा कि बीकानेर का तकनीकी विश्वविद्यालय बंद नहीं होगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): लेकिन बीकानेर के हितों के साथ यह कुठाराघात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: इनका एक भी शब्द अंकित नहीं हो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: किया वह भी काट दो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। बैठ जाइये।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले तीन महीने में 14 बार बीकानेर गया पर आप जैसा कोई माई का लाल नहीं मिला जो काले झण्डे से मेरा स्वागत करें। (व्यवधान) बैठिए, बैठ जाइये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): तैयार है तो बताओ कब आऊं, बताओ कब आऊं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आपको सूचित करके आऊंगा इस बार। बैठ जाओ।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: इनका एक शब्द भी अंकित नहीं हो।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जैसा मैंने पहले भी कहा 42 राजकीय महाविद्यालयों की बिना बजटीय प्रावधान के जाते-जाते घोषणा की, जनता को भ्रमित करने के लिए, उसमें जो बजट हमारे पास उपलब्ध था, 11 कालेज को छोड़कर, बाकी की हमने घोषणा कर दी और वह चल रहे हैं। दुर्भाग्य से कहूं या सौभाग्य से कहूं कि उन 11 कालेजों में इनका कोलायत का कालेज भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बजटीय प्रावधान होगा, बिना राजनैतिक भेदभाव के कोलायत में महाविद्यालय खोला जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं रखी जाएगी। ठीक है, अब बैठ जाइये। (व्यवधान) विराजो। जहां तक बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का सवाल है...

श्री अध्यक्ष: वरिष्ठ सदस्य, माननीय मंत्री महोदय, वरिष्ठ सदस्य कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, बीकानेर का तकनीकी विश्वविद्यालय कोई राजनैतिक विवाद का मुद्दा नहीं है। राजनैतिक विवाद का मुद्दा इसलिए नहीं है कि इसी सरकार ने 2014-15 के बजट में तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए करीब, एग्जेक्ट मुझे ध्यान नहीं है, पर डेढ़ करोड़ से ऊपर रुपये का प्रावधान किया था। किन्हीं कारणों से वह नहीं भी खुल पाया तो मैं आपका ध्यान सिर्फ इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि आल इंडिया कौंसिल आफ टैक्नीकल एजुकेशन के जो नोर्म्स हैं उन नोर्म्स को आप थोड़ा देखने की कृपा करें। उन नोर्म्स के आधार पर जितने कालेजेज जुड़ रहे हैं विश्वविद्यालय से, वह उनके नोर्म्स के खिलाफ हैं और इसलिये राजस्थान के पूर्व में एक विश्वविद्यालय हो और एक विश्वविद्यालय पश्चिम में भी हो और जिसका प्रावधान आपने किया, आप जब शिक्षा मंत्री थे, तब हुआ तो मेरा निवेदन यह है कि वह चाहे लैप्स हो गया है, पर आप उसको ध्यान में रखते हुए तकनीकी विश्वविद्यालय के मामले में ए.आई.सी.टी.ई. के नार्म्स के अनुसार निर्णय करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी कहा है और अब पुन: दोहरा रहा हूं कि मंत्रिमण्डलीय उप समिति जो आदरणीय गृह मंत्री गुलाबजी की अध्यक्षता में बनी हुई है, जिसका मैं भी मैम्बर हूं, राजेन्द्रजी राठौड़ भी मैम्बर हैं और अरुणजी चतुर्वेदी भी मैम्बर हैं, उसमें तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर का मामला समीक्षाधीन है। जैसे ही उसका निर्णय होगा, आपको अवगत करा दिया जाएगा।

मैं राजाखेड़ा के महाविद्यालय की बात कर रहा था। मैं यह बताना चाहता हूं कि जब भैरोंसिंहजी राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तो हमने यह निर्णय किया कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, जहां भी तीन हजार की जनसंख्या है, वहां पर मिडिल स्कूल खोला जाए। उसके बाद जब वसुन्धराजी राजस्थान की मुख्य मंत्री बनीं तो हमने यह निर्णय किया कि जिन-जिन ग्राम पंचायतों में सैकण्डरी स्कूल नहीं है, चाहे वहां से प्रद्युम्नसिंहजी विधायक हैं, चाहे गोविन्द सिंहजी डोटासरा हैं, चाहे रामेश्वरजी डूडी हैं, चाहे राजेन्द्रजी राठौड़ हैं, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हर ग्राम पंचायत में सैकण्डरी स्कूल खोला जाए और हमने 3600 से ज्यादा सैकण्डरी स्कूल उस समय खोले। इस बार जब सरकार बनी तो बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के जितनी भी ग्राम पंचायतें राजस्थान में, जहां निजी विद्यालय भी सीनियर सैकण्डरी के नहीं थे, ऐसी 5000 ग्राम पंचायतों में सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने का निर्णय किया। अब उसके बाद भी आप कहो कि राजनीतिक भेदभाव, आपकी संस्कृति हो सकती है, हम विकास के काम में राजनीति नहीं करते और विशेषकर शिक्षा के काम में तो कोई राजनीतिक भेदभाव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। (व्यवधान) क्या हो गया?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): जहां निजी विद्यालय हैं, वहां कब तक क्रमोन्नत करने का है माध्यमिक को उच्च माध्यमिक?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): वह देवनानीजी देंगे जवाब। मैंने तो जो अभी तक हुआ, वह बता रहा हूं।

फूलचन्दजी भिण्डा ने जो कहा कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये महिला महाविद्यालय खोले जाएं, हमारी भी मंशा है, पर 248 उप खण्ड ऐसे हैं कि जहां राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं हैं इसलिये वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यह निर्णय किया जाएगा। (व्यवधान) अब आप विराजो, विराजो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्षजी, एक निवेदन है। कन्याओं से फीस लेकर कालेज चलाये जा रहे हैं। उनको सरकारी घोषित करें। बिल्डिंग सरकारी है। यह मेरा विशेष निवेदन है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): ठीक है। तिजारा विधायक, आदरणीय मामनसिंहजी ने कहा कि भिवाड़ी, खुशखेड़ा क्षेत्र में बाबा मोहनदास ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल को क्रमोन्नत कर राजकीय कालेज खोला जाए।

एक माननीय सदस्य: कालेज ही है वो।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): संस्था की तरफ से औपचारिक महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव यदि हमारे पास आयेगा तो उस पर विचार करके यह व्यवस्था की जाएगी। आदरणीय जगदीशजी मीणा, मामनसिंहजी, सुखरामजी विश्नोई, कैलाशजी भंसाली, नन्दकिशोरजी महरिया, गोतमजी, मानसिंहजी गुर्जर, इन सबने अपने यहां नया महाविद्यालय खोलने, पी.जी. कालेज में क्रमोन्नत करने, कामर्स का विषय, भूगोल का विषय और अन्य विषय खोले जाने की बात कही है। जहां-जहां वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे, हम खोलने की कोशिश करेंगे। मैंने जैसा पहले कहा कि इस वर्ष क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दिया जाएगा और जो मैंने सारी बात बताई, वह या तो आपने सुनी नहीं, या सुन करके नजरअंदाज कर रहे हो। इस बार क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दिया जाएगा।

श्री रमेश (सपोटरा): आपकी पार्टी के लोग तालियां ही नहीं बजा रहे, आपकी इस बात पर।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): लो। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां कालेजेज में पद रिक्त हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि पिछली सरकार ने आनन-फानन में कालेज तो खोल दिये, परन्तु व्याख्याताओं की भर्ती की चिंता नहीं की। हमने आते ही 1118 रिक्त पदों के लिये आर.पी.एस.सी. में अभ्यर्थना कर दी। उन्होंने विज्ञप्ति निकाल दी। जल्दी से जल्दी इन व्याख्याताओं की नियुक्ति कर दी जाएगी। खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो प्राइवेट कालेजेज हैं, उनके लिये पहले पांच हजार गज का था फिर आपने आठ हजार गज कर दिया, तो उसमें नये नियम अभी प्रक्रियाधीन हैं। आपकी भावना का ख्याल रखा जाएगा। आपने जो बताया है, निजी महाविद्यालय के लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी बोल चुके हैं और आई.टी.आई. के बारे में काफी कुछ कहा है। मैं सिर्फ इतना स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आपने कहा 170 तो राजकीय आई.टी.आई. हैं और 1400 के करीब निजी हैं। मेरा निवेदन है कि आपने जो 45 आई.टी.आई. घोषित किये हैं, उनमें निजी संस्था वहां कार्यरत है या नहीं है, इसकी कोई बाधा तो नहीं आयेगी।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आयेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): हमने यह तय किया है कि प्राथमिकता के आधार पर पहले ऐसी पंचायत समितियों में पोलोटैक्निक कालेज खोले जाएंगे जहां गवर्नमेंट का भी नहीं है और प्राइवेट भी नहीं है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आई.टी.आई.।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): सौरी, आई.टी.आई.। दूसरे चरण में ऐसी पंचायत समितियों में खोले जाएंगे, जहां गवर्नमेंट का कालेज नहीं है। लूणकरणसर में निजी क्षेत्र में कालेज चल रहा है, इसलिये प्रथम चरण में नहीं, द्वितीय चरण में आपके यहां खोला जाएगा।

श्री अध्यक्ष: देवनानीजी।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर विचार हुआ। मेरे 24 माननीय साथियों ने विचार प्रकट किये और 230 कटमोशंस भी प्राप्त हुए। इन सभी का अगले तीन दिन के अन्दर उत्तर भिजवा दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आये, क्योंकि शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। चूंकि यह सारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है और जीवन सभी बातों से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक देश यह नीति बनाते समय सोचता है कि उसके देश को कैसे नवयुवक तैयार करने हैं। संस्कारवान, अच्छे नागरिक बनें। उस देश की अस्मिता, उस देश की संस्कृति को पनपाने के साथ समय की चुनौतियों का सामना करने वाली विशिष्ट नीति अपनाते हैं।

इसी कड़ी में जब अंग्रेजों का यहां पर शासन था, उन्होंने अपना राज यहां पर जमाये रखने के लिये मैकाले को, यहां पर शिक्षा के नाते उन्होंने कुछ कहा। मैं केवल उद्धरण दे देता हूं कि 2 फरवरी, 1835, अर्थात आज से लगभग

(श्री वासुदेव देवनानी)

180 वर्ष पहले लार्ड मैकाले ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव जिस पृष्ठभूमि में डाली, वह यह है। वह कहता है कि मैंने भारत यात्रा एक छोर से दूसरे छोर तक की है। वहां एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा जो भिखारी हो, चोर हो। मैंने उस देश में इतना धन, वैभव देखा है, मैंने इतने अधिक नैतिक मूल्य देखे हैं, इतने क्षमतावान लोग देखे हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी उस देश को जीत पाएंगे। यह तभी सम्भव है यदि हम उस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ डालें, जो उस देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बसती है इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि हम उसकी प्राचीन शिक्षा प्रणाली, उसकी संस्कृति को बदल डालें। यदि भारतीय सोचने लगें कि विदेशी और इंग्लिश ही उनकी अपनी चीजों और भाषा से अधिक श्रेष्ठ है तो भारतीय अपना सम्मान, अपनी संस्कृति खो देंगे। फिर वही करेंगे जो हम उनसे कराना चाहेंगे।

यह मैकाले का सोच था। आज भी लार्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली में संशोधन तो हुए हैं लेकिन अभी तक वह पूरी संशोधित नहीं हो पाई है। इसके दुष्परिणाम का उल्लेख करते हुए माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने कहा है कि आज शिक्षा मैन-मेकिंग की बजाय मनी-मेकिंग वाली बन गई है। वास्तविक शिक्षा वह है जो मैन-मेकिंग के साथ मनी-मेकिंग, दोनों का समन्वय करे, दोनों का साथ करे और वह शिक्षा जो हमें आंख और पांरब, अर्थात अंतर्दृष्टि और क्षमता दे जो व्यक्ति के जीवन और जीविका, दोनों में काम आये। दुर्भाग्य से आजादी के बाद अधिकांश समय कांग्रेस का शासन रहा और उन्होंने साक्षरता को शिक्षा और सूचना को ज्ञान जान बूझ करके माना, जिसके कारण से आज इस देश को वर्षों की सज़ा भुगतनी पड़ रही है। मैं कहना चाहूंगा।

इस जुल्म को तो देखा है, तवारीख की नजरों ने
लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई है।

इस प्रकार के संस्कारविहीन साक्षर से तो शायद, निरक्षर अच्छा है? यह तो साहब, मेरे मित्र हैं। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी भी तो कांग्रेस के ही प्रोडक्ट हैं। यह भी तो कांग्रेस के ही प्रोडक्ट हैं। जो शिक्षा कांग्रेस ने दी थी, मंत्रीजी प्रोडक्ट हैं उसके। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): लेकिन मेरे संस्कार कहीं और से भी मुझे मिले हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

इसीलिए 1986 के पैरा 8.1 में, जब आपकी सरकार थी तब भी उसमें कहा गया कि औपचारिक शिक्षा की जो पद्धति है और देश की जो विविध सांस्कृतिक परम्पराओं के बीच बहुत बड़ी खाई है, जिसको पाटने की आवश्यकता है। यह 1986 में जब शायद, राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे, उस समय भी यह कहा गया।

इसीलिए हमको आज यह तय करना पड़ेगा कि परिवर्तनपरक टैक्नोलाजी और सतत् चली आ रही देश की सांस्कृतिक परम्परा में एक सुन्दर समन्वय की आवश्यकता है कि केवल यदि हम आधुनिकता की ओर बढे तो हम अपने आप संस्कृति और इतिहास से कट जाएंगे और केवल संस्कृति और इतिहास रहा तो आधुनिक टैक्नोलाजी के साथ हम दौड़ में नहीं आ पाएंगे इसलिए आज दोनों की आवश्यकता है।

हमारा प्रदेश शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा रहा है। मैं पढ़ रहा था 1951 में राजस्थान की साक्षरता दर केवल 8.5 परसेंट थी और पुरुष साक्षरता दर 13.88 और महिला की साक्षरता केवल 2.66 थी लेकिन लगातार प्रत्येक सरकार ने अपने प्रयत्न किए और 2011 में जो साक्षरता दर आयी है वह राज्य की साक्षरता दर है 66.11 परसेंट। उसमें पुरुष की है 79.19 और महिला की है 52.52 लेकिन अभी भी राष्ट्रीय औसत से महिला की साक्षरता लगभग 12.5 परसेंट कम है, जिसकी ओर विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

इसलिए आज मैं स्वयंसेवी संगठनों, शिक्षा विभाग के कार्मिकों और विद्यार्थियों के साथ, इससे जुडे हुए सभी पक्षों को धन्यवाद तो देना चाहूंगा जिन्होंने साक्षरता को यहां तक पहुंचाया लेकिन साथ ही हमारे पास अभी बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं जिसके लिए हम सबको प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीया श्रीमती वसुन्धराजी राजे का वर्ष 2015-16 का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 'सब जन विकास, सब जन उत्थान, शिक्षित, विकसित राजस्थान', का ध्येय रखते हुए शिक्षा को विशिष्ट स्थान दिया है। मैं तो कहना चाहूंगा कि यह बजट शिक्षा को समर्पित है। इसमें वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमानों से भी 16 प्रतिशत अधिक का प्रावधान रखा गया है, लेकिन यह सोच माननीया मुख्य मंत्रीजी का पहले से भी रहा है। 2003 से 2008 तक, जब हमारी सरकार थी,

(श्री वासुदेव देवनानी)

उस समय भी हमने महत्वपूर्ण निर्णय किये। उस समय नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले, 6270 राजीव गांधी पाठशाला को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित किया, 21812 प्राइमरी से अपर प्राइमरी हमने क्रमोन्नत किये 17583, उच्च प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक में 4034, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक 1068 और शिक्षा विभाग में लगभग एक लाख शिक्षकों की हमने भर्ती की। माननीया मुख्य मंत्रीजी के निर्देशों में और सौभाग्य से मैं भी उनकी टीम में था। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अबकी बार केन्द्र ने कितना बजट डाउन किया है शिक्षा पर, अबकी बार, मोदीजी ने?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): लेकिन सही योजनाओं में आ रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, मोदीजी ने कितना कम किया, वह बता भी दें थोड़ा सा पूरे सदन को।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वह भी मैं बताऊंगा। बताऊंगा पूरा। एक-एक बताऊंगा। मैं राजस्थान का बोल रहा हूं, उनका भी बताऊंगा।

आज साइकिल वितरण कह रहे हो, 2007-08 में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने ही दसवीं में राजकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के लिए साइकिल वितरण योजना शुरू की थी और औपचारिक शिक्षा से वंचित जो बालक-बालिकाएं थे उनके लिए भी 21 मार्च, 2005 को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की थी जिसमें दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं होती हैं और आज भी कई लोग उसमें परीक्षाएं देते हैं।

लेकिन, मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि गत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में गम्भीर त्रुटियां कीं जिनके कारण वर्ष 2003 से 2008 तक हम 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' की ओर चल रहे थे, राज्य की इस विकास यात्रा को कांग्रेस सरकार ने 'ज्योति मा तमर्गमय' यानी, एक तो हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं लेकिन आपने प्रकाश से अंधकार की ओर धकेल दिया राजस्थान को जिसके कारण से आज स्थिति यह बनी और उस समय बिना किसी वास्तविक आकलन के, मेरे शिक्षक हैं या नहीं हैं, मेरे वहां विद्यालय के भवन हैं कि नहीं हैं, हमने फिर नए विद्यालय खोल दिये और 2776, 2220,

(श्री वासुदेव देवनानी)

3887, पता नहीं, स्कूल आप खोलते गये और इतना यह मकड़जाल हुआ कि केवल वाहवाही तो लूटी लेकिन न शिक्षकों की व्यवस्था हुई, न भवनों की व्यवस्था हुई, जिसके कारण से इतनी दयनीय स्थिति बनी है जो हमको विरासत में मिली है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह सब तो बंद कर दिये आपकी सरकार ने।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): बता रहा हूं, आ रहा हूं, उस पर, एक-एक का बताऊंगा। आज आप बैठिए, एक-एक का जवाब भी दूंगा और यहां तक, सुनो पहले, आपने केन्द्र सरकार की बात की।

केन्द्र सरकार से आपको 2010-11 में 5400 करोड़ रुपये 2392 विद्यालयों के लिए मिले, जिससे आपको 11200 निर्माण कार्य करने थे लेकिन आपने एक भी शुरू नहीं किया। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि 2011-12 में आपको एक पैसा नहीं मिला। अब इनकी कीमत बढ़ गयी, 748 करोड़ हुये, फिर आपको 2013-14 में भारत सरकार ने 124 करोड़ रुपये दिये, कम करके। उसको भी आपने शुरू नहीं किया। अब स्थिति यह बनी कि 2014-15 में हमको एक भी पैसा भारत सरकार से नहीं मिला। हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सहृदयता से जो कोस्ट बढ़ी, उसमें 244 करोड़ रुपये अपने स्टेट बजट से देकर 748 करोड़ से, आज सारे विकास के काम शुरू हो रहे हैं।

श्री संजीव कुमार (भादरा): सीखो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): और, दूसरा बताता हूं आगे। आपने आरटैट के बारे में जो दोषपूर्ण नीति अपनाई इसीलिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती स्थगित कर दी और आज भी वह भर्ती कानून में फंसी हुई है। इसमें यदि मैं कहूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी शायद नियति यही है कि जब 1998 से 2003 तक थे तब भी इन्होंने इस प्रकार की नीति की कि एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं कर पाये। जब हम 2003 से 2008 में सत्ता में आये तो 576 याचिकाओं का निस्तारण करके हमने आर.पी.एस.सी. से शिक्षकों की भर्ती करवायी और उस भर्ती के बाद जब यह लोग सत्ता में आये तो फिर शिक्षकों की भर्ती शायद करनी नहीं थी, ऐसे नियम बना दिये कि आज भी कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन में हम लोग लड़ रहे हैं और यह सारी आप लोगों की देन है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

आज नामांकन में बहुत कमी आयी है। आज इसके लिए सारा यदि मैं दोष दूं तो शायद, पिछली सरकार के हिसाब की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने प्रारम्भ से ही राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का तय किया है, दृढ़ निश्चय किया है, पिछड़े से पिछड़े वर्ग तक शिक्षा की पहुंच के साथ गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने स्कूलों को बंद कर दिया, पहले एक व्यवस्था थी कि कोई स्कूल क्रमोन्नत हुआ, उससे कक्षा 1 से 5 वाला प्राइमरी स्कूल अलग हो जाता था। फिर स्कूल क्रमोन्नत हुआ तो 6 से 8वीं तक वाला, अपर प्राइमरी वाला अलग हो जाता था। इसके आधार पर हमने उन सारी अव्यवस्थाओं को समाप्त किया है, 11591 प्राइमरी और 1659 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 7074 माध्यमिक विद्यालय और 3856 उच्च माध्यमिक विद्यालय में समन्वित किया है, हमने समन्वित किया है, बंद नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, ताले लग गये।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं बता रहा हूं। बिल्डिंगों के लगे हैं, स्कूल बंद नहीं हुए हैं। आपकी स्थिति बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 1 लाख 17 हजार ड्राप आउट हो गये।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह आपका कहना गलत है। आपका नामांकन ही बता रहा हूं मैं। कक्षा 1 से 10 तक इस समय 3461 और 1 से 12 तक 8342 विद्यालय चालू हैं और इसके लिए आपके ...(व्यवधान) हां, बता रहा हूं मैं। आपने जो शिक्षण व्यवस्थाएं कीं पांच साल उसका हाल यह हुआ कि 17 हजार स्कूल ऐसे मिले जहां पर जीरो, ढाई सौ स्कूल तो ऐसे थे जहां पर जीरो विद्यार्थी था और बाकी के इतने मिले जिसमें 15, 16, 10, केवल स्कूल खोलने हैं क्या और वहां पर अध्यापक लगे हुए हैं इसलिए उन सबको एक गुणवत्ता के आधार पर समन्वित किया है। हमने जोड़ा है, हमने कहीं भी और उसमें भी कह रहे थे ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): तोड़ा नहीं है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): तोड़ा नहीं है। इसलिए आप जो पूछ रहे थे, हमने एक निर्णय किया। कोई कह रहा था नेशनल हाई-वे, किसी ने कहा कि वहां पर कहीं नाला आ जाता है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जहां पर भी 30 से अधिक बच्चे हैं, वह पहले के स्कूल के भवन में ही चलेंगे और जहां पर 30 से कम हैं वह ही केवल मर्ज होगा, बंद तो नहीं होगा, मर्ज होगा और जहां पर 30 से अधिक बच्चे हैं उनका प्रशासनिक नियंत्रण जरूर हमने सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल के पास रखा है ताकि वहां अध्यापक जाएं, स्कूल में पढ़ाई हो, सारी व्यवस्थाएं ठीक हों। नहीं तो आप लोग ही कहते कि स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, कहीं रेलवे की पटरी आ रही है, कहीं हाइवे आ रहा है, कहीं नाला है। उन सबको हमने इससे मुक्त रखा है और आज भी सारे जन-प्रतिनिधियों को मैंने एक पत्र भी भेजा है और आपको कह रहा हूं यदि कहीं नियमों में कोई स्कूल आपको लगता है कि बंद नहीं होना चाहिये था, मर्ज नहीं होना चाहिये था, आप आयें, तत्काल हम उस स्कूल को वापस शुरू कर देंगे। कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुमास जाटान में सैकण्डरी स्कूल संचालित था मंत्रीजी, वहां आपने पूरा का पूरा प्राइमरी तक ही बंद कर दिया। पंचायत मुख्यालय पर स्कूल ही नहीं है। आपने यह स्थिति कर दी।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वह बता रहा हूं। यदि कोई पर्टीकूलर केस से आप लायेंगे, आप इतने दिनों में मिले ही नहीं। आपका यह फर्ज था यदि आपको शिक्षा की इतनी चिन्ता थी, चार महीने से यह दायित्व मेरे पास है, आप आते, मैं आपकी समस्या सुनता और वहीं उसका समाधान कर देता। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने उच्च शिक्षा में भी तय किया कि हमने विस्तार तो पर्याप्त किया, अब गुणवत्ता, सुदृढ़ीकरण की ओर बढ़ें। बच्चे कक्षा एक से पांचवीं तक एक स्कूल में जाते हैं, छठी के लिये उनको दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है, आठवीं के बाद नवीं में उसको तीसरा स्कूल बदलना पड़ता है। सरकार ने तय किया है कि हर पंचायत में कम से कम एक स्कूल ऐसा हो, जिसमें कक्षा एक से लेकर बारहवीं तक पूरी शिक्षा हो। जिसके आधार पर हमने स्कूलों को मर्ज किया और आज उन बारहवीं तक के स्कूलों में इतने

(श्री वासुदेव देवनानी)

दिनों में केवल आजादी के 66-67 वर्षों में सीनियर हायर सैकण्डरी के स्कूल कितने हैं? 4431 हैं। हमने एक ही वर्ष में, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, चूंकि उनका पूरा जोर शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और गरीब बच्चों के प्रति शिक्षा देने का है तो उन्होंने 5 हजार स्कूलों को एक साथ क्रमोन्नत कर दिया जो कि एक से बारहवीं कक्षा तक चलेंगे। फिर यहीं तक सीमित नहीं रहे। (व्यवधान) वो बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं। सुखरामजी, इसके बाद अध्यापकों पर ही आ रहा हूं। (व्यवधान) अभी खोले कहां हैं? जुलाई से खोलेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि खुल गये मतलब घोषणा कर रहा हूं, स्कूल तो जुलाई से शुरू होंगे और अध्यापक आ जाएगा। आप जितना जोर से बोलोगे उतना जोर से उत्तर दूंगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी इतनी सहृदयी हैं कि जो 718 नई पंचायतें हुईं, लोगों ने कहा कि इनका क्या होगा? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि इन पंचायतों में भी हम चरणबद्ध रूप से सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल स्थापित करेंगे। इसके आधार पर आगामी तीन वर्षों में, क्योंकि यह तो मैं भी मानता हूं कि आप कह देंगे कि साहब अगली बार का जैसे माननीय विधायक महोदय, सुखरामजी पूछ रहे हैं कि अगले साल यह कहां हुआ? तो इसमें चरणबद्ध शब्द नोट कर लीजिये। इसमें 4431 स्कूलों को तो हम 2016-17 तक करेंगे और बाकी के स्कूलों को, पूरे 9,895 को 2017-18 तक आदर्श स्कूल के रूप में खड़ा करेंगे, जिसमें न तो कोई अध्यापक की कमी होगी, वहां पर कम्प्यूटर की सारी व्यवस्था होगी, कहीं पर भी कमरों की कमी नहीं होगी और बिलकुल एक आदर्श स्कूल के रूप में जहां पर बच्चे पहली कक्षा से बारहवीं तक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसकी सारी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सुखरामजी वाली स्कूल में जरूर कर देना।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): सब करेंगे। साथ में अभी जो माननीय सचेतक महोदय पूछ रहे थे.... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): इस तीन साल की अवधि को कृपया दो साल करें तो बहुत आदर्श होगा, क्योंकि अभी यह 2015-16 का साल है, फिर 2016-17 का भी साल है। जो भी नई पंचायतों का गठन हुआ है, उनके लिये मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इनको दो साल की प्रक्रिया में ही सब जगह उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करें।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय, हम तैयारी करेंगे लेकिन घोषणा होती है, मैं केवल यहां पर आश्वासन देकर, घोषणा करके इतने लैक्चरर्स, जो आदर्श स्कूल होगा, उसमें एक प्रिंसिपल होगा, 5 लैक्चरर्स होंगे, 3 विषय-अध्यापक होंगे, तो सब की व्यवस्था और आर.पी.एस.सी. से कुछ लोग चयनित होंगे, कोई डी.पी.सी. होगी, इसलिये सारी व्यवस्थाएं करने में जितना न्यूनतम समय लगेगा उतना हम उसमें लगायेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बहुत मोटा काम है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): कोई छोटा काम नहीं है। इसलिए कई बार कहते हैं जो हमने क्रमोन्नत किया, जब 4431 से 9 हजार हो गये तो आधे में तो सारे देवी-देवता और आधे में क्षेत्रपाल, यह जो राजस्थानी कहावत है उसको हमने चरितार्थ किया है। अब उसमें हम यहां भी सीमित नहीं रहे हैं। हमने आदर्श विद्यालय खड़ा करने का तय किया है। राजस्थान के अन्दर भारत सरकार की ओर से एक-एक पिछड़े ब्लाक के अन्दर राजकीय माडल स्कूल खड़ा करने का प्रावधान आया और उसका नाम हमने स्वामी विवेकानन्द के नाम पर रखा। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था 'हमें ऐसे बालकों का निर्माण करना है, जिनके चेहरों पर आभा, भुजाओं में बल, जीवन में स्वावलम्बन, बुद्धि में पांडित्य, मन में प्रचण्ड इच्छाशक्ति तथा हृदय में ध्रुव प्रह्लाद और शिवा की जीवन गाथाएं अंकित हों, जिन्हें देकर महापुरुषों की स्मृतियां झंकृत हो उठें। इसीलिये हमने इन माडल स्कूल का नाम स्वामी विवेकानन्द पर रखा। आज 66 स्वामी विवेकानन्द माडल स्कूल चल रहे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी एक मिनट लूंगा। मेरा निवेदन है कि मैं पर्टीकूलर पार्टी की बात नहीं कर रहा। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की रही, लेकिन जहां अपन बैठे हैं, सदन है, यह प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है और यहां पर सारे प्रदेश की जनता देख रही है आप जो बोल रहे हो, और यह कल छपेगा भी, लेकिन एक बड़े शर्म की बात है सभी पार्टियों के लिये, मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी के लिये या कांग्रेस के लिये, आठवीं क्लास का स्टूडेंट है, वह हिन्दी नहीं पढ़ सकता, नहीं मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुन लो। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आ रहा हूं, इसी पर आ रहा हूं।

श्री रमेश (सपोटरा): और एक दिन ऐसा आयेगा राजस्थान का... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने ऐसी स्थिति पैदा की, कांग्रेस ने ऐसी स्थिति पैदा की, जिसके कारण से यह स्थिति बनी। (व्यवधान) गहलोत जी और कांग्रेस के कारण से यह स्थिति बनी है कि आपने आठवीं तक फेल नहीं करने का जो निर्णय लिया था, यही वह कारण है। (व्यवधान) उसका कारण आप हैं, कांग्रेस है। रमेशजी, यह कांग्रेस के कारण से स्थिति पैदा हुई। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा): आपने राजस्थान के ऐसे हालात पैदा किये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): कांग्रेस के ऐसे कारनामे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कांग्रेस के कारण से यह स्थिति बनी है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): इस दिशा में निर्णय लें, नहीं तो आने वाली जनरेशन आपको कभी माफ नहीं करेगी। मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: रमेशजी, यह आपके यूपीए सरकार की देन है।

श्री रमेश (सपोटरा): पार्टियों में ही वाहवाही ले सकते हो। आने वाली जनरेशन आपको ..(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इसका जवाब तो आपको देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): इस पर निर्णय होना चाहिये कि फाउण्डेशन... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पूरी जवाबदारी आपकी है, कांग्रेस पार्टी जवाबदार है इसके लिये। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): कैसे बढ़ायें, इस पर विचार हो। आप वाहवाही लूटकर जाओगे, अख़बार में छप जायेगी, इससे होगा क्या?

श्री हीरालाल (निवाई): कांग्रेस ने देश पर 50 साल राज किया, यह सब आपकी है। 50 साल राज किया, अब पूछ रहे हो। क्या कर रहे हो यूं? (व्यवधान) 50 साल राज किया कांग्रेस ने। सारा भट्ठा बिठा दिया देश का। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सक्षम हूं। 2014-15 के अन्दर 66 स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल

(श्री वासुदेव देवनानी)

शुरू हो गये। इन माडल स्कूलों में 8,940 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और 2015-16 के अन्दर हम 5 नये स्कूल शुरू कर रहे हैं और यह सारे सी.बी.एस.ई. से सम्बद्ध होंगे। अंग्रेजी माध्यम के होंगे और इनमें सारी आधुनिक तकनीक होगी, जिसमें आई.सी.टी., लैब, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सैटकाम, इंग्लिश लेंग्वेज लैब, इसमें गरीब वर्ग के जब बच्चे होंगे, मैं समझता हूं आपको तो पीठ थपथपानी चाहिये कितना महत्वपूर्ण काम हो रहा है। और 2015-16 के अन्दर...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप इंग्लिश की बात कर रहे हो, उधर मैकाले को गाली निकाल रहे हो। आपने खुद विवेकानन्द माडल स्कूल में इंग्लिश शिक्षा को चालू किया। एक तरफ मैकाले को गाली, एक तरफ इंग्लिश में भर्ती, यह दोगली बात क्यों हो रही है? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह सुखरामजी सबसे दु:खीराम हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): स्वामी विवेकानन्द ने कभी भी अंग्रेजी पढ़ने के लिये मना नहीं किया। शिकागो गये, उन्होंने अंग्रेजी में भाषण किया। उनका अंग्रेजी भाषा से विरोध नहीं था। 2015-16 के अन्दर हम नये विद्यालय और 63 माडल स्कूल्स शुरू कर रहे हैं। अब आप सुनो 63 माडल स्कूलों के लिये 2010-11 के अन्दर पैसा आया 3 करोड़ 2 लाख रुपये लेकिन इकाई लागत में वृद्धि होने के कारण आपने निर्माण काम शुरू नहीं किया और आज माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 237 करोड़ 90 लाख रुपये अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराकर इन माडल स्कूलों का निर्माण करने के लिये हमको दिया है। आपने कहा इंग्लिश मीडियम, इन माडल स्कूलों में नैतिक मूल्यों, भारतीय संस्कारों एवं सह-शैक्षिक गतिविधियों पर विशेष बल दिया जा रहा है, जैसे सूर्य नमस्कार, योग, मेडिटेशन इन सबको हम लोग समावेश करने वाले हैं। आपमें से कुछ सदस्य कह रहे थे कि यह जो माडल स्कूल बने हैं इसमें अभी कमियां हैं।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): सुनो। इनको जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड बिदकता है न वैसे सूर्य नमस्कार के नाम से इनको ... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं तो आगे भी कहने वाला हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन विद्यालयों को आर.एस.एस. की शाखा मत बनाओ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): सूर्य नमस्कार न आर.एस.एस. का है न बी.जे.पी. का है, सूर्य तो पता नहीं हजारों वर्षों से है, उससे आप भी ऊर्जा लेते हो और यह तो व्यायाम है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): कांग्रेस पार्टी का जन्मदाता ...(व्यवधान) इनको तो जितनी बात होगी उतनी ही बात करेंगे।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अब 71 माडल स्कूलों में भी जो कुछ कमियां रही हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी राज्य सरकार के द्वारा 200 करोड़ 66 लाख रुपये का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया है ताकि यह भी विद्यालय व्यवस्थित हो सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह शिक्षा विभाग का दायित्व मेरे पास आया उस समय केन्द्र सरकार की जो योजना है रमसा उसमें राजस्थान तेरहवें नम्बर पर था लेकिन आज फरवरी आते-आते यह राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर आ गया है। दूसरे नम्बर पर तमिलनाडू है, तीसरे नम्बर पर कर्नाटक है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसा क्या कर दिया कि 12 महीने में पहले नम्बर पर आ गये?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हां वो ही बता रहा हूं। इसमें यह किया कि सारे पैसे जो आपने खर्च नहीं किये, हमने सही ढंग से खर्च कर के यू.सी. भेज दी, इसके आधार पर हम पहले नम्बर पर आये हैं और हमको और पैसा मिला है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मंत्री महोदय, आप में इतना जोश कैसे है, मेडिकल कराने की आवश्यकता है क्या?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। आज डोटासराजी नहीं आते तो मजा ही नहीं आता।

अब असली बात। एक बात और जो महत्वपूर्ण है। (व्यवधान) सुनो तो सही। यह सूर्य नमस्कार का परिणाम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब लगभग सभी माननीय सदस्यों ने रिक्त पदों की बात कही कि स्कूलों में पद नहीं है, मैं यह बात मानता हूं पदों की बहुत कमी है और मुझे यह सब विरासत में मिला है। विरासत में जो कुछ

(श्री वासुदेव देवनानी)

मिला है उसकी स्थिति का यदि वर्णन करूंगा तो मुझे भी बहुत बड़ी पीड़ा होती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कालीचरणजी ही तो देकर गये हैं विरासत।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं, आपने दी है। (व्यवधान)

आज यह तथ्य है कि प्रधानाचार्यों के पद 46.6 परसेंट खाली हैं। प्रधानाध्यापक के पद 38 परसेंट खाली हैं और व्याख्याताओं के पद 55 परसेंट खाली हैं, बाकियों के पद खाली हैं लेकिन हमारी सरकार ने आते ही पिछले चार महीने के अन्दर हमने प्रयत्न किया, विषय अध्यापक 47 परसेंट खाली थे, हमने 21,843 शिक्षकों के पद भर करके आज केवल 12 परसेंट खाली रह गये हैं जिसको भी हम आगामी दिनों में भर देंगे। जहां तक प्रधानाचार्य की बात है, 2014-15 की डी.पी.सी. हो गयी, उसमें 1604 पद हमने भर दिये हैं, पोस्टिंग होनी है, विधान सभा सत्र होने के बाद उनकी पोस्टिंग हो जायेगी। आपने कहा कि स्कूल क्रमोन्नत होते हैं पद सृजित नहीं होते, आपको सुन कर सुखद अनुभूति होगी कि हमने जो नये स्कूल खोले उसके लिए 5000 प्रिंसिपल के पद सृजित कर दिये हैं और प्रधानाध्यापकों के पद 1007 डी.पी.सी. से और 535 पद आर.पी.एस.सी. से हमने भर दिये। जो व्याख्याताओं के हैं, जो सारी पीड़ा है वो अधिकतर व्याख्याताओं की है। मुझे पता है, मैं अध्यापक हूं। यहां पर अध्यापक के नाते बोल रहा हूं, मंत्री के नाते नहीं बोल रहा हूं। यदि किसी स्कूल में हैडमास्टर या प्रिंसिपल नहीं होता, किसी स्कूल में व्याख्याता नहीं होता उस स्कूल की क्या स्थिति होती है, मैं समझ सकता हूं। यह जो स्थिति बनी है, यह बिजली का बटन नहीं है कि आन-आफ करते ही सारे भर दिये जाएं, इसमें समय निश्चित रूप से लगेगा इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी दिनों में हम लगभग 12 हजार व्याख्याताओं के पद भरने जा रहे हैं। आर.पी.एस.सी. ने अभी चार विषयों के तो परिणाम घोषित कर दिये और आगामी सप्ताह, दस दिन में बाकी विषयों की भी हो जाएगी।

जहां तक विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों की बात है वो 21 हजार मैंने आपको बता दिया। शारीरिक शिक्षक की बात आयी कि साहब, पी.टी.आई. नहीं हैं, शारीरिक शिक्षक 1041 सैकण्ड ग्रेड के और 2858 थर्ड ग्रेड के, इन रिक्त पदों के लिए आर.पी.एस.सी. के द्वारा परीक्षा हो चुकी है, परिणाम की प्रतीक्षा है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो ना पक्ष में बैठे हैं उनका काम समस्याएं खड़ी करना रहा है, 'ये दर्द देते हैं हम दवा करते हैं, पहले आग लगा फिर अब हवा करते हैं। 1998 से 2003 की सरकार में पैराटीचर की भर्ती कर हमारे लिए समस्याएं छोड़ गये। हमने उसको प्रबोधक बना करके उस समस्या का समाधान किया।

आज भी आपने यहां पर बहुत बड़ी समस्या छोड़ी है। अब हमारे सामने विद्यार्थी मित्र के बारे में जो चर्चा आयी उसमें ...(व्यवधान) पांच साल तक आपने तो कुछ नहीं किया। अब आप और हम, इस पर मैंने पहले ही कहा कि शिक्षा के अन्दर, मैं आगे कहने वाला हूं, राजनीति के अन्दर तो शिक्षा चाहिए लेकिन शिक्षा के अन्दर राजनीति नहीं चाहिए। यह सबको ध्यान में रखना चाहिए।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): ज्ञान की बात कही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ले रहे हो क्या मंत्रीजी, विद्यार्थी मित्रों को?

एक माननीय सदस्य: सुनो, सुनने का माद्दा रखो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इसलिए इन विद्यार्थी मित्रों के लिए विद्यालय सहायक के नाम से नया संवर्ग सृजित करने का निर्णय लिया जा चुका है, प्रोसेस में है, बहुत जल्दी इसकी विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी जिससे इनको भर्ती देकर कर हम इन लोगों को राहत प्रदान करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहें, शांत रहें। मंत्रीजी का वक्तव्य होने दीजिए। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मैं, मंत्री महोदय, एक बात कहना चाहूंगा कि विद्यार्थी मित्रों को हटाने से जुलाई से जो विद्यालय बंद हुए हैं उनको भी चालू करने का सरकार विचार रखती है क्या? हुए हैं, बीकानेर में हुए हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): बैठिये। जवाब दे रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि सरकार का मानस एक भी विद्यालय बंद करने का नहीं है। हम उसको व्यवस्थित और रेशनलाइज कर रहे हैं, समन्वित कर रहे हैं लेकिन कहीं भी बंद करके विद्यार्थियों का अहित यह सरकार नहीं करेगी, न मैं शिक्षक होने के नाते करूंगा।

(श्री वासुदेव देवनानी)

लिपिकों की बात कही गयी, कई ने कहा, एकाध प्रश्न भी आये और बाकी ने भी कहा, 5720 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की जो अर्थना आयोग को भिजवायी थी, आयोग परीक्षा आयोजित करवा चुका है, हम केवल उसके परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इसके अलावा अधीक्षक के 91, कार्यालय सहायक के 206, वरिष्ठ लिपिक के 996, कनिष्ठ लिपिक के 359 और जमादार के 107 रिक्त पदों को डी.पी.सी. से भरा है। मेरी एक मान्यता है, हमारे जिस भी कर्मचारी का जो कुछ ड्यू है वो उसको सही समय पर मिलना चाहिए। पांच साल तक आपने डी.पी.सी. नहीं करायी, सारे हमारे जो भी कर्मचारी हैं, शिक्षक भाई हैं उन सबके साथ अन्याय हुआ है इसलिए आते ही इसको प्रारम्भ किया और आज यह सदन के सामने आश्वस्त करता हूं कि अभी तो 31 मार्च तक की डी.पी.सी. करवा ली, एक अप्रैल, 2015 से हम अगले वर्ष की भी डी.पी.सी. प्रारम्भ कर देंगे ताकि कोई भी कर्मचारी इससे वंचित न रहे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, 2012 में थर्ड ग्रेड के लगे थे उन अध्यापकों को दो साल हो गये, आप उनको नियमित तो कर दीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वो बता रहा हूं। आज शायद मैंने कहा है कि आपके किये हुए जो भी काम हैं उसके कारण से कोर्टों के अन्दर लम्बित प्रक्रियाएं हैं, उन सबसे जैसे ही निजात मिलेगी हम निश्चित रूप से अपेक्षित कार्यवाही जरूर करेंगे। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आपके किये हुए पाप।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह आपके पाप तो शब्द, चूंकि मैं एक शिक्षक हूं इसलिए पाप तो नहीं कहता इसलिए मैंने काम कहा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कालीचरणजी की बात मत मानो। इनकी बात मत मानो आप।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं आपकी बात मान रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो-तीन बिन्दु और हैं। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए है, माननीय नरेन्द्र मोदी का आह्वान है कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और इसके लिए हमने साइकिलें खरीद कीं, अब साइकिल वितरण योजना है ...

श्री रमेश (सपोटरा): अभी तक नहीं दे पाये।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): सुनो तो सही, बता रहा हूं। पूरा सुनने के बाद जितने प्रश्नों के उत्तर होंगे, एक-एक देने के बाद इस सदन से जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): साइकिल वितरण योजना निश्चित रूप से 2007-08 की घोषणा हुई थी अब 2014-15 की बजट घोषणा में नवीं में पढ़ने वाली, आपने तो नकद राशि देकर के अपना पिंड छुड़ाया था, हमने तय किया कि हम नकद राशि नहीं देंगे, हम साइकिल देंगे और वो साइकिल ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): साइकिल में कमीशन लेंगे... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): कोई कमीशन नहीं है। आज कहीं भी यह सिद्ध कर दो तो मैं शायद, केवल विपक्ष का काम है, आप आरोप लगाते हो। आपने कमीशन लिया होगा इसलिए शायद ...(व्यवधान) आपका यह कल्चर है, संस्कृति है, इसमें मैं नहीं पड़ता।

इस बार 2 लाख 68 हजार साइकिलें वितरित की हैं और वह लगातार चल रही हैं। सदन को आश्वस्त करता हूं कि इस साल तो देर हुई है लेकिन अगले साल आजादी के दिन, 15 अगस्त से पहले बच्चियों को नई साइकिलें मिल जाएंगी, यह मैं सदन में घोषणा करता हूं। व्यवस्थाओं को सुधारने में समय लगता है। मैं व्यवस्थाएं ठीक कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: डोटासरा साहब भी मेज थपथपा रहे हैं आपके इस स्टेटमेंट पर।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): जो बालिकाएं 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से आती हैं, जो साइकिल की योजना में नहीं आती हैं। उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा दी जा रही है और 2015-16 से पंचायत समिति स्तर पर विवेकानंद राजकीय माडल स्कूल हैं, उनमें भी बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा हम लोग देंगे। यह मैं घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शारदीय बालिका छात्रावास की बात आई। 186 ब्लाकों में से 125 ब्लाकों में आज वह चल रहे हैं। 2015-16 में हम 24 और नये छात्रावासों का निर्माण कार्य पूरा करके संचालन प्रारम्भ कर देंगे और

(श्री वासुदेव देवनानी)

शेष जो 37 हैं, उन छात्रावासों का निर्माण कार्य हम 2015-16 में प्रारम्भ कर देंगे। आप वाहवाही तो लूटते थे लेकिन आप इन बच्चियों को कितना पैसा देते थे? 850 रुपये, इन रुपयों से कभी यह सम्भव है, हमने उसको बढ़ाकर के 1500 रुपये किया है ताकि बच्ची आराम से खा-पी सके।

साथ ही अभी मेरे कुछ बन्धुओं ने कहा कि छात्रावासों की स्थिति ठीक नहीं है। स्वच्छ पेयजल हेतु वह आर ओ लगवाएं, अन्य सुविधाएं विकसित हों और वहां पर साफ-सुथरे बिस्तर हों, इसलिए ढाई लाख रुपये प्रति छात्रावास हमने उनको देने का निर्णय किया है।

और आगे सुनो, बालिका शिक्षा फाउंडेशन से गार्गी पुरस्कार तो काफी समय पहले से चल रहा है। लेकिन इसमें बच्चियां अधिक से अधिक संख्या में आएं और इस बार मुझे प्रसन्नता है कि 44 हजार बालिकाओं ने गार्गी पुरस्कार प्राप्त किया। इसके लिए मैं निश्चित रूप से सबको बधाई देता हूं। कोशिश करता हूं कि यह संख्या और नियमित रूप से बढ़े। जहां पर 'आपकी बेटी' हमारी योजना है, उसमें भी इस बार संख्या में वृद्धि हुई है, 25094 बालिकाओं को हमने कक्षा 1 से 8 और 9 से 12 में जिनके माता-पिता या दोनों में से कोई एक नहीं हो, उनको 1100 रुपये, 1500 रुपये हम देते हैं, वह भी 25 हजार बालिकाओं को हमने दिया है।

विद्यालयों में भवन निर्माण, आपने कहा कि निर्माण नहीं हुए। लेकिन मैंने कहा कि आपने तो कुछ खर्चा ही नहीं किया। हमारी सरकार ने आते ही सर्व शिक्षा अभियान में 802 नवीन विद्यालय भवन, 2602 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 678 शौचालय और 155 पेयजल सुविधाएं दिसम्बर, 2013 के पश्चात् निर्माण कार्य करवाये हैं। इसी तरह हमने 2014-15 के अन्दर 1114 करोड़ की लागत से 3406 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 3030 विज्ञान प्रयोगशालाएं, 2633 कम्प्यूटर कक्ष, 1658 पुस्तकालय कक्ष, 3371 आर्ट/क्राफ्ट/कल्चर रूम, 1198 शौचालय एवं 144 पेयजल सुविधाओं सहित 15530 इकाइयों का निर्माण किया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): शौचालय तो बना रहे हो लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने बजट में टायलेट क्लिनर तो महंगा कर दिया।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजें। उनको पूरा करने दें।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आ रहा हूं। उस पर भी आ रहा हूं। इसी तरह लैपटाप वितरण की योजना ...(व्यवधान) बहुत मैटर है, आप चिंता मत करो। लैपटाप योजना में 2013-14 में हमने तय किया कि जो दसवीं और बारहवीं में प्रथम 6 हजार बच्चे आते हैं और उसके बाद आठवी में वैकल्पिक बोर्ड है, उसमें जो पहले 5 हजार होंगे तो 18 हजार तो यह हुए लेकिन हम संवेदनशील हैं, इस 18 हजार में सोचा कि कई अच्छे विद्यार्थियों का नाम, गांव के विद्यार्थियों का नाम नहीं आता। हर जिले के पहले 100 प्रत्येक वर्ग के अन्दर जो विद्यार्थी होंगे उनको भी हम लैपटाप देंगे। इस तरह मिलाकर के पूरे राजस्थान के लोगों को हम लैपटाप दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): निजी स्कूलों के छात्र-छात्राओं को?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वह बता रहा हूं, निजी वालों को उनका मैनेजमेंट दे। हम सरकारी स्कूलों को देंगे। निजी मैनेजमेंट उनसे फीस लेता है और सब कुछ करता है तो निजी स्कूलों को वह बढ़ावा देने के लिए दें।

समावेशी शिक्षा, जो विशेष योग्य जन हैं, इसमें पद का, प्रमोशन का कहीं कोई प्रावधान नहीं था। पिछले दिनों मंत्रिमंडल के अन्दर इसके 485 पदों में से डीपीसी द्वारा भरे जाने वाले 283 का द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदस्थापन किया है। एक कैडर शुरू किया ताकि यह भी सैकिण्ड ग्रेड टीचर बन सकें। इसकी व्यवस्था की है। साथ में मैं एक घोषणा कर रहा हूं कि आज तक कामर्स के, कृषि के, संगीत के, चित्रकला के अध्यापकों के प्रमोशन का कहीं कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस बार यह लगभग 10 हजार अध्यापक हैं, जो शायद थर्ड ग्रेड में रिटायर होते, इनकी भी डीपीसी कराने की स्वीकृति दी जा चुकी है और यह भी सैकिण्ड ग्रेड टीचर बनेंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय मंत्री महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि थर्ड ग्रेड अध्यापकों के वेतन में विसंगति है, इसको दूर कब कराओगे?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वह भी आ रहा हूं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उसकी बताइये। मंत्री महोदय, आप अध्यापक हैं और अध्यापक के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए विशेष कहना चाहता हूं कि गम्भीर विसंगतियां हैं उसको दूर कराइये।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आप जिस हालत में छोड़ गए और जो दुर्दशा देखी, सारे देश भर में उसकी जो हालत खराब हुई। मैं अच्छे शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। पेपर आउट होना एक बात थी, लेकिन किस तरह से वहां का फाइनैन्सियल आफिसर पकड़ा गया और सारी बातें हुई। लेकिन आज वापिस वह बोर्ड अपने गरिमामय स्थान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ गया है। इस बार बोर्ड में 80 हजार से ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। टोटल 19 लाख 41 हजार छात्र इस बार दसवीं और बारहवीं की परीक्षा दे रहे हैं। इतना ही नहीं बोर्ड को हमने आठवीं की परीक्षा भी लेने को कहा। कई और परीक्षाएं भी वह करा रहा है। बोर्ड की गरिमा आगे बढ़ रही है। इस बार बोर्ड ने घोषणा की कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी एवं शिक्षकों को प्रोत्साहन देकर, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यालयों को प्रति वर्ष 50-50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

मैंने पूर्व में कहा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी कितनी दूरदर्शी हैं कि उन्होंने 2005 में स्टेट ओपन स्कूल शुरू किया। आज जब उन्होंने पंचायत चुनाव में शिक्षा का निर्धारण किया तो आपको सुनकर के खुशी होगी कि जबसे दसवीं किया इस बार हमारे स्टेट ओपन स्कूल में पहले की तुलना में ढाई गुणा पढ़ने वालों की वृद्धि हुई है। अब हरेक आकर के दसवीं और बारहवीं की परीक्षा देना चाह रहा है। मैं समझता हूं कि यह शिक्षा की ओर अच्छा कदम है। उसमें प्रथम बार हमने पुरुष और महिला वर्ग के जो पुरस्कार हैं, इनका नाम चूंकि विद्यार्थी हैं, बिना शिक्षक के वह परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि यह तो ओपन स्कूल हैं, तो उस पुरस्कार को हमने एकलव्य पुरस्कार नाम से नामांकित किया है। जो महिला हैं उनको मीरा पुरस्कार के नाम से हम 5100 रुपये नकद और प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित कर रहे हैं। साथ में स्टेट ओपन स्कूल का जो भवन है उस भवन का नाम स्टेट ओपन स्कूल लिखा रहता था, उस भवन का नाम भी एकलव्य भवन हमने रख दिया है। जिसके आधार पर लोग प्रेरणा ले सकें कि एकलव्य की तरह हमको पढ़ाई करनी है। यह संस्कार पड़ेंगे, नाम से भी संस्कार आते हैं। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति देखेंगे तो मन में संस्कार आएंगे इसलिए हर जगह स्वामी विवेकानंद की मूर्ति भी लगाई है।

इस विभाग द्वारा पंचायत समिति स्तर पर 70 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में जो पुस्तकालय संचालित हुए हैं, उसमें 58 स्थानों पर भवन निर्माण कराया जा रहा है, 11 स्थानों पर पूरा हो गया है, शेष 12 स्थानों पर भी हम बहुत जल्दी जमीन उपलब्ध होने पर शुरू करा सकेंगे।

(श्री वासुदेव देवनानी)

साथ में जो नई पंचायत समितियां बनी हैं, इन पंचायत समितियों में भी पुस्तकालय हम शुरू करेंगे।

अब कुछ जो हमने काम प्रारम्भ किए हैं। शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है आपको पता है, 4 लाख 34 हजार इसमें शिक्षक हैं। शायद राजस्थान का दो तिहाई सरकारी कर्मचारी इस शिक्षा विभाग के अन्तर्गत है। समस्या भी इस कारण से बहुत हैं लेकिन हम समस्याओं से घबराएंगे नहीं, समस्याओं का समाधान करेंगे इसलिए प्रयत्न किया है कि शिक्षा संवाद का एक कार्यक्रम शुरू किया जाए।

(20.00 बजे)

माननीय मुख्य मंत्रीजी की प्रेरणा से एक अभिनव पहल, प्रत्येक जिले में जाकर शिक्षा अधिकारियों की और जन-प्रतिनिधियों की बैठक करके, उनसे समस्याएं लेकर, उनके साथ में संवाद करके उनकी समस्याओं का वहीं समाधान हो। आज तक 11 जिलों में शिक्षा संवाद हो चुका है और आगामी दो-तीन महीनों में बाकी 22 जिलों में होकर पूरे 33 जिलों में हम इसका कार्यक्रम करके इस स्थिति को सुधारने में आगे बढ़ेंगे। (व्यवधान) बिलकुल आप निश्चित रहें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि आखिर शिक्षा हम क्यों देते हैं, शिक्षा कैसी देते हैं, स्वस्थ और संस्कारयुक्त शिक्षा व्यवस्था हो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा पैरा 8.21 पर, शरीर और मन के समेकित विकास के साधन के रूप में योग शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा, यह 1986 का है। सभी विद्यालयों में योग की शिक्षा के प्रयास किए जाएंगे। इसी क्रम में और इस समय जब प्रधान मंत्रीजी मोदीजी के कहने पर 21 जून को सारा विश्व योग दिवस मनाने जा रहा है, राजस्थान ने इसमें पहल की, राजस्थान के सारे स्कूलों में सूर्य नमस्कार, योग और ध्यान तीनों वहां पर कराये जाएंगे। सूर्य नमस्कार से शरीर स्वस्थ होगा, योग से शरीर स्वस्थ होगा और ध्यान से मन स्वस्थ होगा इसलिए बालक श्रेष्ठ बनकर आगे बढ़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाए। सूर्य नमस्कार आपने नहीं किया हो...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सूर्य की ओर आप भी नहीं देख सकते, बच्चा तो क्या देखेगा, जब दस बजे स्कूल में जाएगा और गर्मियों

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

में मई, जून में तो सूर्य नमस्कार क्या कराएंगे, आप भी नहीं देख सकते सूर्य को।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप सूर्य नमस्कार का भाव ही नहीं समझे। आप केवल अक्षरों तक जाते हो, सूर्य नमस्कार एक योग का नाम है जिसमें नौ योग सम्मिलित हैं, उन नौ योगों के पूर्ण योग को सूर्य नमस्कार कहा जाता है, उसको करवाते हैं। (व्यवधान) नई शिक्षा नीति के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी की प्रेरणा से देश के शिक्षाविदों की बैठक की है। (व्यवधान) आप उस सूर्य नमस्कार को कुछ और कह देना मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन होगा सूर्य नमस्कार।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि नवीन संकाय खोले जाएं। विद्यार्थियों की मांग और आवश्यकता के अनुरूप हम नए संकाय भी खोलेंगे और जन प्रतिनिधियों की भावनाओं के अनुरूप जहां 30 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय होंगे वे पूर्ववत भवनों में संचालित किए जाएंगे।

अब एक मुद्दा और है, प्राइवेट स्कूलों की समस्या। प्राइवेट स्कूलों में फीस नियंत्रण का कार्यक्रम चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान) बता रहा हूं सुन तो लें। (व्यवधान) वही कर रहा हूं उसी के सहयोग के लिए कर रहा हूं। न तो प्राइवेट स्कूल के संचालकों को दिक्कत हो, न अभिभावकों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए इसके लिए मैंने बाकी प्रांतों में भी क्या व्यवस्था है वहां से सारे डाटा मंगवाए हैं, दोनों के प्रतिनिधियों से मैंने बात भी की है और उस बातचीत के आधार पर हम बहुत जल्दी कोई न कोई परिणाम तक पहुंचेंगे। आपकी भावनाओं से मैं सहमत हूं कि शिक्षा का निजीकरण होना चाहिए लेकिन उसका व्यावसायीकरण नहीं होना चाहिए इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। (व्यवधान) हमारे यहां जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आई, जो आपने कहा,...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय कालीचरणजी को मत देना नहीं तो यह व्यावसायीकरण सिखा देंगे।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्य को व्यावसायीकरण और राजनीतिकरण का पता ही नहीं है, चाहे जो बोल देते हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात शिक्षा की सारी व्यवस्थाएं तो हो जाएंगी लेकिन इनकी यदि मानिटरिंग नहीं होगी तो व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो सकतीं। मुझे कहते हुए बहुत पीड़ा होती है कि 16 साल, 1998 में आपने एक निर्णय लिया कि 50 पर्सेण्ट पद हम डीईओ के डाइरेक्ट सीधी भर्ती से करेंगे और 50 परसेंट डीपीसी से करेंगे लेकिन वह कभी भी सीधी भर्ती से हुए नहीं इसलिए डीपीसी से जो 50 परसेंट थे उनमें से कभी 40 परसेंट उपलब्ध होते और कभी 45 परसेंट होते तो एक तिहाई डीईओ से गाड़ी चल रही थी लेकिन हमने निर्णय किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, मैं उनकी निश्चित रूप से कृतज्ञता करूंगा कि उन्होंने 142 डीईओ को एक बार सारे पद सीधी भर्ती की जगह डीपीसी से भरने के लिए अनुमति दे दी है, जिसको 1 अप्रैल को प्रारम्भ करके 15 अप्रैल तक हम इन सबको नियुक्तियां भी दे देंगे, पद स्थापन कर देंगे। यह एक ऐतिहासिक काम होगा। फिर एक बड़ी समस्या और थी माननीय अध्यक्ष महोदय, व्याख्याता और प्रधानाध्यापक, दो पद थे जिनका प्रिंसीपल में प्रमोशन होता है, व्याख्याता तो थे 33 हजार और प्रधानाध्यापक थे 9 हजार, उसमें से भी अभी 5 हजार क्रमोन्नत हो गए तो 50:50 रेशो था। सरकार ने तय किया कि यह रेशो 67:33 होगा जिसके कारण व्याख्याताओं के साथ न्याय हो सके, इससे हमें सब जगह व्याख्याता भी मिलेंगे और सब व्यवस्थाएं भी ठीक होंगी।

सबको जब काम करना होता है तो विश्वास में भी लेना होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको शायद आश्चर्य होगा कि इन शिक्षक संगठनों के साथ किसी ने बात तक नहीं की। जितने भी राजस्थान के शिक्षक संगठन हैं, उन सबके अध्यक्षों और महामंत्रियों को बुलाया, मैंने बातचीत की, मैंने कहा आपकी डीपीसी करवा रहे हैं, आपके नए पद भर रहे हैं, आइए आप भी सरकार के इस विद्या के यज्ञ में शामिल होइए नामांकन बढ़ाइए, ठहराव बढ़ाइए, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए, इस प्रकार का उनसे अनुरोध किया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह प्रदेश स्वर्ग कब तक बन जाएगा आपके हिसाब से?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वही जवाब दे रहा हूं, आपका सहयोग मिलेगा तो जल्दी बनाएंगे, आप सहयोग करेंगे तो जल्दी बनाएंगे। (व्यवधान) यह सहयोग आप लोग करते तो पांच साल में बना लेते लेकिन अब हम आएं हैं तो करेंगे।

(श्री वासुदेव देवनानी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा पहले कहा कि शिक्षा में राजनीति नहीं बल्कि राजनीति में शिक्षा की आवश्यकता है। प्रत्येक बालक को शिक्षित, दीक्षित करना हमारा साध्य है। एक विद्वान ने कहा कि केवल शिक्षा के लिए वातावरण बनाने की आवश्यकता है, शेष बातों के लिए शिक्षा अपने आप वातावरण बना लेगी इसलिए आज आवश्यकता है कि हम शिक्षा का वातावरण बनाएं। जिस तरह शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करती है उसी तरह शिक्षा से हम राज्य का सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। हमारे यहां केवल जो बजट की घोषणाएं थीं उनकी हमने मानीटरिंग के लिए कहा। आप सबने कहा कि दूसरी कक्षा के बालक को पढ़ना नहीं आता ...(व्यवधान) मैं उत्तर दे रहा हूं आपकी बात का ही।

श्री रमेश (सपोटरा): तबादला नीति की पालिसी बताओ न।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वह तो जब कई प्रश्नों के उत्तर आएंगे, जब मैं बैठूंगा तो उत्तर पूछ लेना।

अब प्रदेश के जिलों में राजकीय विद्यालयों में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में भी कहा वास्तव में गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। प्राइमरी और मिडल स्कूल के बच्चे की पढ़ाई का स्तर कमजोर नहीं हो उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड की स्थापना करेंगे। जिसमें अभिभावक भी होगा, शिक्षक भी होगा, सिविल सोसायटी के लोग भी होंगे, जन-प्रतिनिधि भी होंगे और जिला प्रशासन का प्रतिनिधित्व भी होगा। ये पांचों मिलकर अपने क्षेत्र में अपने जिले में एजुकेशन कैसे चल रही है उसका मूल्यांकन करेंगे और उसके साथ प्रति वर्ष इसकी एक रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करेंगे, कोई छिपकर नहीं करेंगे ताकि जो कुछ स्थिति है सामने उसको मिलकर हम सब लोग ठीक करेंगे।

गुणवत्ता सुधार के लिए आवश्यक है कि टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छी हो, इसके लिए पिछले पांच वर्षों में आप बुरा मत मानना डाइट है सीमैट है, एसआईटी है यह सब डिफंक्ट हो गए थे, कहीं कोई काम नहीं था, मैं उदयपुर गया, एसआईटी की बैठक हुई, उसमें मेरे को जो दृश्य मिला, वास्तव में एक शिक्षक होने के नाते पीड़ादायक मिला। आज इन सबको वापस रिवाइव करने की आवश्यकता है और साथ में आधुनिक टैक्नोलोजी को भी आगे लाना है तो

(श्री वासुदेव देवनानी)

हमने डिस्ट्रिक्ट इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन्स हैं, इनको नेटवर्किंग करके ई ट्रेनिंग की व्यवस्था प्रारम्भ करेंगे। अध्यापकों को नवीन तकनीक के गुणात्मक प्रशिक्षण दिलवाने हेतु इनमें वीडियो कांफ्रेंसिंग, डिजीटल पुस्तकालय, ई टीचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, ऐसा नहीं कि केवल घोषणा कर रहा हूं, इनमें से प्रत्येक इन्स्टीट्यूट को दस लाख रुपए प्रति केन्द्र हम उपलब्ध करवाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इन सब चीजों का कंसोलिशन है तो निश्चित रूप से इसकी एनुअल स्टेटस रिपोर्ट को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है और साथ में बच्चों के अन्दर सड़क सुरक्षा का भाव भी आए इसलिए हमने तय किया है कि राज्य के वियालयों के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाए और साथ में जवाबदेही भी तय हो इसके लिए आपने इस बार देखा होगा कि आठवीं के बोर्ड में पिछली बार केवल डेढ़ लाख बच्चे बैठे और इस बार दस लाख ग्यारह हजार बच्चे परीक्षा में बैठे हैं। लेकिन इस अवस्था पर मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करूंगा जो शायद आप तो नहीं पूछ रहे हो, आज अखबारों में भी छपा है।

आठवीं बोर्ड में जो वियार्थी बैठा उसको स्कूल में दुबारा आठवीं की परीक्षा देनी पड़ेगी? मैं इस सदन में घोषणा करता हूं उन बच्चों को स्कूल की दुबारा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी।

शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करने के लिए टीचर्स परफोर्मेंस एप्रेजल की व्यवस्था भी हमने की है। अध्यापक भर्ती की परीक्षा, जो आप अटका गये थे। आपने कहा आरटैट करवाएंगे, लेवल एक करवाएंगे, लेवल दो करवाएंगे, दो-दो, तीन-तीन परीक्षाएं करवाएंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि हम एक परीक्षा करवाएंगे। रीट, रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्जाम फोर टीचर्स का आयोजन हम बहुत शीघ्र कराएंगे, उसके अगर नियम बन गये, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित होगी, लेकिन दुबारा किसी प्रकार की लिटिगेसी न हो, हमने तय किया जो रीट के अन्दर परीक्षा परिणाम आएंगे उसके आधार पर ही उनको नियुक्ति दी जाएगी, किसी तरह का और उसमें मापदण्ड नहीं होगा। (व्यवधान) बाकी रीडिंग कैम्पेन सम्बलन हमने शुरू कर रखा है।

जहां तक गरीब बच्चे हैं, 25 परसेंट हम प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं ताकि उसका पैसा सरकार देगी। धीरे-धीरे यह संख्या बढ़कर इस वर्ष 4 लाख 10 हजार गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिल रहा है। इस

(श्री वासुदेव देवनानी)

बार सरकार द्वारा 162 करोड़ रुपये इसके लिए चुकाये जा रहे हैं 31 मार्च तक, आप कहेंगे कई कठिनाइयां हैं, इसे ठीक करने की आवश्यकता है।

श्री रमेश (सपोटरा): इसमें आप ध्यान दें, इसमें गड़बड़ हो रही है। आप चाह रहे हैं कि स्कूल में फ्री में पैसा लेंगे, आप भौतिक सत्यापन करवा लें, यह पैसा बेकार जाएगा। इसमें ध्यान देने की जरूरत है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपका सुझाव अच्छा है, बिलकुल करना चाहिए। मैं तो पूरे सदन को कहता हूं किसी भी जगह आपको लीकेज दिखे, किसी भी जगह आपको भ्रष्टाचार दिखे, नि:संकोच आप मुझे बताएंगे, न भ्रष्टाचार करूंगा, न भ्रष्टाचार करने दूंगा, यह मैं शिक्षा विभाग की ओर से आपको कह सकता हूं। (व्यवधान) न खाऊंगा, न खाने दूंगा। (व्यवधान) जहां तक साक्षरता मिशन की बात है। आप कह रहे थे (व्यवधान) इस बार अन्तरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के दिन हमारे माननीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा हमारे साक्षरता मिशन प्राधिकरण जिला सीकर को साक्षरता पुरस्कार मिला है, इसके लिए मैं साक्षरता विभाग के सारे शिक्षकों, सबको और राजस्थान को बधाई देता हूं। इस वर्ष भी जैसा मैंने बताया कि 15808 जन-प्रतिनिधियों ने बुनियादी साक्षरता के लिए पंजीकरण कराया है। यहीं तक सीमित नहीं है, हमने कहा कि कैदियों में भी साक्षरता हो, 3109 कैदियों को गत वर्ष हमने साक्षर करवाया है। (व्यवधान) अब मैंने जो निवेदन किया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आये इसलिए शैक्षणिक कलैण्डर के बारे में कई बार मुद्दे उठते हैं, शैक्षणिक कलैण्डर धीरे-धीरे हम सीबीएसई के कलैण्डर के अनुसार हमारे राज्य का भी कलैण्डर तय करेंगे। पहले चरण में इस बार स्कूल 26 जून को खुलेंगे। सर्दियों की तुलना में हम अध्यापकों का एक भी दिन कम नहीं कर रहे हैं। एक सप्ताह गर्मियों में पहले खोलकर सर्दियों में साधारणतया 25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक बंद रहते हैं। उसके बाद फिर सर्दी पड़ती है। फिर कलक्टर के द्वारा 5 दिन 7 दिन छुट्टी घोषित होती है इसलिए सर्दियों की दो सप्ताह की छुट्टी होगी और गर्मी के दिनों में एक सप्ताह की कम होगी, उसका प्रारम्भ इस वर्ष से हम लोग करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके 4 दिन करने के बाद में कलक्टर छुट्टी नहीं करेगा क्या?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मेरे खयाल में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 26 जून से 10 जुलाई तक विशेष नामांकन व ठहराव अभियान चलाया जाएगा। इस बार हमारा मिशन रहेगा हर अध्यापक पढ़ाए और हर विद्यार्थी पढ़े, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों से भी अपील करूंगा सब लोग मिलकर सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें ताकि राजस्थान को हम अग्रणी राज्य में ले जाएं।

इसके साथ कुछ दो-तीन छोटी-छोटी बातें मैं आपसे निवेदन करूंगा। स्वच्छता अभियान की बात चली। आपने कहा कि स्वच्छता अभियान में शिक्षा विभाग ने पहल की। हर स्कूल को 5 हजार रुपये प्रतिवर्ष हमने केवल सफाई के लिए राजस्थान भर में 37.5 करोड़ रुपये उनको दिये हैं ताकि वे स्कूल में सफाई कर सकें। शौचालयों के लिए बात आगे बढ़ी, कई माननीय सदस्यों ने कहा शौचालय नहीं है। मैंने भी आपको पत्र लिखा था और साथ में यह बात आयी है कि नये सत्र के प्रारम्भ से पूर्व राजस्थान के सभी स्कूलों में बच्चे और बच्चियों के शौचालय स्थापित हो जाएंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। इसमें कहीं कोई कमी दिखे उस कमी के लिए मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, राष्ट्रीय आह्वान है, आपकों मैंने पत्र भी लिखा था अपने विधायक कोष से अपने क्षेत्र के अन्दर 10 लाख कम से कम इन टायलेट्स के लिए दीजिए। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ विधायकों ने दिये हैं और बाकी से भी निवेदन करूंगा, इसके अन्दर हमने कारपोरेट जगत को जोड़ा है, कइयों ने दो-दो जिले अडाप्ट किये हैं, लेकिन जहां कहीं कमी हैं, जहां कम वहां इस तरह का एक मन का सोच बनाते हुए यदि हम आगे बढ़ाएंगे। (व्यवधान)

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): जिन स्कूलों में पानी की व्यवस्था नहीं होगी वहां क्या करेंगे?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वहां भी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पानी की कमी आयी, निश्चित रूप से सरकार भी इस पर गम्भीरता से प्रयत्न करेगी। आप लोगों से भी निवेदन करता हूं शिक्षा ऐसा महापुण्य है जिसके अन्दर यदि आपने अपना सहयोग दिया तो आपको भी बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा, इसलिए सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं आइये, दो करोड़ रुपये जो अपने को मिलते हैं, या बाकी जो भामाशाह आपके सम्पर्क में आते हैं उनका कुछ अंश लगातार पांच वर्ष तक आप शिक्षा में दीजिए, कहीं शौचालय के लिए दीजिए, कहीं पानी के लिए दीजिए। आइये, हम सब मिलकर राजस्थान के स्कूलों को अच्छा बनाएं और आगे बढ़ाएं।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): दो करोड़ से पांच करोड़ करा दें।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह माननीय मुख्य मंत्री का है। अंत में कुछ घोषणाएं हैं, कुछ तो बीच-बीच में आ गयीं, लेकिन जो घोषणाएं हैं...(व्यवधान) पूरी सुन लो, शिक्षा विभाग है। एक लाख 97 अरब का यदि यहां पर बजट प्रावधान है तो उतनी तो चीजें कहीं न कहीं सामने आएंगी।

एक तो मैंने कहा कि साइकिल वितरण 15 अगस्त तक कर देंगे। लैपटाप की बात आयी, लैपटाप अभी तक हम दे नहीं पा रहे हैं, हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगले साल दीपावली के त्यौहार पर बच्चों को लैपटाप की गिफ्ट मिल जाए, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। अगले सत्र से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक भी हम सब में उपलब्ध करा देंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। निजी विद्यालयों की मान्यता, मुझसे मिलने कई बार लोग आते हैं, मान्यता के लिए कठिनाइयां आती हैं। इसका सरलीकरण कर रहे हैं और आनलाइन आवेदन प्रक्रिया को हम अपनाएंगे ताकि किसी को भी आफिसेज के चक्कर नहीं काटने पड़ें, इसकी हम व्यवस्था करेंगे।

इसी तरह सीबीएसई की मान्यता के लिए भी कई स्कूल एप्लाई करते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। मैंने भी इस बार कैम्प लगाकर इनको ठीक कराया है और अगले साल इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को भी हम आनलाइन करेंगे। सारे नवगठित पंचायत समिति मुख्यालयों पर पुस्तकालय खोलेंगे। शिक्षा को आधुनिक बनाना है। सारी प्रक्रिया होने के बाद भी कुछ जगह कमी तो हो सकती है इसलिए अगले वर्ष 4 हजार विद्यालयों में सैटेलाइट के माध्यम से गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में हम अध्ययन कराएंगे, इसका एक स्टूडियो जयपुर में हम स्थापित करेंगे जहां से वह अध्यापक सारे स्कूलों की पढ़ाई कराएगा।

आज कम्प्यूटरीकरण का युग है। प्रारम्भिक व माध्यमिक निदेशालय, बीकानेर का हम पूरी तरह कम्प्यूटरीकरण करेंगे। शिक्षा विभाग बहुत पुराना है, इसके अन्दर जो हमारे शिक्षा सेवा नियम हैं, अधीनस्थ सेवा नियम हैं, कई विसंगतियां हैं, कई कानून ऐसे हैं जो डिफंक्ट हो गये हैं। जो डिफंक्ट हो गये हैं इन कानूनों को हटाकर नये सिरे से एक ही शिक्षा सेवा नियम बनाये जा रहे हैं जो अगले सत्र तक हम बनाकर लागू करा देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): डाइरेक्टर आफिस को जयपुर ला रहे हो या बीकानेर ही रख रहे हो?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं। उसको जहां बुलाएंगे वह काम करेगा। वह शिक्षा विभाग के अधीन है। विज्ञान प्रयोगशालाएं

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर के डाइरेक्टर बीकानेर में कितने दिन विराजते हैं और यहां कितने दिन विराजते हैं, यह बताएं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वह आपको बताऊंगा मैं, आ जाना मेरे पास। जहां तक विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं, अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे यहां संकाय खोलें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक जो संकाय खुलती थी चुपचाप बैठकर आफिसेज में खुल जाते थे चाहे विज्ञान संकाय हो या कला संकाय हो।

पहली बार मैंने दसवीं के विद्यार्थियों से विकल्प पत्र भरवाये कि आप अपने स्कूल में कौनसी संकाय चाहते हैं और उस आधार पर मेरे पास जो आया है कि इन पांच हजार में से केवल 897 स्कूलों में विज्ञान संकाय मांगी है, बाकी सबने कला संकाय के लिए कहा है। हम विद्यार्थियों की जो उपयोगिता होगी, विद्यार्थियों की जो आवश्यकता होगी उसके आधार पर संकाय खोलेंगे, नहीं तो विज्ञान संकाय दें, लैब का निर्माण भी कर दें और पढ़ने वाले बच्चे नहीं रहें, उस आधार पर हम लोग नहीं करने वाले हैं। इसी तरह से वर्तमान में जो विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं इनमें कहीं पर उपकरण नहीं हैं, प्रयोगशालाएं चालू हो गईं तो एक-एक स्कूल की प्रयोगशाला को एक-एक लाख रुपये हमने दे दिये हैं, 33 करोड़ 30 लाख रुपये केवल प्रयोगशालाओं के नवीन उपकरण खरीदने के लिए हमने दिए हैं।

अभी स्कूल क्रमोन्नत की बात आई। चूंकि मैंने कहा कि इस बार सुदृढ़ीकरण होना है, फिर भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि जो नई पंचायतों का गठन हुआ है उन पंचायतों में भी चरणबद्ध रूप से ही करेंगे। इन 47 ग्राम पंचायतों में....

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय के स्वास्थ्य को ध्यान में रखें साहब।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): बस कर ही रहा हूं। वो अभी भी जवान हैं।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय को आप क्या समझते हो, आपसे ज्यादा जवान हैं, समझे आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैंने स्वास्थ्य के लिए कहा है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इसी तरह शाला दर्पण कार्यक्रम में माध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों का मय स्टाफ पूर्ण कम्प्यूटराइजेशन करायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में, हमें कहा गया है कि अन्य स्थानों पर किए गए पाप तो तीर्थ स्थानों पर जाने से धुल जाते हैं परन्तु तीर्थ स्थानों पर किए गए पाप कहीं भी नहीं धुल सकते हैं। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में किए गए अनुचित कार्यों को तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधारा जा सकता है परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अनुचित कार्यों को कहीं भी नहीं सुधारा जा सकता। आज शिक्षा की परीक्षा है, आओ, हम सब मिलकर इसकी समीक्षा करें और इसे समयानुकूल और देशानुकूल बनाएं क्योंकि बड़ी तीव्र गति से विश्व बदल रहा है - ''नजर उठा करके देख तो बदल रहा है यह शमां, बदल रही है जमीं और बदल रहा है आसमां'' माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि नया सत्र आने वाला है तो हमारे विद्यालयों में नामांकन बढ़े, शिक्षा में गुणवत्ता बढ़े, इसके लिए हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें ताकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, माननीय मुख्य मंत्रीजी की इच्छा के अनुरूप यह राज्य देश के पहले 10 राज्यों में आ सके। अन्त में कहना चाहूंगा – शिक्षा साधन नव निर्माण, जय हिन्द, जय-जय राजस्थान। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन मांगों को आप पारित करवायें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि मांग संख्या 47 पर्यटन विभाग और मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति विभाग के सम्बन्ध में माननीय विधायकों ने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। ये सुझाव मेरे विभाग के विकास कार्यों के मार्गदर्शन के लिए काम करेंगे इसके लिए मैं माननीय विधायकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुल 130 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनके जवाब कल तक माननीय विधायकों के यहां पहुंच जाएंगे।

मांग संख्या 47 पर्यटन के सम्बन्ध में कहना चाहूंगी कि राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में न केवल देश में अपितु विश्व पर्यटन मानचित्र पर

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर) (दीपा)

प्रमुखता से जाना जाता है। वर्तमान समय में पर्यटन विश्व में सबसे बड़े उद्योग के रूप में उभरा है तथा इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है।

प्रदेश के आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्यटन विकास एवं पर्यटन को जन उद्योग बनाने की दिशा में अनेक कारगर कदम उठाये हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल के वर्षों में पर्यटन क्षेत्र के लिए अनेक सुविधाएं एवं रियायतें प्रदान की हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां –

वर्ष 2014 में राज्य में 330.76 लाख स्वदेशी एवं 15.26 लाख विदेशी पर्यटकों द्वारा भ्रमण किया गया, इस प्रकार राजस्थान में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 6.15 प्रतिशत की वृद्धि, स्वदेशी पर्यटकों के आगमन में 9.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सीएसएस योजना में वर्ष 2013-14 में 10 नवीन परियोजनाएं पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गोडवाड सर्किट (पाली-जालौर-सिरोही), रणथम्भौर टाइगर रिजर्व-सवाई माधोपुर, मत्स्य सर्किट (अलवर-विराट नगर), बूंदी का समग्र विकास, गागरोन फोर्ट-झालावाड़, गढ़पैलेस-झालावाड़, मुचकुण्ड-धौलपुर, डीग फोर्ट-भरतपुर आदि स्थानों के लिए हाल ही स्वीकृत की गई हैं, जिनकी स्वीकृत राशि रुपये 51.74 करोड़ है।

ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 146.83 लाख रुपये सिरोही में गोमुख एवं बाघेरी, बूंदी में भीमलत, दौसा में आभानेरी, बांसवाड़ा में तलवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में देवगढ़ के लिए कार्यकारी एजेंसियों को उपलब्ध कराये गये हैं।

धार्मिक पर्यटन स्थलों एवं भवनों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कार्यकारी एजेन्सियों को राशि रुपये 13.87 करोड़ हस्तांतरित की गई है, जिसमें रामेश्वर घाट-सवाई माधोपुर, दरगाह शरीफ-अजमेर, बांदीकुई व अजमेर में चर्च, उदयपुर में जगत मंदिर एवं करौली में शिव मंदिर, बीकानेर व उदयपुर में हैरिटेज वाक, किशनगढ़ (अजमेर) में टूकड़ा के मकबरे का विकास, पाली में शिव मंदिर, लाखोटिया तालाब, जैन मंदिर आदि, तन्हापीर की दरगाह-जोधपुर, बाडोली मंदिर-रावतभाटा (चित्तौड़गढ़), अर्थुना मंदिर -डूंगरपुर प्रमुख हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको पढ़ा हुआ ही मान लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पास कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: बैठो-बैठो।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): नवीन पर्यटन इकाइयों के 105 प्रोजेक्ट अनुमोदित किये गये हैं जिनमें कुल अनुमानित निवेश राशि रुपये 500 करोड़ है।

विभाग द्वारा दिसम्बर, 2013 से फरवरी, 2015 तक 61 मेले-त्यौहारों का आयोजन किया गया।

पर्यटन में अभिनव शुरूआत करते हुए पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर एवं चूरू में वर्ष 2014 से विश्व पर्यटन दिवस 27 सितम्बर के अवसर पर हैरिटेज वाक प्रारम्भ की गई।

पर्यटन विभाग को दिसम्बर, 2013 से जनवरी, 2015 के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की ट्रेवल मार्टस एवं ट्रेवल मैगजीन्स में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं इनमें से निम्न मुख्य हैं:-

लोनली प्लेनेट मैग्जीन इण्डिया ट्रेवल अवार्ड-2014 में राजस्थान को ''बेस्ट फैमिली डैस्टिनेशन'' का दिनांक 11 जून, 2014 को पुरस्कार प्राप्त हुआ।

नई दिल्ली में दिनांक 13-15 फरवरी, 2014 तक आयोजित ''ट्रेवल एण्ड ट्यूरिज्म फेयर-2014'' में ''बेस्ट डैकोरेशन अवार्ड'' का पुरस्कार प्राप्त किया।

जयपुर में दिनांक 07-09 नवम्बर, 2014 को आयोजित इण्डिया ट्रेवल मार्ट में ''बेस्ट ट्यूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड'' प्राप्त किया।

शिमला में दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 को ''इंटरनेशनल ट्यूरिज्म कान्क्लेव एण्ड ट्रेवल अवार्ड'' में ''बेस्ट वैडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड'' प्राप्त हुआ।

इसके अतिरिक्त भी विभाग को राष्ट्रीय स्तर के 9 अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।

भावी योजनाएं –

इस वित्त वर्ष में पर्यटन, कला एवं संस्कृति का विकास हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता में है। वर्ष 2015-16 में पर्यटन, कला एवं संस्कृति क्षेत्र के लिए 244.46 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान से 68 प्रतिशत अधिक है। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह सब तो बजट भाषण में है। मांगों के ऊपर जवाब दें मंत्री महोदया।

श्री अध्यक्ष: बैठो बैठो बैठो।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): इस वर्ष सरकार द्वारा प्रचार-प्रसार के सभी उपलब्ध माध्यमों का समुचित उपयोग करते हुए राजस्थान में आये हुए पर्यटकों को डेस्टिनेशन के रूप में प्रोजेक्ट किया जायेगा।

साथ ही देशी पर्यटकों के समक्ष राजस्थान को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जायेगा एवं जयपुर शहर को एमआईसीई (Meetings, Incentive, Conference and Exhibitions) डेस्टिनेशन के रूप में डवलप किया जायेगा।

माह अप्रैल, 2015 में भारत सरकार एवं फिक्की के सहयोग से जयपुर में ग्रेट इण्डियन ट्रेवल बाजार का आयोजन किया जायेगा, जिसमें 45 देशों के 227 विदेशी बायर्स तथा 185 भारतीय क्रेता भाग लेंगे।

राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए निम्नलिखित कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं:-

(1) मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा का विकास कार्य।

(2) जयसमन्द झील, उदयपुर का विकास कार्य।

(3) शेखावाटी क्षेत्र में हवेलियों का संरक्षण एवं आधारभूत सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास कार्य।

(4) भरतपुर में चौबुर्जा, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद एवं पुराने शहर करौली एवं नक्की झील, माउंट आबू के चारों तरफ प्रमुख मार्ग तथा अजमेर में दरगाह व निकट के क्षेत्र किंग एडवर्ड मेमोरियल को शामिल करते हुए हैरिटेज वाक-वे को डवलप कराया जायेगा।

(5) पर्यटन स्थल काकूनी व भंडदेवरा, जिला बारां का विकास कार्य।

(6) गावड़ी तालाब, झालावाड़ का सौन्दर्यीकरण एवं झालावाड़ जिले में कोल्वी बिंदायका एवं झालरापाटन के चन्द्रावतजी की बावड़ी के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य।

(7) जैसलमेर में स्थित कुलधारा गांव में 13वीं शताब्दी के अवशेष के विकास कार्य।

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर) (दीपा)

(8) जैसलमेर के सोनार किले का पुररुद्धार कार्य करवाया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 राजस्थान गौरवशाली एवं...

श्री अध्यक्ष: आपकी मांग संख्या-47 है।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): ...प्रेरणादायक, समृद्ध एवं सांस्कृतिक धरोहर वाला प्रदेश है। राजस्थान सरकार ने धरोहरों के सतत एवं समयबद्ध संरक्षण एवं विकास हेतु जन सहभागिता सुनिश्चित...

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): डोटासरा जी, आपसे चुप नहीं बैठा जाता है क्या।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): ...करने के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी के विशेष प्रयासों से ''राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण'' को पुनर्जीवित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा भक्त शिरोमणी मीराबाई पेनोरमा मेड़ता सिटी, अजय योद्धा महाराजा सूरजमल पेनोरमा किशोरी महल भरतपुर, पौराणिक तीर्थ बूढा पुष्कर, ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह बजट की पुनरावृत्ति हो रही है। बजट थोड़े ही दुबारा पढ़ रहे हैं। आप टेबल करा दो ना।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): यह क्या हो रहा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मंत्री महोदय के मूल विचार आ रहे हैं, बिलकुल मूल विचार हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर यही परफोर्मेंस रही मंत्रियों की तो भट्टा बैठने वाला है प्रदेश का, कोई पर्यटन का विकास नहीं होगा। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके समझ में आयेगा। पर आपका ध्यान तो कहीं और है।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): ...गोविन्द गुरु स्मृति उद्यान, मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा, वीरवती हाड़ी रानी, सलूम्बर, साहवा सरोवर निर्माण (दशम गुरु गोविन्द सिंह की स्मृति में) साहवा, चूरू, लोक देवता गोगाजी, गोगामेड़ी (हनुमानगढ़), लोक पूज्य देवता वीर तेजाजी, खरनाल, नागौर लोक पूज्य देवता जम्भोजी, पींपासर जिला नागौर में पेनोरमा निर्माण एवं

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर) (दीपा)

नर्बदेश्वर धाम सीलू (जालौर) में नव घाटों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा राणा सांगा पेनोरमा, खानुवा (भरतपुर), संग्रहालय माउंट आबू (सिरोही), सफेद महल (वाटिका एवं महल) भरतपुर, वैर किला, भरतपुर, प्राचीन अवशेष मठबोरदा झालावाड़, प्राचीन अवशेष दलहनपुर, झालावाड़ एवं कमलेश्वर महादेव मंदिर, बूंदी में संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य करवाये जा रहे हैं।

बूंदी में संग्रहालय स्थापना हेतु सुखमहल परिसर में संग्रहालय भवन का निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस संग्रहालय को शीघ्र ही पर्यटकों के लिए खोल दिया जायेगा।

जयपुर स्थित स्मारकों एवं संग्रहालय में प्रवेश टिकट की आनलाइन व्यवस्था प्रारम्भ की गई।

आमेर महल में रात्रि पर्यटन प्रारम्भ किया गया तथा महल में पर्यटकों हेतु नि:शुल्क वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

सुप्रसिद्ध वास्तुकार आचार्य चार्ल्स कोरिया के प्रतिनिधि धवल मलेशा के निर्देशन में जवाहर कला केन्द्र के पुनरुद्धार का किया जा रहा है।

अंग्रेजी सेवा द्वारा लोकपूज्य देवी सुगाली माताजी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसे हूबहू सेम टू सेम मूर्ति बनाकर पुन: ससम्मान स्थापित किया जायेगा।

झुंझुनूं जिले एवं शेखावाटी के शूरवीर सैनिकों ने राष्ट्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं और कुर्बानियां दी हैं, उन शूरवीरों के सम्मान और प्रेरणादायी जीवन को आम समाज के समक्ष ससम्मान झुंझुनूं में स्थापित करने के लिए एक शौर्य उद्यान का निर्माण किया जायेगा।

श्री करणी माता, लोक देवता पीपाजी, लोक पूज्य देवता रामदेवजी, संत सुन्दरदासजी के महान कार्यों को प्रेरणादायी एवं चिरस्थाई बनाने के लिए सुन्दर पेनोरमाओं में प्रस्तुत किया जायेगा।

मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहती हूं कि जो कांग्रेस में विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, अगर आपने कभी ट्यूरिज्म का काम किया या कहीं गये तो हमसे बात करते। हाय-हुल्ला मचाने से आपको पता नहीं चलेगा, कौनसे, कितने विभाग में, क्या-क्या चीज हैं आपके पास। इन्होंने तो भट्ठा ही बैठा दिया पूरा ट्यूरिज्म का, तभी यह पांचवें नम्बर पर गया है।

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर) (दीपा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर में अरावली पर्वत पर हैप्पी वैली के विकास हेतु आगामी वर्ष में प्रस्ताव बनवा दूंगी और जब बजट उपलब्ध होगा तो इनका भी काम करायेंगे। इसी तरह से भरतपुर में ब्रज चौरासी कोस, जो परिक्रमा मार्ग है, जहां पर बहुत लोग परिक्रमा में जाते हैं, इसका भी प्रस्ताव बनाकर अगले वर्ष में जब बजट उपलब्ध होगा, इन कार्यों को मैं करा दूंगी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मैं विश्वास दिलाती हूं कि राजस्थान का गौरवशाली इतिहास है, इसको जितना आगे बढ़ाने की क्षमता हमारे में है, उसका उपयोग करके हम जनता को समर्पित करेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-47 एवं 24 को पारित करें।

मांग संख्या-24 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 197,96,33,11,000/- (रुपये एक सौ सतानवे अरब छियानवे करोड़ तैतीस लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-47 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-47 पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,05,67,61,000/- (एक अरब पांच करोड़ सड़सठ लाख इकसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 21 मार्च, 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.41 बजे शनिवार, दिनांक 21 मार्च 2015 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

दी राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक में साफ्टवेयर स्थापना में हुई अनियमितता की जांच

289. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दी राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक में राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट लिमिटेड (रील) द्वारा नये साफ्टवेयर पर माह अक्टूबर, 2014 में करवाया गया माइग्रेशन असफल रहा एवं तीन माह उपरांत भारी लेखांकन अनियमितताओं व लेखों में अन्तर के कारण बन्द करना पड़ा?

(2) उक्त को-आपरेटिव बैंक में अक्टूबर, 2014 में माइग्रेशन उपरांत प्रथम दिवस की ई.ओ.डी. उपरांत संतुलन चित्र में कितना अन्तर था एवं माह जनवरी में बंद करने पर कितनी राशि का अन्तर था? इस अन्तर के क्या कारण थे एवं उसके समाधान के लिए साफ्टवेयर कम्पनी द्वारा साफ्टवेयर में क्या कोई परिवर्तन किये गये हैं?

(3) क्या बैंक के उक्त माइग्रेशन पर शाखा प्रबंधकों व प्रतिनिधि यूनियनों द्वारा कोई कमियां बैंक प्रबंधन को बताई गयी थीं? यदि हां, तो उनकी तिथिवार सूची मय किये गये समाधान के सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त माइग्रेशन प्रक्रिया व साफ्टवेयर में प्रदाता कम्पनी की उक्त कमियों में जिला सहकारी बैंकों में कम्प्यूटराइजेशन से पूर्व दुरुस्त कराने की जिम्मेवारी जिन अधिकारियों की थी, उनके नाम सरकार द्वारा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अक्टूबर 2014 में माइग्रेशन के दौरान त्रुटियां आने पर रिमाइग्रेशन किया गया। टीसीएस साफ्टवेयर के आर्किटेक्चर के अनुरूप बिजनेस प्रोसेस रिइंजिनियरिंग करने की आवश्यकता के तहत कम्प्यूटराइजेशन में आ रही व्यवहारिक एवं परिचलनात्मक कठिनाइयों के निराकरण एवं शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय द्वारा दैनिक बाउचर पोस्टिंग के बैकलोग की समस्या को समाप्त करने के लिए माइग्रेशन प्रक्रिया को बन्द कर रिमाइग्रेशन किया गया। उपरोक्त प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। यद्यपि लेखों में अन्तर प्रकट हुआ है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) दिनांक 7 अक्टूबर, 2014 को नये साफ्टवेयर की बैलेन्स शीट में राशि रुपये 5796.51 लाख का अन्तर था। माह जनवरी में 5 दिसम्बर, 2014 तक की गई प्रविष्ठियों के उपरांत नये साफ्टवेयर के संतुलन चित्र में राशि रुपये 12931.58 लाख का अन्तर था। वर्तमान में यह अन्तर शून्य है। साथ ही अन्तरों का प्रकट होना एवं निराकरण करना सतत बैंकिंग प्रक्रिया है। अन्तर का मुख्य कारण पुराने व नये साफ्टवेयर की लेखांकन पद्धतियों में अन्तर होना एवं टीसीएस साफ्टवेयर पर शाखाओं एवं प्रधान कार्यालय द्वारा दैनिक वाउचर पोस्टिंग का बैकलाग है।

एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर माइग्रेट करने के प्रारम्भिक चरणों में परिचलनात्मक व व्यवहारिक समस्याओं एवं व्यवसायिक प्रक्रिया में बदलाव करने के कारण अन्तिम लेखों में अन्तर प्रदर्शित हुए हैं। जिन्हें सिस्टम में दुरस्त किया जाकर एवं बैकलाग की समस्या का निराकरण कर अन्तर का मिलान किया जा चुका है। सिस्टम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जाना एक निरन्तर प्रकिया है।

(3) जी हां। उक्त माइग्रेशन शाखा प्रबन्धकों एवं यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा 14 अक्टूबर, 2014 को समस्याएं अवगत कराई गई थीं जिनका साफ्टवेयर प्रदाता कम्पनी टीसीएस द्वारा साफ्टवेयर आर्किटेकचर की सीमाओं में निराकरण किया गया। साथ ही शीर्ष बैंक की प्रधान कार्यालय एवं शाखाओं द्वारा समय-समय पर प्राब्लम ट्रेकर टूल से अवगत कराई गई समस्याओं का भी समाधान किया गया। तिथि वार समस्याओं के निराकरण व प्रोब्लम ट्रेकर टूल में अवगत कराई गई समस्याओं के निराकरण की विगत परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) उक्त माइग्रेशन केवल शीर्ष बैंक की शाखाओं में ही किया गया था। सर्वप्रथम शीर्ष बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के बैंकिंग विशेषज्ञों की राज्य स्तरीय कमेटी व फंक्शनल इवेलूएशन समिति द्वारा सीबीएस साफ्टवेयर्स का सहकारी बैंकों की आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु आंकलन किया गया। तदुपरान्त कम्प्यूटराइजेशन से पूर्व साफ्टवेयर में कमियों को दुरूस्त करवाने हेतु सीबीएस साफ्टवेयर का एसआरएस एवं गैप एनालिसिस के आधार पर प्रदाता कम्पनी द्वारा कस्टमाइजेशन किए जाने के उपरान्त सहकारी बैंकों के माडयूल एक्सपर्टस की टीम द्वारा यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट अप्रूवल की प्रक्रिया

(सहकारिता मंत्री)

अमल में लाई गई व उसके उपरांत ही साफ्टवेयर शाखाओं में क्रियान्वित किया गया। अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदाता कम्पनी द्वारा किया गया यूएटी (यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट) विगत परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत राशि

290. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के पर्यटन स्थलों के विकास की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कितनी राशि कहां-कहां स्वीकृत की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में रक्तांचल पर्वत स्थित प्राचीन किला एवं पीर का स्थान तथा निवाई कस्बे में नाथ सम्प्रदाय का जालन्दनाथ मंदिर एवं ब्रह्माणी माता मंदिर ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? क्या सरकार उक्त महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कोई बजट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा राज्य योजना एवं सी.एस.एस. योजना के तहत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर पर्यटन विकास कार्य कराये जाते हैं।

(2) राज्य योजना के तहत पर्यटन स्थलों के विकास हेतु गत तीन वर्षों में स्वीकृत राशि एवं कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर, इसी अवधि में सी.एस.एस. योजना के तहत स्वीकृत राशि एवं कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर एवं योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि एवं कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(पर्यटन मंत्री)

(3) पर्यटन विभाग में वर्तमान में उक्त स्थलों के विकास हेतु ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

विभाग में उपलब्ध बजट संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों से वंचित ग्राम पंचायतें

291. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 2014-15 में कितनी ग्राम पंचायतों में सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की घोषणा की गई है, उनमें से कितने विद्यालय प्रारम्भ हो गये व शेष विद्यालय कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे?

(2) प्रदेश में वर्तमान में कितने सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं तथा उनमें से कितने ग्राम पंचायतों में संचालित हैं? वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतें सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों से वंचित हैं?

(3) प्रदेश में कितनी नवगठित ग्राम पंचायतें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों से वंचित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वंचित ग्राम पंचायतों में राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से पूर्व राज्य की 9177 ग्राम पंचायतों में से, जिन ग्राम पंचायतों में राजकीय अथवा निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित नहीं था, उन 5000 ग्राम पंचायतों में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। उक्त 5000 उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ष 2015-16 से संचालित होंगे।

(2) प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत से पूर्व कुल 4456 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित थे, इनमें से 3453 उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम पंचायतों में संचालित थे। वर्तमान में 5000 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

(शिक्षा राज्य मंत्री)

में क्रमोन्नत करने से ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से पूर्व कुल 8453 ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गये हैं। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के पश्चात 657 ग्राम पंचायतें उच्च माध्यमिक विद्यालयों से वंचित हैं।

(3) प्रदेश में नवगठित 718 ग्राम पंचायतों में से 451 ग्राम पंचायतें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों से वंचित हैं। 645 ग्राम पंचायतें (451 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए) उच्च माध्यमिक विद्यालय से वंचित हैं। ग्राम पंचायतों की सूची परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(4) माननीया मुख्य मंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2015-16 की बजट घोषणा सं. 97 के अनुसार 657 ग्राम पंचायतों जहां निजी अथवा राउमावि संचालित नहीं है, में Phase Manner में चयनित स्कूलों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जावेगा।

उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन हेतु स्थानीय मांग प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं निर्धारित मापदण्डों के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बड़ी सादड़ी में रोजड़ों से फसलों को होने वाले नुकसानों को रोकने की कार्य योजना

292. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में रोजड़ों (नीलगाय) से कितनी जनहानि एवं फसलों को नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के समक्ष रोजड़ों (नीलगाय) की संख्या एवं इनसे होने वाली जनहानि एवं आर्थिक हानि को रोकने की कोई कार्य योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में रोजड़ों से जनहानि का कोई प्रकरण वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में संज्ञान में नहीं आया है। रोजड़ों से फसलों को हुए नुकसान का आकलन विभाग द्वारा नहीं करवाया जाता है।

(वन राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं। परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस समस्या की गम्भीरता के मध्यनजर पूर्व से ही निम्न कदम उठाये हैं:-

1. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वन सीमा पर विभिन्न योजना अन्तर्गत लगभग 32 किमी. लम्बाई में दीवार निर्माण किया गया है जिससे वन्यजीवों/रोजड़ों के वन क्षेत्र से बाहर निकलने पर अंकुश लगा है।

2. किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नील गायों की संख्या पर नियंत्रण हेतु सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, उप खण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, सहायक वन संरक्षक, विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं थाना प्रभारी अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में नीलगाय को मारने की अनुमति देने हेतु वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 11 (1) (बी) के तहत प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। (संलग्न परिशिष्ट 1 से 4)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मकराना नगर परिषद में अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में विकास कार्य

293. श्री श्रीराम भींचर (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नगरपालिकाओं/नगर परिषदों में विकास हेतु आबंटन की जाने वाली राशि में से अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों के विकास के लिए अलग से राशि आबंटन करती है? यदि हां, तो कुल आबंटन का कितने प्रतिशत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद मकराना को अप्रैल, 2010 से अप्रैल, 2014 तक विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों के विकास के लिए राशि आबंटन की गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नगर परिषद मकराना द्वारा आबंटित राशि के विरुद्ध किस-किस अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में क्या-क्या विकास कार्य करवाये गये? कार्य का नाम स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कार्य की वर्तमान स्थिति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरीय निकायों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों का पृथक से वर्गीकरण नहीं होता है और ना ही किसी योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों के विकास के लिये राशि आबंटन का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। नगरीय निकायों को अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों के विकास के लिये पृथक से राशि आबंटन का प्रावधान नहीं है।

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 2 के उत्तर में निहित है।

पिण्डवाड़ा उप खण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

294. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार पिण्डवाडा उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में पिण्डवाड़ा में निजी क्षेत्र में 2 सहशिक्षा के महाविद्यालय संचालित है।

निर्धारित मानदण्ड पूर्ण होने एवं वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता पर पिण्डवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

चौहटन में नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना के विस्तार की योजना

295. श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना से वर्तमान में कितने गांव लाभान्वित हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना के तहत चौहटन विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री तरुण राय कागा)

(3) क्या सरकार चौहटन विधान सभा क्षेत्र के दूरदराज के सीमावर्ती मरुस्थलीय गांवों में नर्मदा सिंचाई परियोजना का विस्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश के उत्तर पश्चिम छोर से आ रही इंदिरा गांधी नहर एवं दक्षिण पश्चिम छोर से आ रही नर्मदा नहर को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना से इस वर्ष 28 गांव लाभान्वित हुये हैं, विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) नर्मदा नहर परियोजना के तहत चौहटन विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। परियोजना में अतिरिक्त पानी उपलब्ध नहीं होने से परियोजना का विस्तार किया जाना विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में छात्रवृत्ति के लिए प्रमाण-पत्रों की वैधता अवधि में वृद्धि

296. श्री शंकरसिंह (ब्यावर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्राप्त करने के लिए कम से कम छह माह में बना हुआ जाति, मूलनिवास व आय प्रमाण-पत्र पेश करने पर ही छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार जाति, मूल निवास प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत केवल आय प्रमाण-पत्र ही छह माह में बना हुआ दिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि आय समान नहीं रहती है।

(2) विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं मूल निवास प्रमाण हेतु अवधि की वैधता नहीं है।

घरेलू गैस उपभोक्ताओं को बीमा पालिसी देने की योजना

297. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में घरेलू गैस सिलैंडर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिये दुर्घटना बीमा पालिसी का प्रावधान है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बीमा पालिसी की क्या-क्या शर्ते होती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गैस उपभोक्ताओं को उक्त बीमा पालिसी दी गई है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत उपभोक्ताओं को? यदि नहीं, तो क्यों व इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार तीनों आयल कम्पनियों (आई.ओ.सी.एल./बी.पी.सी.एल./एच.पी.सी.एल.) द्वारा एक विस्तृत बीमा पालिसी एल.पी.जी. वितरकों के साथ अनुबंधित है, जिसके द्वारा एल.पी.जी. दुर्घटना में व्यक्ति तथा सम्पत्ति को कवर किया जाता है। इसे "पब्लिक लाइबिलिटी पालिसी फोर आयल कम्पनीज" के नाम से जाना जाता है।

यह किसी व्यक्ति के नाम पर अथवा विशेष एल.पी.जी. ग्राहक के लिए नहीं है।

इस पालिसी के अन्तर्गत एल.पी.जी. उपभोक्ता के साथ कोई दुर्घटना होने की स्थिति में उसे तत्काल तेल निगम, जिस कम्पनी का गैस कनेक्शन है, उसे सूचित किया जाना होता है तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच करके बीमा कम्पनी के क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत कराते हैं तथा सम्बन्धित बीमा कम्पनी बीमा पालिसी में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर दुर्घटना के दावे की राशि निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही करती है।

(2) सर्वप्रथम उपभोक्ता को एल.पी.जी. से सम्बन्धित किसी भी दुर्घटना की सूचना उस गैस वितरक कम्पनी को तत्काल देनी होती है, जिससे उसने गैस कनेक्शन प्राप्त किया है। इस सम्बन्ध की जानकारी उपभोक्ता को कनेक्शन लेते समय दिये गये बाउचर के पृष्ठ भाग पर स्पष्ट अंकित होती है,

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

जिसमें उपभोक्ता को सीधे बीमा कम्पनी से सम्पर्क करने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि गैस वितरक को दुर्घटना की सूचना तत्काल देनी होती है। तीनों आयल कम्पनियों द्वारा प्रचलित विस्तृत बीमा पालिसी के तहत दावों का भुगतान (1) विधिक जिम्मेदारी, (2) व्यक्तिगत दुर्घटना को कवर करता है, जो कि अधिकृत उपभोक्ता को पंजीकृत परिसर में हुए चिकित्सा व्यय, सम्पत्ति को नुकसान इत्यादि जोकि पालिसी के अन्तर्गत आते हैं।

(3) बीमा पालिसी 'पब्लिक लाइबिलिटी पालिसीज' है, जो कि तेल कम्पनियों एवं वितरकों द्वारा शत-प्रतिशत रजिस्टर्ड गैस उपभोक्ताओं के लिए ली गई है।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों को हानि से उबारने के लिए सहायता राशि

298. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कितने केन्द्रीय सहकारी बैंक संचालित हैं तथा विगत तीन वर्षों में इनके लाभ एवं हानि की स्थिति क्या रहीं? जिलेवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे केन्द्रीय सहकारी बैंक जो हानि में हैं तथा जिन बैंकों की सी.आर.ए.आर. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानदण्डों से कम है, ऐसे बैंकों को इस समस्या से उबारने के लिए सहायता राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक संचालित हैं। विगत तीन वर्षों में इनके लाभ एवं हानि की स्थिति निम्नानुसार है -

वित्तीय वर्ष	लाभ में रहने वाले बैंकों की संख्या	हानि में रहने वाले बैंकों की संख्या
2011-12	28	1
2012-13	28	1
2013-14	23	6

(सहकारिता राज्य मंत्री)

बैंकवार लाभ हानि की विगत परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में राज्य सरकार स्तर से हानि में रहने वाले तथा निर्धारित मापदण्डों से कम सी आर ए आर वाले बैंकों को सहायता राशि प्रदान करना विचाराधीन नहीं है। कम सी आर ए आर वाले बैंकों की सतत मोनिटरिंग एवं सुधारात्मक उपाय लागू करने हेतु शीर्ष बैंक स्तर से एक्सपर्ट एडवाइजरी टीम का गठन किया गया है। बैंकों द्वारा हिस्सा राशि विभाजन में संशोधन, स्थायी परिसम्पत्तियों का पुर्नमूल्यांकन दीर्घावधि जमा योजनाएं जैसे सुधारात्मक उपाय लागू किये जा रहे हैं। सी आर ए आर में कमी के कारण किसी सहकारी बैंक पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ें, इस हेतु प्रावधानों में संशोधन हेतु राज्य सरकार के स्तर से केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को पत्र लिखा गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महाराणा प्रताप के राजतिलक स्थान का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

299. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने मेवाड़ काम्प्लेक्स में महाराणा प्रताप से जुडे स्थानों को पर्यटन स्थल में विकसित करने की कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में महाराणा प्रताप के राजतिलक स्थल को विकसित करने के लिए कितनी राशि व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार महाराणा प्रताप से जुडे स्थान मायरा गुफा, शस्त्रागार, राणा व धोलिया आदि स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मेवाड़ काम्प्लेक्स के अन्तर्गत महाराणा प्रताप से जुडे हल्दीघाटी, गोगुन्दा, दीवेर, छापली व चावण्ड स्थित स्थलों के संरक्षण एवं पर्यटन विकास हेतु राशि रु. 7.93 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार कर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गयी है।

(पर्यटन राज्य मंत्री)

(2) महाराणा प्रताप के राजतिलक स्थल को विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 में राशि रु. 140.97 लाख के विकास एवं संरक्षण कार्य कराये गये हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में पर्यटन विभाग में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट अ'

पर्यटन विभाग द्वारा महाराणा प्रताप के राजतिलक स्थल गोगुन्दा में वर्ष 2008-09 में राशि रु. 140.97 लाख के निम्नानुसार विकास एवं संरक्षण कार्य पूर्ण कराये गये हैं :-

1. पाथवे का निर्माण
2. संग्रहालय
3. एम्पीथियेटर का निर्माण
4. रेस्टोरेंट का विस्तार तथा
5. बावड़ी का पुर्नरुद्वार का कार्य

जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवन

300. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों की कई इमारतें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? यदि हां, तो उक्त स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रखें। .क्या सरकार ऐसी स्कूलों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में कई सरकारी विद्यालय किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूलों के कई किराये के भवन सुरक्षित नहीं हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में 9 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत योग्य हैं। इन मरम्मत योग्य राजकीय विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। राजकीय विद्यालयों में मरम्मत हेतु प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान की आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2015-16 में भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तावित किये जा रहे हैं। अनुमोदन होने पर इन विद्यालयों में वृहद मरम्मत कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित माध्यमिक सैटअप के कोई भी विद्यालय जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं हैं।

(2) जी हां। जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में 18 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय किराये के भवनों में चल रहे हैं। विद्यालयवार सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में माध्यमिक सैटअप में 3 विद्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं, जो निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	नाम विद्यालय
1	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महामन्दिर
2	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बम्बा
3	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, श्यामसदन

(3) जी हां। उक्त 18 किराये के भवन में से 4 विद्यालय में वृहद मरम्मत की आवश्यकता है, सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है। विद्यार्थियों को भवन के जीर्ण-शीर्ण भाग में नहीं बैठने के लिए विभाग द्वारा समस्त अधिनस्थ अधिकारियों/संस्था प्रधानों को प्रतिवर्ष निर्देशित किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले में गैस कुओं की खोज में कार्यरत कम्पनियां

301. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री छोटू सिंह)

(1) जैसलमेर जिले में गैस के कुंओं की खोज हेतु कितनी कम्पनियां कार्यरत हैं? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिले में फोकस एनर्जी द्वारा गैस हेतु कितने कुएं खोदे गये एवं कितने कुओं में गैस प्राप्त हुई? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में गैस के कुओं की खोज हेतु 10 कम्पनियां कार्यरत हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जिले में फोकस एनर्जी द्वारा गैस हेतु खोदे गये कुओं का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है एवं ब्लाक Rj-ON-6 में 27 कुओं में गैस के भण्डार प्रमाणित हुये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुख्य मंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजना के निर्धारित लक्ष्य

302. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) एवं **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2012-13 में मुख्य मंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजना स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत कितने लोगों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित था?

(2) क्या यह सही है कि अब इस योजना को बंद कर दिया है? यदि हां, तो क्यों तथा कब से?

उत्तर

(1) जी हां। मुख्य मंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना वर्ष 2012-13 में प्रारम्भ की गई थी। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष एक लाख शहरी बीपीएल परिवारों को आवास अनुदान सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था।

(2) मुख्य मंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना बंद नहीं की गई है, अपितु राज्य सरकार द्वारा उक्त योजनान्तर्गत नवीन स्वीकृतियां जारी नहीं की जा रही हैं।

अराई (अजमेर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

303. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भागीरथ चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ (अजमेर) विधान सभा क्षेत्र के अराई कस्बे में कोई राजकीय या निजी महाविद्यालय संचालित नहीं है? यदि हां, तो कस्बे से कितनी दूरी पर कौन-कौन से राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अराई कस्बे एवं तहसील के गांवों के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अन्यत्र स्थानों पर जाना पड़ता है? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालयों में इस तहसील एवं क्षेत्र के कितने-कितने छात्र छात्राओं द्वारा प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक विभिन्न संकायों में शिक्षा ग्रहण की जा रही है? वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अध्यनरत नियमित छात्र छात्राओं का विषयवार व कक्षावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अराई कस्बे एवं तहसील के गांवों एवं आसपास के क्षेत्रों के उक्त अध्यनरत छात्र-छात्राओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अराई कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। किशनगढ़ (अजमेर) विधान सभा क्षेत्र के अराई कस्बे में कोई भी राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है, तथापि सहशिक्षा का एक निजी महाविद्यालय "स्वर्णरूप महाविद्यालय, अराई" वर्ष 2013 से संचालित है।

अराई कस्बे से अजमेर जिले में संचालित राजकीय महाविद्यालयों की दूरी का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। अजमेर जिले के उक्त राजकीय महाविद्यालयों में अराई कस्बे एवं तहसील के गांवों के छात्र-छात्राओं का वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का संख्यात्मक विषयवार/कक्षावार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) निर्धारित मानदण्ड के पूर्ण होने और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर अराई में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर-जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर से शुद्ध पानी की आपूर्ति

304. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कैलाश चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर का पानी बाड़मेर जिले में पेयजल के लिए और जैसलमेर में कृषि कार्य करने और पेयजल के लिए उपयोग किया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि इंदिरा गांधी नहर का पानी उदगम स्थल से चलकर बाड़मेर-जैसलमेर तक पहुंचते-पहुंचते काफी गंदा हो जाता है?

(3) क्या यह भी सही है कि गंदे पानी को पेयजल के रूप में काम में लेने से पीलिया, कैंसर, हैपेटाइटिस और डायरिया जैसे रोगों का खतरा हर समय बना रहता है?

(4) क्या सरकार जनता को प्रदूषण मुक्त जल (पानी) उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन्दिरा गांधी फीडर/इन्दिरा गांधी नहर के माध्यम से बाड़मेर, जैसलमेर तक पहुंचने वाले पानी के गन्दे होने का मुख्य कारण इन्दिरा गांधी फीडर के उदगम स्थल हरिके के अपस्ट्रीम में पंजाब की औद्योगिक इकाइयों एवं शहरी निकायों द्वारा गन्दा पानी सतलुज नदी में प्रवाहित किया जाना है। यह प्रदूषित जल सतलुज के माध्यम से हरिके पर प्राप्त होता है, यहां से यह इन्दिरा गांधी फीडर में प्रवाहित हो जाता है। जो कि अन्ततः बाड़मेर-जैसलमेर में भी पहुंचता है।

(3) जी हां। प्रदूषित पानी को पेयजल के काम में लिये जाने से कई तरह की बीमारियों की सम्भावना रहती है।

(4) राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण मुक्त जल उपलब्ध करवाने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कारवाई का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घड़साना पंचायत समिति (श्रीगंगानगर) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी

305. श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती शिमला बावरी)

(1) क्या पंचायत समिति घड़साना जिला श्रीगंगानगर में विधवाओं, वृद्धों तथा नि:शक्तजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है? यदि हां, तो कितनी-कितनी व कब-कब उक्त पेंशन की पात्रता की शर्तों एवं प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिन वृद्ध, विधवा व नि:शक्तजनों को पेंशन का पी.पी.ओ. जारी कर दिया जाता है, उन्हें प्रतिमाह पेंशन दी जाती है?

(3) पंचायत समिति घड़साना में ऐसे कितने पेंशनधारी हैं, जिनको पी.पी.ओ. जारी होने के बाद गलत पते के कारण पेंशन नहीं दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति घड़साना जिला श्रीगंगानगर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत निम्नांकित योजनाएं उनके समक्ष अंकित दिनांक से संचालित की जा रही हैं :-

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (दिनांक 6.11.2007)
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (दिनांक 7.10.2009)
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना (दिनांक 24.11.2009)
4. मुख्य मंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (दिनांक 1.4.2013)
5. मुख्य मंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना (दिनांक 1.4.2013)
6. मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (दिनांक 1.4.2013)

भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी पी एल परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत, 40 वर्ष व अधिक आयु की बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिलाओं को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत तथा बी.पी.एल. परिवार के व्यक्ति जो गुरूत्तर नि:शक्तता या बहुनि:शक्तता से ग्रसित हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक तथा विकलांगता का स्तर 80 प्रतिशत हो तो इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजनान्तर्गत नियमानुसार पेंशन देय है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

मुख्य मंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरुषों को, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को एवं मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत किसी भी आयु के विशेष योग्यजन व्यक्ति, जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चलन नि:शक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) प्राकृतिक रूप से बौनेपन (व्यस्क व्यक्ति के मामले में उसकी ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत प्रमाण-पत्र धारक हो) एवं प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से ग्रसित हो, को नियमों में वर्णित पात्रतानुसार पेंशन देय है।

प्रदेश में वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशनरों को देय पेंशन की दर निम्नानुसार है :-

1. 75 वर्ष एवं अधिक आयु के पेंशनर 750 रुपये प्रतिमाह
2. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर 500 रुपये प्रतिमाह
3. 08 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर 250 रुपये प्रतिमाह

पंचायत समिति घड़साना जिला श्रीगंगानगर में पेंशनरों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	पेंशन श्रेणी	पेंशनरों की संख्या
1.	वृद्धावस्था पेंशन	9784
2.	विधवा पेंशन	1963
3.	विशेष योग्यजन पेंशन	1123

(2) जी हां। जिन वृद्ध, विधवा एवं विशेष योग्यजन को पेंशन का पी.पी.ओ. जारी कर दिया जाता है, उन्हें नियमित रूप से प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

(3) पंचायत समिति घड़साना में पेंशनधारी जिनको पीपीओ जारी होने के बाद गलत पता/निवास स्थल छोड़ने के कारण पेंशन नहीं दी जा रही है, की सूची विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौमूं तहसील में गलत राशन कार्ड बनाने वाली कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही

306. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चौमूं तहसील में नवीन राशन कार्ड बनाने के लिए जिस फर्म से अनुबंध किया गया, उस फर्म के द्वारा आज तक भी राशन कार्ड तैयार करके उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि जो राशन कार्ड तैयार किये गए उनमें काफी गलतियां हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी शिकायतें नगरपालिका एवं पंचायत समिति को प्राप्त हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। चौमूं तहसील में नवीन राशन कार्ड बनाने के लिये मैसर्स मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर को अधिकृत किया गया था। फर्म द्वारा तहसील चौमूं के समस्त राशन कार्ड उपलब्ध करवा दिये गये है।

(2) जी हां। यह सही है कि फर्म द्वारा तैयार राशन कार्ड में गलतियां हैं। नगरपालिका चौमूं में 1118 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 818 का निस्तारण किया जा चुका है, शेष 300 में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं पंचायत समिति गोविन्दगढ में 456 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(3) जी हां। राशन कार्ड में पाई गई त्रुटियों को संशोधित कर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने वाली फार्म्स के विरुद्ध निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के केन्द्रीय सहकारी बैंकों का नाबार्ड के नियमों के विरुद्ध अंकेक्षण

307. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में प्रदेश में नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से चलने वाले शीर्ष बैंक (अपेक्स बैंक) एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

नाबार्ड के नियमों के विपरीत वार्षिक आडिट करवाने का प्रकरण सामने आया है? यदि हां, तो प्रकरण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब नाबार्ड के नियमों के अनुसार आडिट कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। शीर्ष बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के सांविधिक अंकेक्षण हेतु नाबार्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 4.3.2010 के अनुसार ही शीर्ष बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैकों द्वारा आडिट कराया गया है। गत पांच वर्षो में राज्य में नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से चलने वाले शीर्ष बैंक (अपेक्स बैंक) एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा नाबार्ड के नियमों के विपरीत वार्षिक आडिट कराने का प्रकरण जानकारी में नहीं आया है।

(2) जी हां। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के प्रावधानों एवं नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही शीर्ष बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित लेखा परीक्षकों के पैनल में से स्वयं के स्तर पर नियुक्त लेखापरीक्षक से आडिट करवाया जा रहा है।

तीर्थ पर्यटन योजनान्तर्गत रामेश्वरम घाट एवं अर्णेश्वर महादेव (खण्डार) का विकास

308. श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार खण्डार जिला सवाई माधोपुर के अन्तर्गत धार्मिक स्थान रामेश्वरम घाट और अर्णेश्वर महादेव को "तीर्थ पर्यटन योजना" में शामिल कर इनका समुचित विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। पर्यटन विभाग द्वारा राज्य योजना के तहत रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में वर्ष 2013-14 में धार्मिक पर्यटन योजना के अन्तर्गत राशि रु. 100.00 लाख की परियोजना स्वीकृत कर कार्यकारी एजेंसी वन विभाग के माध्यम से रामेश्वर घाट का पुनरोद्धार, रामेश्वर घाट पर खरंजों का निर्माण, जैटी का निर्माण, शिव मंदिर से घाट तक पाथ-वे एवं प्रकाश व्यवस्था सम्बन्धी विकास कार्य कराये गये हैं।

प्रदेश में प्रबोधकों की स्थानान्तरण नीति

309. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रबोधकों के स्थानान्तरण की कोई नीति नहीं बनाई गई है?

(2) क्या सरकार प्रबोधकों का स्थानान्तरण जिले में ही करने हेतु नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों की स्थानान्तरण नीति में प्रबोधकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में भी आवश्यक विचार किये जावेंगे।

प्रदेश में बजरी खनन में हो रही कालाबाजारी से राजस्व घाटा

310. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्तमान में बजरी खनन हेतु पट्टे आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में कालाबाजारी के कारण बजरी बहुत ऊंची दरों पर प्राप्त हो रही है व बजरी माफियाओं द्वारा बजरी की मनमाफिक रेट ली जा रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि बजरी माफिया नदी के अलावा बिना आबंटन के किसानों के खेतों से भी बजरी ले रहे हैं? यदि हां, तो इससे सरकार को कितनी राजस्व की हानि हो रही है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार बजरी माफियाओं पर अंकुश लगाने हेतु पंचायत स्तर पर पट्टे देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में बजरी खनन हेतु खनन पट्टे जिला बीकानेर में 78, जैसलमेर में 2 आबंटित हैं। इसके अलावा 103 खनन पट्टों हेतु आवेदकों को आवश्यक पूर्तियां करने बाबत मंशा पत्र (एल.ओ.आई.) जारी किये गये हैं। खनन पट्टों की सूची परिशिष्ट- "अ" पर एवं मंशापत्र धारकों की सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(2) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपयोगिता विभाग द्वारा राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य) विधेयक, 2014 के अन्तर्गत जिला कलक्टरों को खनिज बजरी की विक्रय दरें निर्धारित करने हेतु अधिसूचना दिनांक 7.2.2014 को जारी की गई जिसके क्रम में जिला कलक्टरों द्वारा खनिज बजरी की दरें निर्धारित की गई थीं। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन नम्बर 2674/2014 में पारित आदेश दिनांक 11.8.2014 एवं 22.9.2014 के क्रम में सभी जिला कलक्टरों द्वारा खनिज बजरी की दरें पुन: निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में राज्य में निर्धारित दरों के अनुरूप ही खनिज बजरी का निर्गमन हो रहा है।

(3) जी नहीं। नदी क्षेत्रों में जारी एल.ओ.आई. अनुमति धारकों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई अस्थाई कार्यानुमति के तहत राजकीय भूमि में खनन कार्य कर रहे हैं, परन्तु सीकर, झुंझुनूं व कोटपूतली क्षेत्र में खातेदारी भूमि में बजरी खनन पाये जाने पर अवैध खनन कार्य बन्द करवाया गया तथा सम्बन्धित खातेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है। इसके अलावा सहायक खनि अभियन्ता, सवाई माधोपुर के पास एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच शीघ्र करवाई जा रही है।

(4) जी हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नदी क्षेत्रों में नदी स्ट्रेचवार खनन पट्टों के प्लोट बनाकर एल.ओ.आई. जारी की गई थी एवं जो क्षेत्र रिक्त बचे हुए हैं उनमें छोटे प्लोट 50 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के बनाकर खनन पट्टे आबंटन हेतु नीति प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर एवं संगरिया के निजी कालेजों को पुन: सरकारी कालेज का दर्जा

406. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर एवं संगरिया में निजी शिक्षण संस्थानों को सरकारी कालेज का दर्जा दिया गया था? यदि हां, तो कब? क्या उक्त सरकारी कालेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है तथा इन्हें पुन: निजी शिक्षण संस्था का दर्जा दे दिया गया है, यदि हां, तो क्यों विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर एवं संगरिया की इन निजी शिक्षण संस्थाओं को पुन: सरकारी कालेजों का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं,तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर तथा संगरिया में निजी क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों को निम्न आदेशों से राज्याधीन किया गया था:-

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	शहीद भगत सिंह कालेज, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)	20(101)02/Plan/DCE/2013-14 दिनांक 26.7.2013
2.	ज्ञान ज्योति कालेज, श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)	20(101)02/Plan/DCE/2013-14 दिनांक 26.7.2013
3.	मीरा गर्ल्स कालेज, संगरिया (हनुमानगढ़)	एफ.1(23)शिक्षा/ग्रुप-3/2013 दिनांक 31.8.2013

उपर्युक्त आदेशों पर पुनर्विचार कर राज्य सरकार ने रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर एवं संगरिया में निजी क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों के अधिग्रहण को अपास्त करने हेतु दिनांक 26.9.2014 के आदेश जारी किये गये।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर तथा संगरिया में निजी क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों का विवरण निम्नानुसार है:-

स्थान	सहशिक्षा	महिला	योग
रायसिंहनगर	6	2	8
श्री करणपुर	3	3	6
संगरिया	2	2	4

राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में उक्त निजी महाविद्यालयों से सम्बन्धित प्रकरण न्यायाधीन (sub judice) हैं तथा तीनों स्थानों पर निजी शिक्षण संस्थानों की पर्याप्त संख्या को देखते हुए उक्त निजी महाविद्यालयों का अधिग्रहण प्रस्तावित नहीं है।

शहीद जवानों के परिवारजनों को देय सुविधाएं

407. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गत तीन वर्षों में कितने जवान सीमा पर, नक्सली हमले व आतंकी हमलों में शहीद हुये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त शहीद जवानों के परिवारजनों को क्या-क्या सुविधाएं/सहायता उपलब्ध करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त शहीदों के बच्चों को शिक्षा व अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में गत तीन वर्षों में 36 जवान सीमा पर, नक्सली हमले व आतंकी हमलों में शहीद हुये हैं। इनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) शहीद जवानों के परिवारजनों को सरकार द्वारा देय कारगिल पैकेज के अन्तर्गत सुविधाएं/सहायता उपलब्ध करवाई गई है। इसका विवरण परिशिष्ट 'ख' एवं 'ग' पर संलग्न है।

(सैनिक कल्याण मंत्री)

(3) राज्य सरकार द्वारा शहीदों के बच्चों को कारगिल पैकेज के द्वारा शिक्षा व अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसका विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आहौर उप खण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

408. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आहौर के आहौर उपखण्ड पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट भाषण वर्ष 2015-16 के बिन्दु संख्या-111 में आहौर जिला जालौर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। शैक्षणिक सत्र 2015-16 से राजकीय महाविद्यालय, आहौर प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। (संलग्न परिशिष्ट-1)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के बकाया वेतन भत्ते

409. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के किन-किन विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की पेंशन, जी पी एफ, ग्रेच्यूटी या अन्य कटौतियों की कितनी-कितनी राशि जमा करवाई जानी शेष है? विश्वविद्यालय वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त किस-किस विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त व्यक्तियों की बकाया कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त किस-किस विश्वविद्यालयों में किस-किस माह तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है तथा कितने कर्मचारियों का वेतन भुगतान बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल नागर)

(4) क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालयों के बकाया भुगतानों की समस्या का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर सूचना संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(2) विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर सूचना संलग्न परिशिष्ट-2 में अंकित है।

(3) विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर सूचना संलग्न परिशिष्ट-3 में अंकित है।

(4) जो भी नियमानुसार देय भुगतान है, उनका प्रक्रिया पूर्ण कर भुगतान करने हेतु विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा में संचालित संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद

410. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में उच्च प्राथमिक, प्रवेशिका व वरिष्ठ उपाध्याय के विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कुल कितने-कितने पद श्रेणीवार स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों में से कितने-कितने पद कौन-कौन से विद्यालयों में रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में संस्कृत शिक्षा विभाग के संचालित राजकीय संस्कृत विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में संस्कृत शिक्षा विभाग के संचालित राजकीय संस्कृत विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-1 में निहित है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

परिशिष्ट-1

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में संचालित संस्कृत विद्यालय एवं इनमें स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम विद्यालय	प्राचार्य		व.अ.I ग्रेड		अध्यापक ग्रेड-II		अध्यापक	
		स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, किशनगढ़ रैनवाल	01	-	05	02	05	01	3	-
2	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बागावास	-	-	-	-	01	0	6	1
3	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, शिवतलाई	-	-	-	-	01	0	4	-
4	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, फुलेरा	-	-	-	-	01	0	4	1
5	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत. विद्यालय, सांभरलेक	-	-	-	-	01	0	5	-
6	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, अमरावाली ढाणी	-	-	-	-	01	0	5	-
7	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, सूतल्या की ढाणी	-	-	-	-	01	0	4	1

विराटनगर (जयपुर) में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

411. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने प्रदेश में पंचायत समिति मुख्यालयों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो ऐसी कौनसी पंचायत समितियां हैं, जहां पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विराटनगर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा 45 पंचायत समिति स्थानों पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किये गये हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

प्रदेश में 17 पंचायत समिति स्थानों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(2) स्थानीय मांग, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर गुणावगुणों के आधार पर पंचायत समिति विराटनगर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने बाबत निर्णय लिया जा सकेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बूंदी में थड़ी ठेले वालों को स्थान उपलब्ध कराने की योजना

412. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद बूंदी को थड़ी ठेलेवालों से रोजाना कितनी आमदनी होती है? गत पांच वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नगर परिषद, थड़ी ठेले वाले गरीबों को रोजगार की सुनिश्चितता हेतु उपयुक्त जगह उपलब्ध कराने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा गत 5 वर्षों में कितनी राशि का जुर्माना वसूल किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अशोक डोगरा)

(4) उक्त नगर परिषद द्वारा गत 5 वर्ष में कितनी राशि के कौन-कौन से सामान क्रय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद बूंदी को थड़ी ठेलेवालों से औसतन तीन हजार रुपये प्रतिदिन की आमदनी होती है। विगत पांच वर्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. वर्ष 2009-10 1219465.00
2. वर्ष 2010-11 1158695.00
3. वर्ष 2011-12 1134535.00
4. वर्ष 2012-13 1096680.00
5. वर्ष 2013-14 1019590.00

(2) जी हां। सभी जिला मुख्यालयों एवं एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल 40 शहरों में स्ट्रीट वेडर्स का सर्वे किया जाकर आन-लाइन फीडिंग कर स्ट्रीट वेडर्स को बसाने हेतु योजना (वेडिग प्लान) बनाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

(3) नगर परिषद बूंदी के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने गत 5 वर्षों में निम्नानुसार जुर्माना राशि वसूल की गयी है:-

1. वर्ष 2009-10 4000.00
2. वर्ष 2010-11 7000.00
3. वर्ष 2011-12 6300.00
4. वर्ष 2012-13 5100.00
5. वर्ष 2013-14 5700.00

(4) नगर परिषद बूंदी में गत 5 वर्ष में क्रय किये गये सामान का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

छापोला की ढाणी (सांगानेर) में अतिक्रमण

413. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि छापोला की ढाणी, शिवानगर सांगानेर जयपुर में आम रास्ते पर अतिक्रमण के कारण जगह-जगह कचरे के ढेर एवं गंदा पानी

(श्री केसाराम चौधरी)

भरा रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाकर पानी की निकासी की सुदृढ़ व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। छापोला की ढाणी, शिवानगर में बसी आबादी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं है। मौके की जांच से यह सामने आया है कि क्षेत्र में नालियां निर्मित हैं, जिनकी सफाई नगर निगम द्वारा समय-समय पर करवाई जाती है।

जोधपुर शहर में फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण की कार्य योजना

414. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जोधपुर की व्यस्ततम सड़कों पर ट्राफिक की समस्या से आमजन को निजात दिलाने के लिए शहरी ढांचागत सुधार योजना के अन्तर्गत विभिन्न चौराहों पर फ्लाई ओवर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन मार्गों पर कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जोधपुर शहर की सबसे व्यस्ततम सड़क (हार्ट लाइन) चौपासनी से पावटा चौराहा तक के मध्य आने वाले प्रमुख चौराहों पर फ्लाई ओवर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर विकास प्राधिकरण में शहरी ढांचागत सुधार योजना वर्तमान में प्रगतिरत नहीं है। जोधपुर शहर की व्यस्ततम सड़कों पर ट्राफिक की समस्या के स्थाई समाधान के लिये जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पावटा चौराहा, जालोरी गेट एवं पांचवी रोड पर फ्लाई ओवर निर्माण हेतु तकमीना तैयार किया गया है।

(2) जी हां। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोधपुर शहर की व्यस्ततम सडक (हार्ट लाइन) चौपासनी से पावटा चौराहा तक के मध्य पावटा चौराहा, जालोरी गेट एवं पांचवी रोड पर फ्लाई ओवर निर्माण हेतु तकमीना तैयार किया गया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण की वित्तीय परिस्थितियां

(स्वायत्त शासन मंत्री)

अनुकूल नहीं होने के कारण वर्तमान में इन फ्लाई ओवरों का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

इन्दिरा गांधी नगर योजना (जयपुर) में विधायकों को मकान आबंटन

415. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा तेरहवीं विधान सभा के माननीय सदस्यों को इंदिरा गांधी नगर में मकान आबंटित किये गये हैं लेकिन इससे पूर्व के माननीय सदस्यों को प्लाट आबंटित नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। वर्ष 2006 में दिनांक 24.4.2006 से 15.6.2006 तक 12वीं विधान सभा के माननीय विधायकों के अतिरिक्त प्रदेश के सांसदों/पूर्व विधायकों हेतु प्रताप नगर सांगानेर आवासीय योजना में बहुमंजिले आवासों हेतु पंजीकरण योजना आरम्भ की गई थी। माननीय सांसदों/विधायकों के द्वारा बहुमंजिले आवास लेने हेतु असहमति जाहिर करने पर एक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित किया। जिस पर माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 13.1.2012 को आयोजित बैठक में इन आवेदकों को प्रताप नगर आवासीय योजना के स्थान पर इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जगतपुरा, जयपुर में 11.25X21.00 वर्गमीटर के प्लिंथ स्तर के आवास आबंटित किये जाने का निर्णय हुआ। निर्णय लम्बित रहने के कारण आवास आबंटन में विलम्ब हुआ। इसके पश्चात जिस भूमि पर आवास निर्मित किये जाने थे, उस भूमि पर खातेदारों से भूमि विवाद होने के कारण एवं भूमि मण्डल के कब्जे में नहीं होने के कारण, इन पंजीकृत आवेदकों को आवास आबंटित नहीं किये जा सके थे।

इसी बीच 13वीं विधान सभा के माननीय विधायकों एवं प्रदेश के वर्तमान सांसदों हेतु विशिष्ठ पंजीकरण योजना दिनांक 19.6.2012 से 30.9.2012 तक आरम्भ की गई, जिसमें 117 माननीय सांसदों/विधायकों के द्वारा पंजीकरण करवाया गया। उक्त पंजीकृत माननीय विधायकों एवं सांसदों हेतु योजना के सैक्टर 8 में भूमि उपलब्ध थी। सैक्टर 8 में उपलब्ध भूमि

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

पर 12X18 मीटर के आवासों का निर्माण किया जाना था। अत: 13वीं विधान सभा के पंजीकृत आवेदकों को प्लिंथ स्तर पर निर्मित आवास आबंटित कर दिये गये।

वर्ष 2006 में पंजीकृत 133 माननीय सांसदों/विधायकों को आवास आबंटित कर दिये गये हैं। वर्ष, 2006 में पंजीकृत 16 विधायकों/सांसदों को पूर्व ग्रहण राशि जमा नहीं करवाने के कारण आवास आबंटित नहीं किये जा सके हैं। पूर्व ग्रहण राशि जमा करवाने के पश्चात आबंटन लाटरी के माध्यम से आवास आबंटित कर दिये जायेंगे।

उक्त वर्ष, 2006 में पंजीकृत 16 आवेदकों के अतिरिक्त कोई माननीय विधायक/सांसद आवास की प्रतीक्षा में नहीं है।

अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय कालोनियां

416. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

अजमेर विकास प्राधिकरण की वर्तमान में कुल कितनी आवासीय कालोनियां प्रस्तावित हैं? उक्त योजनाओं के क्या-क्या नाम प्रस्तावित हैं एवं इनमें किसानों की कितनी सरकारी एवं कितनी सिवायचक भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है? प्रस्तावित योजनाओं के क्षेत्र में अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में वर्तमान में निम्नांकित आवासीय कालोनियां प्रस्तावित की गई हैं, जो कि निम्नांकित ग्रामों में बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें निम्नानुसार खातेदारी एवं सिवायचक भूमि शामिल है :-

क्र. सं.	**नाम प्रस्तावित योजना**	**ग्राम का नाम**	**शामिल खातेदारी भूमि**	**शामिल सिवायचक भूमि**
1.	एन.आर.आई. एवं एन.आर.आर. योजना	माकड़वाली	-	123-15-00 बीघा

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

क्र. सं.	नाम प्रस्तावित योजना	ग्राम का नाम	शामिल खातेदारी भूमि	शामिल सिवायचक भूमि
2.	हेमू कालोनी नगर योजना	कायड़ व माकड़वाली	695-05-10 बीघा	15-05-10 बीघा
3.	सावित्री नगर योजना	कायड़ व माकड़वाली	901-14-00 बीघा	177-14-00 बीघा
4.	दाहरसेन नगर योजना	लोहागल	368-00-00 बीघा	13-00-00 बीघा

एन.आर.आई. व एन.आर.आर. योजना की राज्य सरकार द्वारा धारा 32(1) के तहत अधिसूचित किये जाने के उपरान्त योजना क्रियान्वित की कार्यवाही की जा रही है।

हेमू कालोनी नगर, सावित्री नगर व दाहरसेन नगर के सम्बन्ध में निर्णय प्राधिकरण स्तर पर विचाराधीन है।

सचिवालय नगर योजना (जयपुर) का नियमन

417. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की सचिवालय नगर योजना में कुल कितने भूखण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में कितने भूखण्डधारियों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे आबंटित किये जा चुके हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में नियमन से वंचित रहे अनेक भूखण्डधारियों ने जयपुर विकास प्राधिकरण में सचिवालय नगर एवं सचिवालय नगर विस्तार में अपने भूखण्ड के नियमन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं? यदि हां, तो किन-किन भूखण्डधारियों के नियमन हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए एवं प्राप्त आवेदनों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल)

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना के नियमन की पत्रावली निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित की गयी थी? यदि हां, तो निबन्धक द्वारा इस योजना के नियमन के सम्बन्ध में अपनी क्या राय प्रस्तुत की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार इस योजना के नियमन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की सचिवालय नगर योजना में कुल 740 भूखण्ड हैं।

(2) उक्त योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 651 पट्टे जारी किये गये हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है

(3) जी हां। भूखण्डधारियों के नियमन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की सूची उपलब्ध पत्रावली अनुसार परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

गैर अनुमोदित भाग की 90बी की कार्यवाही माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त द्वारा अपील संख्या 81/2011 निर्णय दिनांक 24.6.2014 व अपील संख्या 82/2011 निर्णय दिनांक 24.6.2014 के द्वारा निरस्त किये जाने से प्राप्त आवेदन पत्रों (अभ्यावेदन) पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं है। निर्णय की प्रति परिशिष्ट "स" व "द" पर संलग्न है।

(4) जी हां। योजना की 90बी की पत्रावली निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा चाहे जाने पर पत्र क्रमांक : 4051 दिनांक 21.1.2015 के द्वारा निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर को भेजी गई है। प्राप्त एवं प्रेषित पत्रों की प्रति परिशिष्ट "य" व "र" पर संलग्न है। पत्रावली राजस्व मण्डल, अजमेर से वापिस प्राप्त नहीं हुई है।

(5) यदि निरस्त की गई 90बी के निर्णय न्यायालय राजस्व मण्डल से बहाल हो जाये तो ही नियमानुसार नियमन की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तारानगर में अभियन्ताओं के रिक्त पद

418. श्री जयनारायण पूनियां (तारानगर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जयनारायण पूनियां)

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में विभाग के अभियन्ताओं व कार्मिकों, बेलदार, सुपरवाइजर व सहायक आदि के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार क्षेत्र की सिंचाई प्रणालियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1)

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
अधिशासी अभियन्ता	1	1	0
सहायक अभियन्ता एवं तक. सहा.	1	1	0
सहायक अभियन्ता एवं तक. सहा. II	1	1	0
सहायक अभियन्ता, पी.एस. II	1	0	1
सहायक अभियन्ता	3	2	1
खण्डीय लेखाकार	1	1	0
लेखाकार	1	0	1
कनिष्ठ अभियन्ता	14	8	6
कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
क्लर्क ग्रेड-I	6	2	4
क्लर्क ग्रेड-II	9	5	4
वरिष्ठ प्रारूपकार	1	0	1
कनिष्ठ प्रारूपकार	1	0	1
अनुरेखक	1	0	1
धूपदर्शक	1	0	1
जमादार	1	1	0
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	8	8	0
पटवारी	1	1	0
योग	**53**	**31**	**22**

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

कार्यप्रभारी कर्मचारियों का विवरण

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
बेलदार	73	31	42
मेट/सुपरवाईजर/वक मिस्त्री	19	12	7
पम्प चालक	3	0	3
गेज रीडर	12	0	12
चौकीदार	14	14	0
माली	7	0	7
खानसामा	3	0	3
कुक	5	0	5
ड्राईवर	2	1	1
योग	**138**	**58**	**80**

(2) उपलब्ध अधिकारी/कर्मचारियों से सिंचाई प्रणाली सुचारु रूप से चलायी जा रही एवं आवश्यकता अनुरूप रिक्त पदों को पदस्थापन द्वारा भरा जाता है।

प्रदेश की नदियों को जोड़ने हेतु कार्य योजना

419. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश की नदियों को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार? कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य प्रारम्भ किया है, जिसके अन्तर्गत ब्राहमणी नदी को बनास नदी से तथा पार्वती-कालीसिंध को बनास, गम्भीर एवं पार्बती नदियों से जोड़ने हेतु इन्हें राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किये जाने एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय जल आयोग से निवेदन किया गया है। इन परियोजनाओं पर संसाधन उपलब्धतानुसार अग्रिम कारवाई की जानी प्रस्तावित है।

(जल संसाधन मंत्री)

चम्बल, माही, साबरमती, लूनी, वेस्ट बनास एवं सुकली बेसिन में सहायक नदी/नालों पर फोर वाटर कन्सेप्ट के अन्तर्गत एकीकृत कमाण्ड एवं जल ग्रहण क्षेत्र विकास आधारित कार्य हाथ में लिये गये है, जिससे नदियों की सहायक नदियों/नालों में बारहमासी पानी की मात्रा में बढ़ोत्तरी होकर नदी बेसिन की धारायें आपस में अधिक समय तक जल प्रवाह से जुडी रहेगी।

चम्बल नदी का पानी जगर बांध में लाने की योजना

420. श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि चम्बल का पानी पांचना बांध में और पांचना बांध से जगर बांध में लाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त योजना की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में चम्बल का पानी पांचना बांध में एवं पांचना बांध से जग्गर बांध में लाने हेतु कोई सिंचाई परियोजना विचाराधीन नहीं है, क्योंकि चम्बल नदी पर प्रस्तावित अन्य योजना 'धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना' के क्रम में वन्यजीव मण्डल की स्थाई समिति की 22वीं बैठक में "चम्बल नदी में घड़ियाल अभयारण क्षेत्र होने से यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में चम्बल नदी से पानी लिफ्ट कर निर्मित की जाने वाली योजना पर विचार नहीं किया जावेगा"।

अत: वर्तमान में चम्बल-पांचना-जग्गर एकीकृत पेयजल आधारित योजना तैयार करने के प्रस्ताव हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कारवाई की जा रही है। परियोजना स्थल पर जल उपलब्धता गणना हेतु केन्द्रीय जल आयोग से डाटा प्राप्त कर तदानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जानी प्रस्तावित है।

बीसलपुर बांध की सुरक्षा का कार्य सी.आई.एस.एफ. को देने की योजना

421. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कन्हैयालाल)

(1) क्या सरकार बीसलपुर बांध की सुरक्षा निजी सुरक्षा कम्पनियों से हटाकर सी. आई. एस. एफ. देवली को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की 15 ग्राम पंचायतों पर एनिकट निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त एनिकटों के निर्माण के प्रस्ताव मय तकमीने के तैयार किये जा चुके हैं? यदि हां, तो निर्माण कार्य शुरु नहीं होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार इस हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि विभाग द्वारा निदेशक सी.आई.एस.एफ. हैड क्वार्टर्स, नई दिल्ली से बीसलपुर बांध की सुरक्षा हेतु निवेदन किया था। परन्तु महानिदेशक कार्यालय द्वारा उक्त कार्य करने में असमर्थता प्रकट की थी।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की 12 ग्राम पंचायतों में 14 एनिकट निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिनकी हाइड्रोलोजी गणना टी.ए.सी में प्रक्रियाधीन है। प्रस्तावों का परीक्षण कर गुणावगुण एवं संसाधन उपलब्धतानुसार निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। 14 एनिकटों के तखमीने तैयार किये गये हैं परन्तु इनकी हाइड्रोलोजी गणना टी.ए.सी. में प्रक्रियाधीन है। हाइड्रोलोजी अनुमोदन पश्चात संसाधन उपलब्धतानुसार अग्रिम कारवाई की जानी प्रस्तावित होने से कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रदेश के छात्रावासों में देय मूलभूत सुविधाएं

422. श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में छात्रवृत्ति नहीं दी गई है? यदि हां, तो ऐसे कितने छात्र-छात्रायें हैं? संख्या सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(श्रीमती कमसा)

(2) सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं की क्या-क्या कमी है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) जोधपुर जिले में छात्रावासों में रहने वाली बालिका एवं बालकों की संख्या कितनी-कितनी है? छात्रावास अनुसार पृथक-पृथक सूची सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमानुसार पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है। कुछ विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में आक्षेप होने के कारण स्वीकृत नहीं हो पाई है। वर्ष 2013-14 के 33771 एवं 2014-15 (फरवरी, 2015 तक) के 260891 छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र लम्बित हैं।

(2) सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित छात्रावासों में से कतिपय छात्रावासों में चारदीवारी, स्नानघर, शौचालय, पर्याप्त पेयजल आपूर्ति, बिजली फिटिंग, सेनेटेशन तथा साधारण मरम्मत आदि मूलभूत सुविधाओं की कमी है। मूलभूत सुविधाओं की इन कमियों की पूर्ति हेतु जिलाधिकारियों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जोधपुर जिले में संचालित 25 छात्रावासों में 1019 छात्र एवं 5 छात्रावासों में 211 छात्राएं आवासरत हैं। जिनका छात्रावासवार विवरण परिशिष्ट ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने की योजना

423. **श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि देश के अनेक राज्यों में जैन समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया हुआ है? यदि हां, तो किन-किन प्रदेशों में व कब से? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री मनोज कुमार)

(2) क्या सरकार राज्य में जैन समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) इसका सम्बन्ध केन्द्र सरकार से है।

(2) जी हां। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना फा.सं. 1-1/2009-एनसीएम दिनांक 27.01.2014 द्वारा जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक रूप में अधिसूचित किया गया है। इसी क्रम में अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान सरकार द्वारा क्रमांक प.19(5)अल्प.वक्फ/2014 जयपुर दिनांक 14.03.2014 जारी कर जैन समुदाय के भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया है।

प्रदेश में दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं को मुआवजा

424. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो अधिकतम कितना मुआवजा देय है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मुआवजा राशि केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला को ही देय है एवं सामान्य वर्ग की महिला या ओबीसी वर्ग की महिला को मुआवजा राशि देय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार सामान्य वर्ग व ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी मुआवजा राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अनुसूचित जाति और जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नियम 1995 के 12(4) के अन्तर्गत प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की महिलाओं के साथ गैर अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म करने पर पीड़िताओं को अधिकतम 1.80 लाख रुपये तथा राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2012 के अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिला या ओबीसी वर्ग की महिला को अधिकतम 3.00 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) जी नहीं। अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को मुआवजा राशि देय है तथा राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2012 के अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिला या ओबीसी वर्ग की महिला को भी आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं को पूर्व से ही अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को तथा राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2012 अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिला या ओबीसी वर्ग की महिला को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत अनियमितताओं की जांच

425. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा/तलाकशुदा व विशेष योग्यजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृत किये जाने के क्या मानदण्ड/नियम निर्धारित हैं? नियम/मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर, मावली (उदयपुर) एवं जमवारामगढ़ (जयपुर) में ''प्रशासन गांवों के संग'' अभियान के तहत ऐसे पेंशनधारी जिनके पुत्र/पति/पत्नी राजकीय सेवा में कार्यरत हैं या पेंशनर होते हुए उनकी माता/पिता/पुत्र आदि अभियान में पेंशन स्वीकृत करवाकर पेंशन का लाभ ले रहे हैं, की विशेष जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? तहसीलवार, पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में उक्त पेंशन योजना लागू होने के उपरान्त उक्त विधान सभा क्षेत्रों में ऐसे पेंशनधारी जिनके पुत्र राजकीय सेवा में होते हुए भी पेंशन उठा रहे हैं? क्या सरकार उक्त योजना से उठायी गयी राशि की वसूली करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत निम्नांकित योजनाएं उनके समक्ष अंकित दिनांक से संचालित की जा रही हैं :

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (दिनांक 06.11.2007)
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (दिनांक 7.10.2009)
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना (दिनांक 24.11.2009)
4. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (दिनांक 1.4.2013)
5. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना (दिनांक 1.4.2013)
6. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (दिनांक 1.4.2013)

प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता तथा विशेष योग्यजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृत किये जाने के मानदण्ड/नियम की प्रति परिशिष्ट 1 से 5 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रशासन गांवों के संग अभियान (कैम्प) के समय भी सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था, विधवा/तलाकशुदा पेंशन स्वीकृत करते समय पटवारी पंचायत ग्राम सेवक (पदेन सचिव) द्वारा नियमानुसार आवश्यक जांच किये जाने के उपरान्त ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर पेंशन स्वीकृत/जारी की गई है।

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर, मावली (उदयपुर) एवं जमवारामगढ (जयपुर) में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा "प्रशासन गांवों के संग" अभियान के तहत ऐसे आवेदक जिनके पुत्र /पति/ पत्नी राजकीय सेवा में कार्यरत हैं या पेंशनर हैं, को पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है।

(3) प्रदेश में उक्त योजना लागू होने के पश्चात् विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर, मावली (उदयपुर) एवं जमवारामगढ़ (जयपुर) में ऐसे पेंशनधारी जिनके पुत्र राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, का प्रकरण जानकारी में नहीं आया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में संचालित बालिका एवं किशोर गृह

426. श्री बंशीधर (खण्डेला) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सम्प्रेक्षण गृह अपचारी बालिका गृह एवं किशोर गृह संचालित किए जा रहे हैं? यदि हां, तो जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में संचालित किशोर गृह अपचारी बालिका गृह व सम्प्रेक्षण गृह में कितने बच्चे रह रहे हैं? गत पांच वर्षों में इन गृहों में कितने-कितने बच्चे आये/लाये गये तथा कितने बच्चों को उनके माता-पिता के सुपुर्द किया? जिलेवार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिलों में संचालित उक्त प्रकार के गृहों में किस-किस प्रकार के अपराध के बालक-बालिका सम्प्रेक्षण गृह एवं अपचारी बालिका गृह में लाए गए हैं? अपराध का वर्गीकरण एवं बालक-बालिकाओं की संख्या का जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त संचालित गृहों में से कितने बालक-बालिकाओं पर जे जे बोर्ड में केस चल रहा है व कितनों का निस्तारण किया जा चुका है? गत पांच वर्षों में जे जे बोर्ड के तहत निस्तारित केसों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार द्वारा किशोर गृह अपचारी बालिका गृह एवं सम्प्रेक्षण गृहों में बच्चों को कब से कब तक रखा जाता है तथा इनकी दैनिक दिनचर्या क्या है? उक्त बालक-बालिकाओं पर प्रतिदिन कितनी राशि व किस-किस मद में व्यय की गई? गत पांच वर्षों में जिलेवार सम्प्रेक्षण गृह, अपचारी बालिका गृह एवं किशोर गृह के आय-व्यय का वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में कुल 7 अपचारी बालिका गृह तथा 33 किशोर एवं सम्प्रेक्षण गृह संचालित किये जा रहे हैं, जिनकी जिलेवार सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) उक्त जिलों में संचालित किशोर गृह, अपचारी बालिका गृह एवं सम्प्रेक्षण गृह में कुल 495 बच्चे आवासित हैं, जिसकी जिलेवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

अब तक पिछले पांच वर्षों में आये लाये गये बच्चों एवं माता-पिता को सुपुर्द किये गये बच्चों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) उक्त जिलों में संचालित सम्प्रेक्षण एवं अपचारी बालिका गृहों में हत्या, चोरी, बलात्कार, जानलेवा हमला, अपहरण, मादक पदार्थ, डकैती एवं अन्य प्रकार के अपराधों में बच्चे लाये गये हैं। अपराध का वर्गीकरण के आधार पर वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट द पर संलग्न है।

(4) उक्त संचालित गृहों में आवासित बच्चों पर जे.जे. बोर्ड में केसों के सम्बन्ध में प्राप्त/निस्तारण/लम्बित प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(5) सरकार द्वारा किशोर गृह, अपचारी बालिका गृह एवं सम्प्रेक्षण गृहों में 6 से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के निर्देशानुसार गृहों में प्रवेशित दिया जाता है। उक्त बच्चों की दिनचर्या परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

उक्त बालक बालिकाओं पर प्रतिदिन व्यय किये जाने की मदवार सूची परिशिष्ट-ल पर संलग्न है। विगत पांच वर्षों की आय-व्यय का विवरण वर्षवार एवं जिलेवार सूची परिशिष्ट-व पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के मदरसों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों का नियमितीकरण

427. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित किए जा रहे मदरसों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शिक्षा सहयोगियों के मानदेय में बढ़ोतरी किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान मदरसा बोर्ड में शिक्षा सहयोगी संविदा पर मदरसों में कार्यरत हैं। इनको नियमित किये जाने की कोई योजना नहीं है।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

(2) जी नहीं। शिक्षा सहयोगियों को न्यूनतम मानदेय रुपये 4100/- से अधिकतम रुपये 7500/- के स्लैब में निर्धारित हैं। शिक्षा सहयोगियों को प्रतिवर्ष देय मानदेय में रुपये 400/- की वृद्धि की जाती है।

भीम में उचित मूल्य की दुकानों का संचालन

428. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां संचालित हैं? दुकानदार के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ उचित मूल्य की दुकानों को एटेच भी किया हुआ है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से जून, 2014 तक उचित मूल्य की दुकानों में गबन/अनियमितताओं की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कुल 115 (तहसील भीम में 71, तहसील देवगढ़ में 34 तथा नगरपालिका क्षेत्र देवगढ़ में 10) दुकानें संचालित हैं। दुकानदार के नाम सहित सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में दो उचित मूल्य की दुकानों को एटेच भी किया हुआ है, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से जून, 2014 तक 4 उचित मूल्य की दुकानों में गबन अनियमितताओं की शिकायतें पाई गई। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही दर्ज कर प्राधिकार पत्र निलम्बन, निरस्त, प्रतिभूति जब्त, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत माल जब्त कर माल के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना एवं सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने की कार्यवाही की गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर शहर में राशन कार्डों में हुई त्रुटियों का विवरण

429. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में किन-किन वार्डों में नवीन राशन कार्ड वितरित किये जा चुके हैं तथा किन वार्डों में किया जाना शेष हैं? वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में कितने कार्ड वितरित किये जाने शेष हैं व किस कारण से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है नवीन राशन कार्डो में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों की भारी मात्रा में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो उक्त त्रुटियों के निस्तारण के लिए क्या कार्य किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित किये गये परिवारों को पुराने राशन कार्डों पर मुहर लगाकर चिन्हित किया गया था? यदि हां, तो क्या वर्तमान में बांटे जा रहे/बांटे गये नवीन राशन कार्डस पर भी उक्त मुहर लगाकर ही बांटा गया हैं अथवा कोई अन्य प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में 1 से लगायत 50 वार्डो में नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। वार्डवार राशन कार्डों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) अलवर शहर के सभी वार्डों में राशन कार्ड वितरित किये जा चुके हैं, लेकिन राशन कार्ड वितरण के समय कैम्पों में कुछ उपभोक्ताओं के राशन कार्ड प्राप्त करने नहीं आने से लगभग 4597 राशन कार्ड वितरण से शेष हैं, जिनका वितरण किया जा रहा है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि तैयार राशन कार्डों के मुद्रण में मुख्य रूप से नाम, आयु, सम्बन्ध एवं श्रेणी आदि के सम्बन्ध में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं। इन त्रुटियों को सम्बन्धित फर्म से संशोधित कराकर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिनांक 17.9.2013, 13.1.2014 एवं 27.3.2014 को निर्देश जारी किये गये थे। राशन कार्ड कार्य से सम्बन्धित जिन फर्म्स द्वारा राशन कार्ड त्रुटि सुधार कर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, उन फर्मों के

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

विरुद्ध निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है।

जिला अलवर में सम्बन्धित फर्म द्वारा दिनांक 1.2.2015 से 22.2.2015 तक शिविर लगाकर त्रुटि सुधार का कार्य किया गया है। दिनांक 23.2.2015 से सभी वार्डों के राशन कार्डों की त्रुटियां जिला रसद कार्यालय, अलवर में सुधारी जा रही हैं।

(4) जी हां। यह सही है कि खाद्य सुरक्षा योजना परिवारों को चिन्हित कर पुराने राशन कार्डों में मोहर अंकित की गई थी। नवीन राशन कार्डों में खाद्य सुरक्षा मोहर अंकित नहीं है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना की सूची प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार के पास उपलब्ध है, जिसके आधार पर वितरण कराया जा रहा है। साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित राशन कार्डधारी से सम्बन्धित दस्तावेज, जिसके आधार पर उसे खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित किया गया था, मंगाए जाकर सत्यापन किया जा रहा है। इस आधार पर अंतिम सूची तैयार कर नवीन राशन कार्डों पर एन.एस.एफ.ए. कोड का अंकन किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा जिले में नवीन राशन की दुकानें खोलने की योजना

430. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लालसोट सहित दौसा जिले मे वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन की कितनी लाइसेन्स शुदा दुकानें कहां-कहां व कब से संचालित हैं? वार्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपभोक्ताओं की सुविधार्थ सम्पूर्ण जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण व उसके प्रभावी संचालन के लिये छत्तीसगढ़ पैटर्न को अपनाने के लिये प्रक्रिया विचाराधीन है? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना संचालित है? यदि हां, तो इसके तहत किन-किन को क्या-क्या सामग्री कितनी-कितनी मात्रा

(श्रीमती गोलमा)

में प्रदान की जाती है? तथा इसका क्या माध्यम है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त सामग्री लाभार्थी तक न पहुंचकर बीच में ब्लैक में विक्रय कर दी जाती है? यदि हां, तो इस पर रोक लगाने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्तमान में दौसा जिले में कुल 732 लाइसेन्सशुदा दुकानें कार्यरत हैं, जिसमें से विधान सभा क्षेत्र लालसोट में 154 दुकानें कार्यरत हैं। विधानसभा क्षेत्र लालसोट की उचित मूल्य दुकानों का विवरण परिशिष्ट-1 पर एवं शेष दौसा जिले की उचित मूल्य दुकानों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य में उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 9.2.2015 को जारी किये जा चुके हैं। नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार नवसृजित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आबंटन के सम्बन्ध में सार्वजनिक विज्ञप्ति दिनांक 3.3.2015 को जारी की जा चुकी है, जिसके तहत राशन दुकान डीलर नियुक्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है।

(3) प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण व उसके प्रभावी संचालन के लिये छत्तीसगढ़ पैटर्न के अध्ययन हेतु एक दल का गठन किया गया था। उक्त दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया गया है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावी संचालन हेतु सम्पूर्ण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करने एवं अन्नपूर्णा भण्डार पेटर्न पर उचित मूल्य दुकान संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

(4) जी हां। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को वर्तमान में निम्नानुसार सामग्री का वितरण किया जा रहा है :-

1- खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 35 किग्रा. प्रति परिवार प्रतिमाह, बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को 5 किग्रा. प्रति यूनिट प्रतिमाह एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को समानुपातिक रूप से 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराया जा रहा है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

2- बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को 500 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 13.50 रुपये प्रति किग्रा. की दर से चीनी उपलब्ध कराई जा रही है।

3- बिना गैस कनेक्शनधारी समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को केरोसीन 4 लीटर प्रति राशनकार्ड 17.25 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

(5) सम्पूर्ण राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं सामग्री के विपथन को रोकने के लिये सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को कम्प्यूटराइज्ड किया जा रहा है।

राज्य में नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड वितरित किये गये हैं। सामग्री वितरण हेतु बायोमेट्रिक प्रणालीयुक्त पोश (POS-Point of Sale) मशीन उपलब्ध करवाई जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ में राशन की नवीन दुकानें

431. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राशन की दुकान स्वीकृत किये जाने के क्या मानदण्ड/नियम निर्धारित हैं? मानदण्ड/नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में राशन की कितनी दुकान कहां - कहां स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों में नयी राशन की दुकान खोले जाने हेतु ज्ञापन/पत्र/प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? प्राप्त ज्ञापन/पत्र/प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी और उनके आधार पर कहां-कहां पर नयी राशन की दुकान खोली गयी और किस-किस स्थान का प्रस्ताव निरस्त किया गया? प्रस्ताव निरस्त करने के क्या कारण रहे? प्राप्त ज्ञापन/पत्र/प्रार्थना-पत्रों की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र में नवलगढ़ के मोहब्बतसरी गांव में नई राशन की दुकान स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राशन की दुकानें स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक एफ 13(10)खा.वि./खा.सु.अध्या./2013 दिनांक 6.9.2013 में उचित मूल्य दुकान स्वीकृत करने के मानदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर एवं दिनांक 9.2.2015 को जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में राशन की 110 दुकान स्वीकृत हैं, जिनमें से 80 ग्रामीण व 30 शहरी क्षेत्र में हैं। विस्तृत सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में गत तीन वर्षो में नयी राशन की दुकान खोले जाने हेतु ज्ञापन/पत्र/प्रार्थना पत्र मात्र ग्राम मोहब्बतसरी हेतु दिनांक 2.2.2015 को प्राप्त हुआ था, जिसकी प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। ग्राम मोहब्बतसरी में नवीन डिजिटाइज्ड राशनकार्डधारी केवल मात्र 203 ही है। दिनाक 7.6.2012 को विज्ञप्ति जारी कर विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में रिक्त 4 उचित मूल्य दुकानों पर डीलर नियुक्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 7.3.2013 को 3 स्थानों पर डीलरों की नियुक्ति की गयी एवं 1 स्थान निवाई हेतु आवेदन प्राप्त नहीं होने से नियुक्ति नहीं की गई। सूची परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के ग्राम मोहब्बतसरी में नयी उचित मूल्य दुकान खोलने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिनांक 2.2.2015 को प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार की नीति के अनुरूप नयी उचित मूल्य दुकान का सृजन 500 राशनकार्ड होने पर ही किया जा सकता है। नवीन डिजिटाइज्ड आंकड़ों की जांच करने पर ग्राम मोहब्बतसरी में केवल मात्र 203 राशनकार्डधारी हैं। ग्राम मोहब्बतसरी के उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु ग्राम घोडीवाडाखुर्द के साथ ग्राम मोहब्बतसरी को जोड़कर उचित मूल्य दुकान संचालित की जा सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्वायत्तता

432. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(1) क्या प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु सरकार द्वारा बनाये गये राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार सहकारी संस्थाओं में निर्वाचन से सम्बन्धित प्रावधानों में संशोधन करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन सहकारी संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उनका चुनाव कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्राथमिक सहकारी समितियों का कार्यकाल आधे से अधिक पूर्ण हो चुका है व इन्हीं के आधार पर केन्द्रीय सहकारी बैकों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों का निर्वाचन होगा तथा सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन पांच वर्ष के लिये किया जाता है जबकि इन प्राथमिक सहकारी समितियों के आधार पर होने वाले बोर्ड का कार्यकाल 2.5 वर्ष ही रहेगा? क्या सरकार इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने की कोई कार्य योजना बनाने का विचार है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 33 के अनुसार राज्य की सभी सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कर और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी में निहित है।

जी नहीं। सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा करवाए जाने सम्बन्धी प्रावधानों में संशोधन के कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) जैसा कि प्रश्न के खण्ड-1 में उल्लेख है, सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन की शक्तियां राज्य सरकार में निहित नहीं है, अपितु यह शक्तियां राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी में निहित हैं।

(3) जी हां। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 550 प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के निर्वाचन ड्यू हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की अनेक अन्य प्रकार की सहकारी समितियों में भी निर्वाचन ड्यू हो चुके हैं।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 27 के प्रावधानानुसार किसी सहकारी सोसाइटी में निर्वाचित संचालक मण्डल का कार्यकाल सामान्यतया पांच वर्ष निर्धारित है, किन्तु अनेक बार राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 28 व 30 एवं राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 33 व 34 में वर्णित आधारों पर संचालक मण्डल अथवा उसके किसी सदस्य को उक्त अवधि से पूर्व भी हटाये जा सकने के प्रावधान हैं।

विभाग स्तर पर अभी तक अधिनियम के उक्त प्रावधानों में संशोधन किये जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन

433. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करने हेतु कोई नीति निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में अधिकांश जिलों में दो ग्राम पंचायतों के लिए एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सहकारिता क्षेत्र में किसानों को अधिकाधिक लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का संचालन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) अजमेर जिले में वर्तमान में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समिति का संचालन किया जा रहा है? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या डी.124/मं.मं./2011 दिनांक 21.9.2011 के अनुसरण में विभागीय आदेश दिनांक 26.9.2011 जैसलमेर जिले के आई.जी.एन.पी. (सी.ए.डी.) क्षेत्र को छोड़कर तथा मंत्रिमण्डल की आज्ञा डी.125/मं.मं./2013 दिनांक 27.6.2013 के अनुसरण में विभागीय आदेश

(सहकारिता राज्य मंत्री)

दिनांक 11.7.2013 के द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना (सी.ए..डी.) द्वितीय चरण, जैसलमेर में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। राज्य में वर्तमान में अधिकांश जिलों में एक से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का संचालन किया जा रहा है।

मंत्रिमण्डल की आज्ञा 183/2008 दिनांक 6.10.2008 के पश्चात् नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन में ग्राम पंचायत को आधार मानकर गठन की प्रक्रिया शुरू की गई। जिलों से प्राप्त सूचनानुसार जहां राज्य में 9900 ग्राम पंचायतें हैं उनमें 2386 पैक्स/लैम्पस में एक से अधिक ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं। (परिशिष्ट-2)

(3) जी हां। सहकारिता क्षेत्र में किसानों को अधिकाधिक लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

(4) अजमेर जिले में 170 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का संचालन किया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फतेहपुर शेखावटी के पुरा स्मारकों/हवेलियों के संरक्षण की कार्य योजना

434. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार फतेहपुर की अनुपम हवेली, भित्ती चित्रों व चित्रकला शैली को बढ़ावा देने, उनका संरक्षण एवं प्रचार प्रसार करने हेतु बजट उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार फतेहपुर शेखावटी के पुराने स्मारकों को संरक्षित घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन को व नहीं, तो क्यों? सूची विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

(3) क्या यह सही है कि फतेहपुर शेखावटी में हवेलियां व इमारतें देखरेख के अभाव में खण्डहरों में तबदील हो रही हैं व उन पर अतिक्रमण हो रहे हैं?

(4) क्या सरकार पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण उक्त प्राचीन हवेलियों व इमारतों का संरक्षण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) फतेहपुर शेखावटी में फतेहपुर का किला विभाग द्वारा संरक्षित घोषित है। अन्य स्मारकों को संरक्षित करने के सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। फतेहपुर शेखावटी की कुछ हवेलियां तथा इमारतें देखरेख के अभाव में क्षतिग्रस्त हो रही है। इन पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है।

(4) शेखावटी क्षेत्र की पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राचीन हवेलियां व इमारतें विभाग द्वारा संरक्षित नहीं हैं, परन्तु विभाग द्वारा इनका विस्तृत सर्वे करवा लिया गया है। इन हवेलियों के संरक्षण एवं पुनरूद्धार के सम्बन्ध में नीति निर्धारण तथा कार्य योजना बनाने के प्रयास निरन्तर जारी हैं।

प्रदेश में नवीन पर्यटन नीति जारी करने की योजना

435. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नवीन पर्यटन नीति लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या सरकार नवीन पर्यटन नीति में होटल व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उन औद्योगिक क्षेत्रों में जहां उद्योग नहीं पनप रहे हैं, वहां होटल व्यवसायी को व्यवसाय करने की छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विभाग में नवीन पर्यटन इकाई नीति को लागू करना प्रक्रियाधीन है।

(2) पर्यटन को उद्योग का दर्जा वर्ष 1989 से ही प्रदत्त है, जिसमें होटल व्यवसाय भी सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) पर्यटन इकाई नीति-2007 एवं राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम-2014 में सम्पूर्ण राज्य में नवीन पर्यटन इकाइयों (होटल सहित) की स्थापना पर अनेक प्रकार की रियायतें उपलब्ध हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश की पंचायतों में सीनियर सैकण्डरी स्कूल का क्रमोन्नयन

436. श्रीमती अनीता (नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश की समस्त पंचायतों में सीनियर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्न्त करने का आदेश पारित किया है? यदि हां, तो उक्त आदेशों के अनुसार कितने शिक्षक व कला, वाणिज्य, विज्ञान के विषयवार कितने व्याख्याताओं की आवश्यकता पड़ेगी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त शिक्षकों की भर्ती कब तक करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार नये शिक्षा सत्र शुरू होने पर उक्त व्याख्याताओं को विद्यालयों में पदस्थापन कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्कूलों का एकीकरण का आदेश जारी है? उक्त एकीकरण प्रक्रिया से कितने विद्यालय प्रभावित हुए हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि एकीकरण के कारण अनेक स्कूलों की इमारतें खाली हो गई हैं? ऐसी सभी स्कूल इमारतों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि एकीकरण के आदेश के तहत जो स्कूल इमारत खाली हुई है वह आज तक खाली ही है? यदि हां, तो क्या इनकी देखरेख के लिए कोई नियम बनाया गया है?

उत्तर

(1) वर्ष 2014-15 में राज्य की पुनर्गठन से पूर्व की कुल 9177 ग्राम पंचायतों में से 5000 ऐसी ग्राम पंचायतों, जिनमें निजी/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है, के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने के आदेश जारी किये गये। क्रमोन्नत विद्यालयों में संकायों का पुनर्निर्धारण प्रक्रियाधीन है। इसके पश्चात ही मानदण्डानुसार विषयवार व्याख्याताओं की आवश्यकता का आंकलन सम्भव हो सकेगा।

(2) 8203 व्याख्याताओं के रिक्त पदों को व 13016 वरिष्ठ अध्यापकों के पदों को डीपीसी से भरा गया है। 8857 वरिष्ठ अध्यापक के पद सीधी भर्ती से भरे गये हैं। उक्त नवक्रमोन्नत विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या का आंकलन करने के पश्चात ही पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी।

(3) 8203 व्याख्याताओं के रिक्त पदों को डीपीसी से भरा गया। उक्त नवक्रमोन्नत विद्यालयों में विषयवार व्याख्याताओं एवं संकाय के आंकलन पश्चात वांछित कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) जी हां। विद्यालयों का समन्वयन किया गया है। जिलेवार संख्या परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(5) जी हां। एकीकरण की वजह से खाली स्कूल इमारत की जिलेवार सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(6) जी हां। स्कूल की खाली इमारतें की देखरेख आदि के सम्बन्ध में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-1/आदर्शविद्यालय/21312/वो-2/2014, दिनांक 12 फरवरी, 2015 से निर्देशित किया गया है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ के विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पद

437. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जगदीश नारायण)

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के पद किस-किस विषय के कहां-कहां पर कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में फर्स्ट ग्रेड, द्वितीय ग्रेड और तृतीय ग्रेड के अध्यापकों के विषयवार पद कब से रिक्त हैं, का विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-''क'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। फर्स्ट ग्रेड-4010 पदों की अर्थना आयोग को प्रेषित किये जाने पर आयोग द्वारा परीक्षा ली जा चुकी है। परीक्षा परिणाम जारी किया जाना शेष है।

तृतीय ग्रेड के अध्यापकों की भर्ती ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जिला परिषद के माध्यम से की जा रही है।

अत: तद्नुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से आशार्थी उपलब्ध होने पर फर्स्ट ग्रेड और द्वितीय ग्रेड के पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सर्व शिक्षा अभियान के तहत अलवर जिले में व्यय राशि

438. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2014-15 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2014-15 में अलवर जिले में किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? तहसीलवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2014-15 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न कार्यों हेतु व्यय की जाने वाली राशि का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(2) सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2014-15 में अलवर जिले में विभिन्न कार्यो हेतु व्यय की गई राशि का ब्लाकवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली में अध्यापकों के रिक्त पद

439. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" तथा "ख" पर संलग्न है।

(2) तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्ति की कार्यवाही पंचायती राज विभाग में प्रक्रियाधीन है। विधान सभा क्षेत्र करौली के उक्त रिक्त पद जिला परिषद करौली द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति से भरे जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सरदारशहर में भवन रहित विद्यालय

440. श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के कौन-कौन से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन रहित संचालित हैं? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भवन रहित विद्यालयों हेतु भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में संचालित कोई भी राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन रहित नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में संचालित कोई भी राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन रहित नहीं है।

राजकीय विद्यालय भानपुर कलां (जयपुर) की भूमि का बेचान

441. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानपुर कलां तहसील जमवारामढ़ जिला जयपुर की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण है? यदि हां, तो किस-किस खसरे पर व कितना व किस-किस के द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय की खातेदारी भूमि का अवैध रूप से बेचान किया गया है? यदि हां, तो किसके द्वारा व कब?

(3) क्या यह सही है कि अवैध रूप से बेचान करने वालों व क्रेताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करने के लिये सक्षम अधिकारियों को शिकायती पत्र दिये गये हैं? यदि हां, तो कब व किस-किस अधिकारी को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि शिकायती पत्र प्राप्त होने के पश्चात सक्षम अधिकारियों द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार दोषी व्यक्तियों को बचाने एवं उनसे मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटाकर राजकीय स्कूल की भूमि को मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भानपुरकलां, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर की खातेदारी भूमि के खसरा नं. 522 में 2 बीघा 4 बिस्वा जमीन है, जिस पर क्रमश: श्री राजकुमार खण्डेलवाल, श्री बिरदाराम मीणा, श्री महादेव एवं श्री नाथू कुम्हार के द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(2) उक्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भानपुरकलां, जमवारामगढ़, जिला-जयपुर की खातेदारी भूमि का अवैध रूप से बेचान नहीं किया गया है अपितु राज्य सरकार द्वारा उक्त विद्यालय को विद्यालय भवन से पृथक लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित भूमि का आबंटन किये जाने के पश्चात् तत्कालीन प्रधानाध्यापक श्री सिद्धार्थ देव शर्मा द्वारा वर्ष 1974 में तत्समय विद्यालय भूमि पर अतिक्रमी कब्जाधारियों के साथ मात्र इकरारनामा किया गया था।

(3) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-द्वितीय, जयपुर को शिकायती पत्र दिनांक 24.7.2012 को शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक, जयपुर तथा शिकायती पत्र दिनांक 1.10.2012 द्वारा जिला कलक्टर, जयपुर को प्राप्त हुआ।

(4) जी हां। शिकायत की जांच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-द्वितीय, जयपुर द्वारा प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रूण्डल (आमेर) जयपुर एवं प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भादवा (सांभर), जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में श्री सिद्धार्थ देव शर्मा, तत्कालीन प्रधानाध्यापक को दोषी माना गया। श्री सिद्धार्थ देव शर्मा, प्रधानाध्यापक की मृत्यु दिनांक 22.12.1983 को ही हो जाने के कारण दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(5) जी हां। जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में आरोपी कार्मिक तत्कालीन प्रधानाध्यापक श्री सिद्धार्थ देव शर्मा का दिनांक 22.12.1983 को निधन हो जाने के कारण विभाग स्तर से कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है एवं जांच अधिकारी द्वारा अन्य किसी को दोषी नहीं माना गया है।

(6) जी हां। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भानपुरकलां, जयपुर की भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-द्वितीय, जयपुर को प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित संस्था प्रधान को निर्देशित किया गया कि आप अपने स्तर पर भी कार्यवाही करें, जिसके उपरान्त प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भानपुरकलां द्वारा जिला कलक्टर, जयपुर, तहसीलदार जमवारामगढ़ को क्रमश: पत्र दिनांक 7.12.2012, दिनांक 7.7.2014 व दिनांक 6.3.2015, दिनांक 18.12.2012 व

(शिक्षा राज्य मंत्री)

दिनांक 4.12.2013 के द्वारा संस्था प्रधान द्वारा अतिक्रमण हटाने के निरन्तर प्रयास जारी हैं।

अटरू व कवाई (बारां) में नवीन महाविद्यालय की स्थापना

442. श्री रामपाल (बारां-अटरू) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार बारां जिले के अटरू व कवाई में नवीन महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

अटरू उपखण्ड मुख्यालय पर निजी क्षेत्र में सहशिक्षा का केशव महाविद्यालय वर्ष 2007 से संचालित है एवं कवाई कस्बे में कोई निजी महाविद्यालय संचालित नहीं है।

निर्धारित मानदण्ड पूर्ण होने एवं वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर अटरू उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

मावली पंचायत समिति (उदयपुर) के गांवों में दूषित पानी से बीमारियां फैलने का खतरा

443. श्री दलीचन्द डांगी (मावली) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा माइन्स से निकलने वाले दूषित पानी से पंचायत समिति मावली के कई गांवों को गम्भीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त दूषित पानी को शुद्ध कर उपयोग में लिये जाने की कोई योजना संचालित की जा रही है?

(2) पंचायत समिति मावली के ऐसे कौन-कौन से गांव हैं, जो उक्त दूषित पानी से ग्रसित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पंचायत समिति मावली का कोई भी गांव हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा माइन्स के दूषित पानी से ग्रसित नहीं है।

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

विभाग की जानकारी में उक्त पंचायत समिति में किसी भी गांव का पानी प्रदूषित नहीं है।

खानपुर में वन भूमि पर नये एनिकटों का निर्माण

444. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र खानपुर में वन भूमि पर कितने एनिकट कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में वन भूमि पर नये एनिकट बनाने का विचार रखती है यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत रेंज बकानी में ग्राम नाहर खो (रीझोन) में एक एनीकट टाइप II नाबार्ड योजनान्तर्गत राशि 6.50 लाख का स्वीकृत है तथा एनिकट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

(2) वन भूमि पर एनिकट निर्माण क्षेत्र की आवश्यकता एवं बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है।

प्रश्न संख्या-445

(स्थगित)

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सरकारी महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

2. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में नैयला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

3. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के खानपुर मुख्यालय में पी.जी. कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के खेल मैदानों पर से अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

5. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन एवं वास्तविक छात्र संख्या की निष्पक्ष जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रथम कक्षा के साथ ही नर्सरी कक्षाएं भी प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में एकीकरण के पश्चात् विद्यालयों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार समीक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के विद्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

9. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नव क्रमोन्नत सीनियर विद्यालयों में संकायवार विषय अध्यापक/प्राचार्य एवं रिक्त पदों के भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

10. अलवर जिले में अनेक विद्यालयों द्वारा पंचायत चुनावों के दौरान जारी फर्जी प्रमाण पत्रों एवं टी.सी. से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. अलवर शहर के पटरी पार क्षेत्र में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

12. प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) :

13. विधान सभा क्षेत्र आहोर में ग्राम गुड़ा बालोतान में सीनियर हायर सेकेण्ड्री विद्यालय में विज्ञान संकाय एवं ग्राम सांकरना में वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) :

14. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू में पिण्डवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

15. विधान सभा क्षेत्र महुवा के महुवा में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

16. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के राजकीय विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में सभी राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति/पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में पंचायत मुख्यालय पर राजकीय सीनियर सेकेण्ड्री विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में गत वित्तीय वर्ष शिक्षा से सम्बन्धित की गई घोषणाओं की अभी तक क्रियान्विति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

20. प्रदेश के विद्यालयों में चारित्रिक, सांस्कृतिक एवं योग शिक्षा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. प्रदेश में रोजगारोन्मुख शिक्षा को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिजोरावास, नीमोर एवं मोमनपुर को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा खेत्र बहरोड़ में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. राजकीय धर्मचन्द गांधी महाविद्यालय बहरोड़ में विज्ञान संकाय एवं भूगोल संकाय और स्नातकोत्तर कक्षाओं में हिन्दी साहित्य एवं भूगोल विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

25. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में श्रीमती कलावती देवी महावर राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय एवं कोटकासिम में आचार्य (एम.ए.) स्व:वित्तपोषित को राजकीय घोषित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के राजकीय माध्यमिक विद्यालय नसोपुर (कोटकासिम) में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में वंचित रही ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

30. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद के 42 अभ्यर्थियों को द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 में नियुक्ति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

31. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. राजकीय महाविद्यालय, बालेसर के लिए भूमि आबंटन करवाकर महाविद्यालय भवन का निर्माण करवाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, शेरगढ़ को शास्त्री महाविद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में उपखण्ड शेरगढ़ मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक एवं संस्कृत विद्यालयों में व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व अन्य वर्ग के रिक्त पदों को भरने एवं नव क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन पद सृजित कर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

36. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के सावर तहसील मुख्यालय पर राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

37. बाड़मेर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के क्षतिग्रस्त छात्रावास की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में लोक देवता महात्मा ईशरदासजी के जन्म स्थान भादरेश का विकास एवं संरक्षण को लेकर पैरोनोमा बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में शिक्षक भर्ती 2012 में भर्ती शिक्षकों का परिवीक्षाकाल समाप्त होने के बावजूद भी वेतन स्थिरीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में लोक कला को जीवित एवं संवर्द्धन रखने में अगुनी जाति मांगणिभार (लंगा) के जीवन स्तर को सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

कुं. जगत सिंह (कामां) :

41. विधान सभा क्षेत्र कामां के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

42. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सीमलवाड़ा उपखण्ड स्तर पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में गडागोकल, गोहलिया, अम्बाड़ा, मोहरी पटेलन, शिशोर उपली राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में एस.बी.पी. महाविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में संचालित विद्यालयों की चारदीवारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

47. विधान सभा क्षेत्र लूणी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालयों में एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोगड़ाकला, धुन्धाड़ा धवा में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र लूणी में ग्राम पंचायत मुख्यालय झवर एवं केरू में आई.टी.आई. खोलने एवं लूणी आई.टी.आई. में नये ट्रेड खोलने, लूणी कस्बे में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने एवं ग्राम पंचायत झंवर व केरू में माडल स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

49. प्रदेश में अध्यापकों के वेतन आनलाइन खाते में जमा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र करौली के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कनिष्ट लिपिकों की भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र करौली कें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

52. विधान सभा क्षेत्र निवाई के राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम राधाकिशनपुरा, अनवरनगर, झिराना, मोहम्मदनगर, खणदेवत, सिरोही, आकोडिया, बारेडा, गिरधारीपुरा, ककराज, धतूरी, ब्रजलालपुरा, मुमाना के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम लुहारा, सेदरिया, बिडोली, नटवाड़ा, सुनारा, ढाणीजुगलपुरा में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

55. विधान सभा क्षेत्र वैर में महाविद्यालय की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र वैर में आई.टी.आई. कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामपाल (बारां-अटरू) :

57. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू उपखण्ड मुख्यालय में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

म. रणवीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

58. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के विभिन्न विद्यालयों में प्राचार्य, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

59. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में स्थित सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में विषय अध्यापक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

60. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

61. विधान सभा क्षेत्र मावली में राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण कराने एवं शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

62. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में सरकारी बालिका महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

63. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में गणित, भूगोल, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान संकाय खोले जाने एवं उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा का सीमावर्ती एवं दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण रानीवाड़ा मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

65. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में विद्यालयों के खेल मैदान की बाउण्ड्रीवाल कराने एवं समतलीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में समानीकरण योजना के कारण प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन शिक्षक व छात्र रहित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में उपखण्ड स्तर पर महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

68. विधान सभा क्षेत्र चाकसू की ग्राम पंचायत चितौड़ा, पहाड़िया, झाड़ला एवं ग्राम पंचायत काठावाला के ग्राम जानकी बल्लभपुरा के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

69. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-द्वितीय जोधपुर को उपखण्ड मुख्यालय, फलौदी पर स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फलौदी में नये ट्रेड शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक-द्वितीय जोधपुर को उपखण्ड मुख्यालय, फलौदी पर स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय महाविद्यालय, फलौदी में छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर व्याख्याताओं के नये पदों की स्वीकृति एवं विभिन्न संकायों में सीटों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में उपखण्ड मुख्यालय बाप पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

74. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ में पंचायत समिति बावड़ी मुख्यालय पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के विद्यालयों में विषय व्याख्याताओं एवं अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

76. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कला संस्कृति हेतु युवा केन्द्रों में गतिविधियां बढ़ाने एवं युवाओं को युवा केन्द्रों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर (पीजी) में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के विद्यालयों में कक्षा कक्षों के निर्माण एवं खेल मैदान का निर्माण कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ाने एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़) :

81. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के घटियावली बालिका माध्यमिक विद्यालय को बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

82. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के स्कूलों में अध्यापक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) :

83. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में उपखण्ड रानी में नोर्म्स के अनुसार महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. उपखण्ड मारवाड़ जंक्शन पर महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के पंचायत समिति रानी के विनोवा जोड़ के बन्द किये गये प्राथमिक विद्यालय को पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

86. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में आर.एल. सहरिया स्कूल कालाडेरा के पुन: प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

87. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के उपखण्ड मुख्यालय उदयपुरवाटी नगरपालिका क्षेत्र में महाविद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा) :

88. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के अलसीसर (तहसील) में उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय धंधुरी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में सरकारी कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

91. राज्य में 200 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों को 8वीं से 12वीं में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला) :

92. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं विषय अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में खाजूवाला तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

94. प्रदेश में निजी विद्यालय खोलने की मान्यता देने के नियमों में शिथिलता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

95. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की ग्राम पंचायत मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

96. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के बानसूर में सरकारी कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

97. अलवर शहर के पुल पार क्षेत्र में गर्ल्स सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

98. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट में जीव विज्ञान संकाय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर में विज्ञान संकाय आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. जोधपुर के राजकीय पोलिटेक्निक कालेज एवं राजकीय आई.टी.आई. में खनन विद्या से सम्बन्धित तकनीकी कोर्सेज आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय अल्पभाषा राजमहल, राजकीय माध्यमिक विद्यालय विद्याशाला, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय 14 सेक्टर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शोभावतों की ढाणी एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बलेदव नगर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सम्राट अशोक उद्यान में बने खुले रंगमंच को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी को हस्तांतरित कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक कला प्रदर्शन और रंगमंच आयोजन के केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय विद्यालयों में भूमि-भवन, खेल सुविधा, शौचालय, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

103. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में मिड-डे-मील बनाने के लिए कार्यरत कुक कम हेल्पर (सी.सी.एच.) के मानदेय में बढ़ोतरी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की घड़साना के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. प्रदेश में तृतीय भाषा (पंजाबी) विषय अध्यापकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना में ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भवन का निर्माण कराने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

108. प्रदेश में माडल स्कूलों में छात्रावासों का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

110. पूर्व में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय सांचौर को प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. सांचौर मुख्यालय पर स्थित राजाराम शिक्षण संस्थान एवं आजमा शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय दोनों का परीक्षा केन्द्र अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जालौर की मिलीभगत से जानबूझकर राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

112. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवीन कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर) :

113. विधान सभा क्षेत्र जालौर में महिला महाविद्यालय में भूगोल विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

114. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के विद्यालयों में रिक्त पड़े कर्मचारियों एवं अध्यापकों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

115. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बाहेड़ा में वाणिज्य संकाय एवं विज्ञान संकाय में गणित विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय निम्बाहेड़ा के भवन के पश्चिम दिशा में चारदीवारी एवं पूर्व में निर्मित चारदीवारी की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

117. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा में स्नातकोत्तर पर संस्कृत व अंग्रेजी साहित्य तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में समाज शास्त्र व भूगोल तथा वाणिज्यिक संकाय में लेखा शास्त्र एवं सांख्यिकी विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. जनजाति बाहुल्य उपखण्ड छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

120. किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर बालिका शिक्षा एवं स्वरोजगार को बढ़ावा हेतु महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के विद्यालयों में अतिरिक्त व्याख्याता एवं अध्यापकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के प्रमुख कस्बे अराई में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के विद्यालयों में खेल मैदान एवं भवन रहित विद्यालयों के भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

124. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में विराटनगर तहसील मुख्यालय पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण (आई.टी.आई.) संस्थान खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के उपखण्ड विराटनगर मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के तकनीकी महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127. प्रदेश के विद्यालयों में चारित्रिक, सांस्कृतिक एवं योग शिक्षा दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कक्षा कक्षों (Class Room) के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

129. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में कला प्रेमियों, रंगकर्मियों/कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने हेतु कोई नियमित रंगमंच नि:शुल्क उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

130. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

131. विधान सभा क्षेत्र भादरा में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र भादरा के विभिन्न उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, व्याख्याताओं, प्रधानाध्यापकों, अध्यापको एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद शीघ्र भरवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र भादरा के वंचित पंचायत मुख्यालयों के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र भादरा के विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय एवं वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. प्रदेश में अध्यापकों की स्थायी स्थानान्तरण नीति बनाने एवं प्रतिबंधित जिलों (डार्क जोन) के अध्यापकों के स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

136. बीकानेर के डूंगर कालेज में M.COM-MANAGEMENT, M.COM, E AND FM विषय शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

137. बीकानेर से शिक्षा निदेशालय को धीरे-धीरे उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

138. बीकानेर से र.म.सा. (विभाग) को उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) :

139. राजकीय महिला महाविद्यालय सीकर के भवन निर्माण के लिये वित्तीय स्वीकृति जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में सक्षम कुलपति व विशेषाधिकारी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र सीकर के राजकीय विद्यालयों में नये कमरे निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र सीकर के शौचालय रहित विद्यालयों में शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिये वित्तीय स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

144. राज्य में लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिये विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. कोटा में स्वीकृत ट्रीपल आई.टी. कालेज की स्थापना में धीमी गति से स्थिति पर उपन्न चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने, विज्ञान एवं वाणिज्य विषय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. कोटा में स्वीकृत नवीन महाविद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि आबंटन एवं रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. कोटा शहर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों प्रयोगशाला कक्ष सहित आवश्यक निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) :

149. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के उपखण्ड मुख्यालय सैपऊ में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

150. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में राजकीय कालेज न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) :

151. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के सुविधाविहीन स्कूलों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने तथा कक्षा कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. जयपुर शहर के स्कूलों में खाली पडे शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. जयपुर शहर में नये महाविद्यालय प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

154. विधान सभा क्षेत्र जायल में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोमणा, दुगस्ताऊ, दुगौली एवं लुणसरा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र जायल में स्थित विभिन्न वियालयों में सम्बन्धित विषय के व्याख्याताओं तथा प्रधानाचार्या के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र जायल के आदर्श ग्राम जोधियासी में स्थित रा.उ.मा.वि. में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र जायल के उपखण्ड मुख्यालय में राजकीय I.T.I. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

158. विधान सभा क्षेत्र कपासन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र कपासन के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के अनुपात में अध्यापक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र कपासन के प्रा.वि., उ.प्रा.वि., मा.वि. एवं उ.मा.वि. में रिक्त III ग्रेड अध्यापक, II ग्रेड अध्यापक, विषय अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) :

161. बेंगू, गंगरार, रावतभाटा में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

162. झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर स्थित महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं के विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

164. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के राजकीय महाविद्यालय रामगंजमण्डी में व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने एवं विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के मोडक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के नयागांव या बोराबांस में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

169. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की ग्राम पंचायत रूंध इकरन के ग्राम बझेरा के मा. विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्राम महगाया के बालिका विद्यालय को मा. विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के सभी स्कूलों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों के भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की ग्राम पंचायत मडरपुर के ग्राम बराखुर के उ.प्रा.वि. को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

173. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के आबादी चकों में स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के स्कूलों में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के नये राजस्व गांव व ढाणियों में नये स्कूल खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

176. विधान सभा क्षेत्र नगर के राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र नगर में बेर्रू, आलमशाह, जालूकी माध्यमिक स्कूल को उच्च माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र नगर में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल व शौचालय उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

179. राज्य में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिये समय-समय पर अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र नगर में सरकारी विद्यालयों में शुरू की गई कम्प्यूटर शिक्षा पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

181. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की पंचायत समिति सूरतगढ़ के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण एवं भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

184. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की शेखावाटी लोक कला संस्कृति को बचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के रामगढ शेखावाटी कस्बे में संचालित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पद होने से उपन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

188. जयपुर में संचालित प्रदेश के एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय को चालू रखने तथा संसाधन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

189. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में एक पोलोटेक्निक राजकीय महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के विजयनगर में एक महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में राजकीय औद्योगिक संस्थान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्कृत महाविद्यालय को राजकीय संस्कृत महाविद्यालय घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी) :

193. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में जर्जर स्कूलों के नये भवन बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

194. जयपुर जिले में विद्युत एवं पेयजल सुविधाओं से वंचित विद्यालयों में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में विद्यार्थी मित्रों को सेवा में पुन: लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

196. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं कर्मचारियों के रिक्त पदो को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के जिला सीकर के विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) :

198. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ के उ.प्रा.वि. नोसरिया के स्थान पर उ.प्रा.वि. मिगसरिया व उ.प्रा.वि. मिंगसरिया के स्थान पर उ.प्रा.वि. नोसरिया करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के माध्यमिक विद्यालय सांवतसर को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

200. राज्य में हाल ही में आरपीएससी द्वारा चयनित द्वितीय श्रेणी शिक्षकों में से अनेक एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, नि:शक्तजन एवं गम्भीर रोग से पीड़ित चयनित अभ्यर्थियों को उनके मूल जिले से बाहर नियुक्त/पदस्थापन किये जाने से शिक्षकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ शहर में स्थित राजकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण नहीं किये जाने एवं महाविद्यालय में रिक्त पदों को नहीं भरने के कारण विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने से शिक्षा पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

203. संस्कृत शिक्षा विभाग में शैक्षणिक व अशैक्षणिक संवर्ग के पद रिक्त होने से संस्कृत शिक्षा पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

204. संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर में प्रशासनिक खींचतान, अनियमितताओं एवं भर्तियों में की गयी धांधली के कारण विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

205. राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों के किये गये एकीकरण से सीकर जिले में हजारों की संख्या में छात्रों के ड्राप-आउट होने एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक भी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं होने के बावजूद नये स्कूल नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा) :

206. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के भिवाड़ी में महाविद्यालय व आजादी के समय से बनी उप तहसील टपूकड़ा में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में नवीन बनाई गई 11 ग्राम पंचायतों एवं पुरानी ग्राम पंचायतों में रा.उ.मा.वि. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में उच्च मैरिट प्राप्त प्रधानाध्यापकों को अलवर में स्थानान्तरण करने एवं उनका प्रशिक्षण काल एक साल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के नव क्रमोन्नत विद्यालयों में शिक्षा कर्मियों एवं अधिकारियों की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. प्रदेश में विद्यार्थी मित्रों, कम्प्यूटर, शिक्षक की समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

211. विधान सभा क्षेत्र बायतू की प्रत्येक पंचायत समिति और तहसील मुख्यालय पर एक-एक विकसित पुस्तकालय की स्थापना करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

212. विधान सभा क्षेत्र बायतू के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक कम्प्यूटर शिक्षक की अनिवार्यता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र बायतू की बायतू गिडा और पाटोदी पंचायत समिति मुख्यालयों पर बालिका छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र बायतू के विद्यालयों में लैपटाप वितरण की योजना पर पुर्नविचार कर विद्यार्थियों को प्रोत्साहन की अन्य योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

215. उपखण्ड मुख्यालय, बायतू में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करवाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

216. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में हर पंचायत मुख्यालय पर राजकीय सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. विधान सभा क्षेत्र खेतडी में सभी शिक्षण संस्थाओं में मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र खेतडी मुख्यालय पर राजकीय उ.मा.वि. खेतड़ी एवं राजकीय महाविद्यालय में कृषि संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में अंग्रेजी माध्यम का माडल विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा) :

221. वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा की पालना में विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में 10 माडल विद्यालयों की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में नवीन आई.टी.आई. खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

223. प्रदेश में रोजगार एवं कुशलता प्रदान करने वाली शिक्षण व्यवस्था की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

224. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के विद्यालयों में सभी संवर्गों के रिक्त पद भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

225. उपखण्ड मुख्यालय मडरायल (जिला-करौली) में महाविद्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

226. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विद्यालयों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विद्यालयों में बिजली, शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

229. बीकानेर में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के भवन का आधुनिकीकरण एवं उसमें पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

230. विधान सभा क्षेत्र चाकसू की फागी तहसील में नवसृजित ग्राम पंचायत मुख्यालय मोहनपुरा पृथ्वीसिंह के राजकीय विद्यालय को उ.मा.वि. करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-47 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-47 मुख्य शीर्षक पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1 पाली जिले में पर्यटन की दृष्टि से जंवाई बांध के पास ''वाटर पार्क'' हेतु भूमि उपलब्ध करवाने एवं ''बोटेनिकल गार्डन'' बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

2 विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में सिलीसेड में पर्यटकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

3 विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पर्यटकों को सुविधा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4 विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सामोद वीर हनुमान मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

5 विधान सभा क्षेत्र चौमूं में महार मालेश्वर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

6 विधान सभा क्षेत्र खानपुर के महुबोरधा पर्यटक स्थल व गागरोन का सम्पूर्ण विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

7 विधान सभा क्षेत्र सिवाना के हल्देश्वर मिनी माउण्ट को पर्यटन विभाग में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

8 अलवर के सरिस्का क्षेत्र में पर्यटकों के प्रवेश पर पाबन्दी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

9 अलवर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु पर्यटक स्थलों के विकास एवं विशेष पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

10 अलवर में हसन खान मेवाती की बाबड़ी का जीर्णोद्धार करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

11 विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के केलवाड़ा कस्बे में सीताबाड़ी रामगढ़ कस्बे में रामगढ़ माता एवं 16 वीं शताब्दी में बने शाहाबाद किले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) :

12 प्रदेश में पर्यटकों की सुविधाओं में सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

13 बाला किला अलवर में आमेर किले की तरह डे और नाईट सांस्कृतिक प्रोग्राम शुरू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में महाराज भृतहरी धाम का सौंन्दर्यीकरण करके विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नीलकण्ठ महादेव स्थान पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सिलीसेड झील में नौकायान को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17 विधान सभा क्षेत्र बहरोड के तिजारा में सूरजमुखी स्थान का सौन्दर्यीकरण करके विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

18 प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने व मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए प्रभावी पर्यटन नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

19 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के विख्यात बघेरा एवं सरवाड़ स्थित ऐतिहासिक स्मारकों व मंदिरों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

20 पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्व बाड़मेर के ग्राम महाबार के धोरों एवं किराड़ू मंदिर के संरक्षण हेतु कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

कुं. जगत सिंह (कामां) :

21 विधान सभा क्षेत्र कामां के ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल के विकास हेतु विशेष योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

22 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में मानगढ़ धाम जिला बांसवाड़ा को पर्यटन की दृष्टि से राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23 जिला डूंगरपुर में स्थापित देव सोमनाथ मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर, बेडसी गंगाधाम, वादधाम एवं नीलकंठ महादेव को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कड़ाणा बैक वाटर पर जलमग्न पहाड़ियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25 जिला डूंगरपुर के खण्डहर बने किलों एवं दुर्ग को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26 जिला डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

27 विधान सभा क्षेत्र लूणी में हिरणों के प्राकृतिक आवास क्षेत्र धवा व गुडा विश्नोइयान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28 विधान सभा क्षेत्र लूणी में काले हिरणों व जंगली वन्यजीवों के लिए रेस्क्यू सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

29 करौली स्थित रंगमा के ताल का पर्यटन की दृष्टि से सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के सम्बन्धध में चर्चा के लिए।

30 विधान सभा क्षेत्र करौली में स्थित चिनायता देवी के मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

31 विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्राम जहाज में स्थित देव मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

32 भीण्डर, मेणार व सीतामाता अभयारणय को उदयपुर ट्यूरिस्ट सर्किट में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

33 सीकर जिले में पर्यटन को बढावा देने हेतु हैरिटेज हवेलियों एवं बावडियों का सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

34 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

35 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के सूर्य सागर तालाब का एवं उसकी पाल पर बने पार्क का सौन्दर्यीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

36 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित सुन्धा माता मंदिर को पर्यटन के नक्शे में शामिल किये जाने एवं श्री सुन्धा माता मंदिर और श्री अम्बाजी माता मंदिर को धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

37 विधान सभा क्षेत्र घाटोल स्थित माही डैम में पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

38 विधान सभा क्षेत्र फलौदी के फलौदी एवं बाप क्षेत्र को ग्रामीण पर्यटन एवं सोलर हब में विकसित किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

39 राज्य के पर्यटन मानचित्र में फलौदी एवं खींचन की हवेलियों को दर्शाते हुए फलौदी के पुरातात्विक महत्वपूर्ण दुर्ग का जीर्णोद्धार कर पर्यटकों के लिए विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40 विधान सभा क्षेत्र फलौदी के फलौदी एवं बाप क्षेत्र के पर्यावरण एवं जीव प्रेमी बिश्नोई ग्रामीण क्षैत्रों को ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

41 प्रवासी पक्षी साईबेरियन (कुरजां) की शरणस्थली ग्राम खींचन, फलौदी के तालाब पर पर्यटन विकास हेतु मूलभूत सुविधाओं का विकास किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

42 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 फलौदी एवं बाप स्थित पर्यटन विभाग के मिड-वे को पर्यटकों के सुविधार्थ पुन: शुरू करने और आवास सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

43 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर हाडा रानी महल का पर्यटन की दृष्टि से जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के चावण्ड महाराणा प्रताप स्मारक महल में लाइट एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

45 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जयसमंद झील पर रूठीरानी महल से हवा महल तक रोप-वे वायरिंग द्वारा झूले लगाने के संबध में चर्चा के लिए।

46 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की प्राचीन धरोहर भौराईगढ़ को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

47 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की प्राचीन धरोहर सराड़ागढ़ की जीर्ण-शीर्ण अवस्था को देखते हुये नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

48 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के पर्यटन स्थल आचार्य भिक्षु स्थल पर रोप-वे बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49 बजट घोषणा वर्ष 2014-15 में मारवाड़ जंक्शन से मावली रेलवे को हैरीटेज घोषणा की क्रियान्विति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

50 विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के ग्राम गुढ़ा के ऐतिहासिक व धार्मिक तथा अन्य पर्यटन स्थल जो पहाड़ी पर स्थित है, को सुदृढ़, सुरक्षित एवं संरक्षित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा) :

51 मण्डावा शहर को हैरीटेज सिटी बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

52 पाली शहर के लाखोटिया उद्यान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

53 विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की कायलाना झील एवं संलग्न क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

54 विधान सभा क्षेत्र बानसूर में ताल वृक्ष, गटवा जी, शीतलनाथ एवं धामेडा धाम स्थानों का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

55 विधान सभा क्षेत्र भीम में महाराणा युद्ध स्थली दिवेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मथारा पर रोप-वे लाइट एण्ड साउण्ड कैफेटेरिया व हार्स एवं केमल राइडिंग आदि की सुविधा विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

56 अलवर के पांडूपोल हनुमान मंदिर तक पर्यटकों को पहुंचाने के लिये सिरस्का अभयारण्य से रास्ता खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

57 जालौर जिले की धरोहर जालौर दुर्ग एवं सुन्धा माता मंदिर को पर्यटक स्थल घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

58 करौली जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक स्थल केलादेवी, श्री मदनमोहनजी, श्री महावीर जी एवं बालाजी के मंदिरों को धार्मिक पर्यटक स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

59 विधान सभा क्षेत्र चाकसू (चम्पावती नगरी) में बिखरी पड़ी पुरा सम्पदा को संरक्षित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

60 निम्बाहेड़ा नगर के प्रमुख दर्शनीय एवं पर्यटक स्थल श्री अम्बा माताजी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के छोटी सादड़ी के दर्शनीय स्थल श्री भंवर माताजी स्थान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा मेवाड़ एवं मालवा क्षेत्र के ख्यातिनाम स्थल श्री गंगेश्वर महादेव स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63 राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मृतक आश्रितों को दो वर्ष के परिवीक्षा प्रशिक्षु को दी गई नियुक्तियों के 37 कर्मचारियों का फिक्सेशन (स्थायीकरण) करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के झूणजी बाब्जी दर्शनीय स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

65 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के सिलोरा में स्थित दर्शनीय स्थल ''पीताम्बर की गाल'' का जीर्णोद्धार कर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्राम सूरसुरा में स्थित लोक देवता श्री वीर तेजाजी महाराज की निर्वाण स्थली एवं लाछा बावड़ी स्थल को

धार्मिक स्थल घोषित कर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

67 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थल ''मौखम विलास'' के सौन्दर्यीकरण एवं गुन्दोलाव झील ओर हमीर सागर के घाटों पर सौन्दर्यीकरण कार्य करने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

68 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जगदीशधाम, केमरी, घटवासन देवी, गुढाचन्द्रजी एवं गढ़मोरा में मोरध्वज के महल व कुण्ड को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

69 प्रदेश में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

70 प्रदेश में पर्यटक स्थलों में जन सुविधाओं को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

71 विधान सभा क्षेत्र भादरा में गोगामेड़ी स्थित गोगाजी पैनोरमा को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

72 विधान सभा क्षेत्र भादरा में लोक देवता गोगाजी के पवित्र श्रृद्धा स्थल गोगामेड़ी को पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

73 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसील कोटड़ी, भीलवाड़ा में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण चार भुजा नाथ के मंदिर एवं तालाब जहां भगवान का स्नान होता है, को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण घाटारानी मंदिर का विकास कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

75 मुकन्दरा हिल्स कोटा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76 राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा को पर्यटन में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77 विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के हाड़ौती के पर्यटन स्थलों का विकास कर पर्यटन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

78 विधान सभा क्षेत्र कपासन के तीर्थ स्थल मात्रीकुण्डिया, शनि महाराज, सांवरियाजी, दिवानाशाह दरगाह को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) :

79 विधान सभा क्षेत्र बेगू में मेनाल मंदिर एवं झरने को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

80 झुन्झुनूं जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. मंजू बाघमार (जायल)

81 विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्राम गो. मांगलोद में स्थित विश्व प्रसिद्ध दधिमति माताजी के मंदिर का पर्यटन की दृष्टि से जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

82 भरतपुर स्थित घना पक्षी विहार को पांचना बांध से गम्भीर नदी के जरिये पानी दिलाकर पर्यटकों को आकर्षित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

83 भरतपुर स्थित सुजानगंगा नहर का जीर्णोद्धार कर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84 भरतपुर जिले में अनेक पर्यटक स्थल होने के कारण पर्यटक जिला घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

85 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में स्थित जाखम डैम जिला प्रतापगढ़ की पाल पर बने पार्क का विस्तार कर पर्यटन की दृष्टि से विकसित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

86 विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में देशी पर्यटक ट्यूर प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87 विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए सम-खुहडी रोड को चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88 विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में विदेशी पर्यटकों के लिए तेरहवीं शताब्दी के बसे गांवों को पर्यटक स्थल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता (नगर) :

89 केवलादेव के घना में पर्यटन की दृष्टि से पक्षियों की आवक कम होने की चिन्ता को दूर करने के लिए पांचना बांध से पानी की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

90 भरतपुर में आर.टी.डी.सी. में पर्यटकों को बढ़ावा देने की दृष्टि से उनके खानपान व आवागमन की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

91 बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग में यात्रियों की सुरक्षा एवं ठहरने व हैरीटेज सिटी कामां/डीग में समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

92 भरतपुर जिले के पर्यटन स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से पर्यटक स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93 डीग में जल महल के रखरखाव व प्रदर्शनी समय-समय पर लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

94 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के फतेहपुर व रामगढ़ कस्बे में आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

95 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

96 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पर्यटन की दृष्टि से हवेलियों का रख-रखाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

97 फतेहपुर कस्बे स्थित बावड़ी, जोहड़ों एवं क्षतिग्रस्त दर्शनीय स्थलों के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

98 फतेहपुर शेखावाटी में पर्यटकों की संख्या को देखते हुए पर्यटन सेवा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

99 राज्य की नई पर्यटन नीति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा) :

100 विधान सभा क्षेत्र तिजारा में तहसील मुख्यालय पर सदियों पुराना किला–तिजारा पोर्ट के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101 विधान सभा क्षेत्र तिजारा के ग्राम इन्दौर में पुराने किले का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102 विधान सभा क्षेत्र तिजारा में बाबा भृतहरी महाशय गुम्मट का जीर्णोद्वार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

103 आर.टी.डी.सी. में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के कारण आर.टी.डी.सी. को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

104 पर्यटन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

105 विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में स्थित लोहार्गल धाम के विकास की योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

106 देश में आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या में से राज्य में आने वाले विदेशी पर्यटकों का प्रतिशत वर्ष दर वर्ष घटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

107 शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के संरक्षण एवं रख-रखाव हेतु विभाग द्वारा पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं कराये जाने से इन हवेलियों के संरक्षण पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

108 विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के शहर में स्थित पुरा विरासतों को संरक्षित करने एवं हर्ष पर्वत को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

109 बाड़मेर में पर्यटन को विकसित करने के लिए पर्यटन विकास केन्द्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

110 राज्य में पर्यटन को विकसित करने के लिए पुरा स्मारकों, प्राचीन मंदिरों का पुर्नरूद्धार करने व प्रसिद्ध मेले व मंदिरों का विकास करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

111 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थित ग्राम पंचायत गाडराटा में स्थित बाबा सुन्दरदास मंदिर को पर्यटन स्थल बनाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

112 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी भोपालगढ़ को पर्यटन स्थल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

113 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पर्यटन की दृष्टि से होटल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी बाबा रामेश्वर धाम बेसई को पर्यटन स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा) :

115 राज्य के पर्यटकों हेतु संचालित रेलों का उचित प्रबंधन एवं अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116 पर्यटन स्थलों पर असामाजिक तत्वों द्वारा नाम लिखने, चित्रकारी कर या अन्य प्रकार से स्थापत्य कला को नुकसान पहुंचाने के संबध में चर्चा के लिए।

117 राज्य में पर्यटकों की सुरक्षा को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

118 पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु राज्य में मनाये जाने वाले त्यौहारों एवं विशिष्ट उत्सवों का उपयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

119 जिला करौली में नवीन पर्यटक स्थल विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

120 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

121 बीकानेर शहर की हैरीटेज धरोहरों की सुरक्षा एवं रख-रखाव करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

122 बीकानेर शहर में पर्यटन पुलिस की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-3

लिखित वक्तव्य

(मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति व मांग संख्या 47-पर्यटन पर माननीय सदस्य श्री हमीर सिंह भायल का वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया)

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में तीन तहसील 2 उपखण्ड कार्यालय, 3 पंचायत समिति हैं जिसमें लगभग 4 लाख जनसंख्या निवास करती है। 69 ग्राम पंचायतें स्थित हैं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा जिला हमारा बाड़मेर है। बालिका शिक्षा का स्तर बहुत ही कमजोर है, उच्च शिक्षा में मेरे क्षेत्र में एक भी निजी या राजकीय महाविद्यालय नहीं है।

वर्तमान सरकार द्वारा अहम निर्णय लेकर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय खोल दिये गये हैं। सिवाना ब्लाक में लगभग 40 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जिसमें लगभग 800 से 900 छात्र केवल मात्र 12वीं कक्षा में अध्ययन करते हैं। जिसमें से 300 से 400 बालिकाएं अध्यायनरत हैं मेरे सिवाना मुख्यालय से उच्च शिक्षा हेतु जालौर, जोधपुर, बाड़मेर जाना पड़ता है जिसकी दूरी अधिक एवं आना-जाना सुविधाजनक जनक नहीं है।

मेरी अध्यक्ष जी आपके जरिये मांग रहेगी कि पिछले बजट में है कि राजकीय महाविद्यालय-सिवाना मुख्यालय पर बजट सत्र 2015-16 में खुलवाने हेतु मेरा C.M साहिबा एवं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से विशेष आग्रह रहेगा। जनता को वर्तमान सरकार पर पूर्ण विश्वास है।

राजस्थान में कला एवं संस्कृति की कोई कमी नहीं है। कलाकारों की कला को परखने की आवश्यकता है मेरे क्षेत्र में संस्कृति को जीवित रखने हेतु मेलों का आयोजन किया जाता है। उन सबका आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर ही होता है जो वर्तमान में आयोजन करने में असमर्थ है।

कला एवं सांस्कृति मंत्रीजी से मेरा आग्रह रहेगा कि मेरे क्षेत्र में भरे जाने वाले गरे मेले जिनमें-सिवाना का गरे मेला, लाडेरा का गरे मेला, खण्डप का गरे मेला, मीठा का मेला, गोपणेश्वर महादेव मेला आदि को विभाग के अधीन लेकर इनको बड़े स्तर पर मनाने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए।

पर्यटन के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत विकसित हो सकता है। मेरे यहां पर वीर राठौड़ दुर्गादास की कर्मस्थली हल्देश्वर महादेव मंदिर जिसको पश्चिमी राजस्थान का मिनी माउण्ट कहा जाता है, यह स्थान दुर्गम पहाड़ियों में स्थित है, जिसे अरावली पर्वतमाला की सतपुड़ा पहाड़ी कहा जाता है, बरसात के दिनों में झरने से भरपूर यह स्थान बहुत ही रमणीक हो जाता है जहां हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है।

इस गम्भीर एवं दुर्गादास जी की कर्मस्थली को पर्यटन विभाग में लेकर यहां पर सड़क बनवाना, रोप वे लगवाना आदि कार्य करके मंदिर का विकास किया जा सकता है।

इसके अलावा सिवाना का प्राचीन दुर्ग जो अब खण्डहर बनता जा रहा है, प्राचीन चारभुजा मंदिर जो देवस्थान विभाग के अधीन है, मोकलसर की प्राचीन बावड़ियां, सिवाना की प्राचीन संत महात्माओं की समाधियां आदि पर्यटन के माध्यम से विकसित की जा सकती हैं।

मेरे क्षेत्र में प्राचीन हिमलाज माता मंदिर, आसोना ब्रहाजी मंदिर दन्ताला पीरसा की दरगाह पंचतीर्थ स्थल हैं।

मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि सिवाना दुर्ग का विकास एवं दुर्ग की तलहटी में वीर वर दुर्गादास राठौड़ का स्मारक बनाया जाकर एक मेले का आयोजन किया जावे।

इस हेतु मैंने प्रयास भी किया है राजस्थानी संस्कृति धरोहर संरक्षण् प्रौलती प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष जी का दौरा भी करवाया है।

कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग इस ओर पहल करके क्षेत्र के विकास में चार चांद लगा सकते हैं क्षेत्र की जनता की विशेष मांग एवं पश्चिमी राजस्थान का मिनी माउण्ट विकसित हो सकेगा इसमें वन विभाग का सहयोग भी लिया जाना आवश्यक है सिवाना दुर्ग अभी तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है इस हेतु भी कार्यवाही की जाती है।

(मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति व 47-पर्यटन पर माननीय सदस्य श्री भागीरथ चौधरी का वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति एवं मांग संख्या 47-पर्यटन के अन्तर्गत मैं अपने क्षेत्र के शैक्षिक उन्नयन एवं पर्यटन स्थलों को विकसित कर किशनगढ़ में पर्यटन उद्योग

स्थापित करने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर बालिका शिक्षा एवं है। स्वरोजगार को बढ़ाने हेतु महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की महती आवश्यकता है। अत: तकनीकी शिक्षा विभाग की विभागीय कार्य योजना वर्ष 2015-16 में किशनगढ़ में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की सक्षम स्वीकृति जारी करावें एवं किशनगढ़ (अजमेर) स्थित राजकीय शार्दल बालिका माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन हेतु राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कृष्णापुरी के खेल मैदान एवं राजकीय शार्दुल बालिका माध्यमिक विधलय को आबंटित भवन निर्माण भूमि को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कृष्णापुरी के खेल मैदान के रूप में दिलाने की (प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा) परस्पर भूमि हस्तान्तरण कराने की सक्षम विभागीय स्वीकृति अविलम्ब जारी कराएं क्योंकि, गत 06 माह से उक्त पत्रावली स्वीकृति की राह में शासन सचिवालय जयपुर में भटक रही है। अत: मंत्री महोदय इस पत्रावली को तत्काल स्वीकृति करावें।

मैंने गत बजट सत्र 2014-15 में भी अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से किशनगढ़ (अजमेर) स्थित शहरी क्षेत्र में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गत 8-10 वर्षों से स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अध्ययन कराये जाने वाले विषयों जैसे चित्रकला, इतिहास, संस्कृत, गणित एवं कम्प्यूटर विज्ञान आदि के नियमित स्थाई व्याख्याताओं के पदों की स्वीकृति करने की पुरजोर मांग उठाई थी लेकिन नियमित पदों का आबंटन आज दिनांक तक नहीं हुआ है। अत: अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पुन: शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि शैक्षणिक सत्र 2015-16 में उक्त सभी विषयों के पदों की सक्षम विभागीय स्वीकृति जारी करावें ताकि विद्यालय में अध्ययनरत 800 बालिकाओं पर प्रतिमाह पड़ने वाले अनावश्यक आथिक भार से मुक्ति मिल सके। मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ में भी विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान, गणित आदि में छात्र संख्या अधिक होने के फलस्वरूप एक ही कक्षा में ज्यादा छात्रों को बैठाकर एक साथ अध्ययन कराये जाने की समस्या से राहत प्रदान करने हेतु एक-एक अतिरिक्त व्याख्याता के उक्त विषयों के नवीन पदों की स्वीकृति अविलम्ब जारी कराने की मांग भी गत वर्ष आपके समक्ष रखी थी पर उक्त समस्या आज भी जस की तस है। साथ ही मेरे मदनगंज शहरी क्षेत्र में स्थित दो उच्च माध्यमिक

विद्यालयों में जिसमें प्रथम राजकीय शार्दुल प्रथम राजकीय शार्दुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय एवं दूसरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर में वाणिज्य संकाय में अध्ययन की सक्षम स्वीकृति भी शैक्षणिक सत्र 2015-16 में जारी करावे। किशनगढ़ (अजमेर) विधान सभा क्षेत्र के प्रमुख कस्बे अरांई में राजकीय महाविद्यालय खोलने की महती आवश्यकता है अत: आगामी शिक्षण सत्र 2015-16 में इसकी स्वीकृति अविलम्ब जारी करावें। जिससे अराई कस्बे एवं तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के बालक-बालिकाओं को सुलभ एवं सुगम उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। ग्रामीण अंचल के बालक-बालिकाओं पर पड़ने वाले अनावश्यक श्रम, समय एवं आर्थिक भार से मुक्ति मिल सके। वहीं किशनगढ़ (अजमेर) में संत महाकवि श्री नागरीदास जी के नाम से साहित्य एवं चित्रकला अकादमी अथवा आर्ट गैलेरी की स्थापना की महत्ती आवश्यकता है जिससे किशनगढ़ की विश्वविख्यात चित्रकला शैली बणी-ठणी को एक नया आयाम मिलते हुये कला एवं साहित्य जगत में पहचान मिल सके और किशनगढ़ के कलाकारों को रोजगार का परोक्ष लाभ अधिकाधिक प्राप्त हो सके।

इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से अनुदान की मांग संख्या 47 पर्यटन के अन्तर्गत किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 3 प्रमुख स्थानों पर स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पौराणिक पर्यटन स्थलों को विकसित कर किशनगढ़ में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में पर्यटन मंत्री महोदय से निवेदन है कि किशनगढ़ (अजमेर) की पंचायत समिति मुख्यालय सिलोरा में स्थित दर्शनीय स्थल पिताम्बर की गाल का जीर्णोद्धार कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने की प्रभावी योजना का क्रियान्वयन राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के माध्यम से कराकर वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवश्यक बजट की स्वीकृति जारी करायें एवं किशनगढ़ (अजमेर) शहरी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक, पौराणिक स्थल मौखम विलास के सौन्दर्यीकरण एवं गुन्दोलाव झील और हमीर सागर के घाटों पर सौन्दर्यीकरण कार्य कराने की महती आवश्यकता की प्रभावी योजना की क्रियान्विति ''राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना'' के माध्यम से कराने के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करा कर आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 में सक्षम स्वीकृति जारी कर बजट आबंटन भी करायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे क्षेत्र में कई गांव धार्मिक आस्था के प्रमुख केन्द्रों में राज्य में अपना विशिष्ठ स्थान रखते हैं जिसमें मुख्यत: निम्बार्ककाचार्य पीठाधिश्वर सलेमाबाद एवं ग्राम सुरसुरा स्थित श्री वीर तेजाजी महाराज की निर्वाण स्थली प्रमुख है। सुरसुरा स्थित ऐतिहासिक एवं पौराणिक धार्मिक स्थल लोक देवता श्री श्री वीर तेजाजी महाराज की निर्वाण स्थली एवं लाच्छा बावड़ी स्थल को धार्मिक स्थल घोषित करायें।

आपने मुझे, मेरे क्षेत्र की बात रखने का मौका दिया, धन्यवाद।